ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्

भगवान इस जग के कण-कण में विद्यमान हैं।

आदित्य नारायण चोपड़ा

adityachopra@punjabkesari.com

दलदल में ट्रम्प

भारत ने हमेशा युद्ध संकट का समाधान संवाद और कूटनीति से करने का समर्थन किया है। भारत ने हमेशा समूचे विश्व को शांति का संदेश देते हुए बार-बार कहा है कि यह समय युद्ध का नहीं, भगवान बुद्ध के दिखाए मार्ग का अनुसरण करने का है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान के साथ शांतिवार्ता की पहल करने और 5 दिन की युद्ध विराम की घोषणा करने के तुरन्त बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को फोन घुमाया और पश्चिम एशिया संघर्ष और होर्मुज को लेकर चर्चा की। ट्रम्प की इस पहल से स्पष्ट है कि वे पश्चिम एशिया के संकट को सुलझाने के लिए भारत को एक विश्वसनीय मित्र के रूप में देख रहे हैं। शायद ट्रम्प को इस बात का अहसास है कि ईरान के साथ युद्ध विराम को सफल बनाना है और तेल की सप्लाई निर्बाध रूप से जारी रखनी है तो भारत की भूमिका सबसे अहम है। ट्रम्प के शांति संकेत देते ही विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से बातचीत की थी। उसके बाद ट्रम्प की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से बातचीत हुई। इस कूटनीतिक टाइमिंग के पीछे भारत ने बहुत ही सतर्कता और सूझबूझ से काम लिया। जब अमेरिका ईरान के बिजली संयंत्रों और बुनियादी ढांचों को तबाह करने पर आमादा था तब भारत ने वाशिंगटन के सुर में सुर मिलाने से परहेज किया। इसका सीधा कारण यह है कि ईरान के साथ भारत के गहरे ऐतिहासिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंध हैं। भारत ईरान के चाबहार पोर्ट का संचालन कर रहा है, जो मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए भारत का 'गेटवे' है। इसके अलावा, खाड़ी देशों में लाखों भारतीय काम करते हैं। यदि भारत युद्ध के चरम पर अमेरिका का खुला समर्थन करता तो क्षेत्र में उसके अपने हित खतरे में पड़ जाते। नई दिल्ली शुरू से ही कूटनीति और संवाद के जरिए तनाव कम करने का पक्षधर रहा है, न कि बमबारी का। इसलिए जब तक युद्ध के बादल सबसे ज्यादा घने थे, भारत ने पेंटागन की युद्ध नीतियों से खुद को अलग रखा।

> **ट्रम्प का यूटर्न इस बात का संकेत है कि वह युद्ध रोकने के पक्षधर हैं लेकिन इजराइल बेलगाम गुंडे की तरह व्यवहार कर रहा है। ईरान और लेबनान पर लगातार हमले कर रहा है और ईरान भी अपनी मिसाइलों से तेल अवीव से लेकर यरुशलम तक तबाही मचा रहा है। ईरान ने खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर लगातार हमले कर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ईरान ट्रम्प के बातचीत के दावों को पूरी तरह से नकार रहा है लेकिन ईरान के राष्ट्रपति द्वारा रखी गई शर्तों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।**

डोनाल्ड ट्रम्प ने दावा किया है कि ईरान ने अमेरिका को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। यद्यपि उन्होंने विस्तार से बताने से साफ इंकार किया लेकिन ऐसे संकेत हैं कि यह तोहफा तेल और गैस से जुड़ा हुआ है। उनके इस बयान के बाद अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच कोई सीक्रेट डील हुई है। आखिर यह तोहफा है क्या जिसने अमेरिका को जंग रोकने की दिशा में इतना बड़ा कदम उठाने को मजबूर कर दिया है। युद्ध के दौरान कई तरह की बयानबाजी की जाती है, जिन पर भरोसा करना मुश्किल होता है। अब सवाल यह है कि क्या पर्दे के पीछे ईरान और अमेरिका में कोई बातचीत चल रही है। यह भी वास्तविकता है कि ट्रम्प युद्ध के दलदल में बुरी तरह से फंस चुके हैं और वह निकलने के रास्ते तलाश रहे हैं। इस युद्ध में अमेरिका को रोजाना 1.38 अरब डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं और 25 दिन की जंग में अमेरिका लगभग 20 अरब डॉलर खर्च कर चुका है। पैंटागन ने 200 अरब डॉलर से अधिक की राशि और मांगी है। इसे अमेरिकी कांग्रेस यानि संसद से पारित कराना होगा, जिसके पारित होने की उम्मीद कम है। यद्यपि ट्रम्प ने नाटो और यूरोपीय देशों को कायर और कागजी शेर कहा। इसके बावजूद नाटो और सहयोगी देश उनके साथ नहीं आए। किसी ने युद्धपोत नहीं भेजे। कतर में एलएनजी सप्लाई बंद होने से यूरोप में गैस की कीमतें 35 प्रतिशत बढ़ गईं। जापान तक को अपना रणनीतिक भंडार निकालना पड़ा। 9 देशों में 40 ऊर्जा भंडार युद्ध से प्रभावित हुए हैं। वैश्विक तेल आपूर्ति रोजाना 11 मिलियन बैरल घटी है। 66 प्रतिशत अमेरिकी इस युद्ध के खिलाफ हैं और ट्रम्प की लोकप्रियता घटी है।

ट्रम्प का यूटर्न इस बात का संकेत है कि वह युद्ध रोकने के पक्षधर हैं लेकिन इजराइल बेलगाम गुंडे की तरह व्यवहार कर रहा है। ईरान और लेबनान पर लगातार हमले कर रहा है और ईरान भी अपनी मिसाइलों से तेल अवीव से लेकर यरुशलम तक तबाही मचा रहा है। ईरान ने खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर लगातार हमले कर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ईरान ट्रम्प के बातचीत के दावों को पूरी तरह से नकार रहा है लेकिन ईरान के राष्ट्रपति द्वारा रखी गई शर्तों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कूटनीतिक गलियारों से छन-छन कर जो खबरें आ रही हैं उनके अनुसार ईरान ने भविष्य में आक्रामकता के खिलाफ गारंटी, बुनियादी ढांचे को हुए नुक्सान की भरपाई और ईरान के वैध अधिकारों की मान्यता शामिल है। ट्रम्प प्रशासन ने ईरान के तेल पर लगे प्रतिबंधों में एक महीने की ढ ील दी है। जबकि ईरान का कहना है कि उसके पास अतिरिक्त तेल है ही नहीं तो ढील का कोई मतलब ही नहीं है। यद्यपि तुर्की और मिस्र ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता कर रहे हैं लेकिन मध्यस्थता के खेल में पाकिस्तान का शामिल होना काफी अखरता है।

पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर उछल-उछलकर बातें कर रहे हैं। आठ-आठ युद्धों को रुकवाने का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रम्प खुद मध्यस्थ की तलाश में जुटे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान युद्ध में मध्यस्थ की भूमिका निभाने की बात कही है। ईरान के खिलाफ एक लम्बे और महंगे युद्ध का खतरा, तेल की कीमतों में तेज उछाल, गैस संकट और अन्तर्राष्ट्रीय सहयो गयों के दबाव के कारण ट्रम्प अब स्वयं कायर दादा के तौर पर छवि बना चुके हैं। किसी भी राजनयिक प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए ट्रम्प को पहले अपने सहयोगी इजराइल पर लगाम लगानी होगी। इजराइल द्वारा अपनाया गया सैन्य मार्ग स्पष्ट रूप से अपनी सीमाएं दिखा रहा है। ट्रम्प के लिए सबसे कम नुक्सानदेह रास्ता ईरान के साथ संवाद कायम कर युद्ध से बाहर निकलना ही दिखाई देता है। उम्मीद कायम है कि कूटनीति के द्वार खुलेंगे और पश्चिम एशिया में शांति का माहौल कायम होगा। आने वाले दिनों में भारत भी शांति प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। देखना होगा बातचीत किस दिशा में जाती है।

खूनी चीखों का शोर

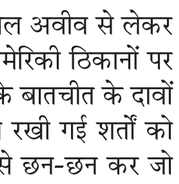

गीता पाढा

"कागज पर शांति, जमीं पर खूनी चीखों का शोर हैं,
हिंसा के इस दौर में, विनाश चारों ओर है,
हर दिल में बैठा अंधेरा गहरा और घनघोर है,
तबाही, स्वार्थ , बमबारी, इन सभी ने मिलकर किया,
इंसानियत की नींव को कमजोर है...।"

मर्यादाएं

चन्द्रमोहन

संपादक : वीर प्रताप

chander_m@ hotmail.com

BLOG: chandermohan.net

लद्दाख की बेचैनी को समझना होगा

चंद्र मोहन

जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक, जिनके जीवन से प्रेरित फ़िल्म 3 इडियट्स बनी थी, रिहा होकर लेह लौट आएं हैं। उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून (एनएसए) के तहत गिरफ्तार किया गया था और जोधपुर जेल में रखा गया था। इस क़ानून के तहत किसी को अधिकतम 12 महीने हिरासत में रखा जा सकता है पर सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी की वकालत करने के बाद सरकार ने वांगचुक को 169 दिन के बाद रिहा कर दिया।जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो बताया गया कि वह 'राष्ट्र विरोधी गतिविधियों' में संलिप्त हैं जिस बात से देश में शायद ही कोई सहमत हो। बहुत लोग तो उन्हें राष्ट्रीय ख़ज़ाना मानते हैं। और अगर वह वास्तव में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त थे तो छोड़ा क्यों गया? सारे मामले से सरकार सही ढंग से नहीं निबटी और जो देश का एक प्रकार से सबसे शांत क्षेत्र था,लद्दाख, उसे बेचैन छोड़ दिया गया है। लद्दाख के बौद्ध और कारगिल के मुसलमान जो सदा एक दूसरे के विरोधी रहे हैं अब केन्द्र सरकार के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। जिस उपराज्यपाल के समय वांगचुक को गिरफ्तार किया गया था को तो अब बदल दिया गया है। नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने रिहाई का स्वागत करते हुए कहा है कि वहां 'आंदोलन और हिंसा की कोई जगह नहीं'। जहां तक हिंसा का सवाल है मैं उनकी बात से बिलकुल सहमत हूं। एक सभ्य समाज में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए पर शांतिमय आंदोलन पर आपत्ति क्यों हो? आंदोलन करना हमारे मूल अधिकारों का हिस्सा है। हमने तो आज़ादी आंदोलन के द्वारा प्राप्त की थी।

लद्दाख जैसा देश में कोई प्रदेश नहीं है। इसकी अद्भुत पर कठोर प्राकृतिक सुन्दरता मंत्रमुग्ध करने वाली है। ऊंचे पहाड़ हैं जिन पर कुछ नहीं उगता। इसे ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। बीच में से शांत सिंधु और जांस्कर नदियां बहती है। 13000-14000 फुट की ऊंचाई पर घाटी स्थित है। आक्सीजन की कमी के कारण कई बाहरी लोगों को समस्या आती है। दुनिया की सबसे ऊंची झील पैंगोंग यहां है जिसको लेकर भारत और चीन के बीच तनातनी रहती है। क्षेत्र अपनी बौद्ध संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है इसलिए शांत है। इसके गोम्पा (मठ) के अंदर अत्यंत शांत वातावरण होता है और बाहर से गए व्यक्ति को लगता है कि वह इस शान्ति का उल्लंघन कर रहा है। पर यह क्षेत्र अत्यंत संवेदनशील भी है क्योंकि चीन के साथ हमारी लम्बी सीमा है जहां लगातार झड़पें होती रहती हैं। हमें वहां के लोगों का अधिक सहयोग चाहिए जो गोली चलाने से अधिकारी इस असुरक्षा की भावना को समझ नहीं सके और पहली बार नौबत यहां तक पहुंच गई कि गोली चलानी पड़ी, चार लोग मारे गए और दर्जनों घायल हो गए। अधिकारियों का कहना था कि सेल्फ़ डिफैंस में गोली चलानी पड़ी। हो सकता है कि उनकी बात सही हो, पर ऐसी हालत ही क्यों बनने दी गई कि 'सेल्फ़ डिफ़ेंस' में गोली चलानी पडे?

अगर लोगों की मांग व्यावहारिक नहीं है तो समझाने की ज़रूरत है। लद्दाख के लोगों की मूल मांगों में स्टेटहुड और संविधान के छठे शेड्यूल में शामिल करना है। वह अपनी ज़मीन पर अपना अधिकार सुरक्षित चाहते हैं। तीन लाख लोगों की आबादी वाले प्रदेश को स्टेटहुड नहीं दिया जा सकता। छठा शेड्यूल आदिवासी क्षेत्रों की व्यवस्था के लिए है जैसे मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम और असम में है। इसे उतर पूर्व के कुछ हिस्सों के लिए बनाया गया था। मणिपुर में यह अभी भी लागू नहीं किया गया। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में इसे देने का वादा किया था पर अब केन्द्र सरकार ने मन बदल लिया लगता है। इस पर फिर से विचार होना चाहिए। केन्द्र सरकार ने लद्दाख की खुले दिल से मदद की है। 2019 से पहले प्रदेश को केन्द्र से केवल 57 करोड़ रुपए वार्षिक मिलते थे जो अब बढ़ कर 6000 करोड़ रुपए हो गए है। इतनी भारी मदद के बावजूद असंतोष है। छह साल से वह लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित हैं। कोई निर्वाचित विधानसभा नहीं है। निर्णय दिल्ली से भेजे प्रशासक ले रहे हैं जिन्हें स्थानीय संवेदनाओ, ज़रूरतों और संस्कारों के बारे कोई ज्ञान नहीं है। उपर से बढ़ती बेरोज़गारी के कारण युवाओं में असंतोष है। परिणाम लेह जैसे शांतिमय शहर में लोगों के असंतोष का विस्फोट हो गया।

इस सब के केन्द्र में सोनम वांगचुक हैं। वह अपनी मांगों के लिए दिल्ली तक पदयात्रा कर चुके हैं। लद्दाख पहुंच कर उन्होंने भूखहड़ताल शुरू कर दी जिसके 15वें दिन स्थिति हाथ से निकल गई और लेह में हिंसा भड़क उठी। सारे लद्दाख में बेचैनी फैल गई और लद्दाखी संगठनों ने केन्द्र के साथ बातचीत बंद कर दी। दूसरा परिणाम यह हुआ कि सोनम वांगचुक जो प्रदर्शन का चेहरा थे को रासुका के अधीन गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर हिंसा उकसाने का आरोप लगाया गया जिसका वह ज़बरदस्त प्रतिवाद करते हैं। वांगचुक ने ज़रूर अपने भाषणों में नेपाल के 'जैन ज़ैड' और 'अरब स्प्रिंग' का ज़िक्र किया था। बेहतर होता कि कोई उन्हें सावधान करता कि यह अनुचित है।

वहां प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई गई। यह कितनी बड़ी त्रासदी थी यहसेवांग थरचिन की मौत से पता चलता है। वह फ़ौजी था और उसका परिवार भी फ़ौजी है। उसके पिता ने कारगिल की लड़ाई में हिस्सा लिया था। वह बताते हैं, "यह कैसे हुआ गलवान के समय भी चीनियों ने ऐसे गोली नहीं चलाई थी। यहां तो पुलिस ने अपने लोगों पर गोली चला दी। आम तौर पर फ़ायरिंग पहले हवा में की जाती है फिर घुटनों के नीचे। मेरे बेटे को तो ज़मीन में लिटा कर गोली मारी गई"। सेवांग का भाई कहता है कि "मैं बता नहीं सकता कि वह कितना बड़ा देश भक्त था। उसने जल्दी रिटायरमेंट ले ली ताकि वह अपने तीनों बच्चों को सैनिक स्कूल भेज सके"। लेह के पुलिस चीफ़ का कहना था कि अगर गोली न चलाते तो 'लेह को आग लग जाती"। उनकी बात सेवांग के परिवार के कथन से मेल नहीं खाती। स्पष्ट है कि प्रशासन ने स्थिति को सही नहीं सम्भाला और जो क्षेत्र देशभक्तों का क्षेत्र है, जो सेना में लोग भेजता है, उसे जज्मा कर दिया गया है। यह मणिपुर नहीं है जहां दो जातियां लड़ रहीं हैं। यहां संवाद कर और किसी प्रकार का प्रतिनिधित्व दे कर मामला सुलझाया जा सकता था। हर जगह प्रशासनिक हथौड़ा नहीं चलना चाहिए।

मेजर जनरल बख्शी जो कभी मोदी सरकार के प्रशंसक रहे हैं पर अब आलोचक हैं, ने बताया है, "लद्दाख के लोग बहुत सीधे और प्यार वाले है। बौद्ध होने के कारण वह बहुत दयालु हैं फिर भी वह दुनिया में सबसे बढ़िया पहाड़ी सैनिक हैं। उन्होंने भारत की सुरक्षा के लिए जानें दी हैं। अशोक चक्र तक सम्मान उन्हें मिले हैं"। लद्दाखी कहते हैं कि हम सेना के साथ साझेदारी करते हैं, उनके हर कदम पर साथ देते हैं। बहुत दुख है कि ऐसे लोगों पर गोली चलाई गई। हमें तो इस नाज़ुक क्षेत्र,जिसकी सीमा चीन और पाकिस्तान से लगती है, के देशभक्त लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। हिंसा ग़लत है पर वहां तक नौबत नहीं आनी चाहिए थी। मेजर जनरल बख्शी का कहना है, "भगवान के लिए हम इस महत्वपूर्ण सीमावर्ती प्रदेश के प्रति उदासीन नहीं हो सकते"।

लद्दाख में भी विरोधाभास है। एक तरफ़ वह तरक्की चाहते हैं। और पर्यटक चाहते हैं पर उन्हें यह भी घबराहट है कि बाहरी लोग उनकी संस्कृति को मिटा रहे हैं। बाहरी लोग ज़मीनें ख़रीद रहे हैं। वांगचुक ने भी कहा है कि "संघर्ष पर्यावरण, संस्कृति, नदियों, ग्लेशियर और लोगों के लिए है"। अब उनकी रिहाई से पता चलता है कि केन्द्रीय सरकार फिर संवाद क़ायम करना चाहती है। वांगचुक भी ले दे कर मसला ख़त्म करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्य सचिव सी फुंतसौंग ने कहा है कि "लद्दाख की भौगोलिक स्थिति और चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा के कारण अशान्ति को बढ़ने नहीं देना चाहिए"। चीन के साथ फिर टकराव हो सकता है इसलिए क्षेत्र में शान्ति चाहिए। वहां के लोग बाग़ी नहीं है। भारत की विभिन्नता हमारी कमजोरी नहीं, ताक़त है। आगे का रास्ता विरोध दबाने का नहीं हो सकता। क्षेत्र की शान्ति और स्थिरता के लिए उच्च स्तर पर संवाद चाहिए।

पाकिस्तानी मुस्लिमों द्वारा सिख महिलाओं का धर्म परिवर्तन

सिख सियासत

सुदीप सिंह

newsreporter.2008@gmail.com

हिन्दू-सिखों का धर्म परिवर्तन भले ही वह जबरन करवाया गया हो या फिर किसी भी तरह के लोभ लालच देकर हो एक बड़ा मुद्दा बन चुका है और खासकर पंजाब में इसका प्रभाव सबसे अधिक देखने को मिल रहा है जहां पर ईसाई मिशनरियों के द्वारा गरीब वर्ग के लोगों को अपना शिकार बनाया जा रहा है। इस पर देश के

गृह मंत्री भी चिन्तित हैं और अब तो सुप्रीम कोर्ट भी इस पर सख्त रुख अपनाता दिख रहा है। मगर वहीं विदेशों में पा कि स्ता नी मुस्लिमों के द्वारा ग्रूमिंग गैंग के तहत सिख महिलाओं को मुस्लिम बनाने के लिए ''कौर टू खान'' मुहिम चलाए जाने की बात सामने आ रही है जो बेहद चिन्ता का विषय है। इसके लिए यह भी जानकारी मिल रही है कि 10 हजार पौंड तक उन महिलाओं को दिए जा रहे हैं जिसके लालच में आकर सिख परिवारों की बच्चियां जो पढ़ने के लिए विदेश गई हैं और उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है वह इनके जाल में फंसकर अपना धर्म परिवर्तन करवाती दिख रही हैं। वैसे तो पिछले दो दशकों में यूनाइटेड किंगडम में बच्चों और युवतियों के शोषण से जुड़े कई गंभीर मामले सामने आते रहते हैं मगर हाल ही में सोशल मी ड़िया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसने सिख समुदाय को बेहद चिन्तित कर दिया है।

इतिहास इस बात का गवाह है कि सिख महिलाओं ने कभी धर्म परिवर्तन नहीं किया भले ही उन्हें कई प्रकार के कष्ट झेलने पड़े, यहां तक कि धर्म परिवर्तन ना करने के चलते उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया, उनके सामने उनके बच्चों को बेरहमी से शहीद किया गया पर वह अपने धर्म में पक्के रही। मगर शायद लगता है कि समय के साथ-साथ आज परिस्थितियां बदली हुई हैं जिसके चलते थोड़े से पैसों के लालच में सिख महिलाएं अपना धर्म छोड़ने में जरा भी देर नहीं लगाती। आज एक बार फिर से मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा एक गहरी साजिश के तहत सिख परिवारों की लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है। हाल ही में एक मामला पाकिस्तान गुरुद्वारों के लिए जाने वाले जत्थे में देखा गया जिसमें सरबजीत कौर की महिला ने पहले जत्थे से अलग होकर पाकिस्तान के एक मुस्लिम लड़के से निकाह करके धर्म बदला और अब वहां से सिखों के खिलाफ जहर उगल रही हैं। सिख बुद्धिजीवियों और नेताओं को इसके लिए आगे आकर सिख परिवारों की बच्चियों में जागरुकता लाने की आवश्यकता है क्योंकि जब तक सिख परिवारों की बच्चियां इसके प्रति जागरुक नहीं होंगी ऐसी घटनाएं सामने आती रहेंगी। पंजाब में सबसे ज्यादा प्रचलन सिख परिवारों की लड़कियों का विदेश जाने का रहता है इसलिए वहां जागरुकता अभियान चलाने की अधिक आवश्यकता है। आजकल यह भी देखने में आ रहा है कि कुछ सिखों के द्वारा मुस्लिम समुदाय से मित्रता बढ़ाने का शौक पैदा हो रहा है उन्हें भी इस विषय पर गंभीरता दिखाते हुए मुस्लिम समुदाय के जो लोग ग्रूमिंग गैंग के रुप में कार्यरत हैं उन पर शिकंजा लगवाने के लिए दबाव बनाना चाहिए। वहीं यूके की सरकार को भी जबरन धर्म परिवर्तन या फिर लालच में फंसाकर धर्म परिवर्तन करवाने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाई करनी चाहिए।

"खालिस्तान जनमत संग्रह" आयोजकों के संगठित अपराध से संबंध

हाल के वर्षों में तथाकथित "खालिस्तान जनमत संग्रह" का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस अभियान को मुख्य रूप से सिख फार जस्टिस नामक संगठन द्वारा चलाया जा रहा है, जिनका मकसद केवल सिख प्रवासी समुदाय से पैसा और संसाधन निकालने मात्र है।

हालांकि भारत सरकार द्वारा पहले ही प्रतिबंधित घोषित किया जा चुका है। लेकिन इस पूरे प्रकरण का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि इसके आयोजकों और समर्थकों के कथित तौर पर संगठित अपराध से जुड़े होने के आरोप लगातार सामने आते रहे हैं। यह भी देखा जाता है कि आयोजकों के संगठित अपराध से गहरे संबंध के प्रमाण भी कई बार मिल चुके हैं। दिसंबर 2025 में, कैलिफ़ोर्निया में सिख फार जस्टिस के खालिस्तान जनमत संग्रह के आयोजक जसपाल सिंह को एक हाई स्कूल के बाहर स्टिंग ऑपरेशन में 14 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ अश्लील हरकतें करते हुए पकड़ा गया और पूछताछ के दौरान, उसने आरोपों को स्वीकार किया। ऐसी घटनाएँ दिखाती हैं कि ''खालिस्तानी समूह'' रिको

एक्ट के अंतर्गत आते हैं, जो अमेरिका के उन संगठित आपराधिक गिरोहों को निशाना बनाता है जो अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए बार-बार अवैध गतिविधियों में शामिल होते हैं। "जनमत संग्रह" के नाम पर प्रवासी समुदाय का शोषण करते हुए गंभीर अपराध करना, नेताओं को संघीय अभियोजन के दायरे में लाता है। कई सुरक्षा एजेंसियों और खुफिया रिपोर्टों में यह संकेत मिले हैं कि इस प्रकार के जनमत संग्रह के पीछे केवल राजनीतिक विचारधारा नहीं, बल्कि अवैध गतिविधियों का एक नेटवर्क भी सक्रिय है। इनमें मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स तस्करी, और हथियारों की आपूर्ति जैसे गंभीर अपराध शामिल बताए जाते हैं। इस तरह के नेटवर्क अक्सर अलगाववादी आंदोलनों को आर्थिक और लॉजिस्टिक समर्थन प्रदान करते हैं जिन्हें रोकने के लिए हर देश की सरकारों को सख्ती से पेश आना होगा। ''खालिस्तान जनमत संग्रह" का आयोजन मुख्य रूप से कनाडा, ब्रिटेन, और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में किया जाता है।

इन देशों में सक्रिय कुछ तत्वों पर आरोप है कि वे स्थानीय कानूनों का लाभ उठाकर भारत-विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। कई बार यह भी देखा गया है कि ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को भड़काने और गलत सूचना फैलाने का प्रयास किया जाता है। भारत जैसे विविधता वाले देश के लिए इस प्रकार की गतिविधियाँ आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन सकती हैं।

मोदी सरकार द्वारा सिखों के पांच तख्तों को जोड़ने हेतु रेल सेवा

सिख धर्म के पांच तख्त साहिबान हैं जिनमें सिरमोर श्री अकाल तख्त साहिब है जिसकी स्थापना छठे गुरु हरिगोबिन्द साहिब के द्वारा की गई थी, उसके बाद तख्त पटना साहिब जो कि गुरु गोबिन्द सिंह जी की जन्मस्थली है। इसी प्रकार तख्त सचखण्ड हजूर साहिब नांदेड़, तख्त केशगढ़ साहिब आनंदपुर साहिब और तख्त साबो की तलवंडी बठिण्डा में सुशोभित है। हर सिख की इच्छा रहती है कि वह पांच तख्त साहिबान के दर्शन अपने जीवनकाल में अवश्य करे मगर सीधी रेल सेवा ना होने के चलते कई सिख दर्शनों से वंचित रह जाते हैं।

देश को आजाद हुए आज 79 साल होने को हैं मगर आज तक किसी भी रेल मंत्री के द्वारा इस ओर ध्यान आकर्षित ही नहीं किया गया या यह कहा जाए कि किसी की सोच ही नहीं थी। मगर पंजाब के युवा नेता रवनीत सिंह बिट्टू को जब से रेल मंत्रालय में बतौर रेल राज्यमंत्री का कार्यभार मिला उनकी पूरी कोशिश रही कि किसी भी तरह से सिख धर्म के पांच तख्त साहिबान को आपस में रेल सेवा से जोड़ा जाए और इस कार्य के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से लेकर समूचे मंत्रिमण्डल का उन्हें सहयोग मिल रहा है जिसके चलते अब यह माना जा रहा है कि आने वाले समय में निश्चित तौर पर पांच तख्त साहिबान रेल सेवा के माध्यम से जुड़ सकेंगे। तख्त पटना साहिब कमेटी के अध्यक्ष जगजोत सिंह सोही की मानें तो रवनीत सिंह बिट्टू के प्रयास सराहनीय

हैं, उनकी पूरी कोशिश रहती है कि तख्त पटना साहिब आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ ऐसा किया जाए कि उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। इसी के चलते पटना साहिब स्टेशन पर तकरीबन सभी ट्रेनों का ठहराव दिया जा रहा है, स्टेशन को अत्याधुनिक बनाने और उसके सौंदर्यकरण का कार्य किया जा रहा है। कई नई ट्रेन विभिन्न दिशाओं से चलाई जा रही हैं।

एफसीआरए संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): सरकार ने बुधवार को विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) संशोधन के लिए लोकसभा में जो विधेयक पेश किया उसमें विदेशी वित्त पोषित संगठनों पर निगरानी के साथ यह प्रस्ताव किया गया है कि लाइसेंस गंवाने वाली गैर-लाभकारी संस्थाओं की संपत्तियों को जब्त करने और इनका प्रबंधन करने के लिए एक नया प्राधिकरण बनाया जाएगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में 'विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026' विधेयक पेश किया। इसमें विदेशी अंशदान और संपत्तियों के पर्यवेक्षण, प्रबंधन और निपटान के लिए एक व्यापक वैधानिक ढांचे का प्रावधान भी किया गया है। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि वर्तमान में लगभग 16,000 संगठन अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं और उन्हें सालाना लगभग 22,000 करोड़ रुपये मिलते हैं। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन के अनुसार, प्रस्तावित कानून पूर्व अनुमति के तहत प्राप्ति और उपयोग के लिए समयसीमा प्रदान करने का प्रावधान करता है। यह प्रमाणपत्र की समाप्ति, निलंबन के दौरान संपत्ति के प्रबंधन को विनियमित करने, दंड को तर्कसंगत बनाने और जांच शुरू करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता का प्रावधान भी करता है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक को लेकर विपक्षी सदस्यों की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा कि विधेयक का उद्देश्य वैध गतिविधियों को बाधित करना नहीं, बल्कि विदेश अंशदान की प्रक्रिया को जवाबदेही और पारदर्शी बनाना है। उन्होंने कहा कि भारत की संप्रभुता और देशहित में काम करने वाले संस्थानों के कार्यों में कोई अवरोध पैदा नहीं होगा, लेकिन इसके विपरीत काम करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) में धारा 15 संपत्तियों को निहित करने का प्रावधान करती है, लेकिन ऐसी संपत्तियों के पर्यवेक्षण, प्रबंधन और निपटान के लिए एक व्यापक ढांचे की अनुपस्थिति के कारण प्रशासनिक अनिश्चितता और दुरुपयोग की गुंजाइश पैदा हो गई है। प्रस्तावित कानून के तहत, सरकार ने उन मामलों में विदेशी योगदान से बनाई गई संपत्तियों का अस्थायी या स्थायी नियंत्रण लेने के लिए 'नामित प्राधिकरण' स्थापित करने के लिए एक नया अध्याय 3ए पेश किया है।

लाइसेंस गंवाने वाले एनजीओ की संपत्तियों के प्रबंधन के लिए बनेगा प्राधिकरण

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83

पंजाब केसरी

दिल्ली कार्यालय :

फोन आफिस : 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग : 011-30712224
विज्ञापन विभाग : 011-30712229
सम्पादकीय विभाग : 011-30712292-93
मैगजीन विभाग : 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com

स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रैस, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। –वाल्तेयर

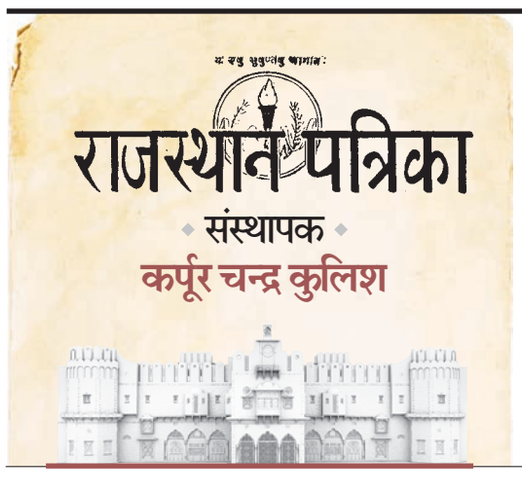

महिलाओं को बिना भेदभाव के आगे बढ़ाएं

सैन्य बलों में महिलाओं की भागीदारी और उन्हें समान अवसर देने का प्रश्न केवल रोजगार या पदोन्नति का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज की सोच, संस्थागत संरचना और संविधान में निहित समानता के मूल्यों की परीक्षा भी है। हाल में सुप्रीम कोर्ट की ओर से शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) वाली महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के मामले में की गई टिप्पणी इसी व्यापक संदर्भ को उजागर करती है। अदालत ने कहा कि स्थायी कमीशन (पीसी) देने की प्रक्रिया में प्रणालीगत भेदभाव और असमान मापदंड अपनाए गए हैं। कोर्ट की यह टिप्पणी केवल प्रशासनिक खामी की ओर इशारा नहीं करती, बल्कि उस मानसिकता को भी सामने लाती है, जो आज भी कई संस्थानों में लैंगिक असमानता को बनाए हुए है।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही सेना में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन का मार्ग प्रशस्त कर चुका है। इसके बावजूद, नए मापदंडों जैसे एसीआर के वेटेज और अन्य शर्तों के माध्यम से महिलाओं को पीछे धकेलने की प्रवृत्ति चिंता का विषय है। सेना में पुरुषों का वर्चस्व ऐतिहासिक रूप से रहा है, लेकिन बदलते समय के साथ यह धारणा अब टिकाऊ नहीं रह गई है। आधुनिक युद्ध और सैन्य प्रशासन केवल शारीरिक क्षमता तक सीमित नहीं हैं। इसमें नेतृत्व, रणनीति, तकनीकी दक्षता और मानसिक दृढ़ता की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। इन सभी क्षेत्रों में महिलाएं अपनी योग्यता सिद्ध कर चुकी हैं। ऐसे में उन्हें समान अवसर न देना न केवल अन्याय है, बल्कि राष्ट्रीय संसाधनों का भी दुरुपयोग है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश कि चयन प्रक्रिया, कट-ऑफ और अंक वितरण की समीक्षा की जाए, एक सकारात्मक कदम है। पारदर्शिता और निष्पक्षता किसी भी संस्था की विश्वसनीयता की आधारशिला होती है। यदि हर बैच और हर कैडर में उपलब्ध वैकेंसी, मापदंड और मूल्यांकन प्रणाली स्पष्ट रूप से सामने रखी जाए, तो न केवल भेदभाव की संभावना कम होगी, बल्कि महिलाओं का विश्वास भी संस्थान में मजबूत होगा।

हालांकि, यह भी एक सच्चाई है कि भारत में लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति अक्सर न्यायिक हस्तक्षेप के माध्यम से ही होती है। यह प्रवृत्ति आत्ममंथन का विषय है। लैंगिक भेदभाव केवल नीतियों में नहीं, बल्कि हमारे सोचने के तरीके में भी गहराई से समाया हुआ है। जब तक यह मानसिकता नहीं बदलेगी, तब तक नियमों में बदलाव भी सीमित प्रभाव ही डाल पाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि ऐसे मामलों में संस्थानों के साथ-साथ समाज के हर स्तर पर जागरूकता और संवेदनशीलता बढ़ाई जाए। यह सभी को याद रखना चाहिए महिलाओं को समान अवसर देना कोई विशेष सुविधा नहीं, बल्कि उनका अधिकार है। मजबूत, समावेशी और आधुनिक भारत का निर्माण करने की चाहत के बीच यह सुनिश्चित करना होगा कि हर क्षेत्र में महिलाओं को बिना किसी भेदभाव के आगे बढ़ने का अवसर मिले।

अंतरराष्ट्रीय प्रभाव : होर्मुज स्ट्रेट बंद रहा और खाड़ी में तेल-गैस का उत्पादन ठप रहा तो ग्लोबल जीडीपी पर भी होगा असर

अर्थव्यवस्थाओं को संकट की ओर धकेल रहा युद्ध

डॉ. रहीस सिंह
अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार
@patrika.com

हर महीने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते लगभग 13.3 लाख टन खाद का निर्यात किया जाता है। इसलिए, अगर यह समुद्री रास्ता सिर्फ 30 दिनों के लिए भी बंद हो जाए, तो दुनिया खाद संकट की चपेट में आ जाएगी। इसका सीधा असर फसलों की उत्पादकता पर पड़ेगा।

आज की दुनिया को देखकर न जाने क्यों यह लगने लगता है कि एक दुनिया मर रही है और जो कुछ भी नया जन्म ले रहा है, वह दुनिया के लिए अपेक्षित तो नहीं है। मैं बात उन युद्धों की कर रहा हूं जो दुनिया को धीरे-धीरे करके मार रहे हैं और किसलिए? सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं और अहमन्यताओं के लिए? ये युद्ध भले ही रूस व यूक्रेन या फिर ईरान व अमरीका-इजराइल के बीच दिख रहे हों लेकिन इनसे पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। कोई भी युद्ध अब युद्ध के मैदान में नहीं लड़ा जाता है, बल्कि वह शहरों से कस्बों और कस्बों से जिंदगियों के बीच भी लड़ा जाता है। उसमें क्षति केवल संसाधनों की नहीं होती है बल्कि जिंदगियों की भी होती है। रूस और यूक्रेन युद्ध से प्रभावित दुनिया अब ईरान केंद्रित अमरीका-इजराइल युद्ध का सामना कर रही है जिसे लेकर अर्थव्यवस्था और लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव की चिंताएं हर तरफ दिखने लगी हैं। ऊपरी तौर पर तो इस प्रभाव को तेल और गैस संकट तक सीमित कर देखा जा रहा है लेकिन यह खाद (फर्टिलाइजर) और खाद्यान्न तक जाएगा जिससे न केवल उत्पादन की लागतें बढ़ेंगी बल्कि जिंदगियों को जीने का खर्च भी बढ़ जाएगा।

ईरान युद्ध की वजह से होर्मुज जलडमरूमध्य (स्ट्रेट ऑफ होर्मुज) से गायब होते तेल और एलएनजी टैंकरों पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। कारण यह कि ईरान और ओमान के बीच मौजूद इस संकरे समुद्री मार्ग से होकर दुनिया का लगभग 20 प्रतिशत कच्चा तेल और एलएनजी गुजरती है। अब इस ऊर्जा संकट के साथ-साथ युद्ध के आइने से उन जहाजों पर नजर भी गड़ाइए जिनमें खेती के लिए खाद और लोगों के लिए भोजन लदा हुआ होता है। यदि यह रास्ता बंद कर दिया जाए तो? जैसा कि अभी है। तो उन देशों की तो पहले रफ्तार रुकेगी जो इन देशों पर तेल और गैस के लिए निर्भर हैं लेकिन संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन अरब जैसे खाड़ी देशों की सांसें भी रुकने लगेंगी क्योंकि होर्मुज जलडमरूमध्य होकर गुजरने वाला समुद्री रास्ता इन देशों के लिए जीवन रेखा है।

मैरीटाइम इंटेलिजेंस कंपनियों और ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस के अनुसार दुनिया में आयात और निर्यात की जाने वाले प्रमुख फर्टिलाइजर्स जैसे अमोनिया, फॉस्फेट और सल्फर का 20 प्रतिशत हिस्सा अकेले खाड़ी देशों से आता है। यही नहीं यूरिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले नाइट्रोजन का लगभग आधा हिस्सा खाड़ी क्षेत्र से आता है जिसमें कतर सबसे आगे है। पिछले दिनों ईरान ने दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी और फर्टिलाइजर हब 'रास लफ्फान' (कतर) पर हमला किया था जिसके कारण कतर एनर्जी को अपना उत्पादन रोकना पड़ा। इसका असर यह हुआ कि लाखों टन जरूरी फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट्स और उन्हें बनाने वाला कच्चा माल जहां का तहां ही रुक गया। विकासशील देशों की मदद करने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था 'यूएनसीटीएडी' के मुताबिक, हर महीने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते लगभग 13.3 लाख टन खाद का निर्यात किया जाता है। इसलिए, अगर यह समुद्री रास्ता सिर्फ 30 दिनों के लिए भी बंद हो जाए, तो दुनिया खाद संकट की चपेट में आ जाएगी। इसका सीधा असर फसलों की उत्पादकता पर पड़ेगा और उत्पादक की कमी कई अन्य प्रभाव डालेगी, जैसे- सप्लाई चेन को कमजोर करेगी, रोजगार घटाएगी, प्रतिव्यक्ति आय में कमी लाएगी और जीडीपी को नकारात्मक दिशा में ले जाएगी। तेल और गैस केवल ट्रांसपोर्टेशन पर ही प्रभाव नहीं डालते, भोजन और उसकी कीमतों को तय करने में भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। फिर वह चाहे खेतों पर चलने वाले ट्रैक्टर हों या खाद्यान्न परिवहन के लिए ट्रक, फसलों को खाने योग्य बनाने वाले प्रोसेसिंग प्लांट और कोल्ड स्टोरेज हों या इन जैसी अन्य इकाइयां। वर्तमान आर्थिक परिदृश्य को देखें तो चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसी एशियाई अर्थव्यवस्थाएं, जो अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल खाड़ी देशों से मंगाती हैं, वहां ईंधन की कीमतों में भारी उछाल देखा जा रहा है। यद्यपि भारत सरकार ने अभी तक डीजल और पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाई हैं, लेकिन यह स्थिति ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएगी। भारत अपनी जरूरत की दो-तिहाई नाइट्रोजन खाद के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर है इसलिए इस दृष्टि से भारत गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है, यदि विकल्प नहीं तलाशे गए तो। यही स्थिति ब्राजील सहित अन्य ब्रिक्स देशों की भी होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि उप-सहारा अफ्रीका के क्षेत्र जो पहले से ही भुखमरी की समस्या से जूझ रहे हैं, वहां यह संकट और गहरा जाएगा। चीन को आज दुनिया के कारखाने के तौर पर देखा जाता है। स्वाभाविक है कि उसकी ग्लोबल सप्लाई चेन में महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

फिलहाल अमरीका ने यह युद्ध शायद इसलिए छेड़ा था ताकि होर्मुज पर कब्जा कर खाड़ी क्षेत्र का गेम प्लेयर बन सके लेकिन अब इसके प्रभाव दूरगामी दिख रहे हैं। गोल्डमैन सैच्स का अनुमान है कि अगर सप्लाई बाधित हुई तो ग्लोबल जीडीपी में 0.4 प्रतिशत तक की गिरावट आ सकती है। लेकिन वह यह भी शंका जाहिर करता है कि होर्मुज स्ट्रेट बंद रहा और खाड़ी में तेल व गैस का उत्पादन ठप रहा तो ग्लोबल जीडीपी पर प्रभाव एकरेखीय नहीं होगा, बल्कि घातीय होगा।

यह युद्ध एक ऐसी नाजुक स्थिति का निर्माण कर चुका है जिससे दुनिया के देशों के बाजार और अर्थव्यवस्थाएं किसी नए झटके को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं होगी। वर्तमान स्थिति यह है कि दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्थाएं संवेदनशील परिस्थितियों से गुजरती हुई दिख रही हैं और यूरोप लड़खड़ाता हुआ, यदि युद्ध लंबा खिंचा तो ये किधर जाएंगी?

प्रसंगवश

सरकारी स्कूलों में नए सत्र में भी नामांकन वृद्धि संसाधन जुटाने से ही

सवाल केवल बजट आवंटन का ही नहीं, बल्कि विश्वास बहाली का भी है

राजस्थान के सरकारी स्कूलों में भी इस बार नया शिक्षा सत्र एक जुलाई के बजाय एक अप्रेल से शुरू हो रहा है। निजी शिक्षण संस्थाओं की ओर छिटकते जा रहे बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करने की दिशा में यह प्रयोग कितना कारगर साबित होगा, यह तो भविष्य ही बताएगा लेकिन इतना तय है कि संसाधन और सुविधाओं की समुचित व्यवस्था किए बिना सरकारी स्कूलों में बच्चों का नामांकन करना आसान काम नहीं है। सवाल केवल बजट का भी नही, विश्वास की बहाली का भी है जो सरकारी स्कूलों की जर्जर हुई इमारतों और पोषाहार में गड़बड़ी, शिक्षकों की कमी आदि को देखते हुए पिछले सालों में कमजोर पड़ा है। परम्परगत रूप से शिक्षा विभाग एक अप्रेल से शुरू होने वाले शिक्षा सत्र के लिए भी ढोल-नगाड़ों के साथ प्रवेशोत्सव मनाएगा। नामांकन बढ़ाने के दावे भी होंगे लेकिन निजी स्कूलों की चकाचौंध के आगे जब सरकारी स्कूल प्रशिक्षित शिक्षकों के बावजूद कमजोर पड़ते दिखें तो यह सब बेमानी ही कहा जाएगा।

गत वर्ष मानसून के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों से सरकारी स्कूलों की ऐसी तस्वीरें आईं जिन्होंने व्यवस्था की पोल खोल दी। कहीं स्कूल की छत ही भरभरा कर गिर गई तो कहीं बच्चों की जान पर बन आई। कहीं बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ने को मजबूर हुए। जब हाईकोर्ट को इस मामले में सख्त टिप्पणी करनी पड़े तो समझ लेना चाहिए कि पानी सिर से ऊपर जा चुका है। भवन के अभाव में शिक्षा के अधिकार का नारा महज एक किताबी जुमला बनकर रह जाता है। हाल ही राज्य सरकार की पहल पर केंद्र सरकार का जर्जर स्कूलों के लिए 300 करोड़ रुपए मंजूर करना एक स्वागत योग्य कदम है। सरकार को यह समझना होगा कि शिक्षा पर किया गया व्यय 'खर्चा' नहीं, बल्कि देश के भविष्य के लिए 'निवेश' है। लेकिन विडंबना यह है कि सरकारी स्कूलों में जहां स्कूल हैं वहां बच्चे नहीं और जहां बच्चे हैं वहां शिक्षकों की कमी की समस्या आम है। इस सत्र में शिक्षा विभाग जर्जर भवनों को सुरक्षित बना पाया तो नामांकन के लिए शिक्षकों को घर-घर जाकर मनुहार नहीं करनी पड़ेगी। - **अनिल सिंह चौहान**

anil.chauhan@in.patrika.com

बुक इनसाइट

ही/शी/दे : जेंडर पहचान पर बात

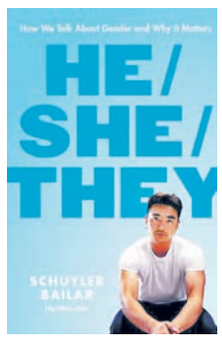

आज के समय में जेंडर पहचान पर बातचीत जितनी जरूरी है, उतनी ही संवेदनशील भी। इसी विषय को सरल, ईमानदार और मानवीय दृष्टि से सामने लाती है 'ही/शी/दे: हाउ वी टॉक अबाउट जेंडर एंड व्हाय इट मैटर्स'। किताब के लेखक शूयलर बैलर अपने व्यक्तिगत अनुभवों के साथ समाज में प्रचलित धारणाओं को चुनौती देते हैं और पाठकों को सोचने के लिए मजबूर करते हैं। यह पुस्तक केवल ट्रांसजेंडर समुदाय की कहानी नहीं है, बल्कि यह संवाद की एक गाइड भी है, कैसे बात करें, क्या न पूछें और सबसे अहम, कैसे सम्मान दिखाएं। बैलर का अंदाज उपदेशात्मक नहीं, बल्कि बातचीत जैसा है, जिससे पाठक सहज रूप से जुड़ पाते हैं। वे बताते हैं कि किसी को समझना जरूरी नहीं, लेकिन उसका सम्मान करना अनिवार्य है। किताब में प्रोनाउन के महत्व, गलतियों से सीखने और बेहतर सहयोगी बनने जैसे मुद्दों को बहुत स्पष्टता से समझाया गया है। साथ ही, इसमें उम्मीद और सकारात्मकता की झलक भी मिलती है, जो इसे केवल जानकारीपूर्ण नहीं बल्कि प्रेरणादायक भी बनाती है।

फैक्ट फ्रंट

फूल जैसा दिखने वाला 'सी एनीमोन'

समुद्र की गहराइयों में अनेक अद्भुत जीव पाए जाते हैं। उन्हीं में से एक है 'सी एनीमोन'। यह मुलायम शरीर वाला शिकारी समुद्री जीव है, जो प्रवाल और जेलीफिश के समूह से संबंधित होता है। देखने में यह किसी रंग-बिरंगे फूल जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में यह एक कुशल शिकारी होता है। सी एनीमोन आमतौर पर समुद्र की सतह पर स्थिर रहते हैं। इनके शरीर के निचले हिस्से में एक पेडल डिस्क होती है, जिसकी मदद से

यह समुद्र तल, चट्टानों या प्रवाल से चिपक जाते हैं। इनका शरीर बेलनाकार होता है और ऊपर की ओर एक केंद्रीय मुख होता है, जिसके चारों ओर कई तंतु यानी टेंटेकल्स होते हैं। यही टेंटेकल्स इनके शिकार पकड़ने का मुख्य साधन हैं। इन टेंटेकल्स पर विशेष प्रकार की डंक मारने वाली कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें नेमाटोसिस्ट कहा जाता है। जब कोई छोटी मछली, क्रस्टेशियन या प्लवक इनके संपर्क में आता है, तो ये कोशिकाएं विष छोड़कर शिकार को लकवाग्रस्त कर देती हैं। इसके बाद एनीमोन आसानी से उसे अपने मुख तक ले जाकर खा लेता है। खास बात यह भी है कि कुछ एनीमोन लगभग 100 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं।

शोध जीन-संपादन तकनीक से होगा लाभ

आनुवंशिक बीमारियों के इलाज में उम्मीद की किरण

आनुवंशिक बीमारी या विकार सुनकर ही एक अजीब सी सिरहन हो उठती है। डर समा जाता है क्योंकि धारणा है कि इनका कोई निदान नहीं है। आनुवंशिक बीमारियां ज्यादातर वो होती हैं जो माता-पिता या बहुत नजदीकी रिश्तेदार के जीन से आती हैं। इन्हें असाध्य माना जाता रहा, लेकिन नए-नए शोधों और प्रयोगों ने नया रास्ता खोल दिया है। कई रोग दिनचर्या में सुधार तथा नियमित चिकित्सा से ठीक हो सकते हैं। हालांकि कई रोग अभी भी असाध्य हैं जिन पर तेजी से शोध हो रहे हैं। संभव है कि भविष्य में ये भी असाध्य नहीं रह जाएंगे।

ऋतुपर्ण दवे
स्वतंत्र लेखक एवं स्तंभकार
@patrika.com

दरअसल, आनुवंशिक बीमारियां बच्चों में दोषपूर्ण जीन से पहुंचती है। इसमें सभी जीवित प्राणियों की आनुवंशिक (जेनेटिक) जानकारी होती है। यही निर्धारित करता है कि शरीर कैसे विकसित होगा, बढ़ेगा और काम करेगा। यह शरीर का वो ब्लूप्रिंट या गाइड है जो बालों-आंखों के रंग जैसी विशेषताएं भी निर्धारित करता है। यही आनुवंशिकता की मूल इकाई है, जो गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम्स में होती है। पीढ़ी-दर-पीढ़ी गुणों को स्थानांतरित करती है। इनके निर्देशों में परिवर्तन से ही शरीर के कार्य बाधित हो रोग उत्पन्न हो सकते हैं। आनुवंशिक रोग कभी माता या पिता से संतान में स्थानांतरित हो सकते हैं और कभी नए आनुवंशिक परिवर्तनों से। आनुवंशिक बीमारियां जटिल और गंभीर होती हैं। चिकित्सा विज्ञान ने इसके निदान की उम्मीद जगाई है। भविष्य में ये ठीक हो सकेंगी। क्रिस्पर यानी क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स (सीआरआइएसपीआर) प्रणाली का उपयोग करके जीनोम को टारगेट कर संशोधित करते हैं। यह वो जीन-संपादन तकनीक है, जिसमें सीएएस-9 प्रोटीन जो कि एक महत्वपूर्ण एंजाइम होता है, का उपयोग करते हैं। एक बेहद महत्वपूर्ण आनुवंशिकी इंजीनियरिंग में यह ताकतवर उपकरण सरीखे काम करती है।

जेनेटिक इंजीनियरिंग में अपार संभावनाएं हैं। भविष्य में यह तकनीक बीमारियों के इलाज के तरीके और मानव जीनोम के बारे में चिकित्सा जगत के नजरिए को भी बदल सकती है। इसकी शुरुआत बैक्टीरिया और आर्किया खोज से हुई लेकिन शोध और प्रयोगों के नतीजों ने जीन संपादन या सुधार (दूषित जीन) के लिए एक बेहद शक्तिशाली उपकरण बना दिया। बस फिर क्या था, इस खोज ने पूरे खेल को बदल दिया और असाध्य माने जाने वाली आनुवंशिक बीमारी के इलाज में आनुवंशिक इंजीनियरिंग की प्रगति और लक्षित जीन थेरेपी ने बड़ी सफलता के लिए द्वार खोल दिए। सीआरआइएसपीआर प्रणाली का उपयोग मलेरिया न फैलाने वाले मच्छर बनाने, जलवायु परिवर्तन के लिए फसलों को बेहतर बनाने और मनुष्यों में बीमारियों का इलाज करने में बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन इसके दुरुपयोग और नैतिक उपयोग को लेकर भी सोचना होगा क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं।

कोलंबिया में लाखों वर्ष पूर्व की प्राकृतिक संरचना
विशाल ग्रेनाइट शिला

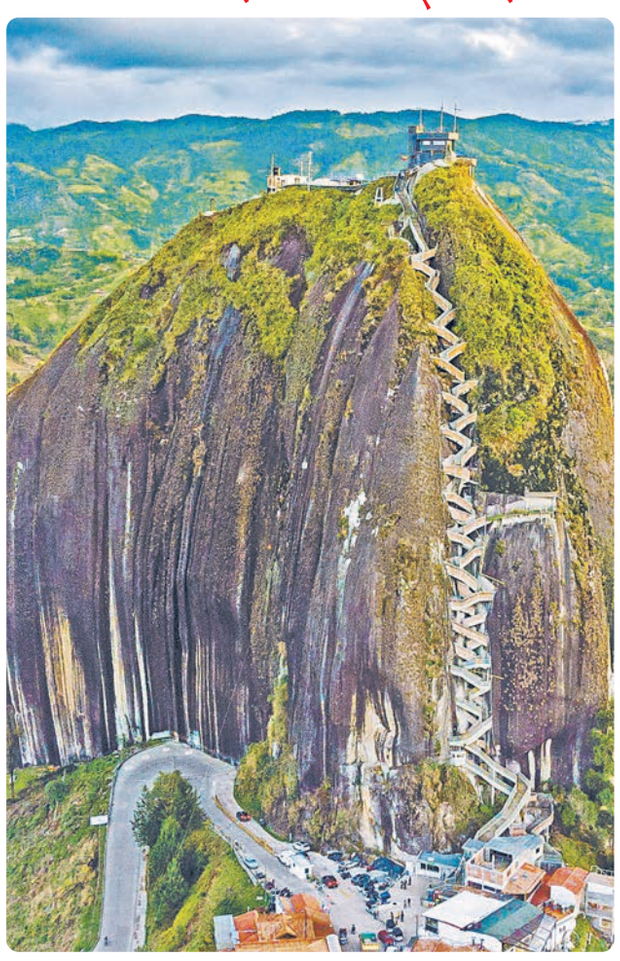

***कोलंबिया** के गुआतापे में लगभग 200 मीटर ऊंची यह ग्रेनाइट चट्टान दक्षिण अमरीका की सबसे अनोखी प्राकृतिक शिलाओं में गिनी जाती है। यह विशाल ग्रेनाइट शिला आसपास की धरती से अचानक उभरती हुई दिखाई देती है। लाखों वर्ष पूर्व आसपास की नरम चट्टानों के क्षरण के बाद यह अकेली संरचना शेष रह गई। इसके भीतर बनी प्राकृतिक दरार में 740 सीढ़ियों का रास्ता शिखर तक पहुंचता है। ऊपर से गुआतापे जलाशय के नीले जल और हरे द्वीपों का मनमोहक दृश्य दिखाई देता है, जो 1970 के दशक में बने बांध से निर्मित हुआ था।*

दृष्टिकोण गाने के द्विअर्थी बोल ने पार की हद

कला माध्यमों की सामर्थ्य का नकारात्मक उपयोग क्यों?

सोशल मीडिया पर इन दिनों बॉलीवुड की एक फिल्म का गाना चर्चा में है। इस गाने पर सहायक कलाकारों के साथ संजय दत्त और नोरा फतेही ने डांस किया है। गाना चूनर सरकने के बोल से शुरू होता है और बाद में इस हद तक द्विअर्थी बंदिशों तक चला जाता है कि मर्यादा शर्मसार होने लगती है। लोग जहां इस गीत के रचनाकार और फिल्म निर्माता को इस मर्यादाहीन प्रस्तुति के लिए कोस रहे हैं, वहीं इस गीत को लेकर तरह-तरह के मीम भी बन रहे हैं। सरकार ने भी इस गाने को इंटरनेट पर प्रतिबंधित करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन क्या ऐसे कानून नहीं बनने चाहिए जो ऐसे लोगों के मंसूबों पर नियंत्रण स्थापित करे, जो अपने व्यावसायिक लाभ के लिए लोगों की कुंठित आकांक्षाओं को उकसाते हैं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं।

सिद्धायनी जैन
स्वतंत्र लेखिका एवं स्तंभकार
@patrika.com

कला जीवन में सौंदर्य का सृजन करती है। कला के मुखर होने में रचनाकार की जीवनदृष्टि और उसकी कल्पना भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पांच दशक पहले तो इस बात पर बड़ी बहस हुआ करती थी कि 'कला, कला के लिए' नारा देने वाले लोग क्या कला के जन सरोकारों को मुखर करने की सामर्थ्य से खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? यह वो दौर था, जब आपातकाल के कटु अनुभवों की टीस लोगों के मन को अब भी बेकल कर रही थी, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से कलाकारों का एक बड़ा समूह आम आदमी के सुख-दुख की बातें करता था और नागार्जुन जैसे कवियों की प्रतिभा लोगों को सुखद आश्चर्य से भर देती थी। ऐसा नहीं है कि उस दौर में भी रचनात्मक प्रस्तुतियों की धार को भौण्डा करने के कुत्सित प्रयास नहीं हुए। उस दौर में भी ऐसे फिल्म निर्माता हुए, जो अपनी फिल्मों के नाम द्विअर्थी रखते थे। हिंदी कवि सम्मेलनों के मंचों पर कुछ कवि द्विअर्थी तुकबंदियां और चुटकुले सुनाने लगे थे। लेकिन तब से समय की नदी में बहुत सारा पानी बह गया है। तब भौण्डी प्रस्तुतियों के शिकार वो ही लोग होते थे, जो उन्हें देखने या सुनने के लिए प्रस्तुति स्थल पर जाया करते थे। जबकि अब सोशल मीडिया ने हालात बदल दिए हैं।

विसंगति यह है कि इस दौर में अश्लीलता और नकारात्मकता के भी पैरोकार मुखर हो गए हैं। अश्लील प्रस्तुतियों का विरोध करने वालों से ये कथित प्रबुद्ध जन यह कहते हुए मिल जाएंगे कि अश्लीलता गाने की प्रस्तुति में नहीं है, तुम्हारे दिमाग में है। ये लोग संस्कारों के निर्वहन को 'पिछड़ापन' और परिवार के लिए समर्पण की आवश्यकता को 'बंधन' बताते हैं। नोरा फतेही पर फिल्माए गए इस गीत जैसी प्रस्तुतियों ने एक बार फिर यह सवाल मुखर कर दिया है कि कला का दुरुपयोग लोगों की कुंठित और अतृप्त कामनाओं को भड़काने के लिए क्यों किया जाता है? बेशक, समय ऐसी प्रस्तुतियों को स्मृतियों के कूड़ेदान में फेंक देगा, लेकिन देखने वालों की मानसिकता को ऐसी प्रस्तुतियां प्रभावित तो करती हैं।

आपकी बात

तकनीक और समन्वय जरूरी

बुजुर्गों के अकेलेपन के समाधान के लिए स्थानीय प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाओं के बीच समन्वय जरूरी है। एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जाए, जो जरूरत पड़ने पर तुरंत संबंधित एनजीओ को सूचना दे सके। - **अशोक रायजादा,** जोधपुर

patrika.com पर पढ़ें

पाठकों की अन्य प्रतिक्रियाएं

पत्रिकायन का सवाल था, 'अकेले रह रहे बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए क्या विशेष कदम उठाए जाने चाहिए?' प्रतिक्रियाएं ऑनलाइन भी देखें।

इसे स्कैन करें https://shorturl.at/5Lw0P

आज का सवाल

मोबाइल बार-बार आपका ध्यान नहीं भटकाए, इसके लिए क्या किया जाए?

ईमेल करें: edit@epatrika.com

बढ़ता तापमान लंबे समय तक तापमान 20 डिग्री से अधिक रहता है, तो लड़कों के जन्म की संभावना में थोड़ी कमी देखी जा सकती है!

बदलता लिंग अनुपात: जलवायु परिवर्तन का अनोखा पहलू

नृपेन्द्र अभिषेक नृप
स्वतंत्र लेखक एवं स्तंभकार
@patrika.com

जलवायु परिवर्तन पर अब तक मुख्य रूप से पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और समाज पर पड़ने वाले प्रभावों के संदर्भ में चर्चा होती रही है। लेकिन हाल के वर्षों में किए गए शोधों ने इसके एक नए और अप्रत्याशित पहलू को सामने रखा है। यह पहलू है बढ़ते तापमान का जन्म के समय लिंग अनुपात पर प्रभाव। लिंग अनुपात से आशय उस संख्या से है, जिसमें यह देखा जाता है कि जन्म लेने वाले बच्चों में लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में कितनी है। यह किसी भी समाज का एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय संकेतक होता है, जो जैविक, पर्यावरणीय और सामाजिक परिस्थितियों को दर्शाता है।

कुछ अंतरराष्ट्रीय शोध संस्थानों और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से जुड़े वैज्ञानिकों की ओर से किए गए अध्ययनों से यह संकेत मिलता है कि बढ़ता तापमान, विशेषकर गर्भावस्था के दौरान लड़कों के जन्म की संभावना को प्रभावित कर सकता है। यह तथ्य इस बात को स्पष्ट करता है कि जलवायु परिवर्तन केवल मौसम और पारिस्थितिकी तंत्र को ही नहीं बदल रहा, बल्कि यह मानव जनसंख्या के स्वरूप को भी धीरे-धीरे प्रभावित कर सकता है।

एक बड़े अध्ययन में पांच मिलियन से अधिक जन्म के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया कि अधिक तापमान और लड़कों के जन्म की संख्या में कमी के बीच एक संबंध दिखाई देता है। इस शोध में भारत और उप-सहारा अफ्रीका के 33 देशों के आंकड़ों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से यह निष्कर्ष निकला कि जब लंबे समय तक तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है, तो लड़कों के जन्म की संभावना में थोड़ी कमी देखी जाती है। यह शोध एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिका में प्रकाशित हुआ और इसने काफी ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि इसमें पहली बार पर्यावरणीय परिस्थितियों को सीधे जैविक परिणामों से जोड़कर देखा गया। भले ही यह बदलाव अल्पकाल में बहुत छोटा दिखाई देता हो, लेकिन बड़ी आबादी वाले देशों में यह छोटे-छोटे परिवर्तन भी लंबे समय में महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय प्रभाव डाल सकते हैं।

वैज्ञानिकों के अनुसार इसके पीछे एक संभावित कारण पुरुष भ्रूण की जैविक संवेदनशीलता हो सकती है। चिकित्सा विज्ञान के कई अध्ययनों में यह पाया गया है कि गर्भावस्था के दौरान पुरुष भ्रूण, महिला भ्रूण की तुलना में बाहरी तनाव और प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। जब तापमान अधिक होता है, तो गर्भवती महिलाओं के शरीर पर अतिरिक्त शारीरिक दबाव पड़ता है। इससे शरीर में पानी की कमी, चयापचय प्रक्रिया में बदलाव और सामान्य स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। इस प्रकार की परिस्थितियां गर्भ के शुरुआती चरणों में पुरुष भ्रूण के लिए अधिक जोखिम पैदा कर सकती हैं। इस प्रकार देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन अप्रत्यक्ष रूप से लड़कों और लड़कियों के प्राकृतिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है। गर्भावस्था के दौरान गर्मी के संपर्क का समय भी इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अध्ययन के अनुसार गर्भावस्था का पहला त्रैमासिक यानी शुरुआती तीन महीने पर्यावरणीय परिस्थितियों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं। यदि इस अवधि में गर्भवती महिला लंबे समय तक अधिक गर्मी के संपर्क में रहती है, तो गर्भपात या भ्रूण के विकास में समस्याओं की संभावना बढ़ सकती है। विशेष रूप से पुरुष भ्रूण इस स्थिति में अधिक प्रभावित हो सकता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि गर्मी सीधे बच्चे का लिंग निर्धारित करती है, बल्कि यह उन गर्भधारणों को प्रभावित कर सकती है जो अंततः सुरक्षित रूप से जन्म तक पहुंच पाते हैं।

हालांकि यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि तापमान और लिंग अनुपात के बीच संबंध अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुआ है। जन्म के परिणामों को कई कारक प्रभावित करते हैं, जैसे आनुवंशिकी, मातृ स्वास्थ्य, पोषण और चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता। इसलिए तापमान को इस प्रक्रिया का एकमात्र कारण नहीं माना जा सकता। यद्यपि अभी तक देखे गए परिवर्तन बहुत बड़े नहीं हैं, फिर भी वे हमें यह समझने के लिए प्रेरित करते हैं कि जलवायु परिवर्तन मानव समाज को कितने सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण तरीकों से प्रभावित कर सकता है।

नेतृत्व का मतलब है कठिन फैसले लेना, भले ही वे अलोकप्रिय हों। नेतृत्व पद नहीं, जिम्मेदारी है। सफलता का असली पैमाना यह है कि आप दूसरों के लिए कितने अवसर बनाते हैं।

जेन फ्रेजर सीईओ, सिटी ग्रुप

पत्रिका फाइनेंस

@बिजनेस & वेल्थ

शेयर बाजार		सोना	चांदी	रुपया
सेंसेक्स 75,273 (+1205)	निफ्टी 23,306 (+394)	स्टैंडर्ड (24K) ₹1,48,500 (प्रति 10 ग्राम) (+4500)	चांदी (999) ₹2,41,000 (प्रति किग्रा) (+13000)	₹93.98 (प्रति 1 डॉलर) (-0.11)

डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग एफएंडओ में लगातार बढ़ रहा ट्रेडिंग वॉल्यूम, 1 अप्रेल से टैक्स बढ़ने पर होगा असली टेस्ट

अगले माह बढ़ेगा एसटीटी, निवेशकों को लगेगा झटका

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

मुंबई. देश में एक अप्रेल से फ्यूचर्स और ऑप्शंस (एफएंडओ) ट्रेडिंग पर बढ़ा हुआ सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लागू हो जाएगा। सरकार ने फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स पर एसटीटी को बढ़ाकर 0.05% कर दिया है। ऑप्शंस प्रीमियम पर टैक्स अब 0.15% और ऑप्शंस के एक्सरसाइज पर 0.15% लगेगा। इस कदम का मकसद डेरिवेटिव्स सेगमेंट में अत्यधिक सट्टेबाजी (स्पेकुलेशन) को रोकना है। बाजार में भारी उठापटक के बावजूद पिछले 6 महीने से लगातार एफएंडओ में ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ रहा है, अक्टूबर में निफ्टी 50 इंडेक्स ऑप्शन का प्रीमियम टर्नओवर 8.99 लाख करोड़ रुपए था, जो मार्च में अब तक 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। जबकि सेबी की स्टडी के मुताबिक इसमें 90% निवेशकों को घाटा ही होता है।

एसटीटी बढ़ने का क्या है मतलब

फ्यूचर्स पर एसटीटी

पहले	0.02%
अब	0.05%

असर: अगर आपने ₹10 लाख का सौदा किया

पहले टैक्स	₹200
अब टैक्स	₹500

ऑप्शंस पर एसटीटी

पहले	0.10%
अब	0.15%

ऑप्शन एक्सरसाइज पर

पहले	0.125%
अब	0.15%

असर: यानी ऑप्शन खरीदने, बेचने और एक्सरसाइज करने तीनों हालात में ज्यादा टैक्स देना होगा।

एक लॉट निफ्टी 50 फ्यूचर्स की सेल पर कितना एसटीटी

चार्ज	मौजूदा दर	नई दरें
ब्रोकरेज	20	20
एक्सचेंज ट्रांजैक्शन	27.88	27.88
जीएसटी	7.11	7.11
एसटीटी	322.29	805.73
सेबी टर्नओवर चार्ज	1.61	1.61
कुल चार्ज	380.50	863.94

*(यानी एक लॉट पर 127% बढ़ गया शुल्क, **मौजूदा दर और नई दरें रुपए में**)*

जेरोधा ने बढ़ाया ब्रोकरेज चार्ज

विशेषज्ञों का कहना है कि टैक्स बढ़ने से ट्रेडिंग की लागत बढ़ेगी, पर वॉल्यूम में ज्यादा गिरावट नहीं आएगी। इस बीच डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म जेरोधा ने भी 1 अप्रेल 2026 से कुछ इंट्राडे डेरिवेटिव ट्रेड्स पर ब्रोकरेज फीस सीधे दोगुना बढ़ाकर 40 रुपए प्रति ऑर्डर करने का फैसला किया है। पहले हर ऑर्डर के लिए ब्रोकरेज फीस 20 रुपए थी। *यह बदलाव उन ट्रेडर्स पर लागू होगा जो सेबी के 50% कैश कोलेटरल नियम को पूरा नहीं करते हैं। आने वाले समय में अन्य ब्रोकरेज कंपनियां भी डेरिवेटिव्स पर इसी तरह के शुल्क बढ़ाने जैसे कदम उठा सकती हैं।*

इन फैसलों से भी लगेगा झटका

1. डेरिवेटिव्स (फ्यूचर एंड ऑप्शंस) पर एसटीटी बढ़ने से एफएंडओ ***ट्रेडिंग की लागत करीब 3 गुना तक बढ़ेगी। इससे निवेशकों की लागत बढ़ेगी जिससे वॉल्यूम घटेगा।***
2. अब डिविडेंड इनकम और म्यूचुअल फंड इनकम के खिलाफ ब्याज खर्च पर टैक्स कटौती नहीं मिलेगी। इसका असर उन निवेशकों पर पड़ेगा, ***जो उधार लेकर या मार्जिन फाइनेंसिंग के जरिए निवेश करते हैं। इससे टैक्स देनदारी बढ़ जाएगी।***
3. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (एसजीबी) पर कैपिटल गेन टैक्स की छूट सिर्फ उन्हीं निवेशकों को मिलेगी, जिन्होंने बॉन्ड ओरिजिनल इश्यू में खरीदे हों और उन्हें मैच्योरिटी तक होल्ड किया हो। इससे ***10 लाख के मुनाफे पर कम से कम 1.25 लाख रुपए टैक्स देना होगा।***

WEALTH **वीमन & मनी** CREATION

महिला निवेशकों का दम 5 साल में डीमैट खातों में 129% उछाल

बचत में आगे... इक्विटी निवेश में पीछे

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

नई दिल्ली. देश की 70% महिलाएं नियमित रूप से बचत करती हैं, पर वे वेल्थ क्रिएशन वाले एसेट्स में निवेश करने में पीछे हैं। महिलाएं 60% निवेश बैंक एफडी में करती हैं। 40% निवेश ही एफडी और सोना-चांदी जैसे पारंपरिक साधनों से इतर स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड जैसे वेल्थ क्रिएशन वाले एसेट्स में करती हैं। यह बताता है कि बचत और संपत्ति निर्माण के बीच अब भी बड़ा गैप मौजूद है। हालांकि, 'हर वेल्थ-हल वे' रिपोर्ट के मुताबिक, करीब 80% महिला म्यूचुअल फंड निवेशक 35 वर्ष की उम्र से पहले निवेश शुरू कर देती हैं, जिसमें एसआइपी का बड़ा योगदान है। एक बार म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू करने के बाद 86% महिलाएं अगले पांच वर्ष निवेश बनाए रखती हैं।

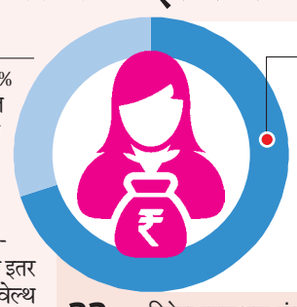

70% **महिलाएं** नियमित रूप से करती हैं बचत, ***पर उनका 60% से ज्यादा निवेश एफडी में***

40% **महिलाएं** ही बैंक एफडी के इतर शेयर, ***म्यूचुअल फंड जैसे अन्य एसेट्स में करती हैं निवेश***

33% निवेश म्यूचुअल फंड्स में महिलाएं एसआइपी के जरिए करती हैं, ***49% निवेश लंपसम यानी एकमुश्त करती हैं***

लक्ष्य आधारित निवेश पर बढ़ा फोकस

एक्सिस के कंज्यूमर ट्रेंड्स के अनुसार, 5 साल में महिलाओं की ओर से खोले गए डीमैट खातों में 129% की बढ़ोतरी हुई है। इसके बावजूद इक्विटी, डेरिवेटिव्स और कमोडिटीज में उनका निवेश बहुत कम है। आधे से अधिक महिलाएं अब भी निवेश सलाह के लिए पुरुष परिवार के सदस्यों पर निर्भर हैं, खासकर टियर-2 और छोटे शहरों में। 57% महिलाएं लंबे समय तक इक्विटी में निवेश बनाए रखने के लिए तैयार हैं, यदि उत्पादों को स्पष्ट रूप से समझाया जाए। 64% महिला म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए एसआइपी पसंद करती हैं।

कारोबार @पत्रिका इंफोग्राफिक्स

लगातार 5वें साल घटा जेम्स-ज्वैलरी का निर्यात

अमरीकी नहीं, अब यूएई भारत का सबसे बड़ा बाजार

नई दिल्ली@पत्रिका. *भारत से रत्न-आभूषणों का निर्यात लगातार 5वें साल घटा है। पहले से ही अमरीकी टैरिफ के कारण दबाव झेल रहे इस सेक्टर पर पश्चिम एशिया तनाव का और असर पड़ सकता है। अमरीका को पीछे छोड़ यूएई भारतीय आभूषणों का सबसे बड़ा बाजार बन गया है।*

ऐसे घटा रत्न-आभूषणों का निर्यात

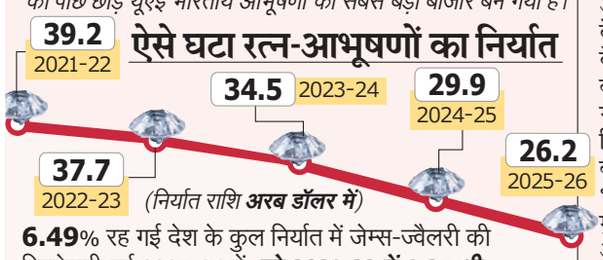

*(निर्यात राशि **अरब डॉलर में**)*

6.49% रह गई देश के कुल निर्यात में जेम्स-ज्वैलरी की हिस्सेदारी वर्ष 2025-26 में, ***जो 2021-22 में 8.2% थी***

यूएई को सबसे अधिक बढ़ा निर्यात

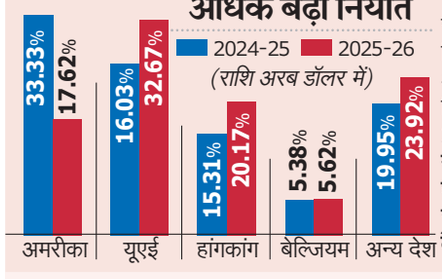

33.3% थी भारत के कुल रत्न-आभूषण निर्यात में अमरीका की हिस्सेदारी 2024-25 में, **जो 2025-26 में घटकर 17.6% रह गई ट्रंप टैरिफ के कारण**

यूएई से आयात भी बढ़ा

कमोडिटी	2024-25	2025-26
सोना	29.19%	23.05%
चांदी	9.19%	4.43%
सोना व अन्य ज्वेलरी	12.99%	7.94%
मोती व कीमती पत्थर	42.70%	48.17%
अन्य कीमती धातु	31.69%	5.14%

48% से अधिक मोती व कीमती पत्थर का आयात अकेले यूएई से भारत ने किया, ***गोल्ड इंपोर्ट में भी यूएई की हिस्सेदारी 23% से अधिक***

बाजार में लौटे बुल, निवेशकों की जेब फुल 2 दिन में 16 लाख करोड़ बढ़ी बाजार पूंजी

भारतीय बाजार अब महंगा नहीं, वैल्यूएशन ग्लोबल बाजारों के बराबर

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

मुंबई. भारतीय शेयर बाजार ऊंचे वैल्यूएशन के लंबे दौर के बाद अब अधिक संतुलित और उचित स्तरों पर आ गया है। वर्ष 2026 में खासकर इस महीने आई भारी गिरावट से निफ्टी 50 का प्राइस-टू-अर्निंग (पी/ई) मल्टीपल अपने हालिया और दीर्घकालिक औसत से नीचे आ चुका है, जो संकेत देता है कि बाजार में सुधार होकर वैल्यूएशन अब 'फेयर वैल्यू' के करीब पहुंच गया है और यह अब ग्लोबल बाजारों के लगभग बराबर है। पिछले कुछ महीनों की सुस्ती और कंपनियों की आय में सुधार के चलते भारतीय बाजार अब पहले के मुकाबले निवेशकों के लिए ज्यादा आकर्षक नजर आ रहा है, जबकि इसकी दीर्घकालिक ग्रोथ स्टोरी अब भी मजबूत बनी हुई है।

इस बीच पश्चिम एशिया में तनाव कम होने के संकेत से बुधवार को शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन जबरदस्त इजाफा देखने को मिला। सेंसेक्स में में 1205 अंक का इजाफा देखने को मिला और यह 75,273 पर बंद हुआ। मंगलवार को भी सेंसेक्स में 1300 से ज्यादा अंकों की तेजी देखने को मिली थी। दो दिन में सेंसेक्स में 2550 से ज्यादा अंकों का इजाफा हुआ है, जिससे कंपनियों की बाजार पूंजी 16 लाख करोड़ रुपए बढ़कर 431.1 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। निफ्टी 50 भी बुधवार को 394 अंक यानी 1.72% की बढ़त लेकर 23,306 पर बंद हुआ। आकर्षक वैल्यूएशन और अमरीका-ईरान के बीच शांति के लिए कूटनीतिक प्रगति के चलते कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर से नीचे आ गईं, जिसे शेयर बाजार ने सकारात्मक रूप में लिया।

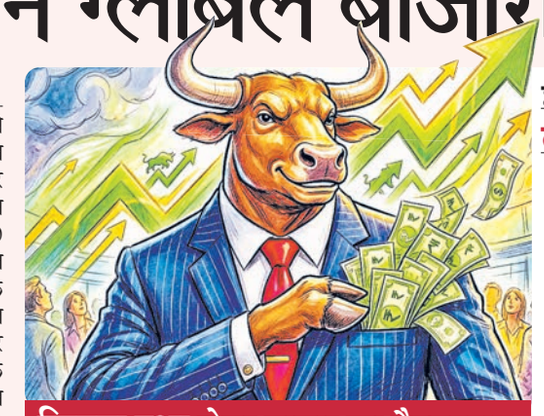

कितना हुआ शेयर बाजार का वैल्यूएशन

बाजार	पी/ई रेश्यो
सेंसेक्स, **भारत**	20.4
निफ्टी 50, **भारत**	20.2
नैस्डैक, **अमरीका**	33.1
डाउजोंस, **अमरीका**	23.8
डीएएक्स, **जर्मनी**	17.9
सीएसी, **फ्रांस**	19.7
निक्केई, **जापान**	21.2

प्राइस-टू-अर्निंग रेश्यो

(प्रति शेयर कमाई के मुकाबले मार्केट प्राइस गुणा में)

ऐसे घटा निफ्टी 50 का वैल्यूएशन

अवधि	पीई रेश्यो (गुणा)
मौजूदा पीई	20.2
1 साल का मेडियन	22.3
5 साल का औसत	25.6
लॉन्ग टर्म एवरेज	23.5

94.05 के ऑल-टाइम लो पर बंद हुआ रुपया अमरीकी डॉलर के मुकाबले, ***बुधवार को 18 पैसे लुढ़का***

शेयर बाजार में लौटी तेजी

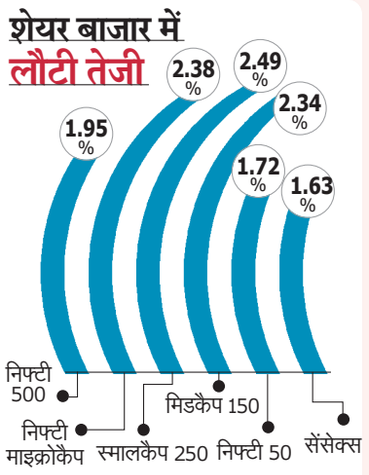

1205 अंक उछला सेंसेक्स 75,000 के पार, निफ्टी भी 1.72% चढ़कर 23,306 पर बंद, ***पश्चिम एशिया तनाव कम होने के संकेत से***

इन सेक्टर्स में जबरदस्त तेजी

कं. ड्यूरेबल्स	3.5%
निफ्टी रियल्टी	2.69%
निफ्टी केमिकल्स	2.68%
निफ्टी मेटल	2.56%
निफ्टी हेल्थकेयर	2.22%
निफ्टी ऑटो	2.22%
निफ्टी बैंक	2.10%

बाजार को इनसे मिलेगा सपोर्ट...

1. मजबूत मैक्रोइकॉनॉमिक आधार बेहतर वैल्यूएशन को सहारा दे रहे हैं। भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.3-7.5% रहने का अनुमान है।
2. पहले बाजार कंपनियों की आय से तेज भाग रहा था, लेकिन ***अब कीमतों में थोड़ी ठंडक आई है और अर्निंग्स ने उस अंतर को काफी हद तक भर दिया है।***
3. भारत अब संरचनात्मक निवेश चक्र में प्रवेश कर रहा है, जिसे ***तीन प्रमुख सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी तेजी सेआगे बढ़ा सकते हैं।***
4. कुछ सेक्टर निवेश आकर्षित कर सकते हैं, जिनमें ईवी, ऑटो ट्रांजिशन के साथ ***इलेक्ट्रॉनिक्स व सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग शामिल***

असर मंजूरी जून 2026 तक होगी लैप्स

13 कंपनियों के ₹18,000 करोड़ के आइपीओ पर संकट

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

मुंबई. भारतीय शेयर में जारी भारी उठापटक और 2026 में आइपीओ का औसत लिस्टिंग गेन 2% पर आने आइपीओ बाजार में भी इस समय सुस्ती देखी जा रही है, जिसका असर कंपनियों की फंड जुटाने की योजनाओं पर पड़ रहा है। करीब ₹18,000 करोड़ के आइपीओ अब खतरे में हैं, क्योंकि 13 कंपनियों को सेबी से आइपीओ लॉन्च करने के लिए मिली मंजूरी जून 2026 तक खत्म होने वाली है। नियम के मुताबिक, कंपनियों को मंजूरी मिलने के 12 महीने के भीतर अपना आइपीओ लॉन्च करना होता है। अगर वे ऐसा नहीं कर पातीं, तो उन्हें पूरी प्रक्रिया फिर से शुरू करनी पड़ती है। इन कंपनियों में हीरो फिनकॉर्प, वेरिटास फाइनेंस जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं, जो हजारों करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में थीं। बाजार में उतार-चढ़ाव के कारण कंपनियां अभी आइपीओ लाने से बच रही हैं।

इन आइपीओ की मंजूरी हो चुकी है लैप्स

कंपनी	आइपीओ साइज
एसएमपीपी लिमिटेड	4,000
वरिंदेरा कंस्ट्रक्शंस	1,200
कुमार आर्च टेक	740
पीएमईए सोलर टेक	600
परमेसु बायोटेक	600
सीआईईएल एचआर	450

(आइपीओ साइज करोड़ रुपए में)

इन कंपनियों ने वापस लिए आइपीओ आवेदन

कंपनी	आइपीओ साइज
फिनकॉर्प इंडिया	2,600
टाटा प्ले	2500
इंडिया फर्स्ट लाइफ	2000
एसके फाइनेंस	2200
पारस हेल्थकेयर	1600

(10 अन्य आइपीओ ने भी सेबी के पास जमा अपने आइपीओ आवेदन को वापस ले लिया)

एफआइआर दर्ज एफडी फ्रॉड का आरोप

कोटक महिंद्रा बैंक से गायब हुए नगर निगम के ₹160 करोड़

पंचकूला. @पत्रिका. कोटक महिंद्रा बैंक के अधिकारियों पर पंचकूला नगर निगम के 160 करोड़ रुपए के गबन का आरोप लगा है। आरोप है कि एफडी के नाम पर जमा कराई गई यह राशि फर्जी खातों में ट्रांसफर कर दी गई और निगम को केवल कागजी रेकॉर्ड थमाए जाते रहे। बैंक अधिकारियों ने मिलीभगत कर जाली खाते खोलकर यह रकम उनमें ट्रांसफर कर दी।

ऐसे सामने आया मामला

मामले का खुलासा तब हुआ जब निगम ने 58 करोड़ रुपए की एक एफडी की मैच्योरिटी राशि अपने खाते में ट्रांसफर करने को कहा। बैंक की ओर से दिए गए स्टेटमेंट में राशि ट्रांसफर दिखाई गई, लेकिन वास्तविक खाते में पैसा नहीं पहुंचा। जांच में पता चला कि स्टेटमेंट भी फर्जी था और रकम गायब है। इस मामले में बैंक ने एक एफआइआर दर्ज कराई है।

सीसीपीए रेस्तरां और होटल को जारी की चेतावनी

बिल में लगाया एलपीजी चार्ज तो कार्रवाई

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

नई दिल्ली. होटलों और रेस्तरां में खाने के बिल पर मनमाने ढंग से एलपीजी शुल्क या गैस सरचार्ज जोड़ने पर सख्ती की गई है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने होटल और रेस्टॉरेंट को चेतावनी दी है कि वे ग्राहकों से एलपीजी चार्ज जैसी अतिरिक्त वसूली न करें। प्राधिकरण ने कहा कि ऐसा करना पूरी तरह से गलत है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्राधिकरण ने इसे अनुचित व्यापार करार दिया है और कहा, 'मेन्यू' में लिखे मूल्य में सिर्फ लागू टैक्स ही जोड़े जा सकते हैं।

परामर्श जारी किया

सीसीपीए ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 10 के तहत एक परामर्श जारी किया है। इसमें कहा गया कि ईंधन, एलपीजी, बिजली और अन्य परिचालन व्यय जैसी कच्चे माल की लागत कारोबार चलाने की लागत का हिस्सा हैं और इन्हें 'मेन्यू आइटम' की कीमत तय करते समय शामिल किया जाना चाहिए। अलग से अनिवार्य शुल्कों के माध्यम से ऐसी लागत की वसूली अधिनियम की धारा 2(47) के तहत अनुचित व्यापार गतिविधियां है। मेनू में जो कीमत लिखी है, वही अंतिम मानी जाएगी। ग्राहक से अलग से एलपीडी चार्ज लेना अपराध है।

...तो 1915 पर करें शिकायत मामले सीसीपीए ने पाया कि सर्विस चार्ज से जुड़े मौजूदा दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर ऐसे चार्ज लगाए जा रहे हैं। प्राधिकरण ने कहा, उपभोक्ताओं को अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य किया जाएगा।अगर बिल में ऐसा कोई चार्ज दिखे तो ग्राहक तुरंत उसे हटाने की मांग कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 पर शिकायत कर सकते हैं।

बैंकिंग

इंसेंटिव फार्मूले का विरोध जारी

नई दिल्ली @ पत्रिका. यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स के संशोधित परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव फार्मूले के विरोध में चल रहे आंदोलन को देशभर में व्यापक समर्थन मिल रहा है। यूनियन का आरोप है कि वित्तीय सेवा विभाग द्वारा प्रस्तावित नया पीएलआइ फार्मूला एकतरफा और विभाजनकारी है, जो मौजूदा द्विपक्षीय समझौते से अलग हटकर कर्मचारियों के बीच असमानता पैदा करेगा। संगठन का कहना है कि इससे टीमवर्क और औद्योगिक सौहार्द प्रभावित होगा। मामला मुख्य श्रम आयुक्त के समक्ष सुलह प्रक्रिया में लंबित है। संगठन ने आइबीए से तत्काल वार्ता कर समाधान निकालने की मांग की है।

कैंपस से कॉरपोरेट तक, गलगोटियाज के छात्रों को मिला रेकॉर्ड प्लेसमेंट

जयपुर@पत्रिका. गलगोटियाज विश्वविद्यालय ने मौजूदा शैक्षणिक सत्र में शानदार प्लेसमेंट प्रदर्शन दर्ज करते हुए छात्रों को ड्रीम जॉब्स दिलाने में सफलता हासिल की है। कड़ी प्रतिस्पर्धा वाले जॉब मार्केट के बावजूद विश्वविद्यालय ने अपनी मजबूत प्लेसमेंट परंपरा को कायम रखा है। विश्वविद्यालय के अनुसार इस वर्ष अधिकतम 60 लाख रुपए वार्षिक पैकेज ऑफर किया गया, जबकि बड़ी संख्या में छात्रों को 15 लाख से 26.6 लाख रुपए सालाना तक के आकर्षक प्रस्ताव मिले। कैंपस प्लेसमेंट में इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, एक्सेंचर, ईवाई और कैपजेमिनी जैसी प्रमुख कंपनियों सहित 1200 से अधिक संस्थानों ने भाग लिया। भर्ती आंकड़ों के अनुसार इन्फोसिस ने सर्वाधिक 526 छात्रों को नियुक्त किया, वहीं कैपजेमिनी में 228, कॉग्निजेंट में 205, एलटीएम में 119, सिटी यूनियन बैंक में 188, एक्सेंचर में 91 और अर्न्स्ट एंड यंग में 61 छात्रों का चयन हुआ। प्रबंधन का कहना है कि यह सफलता छात्र-केंद्रित एक्टिव लर्निंग मॉडल, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और इंडस्ट्री एक्सपोजर का परिणाम है।

नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, सिंगापुर के सहयोग से विकसित इस मॉडल ने छात्रों को कॉरपोरेट दुनिया के लिए तैयार किया है। प्लेसमेंट के साथ ही विश्वविद्यालय स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप को भी बढ़ावा दे रहा है, जिससे छात्र नवाचार और स्व-रोजगार की दिशा में आगे बढ़ सकें।

फर्नीचर मार्केट की क्लियरेंस स्कीम आज से

जयपुर@पत्रिका. फर्नीचर मार्केट इस साल की सबसे बड़ी फर्नीचर क्लियरेंस सेल लेकर आया है। इसमें कीमतें न सिर्फ पिछले रेट्स से काफी कम रखी गई हैं, बल्कि ये अब तक की सबसे कम कीमतें हैं। इस ऑफर में स्टोरेज डबल बेड सिर्फ छह हजार रुपए में, एलशेप सोफा सेट बाइस हजार रुपए में उपलब्ध है। ब्रांड प्रतिनिधि प्रिशा जैन ने बताया कि 26 से 31 मार्च 2026 तक चलने वाली इस विशेष सेल का उद्देश्य सीमित

उपलब्ध स्टॉक को तेजी से क्लियर करना है। इससे शादियों, गृह प्रवेश और घर की साज-सज्जा के लिए ग्राहकों को बेहतरीन क्वालिटी का फर्नीचर किफायती दामों पर मिल सकेगा।

फिर नई ऊंचाई पर पहुंचे सोना और चांदी

SKJ Jewellers VAISHALI NAGAR 0141-4005001 VIDHYADHAR NAGAR 0141-2820777

जयपुर. वायदा बाजार की तेजी से जयपुर सर्राफा बाजार में बुधवार को दोनों कीमती धातुओं में रिकॉर्ड तेजी आई। चांदी 13,000 रुपए की छलांग लगाकर 2,41,000 रुपए प्रति किलो रही। शुद्ध सोना 4500 रुपए बढ़कर 1,48,500 रुपए प्रति दस ग्राम रहा। जेवराती सोना भी 4300 रुपए चढ़ा।

ऊर्जा सचिव से मिला आरएसए का प्रतिनिधिमंडल

जयपुर@पत्रिका. राजस्थान सोलर एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने ऊर्जा सचिव आरती डोगरा से मुलाकात की। इसमें आरएसए सीईओ नितिन अग्रवाल, उपाध्यक्ष अरुण महला, शैलेष गर्ग और नितिन गोयल शामिल थे। आरएसए की ओर से आरती डोगरा को नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से राजस्थान में चलाए जा रहे 'खेजड़ी से कल-ग्रीनर राजस्थान मिशन' की

जानकारी दी। इस अवसर पर डोगरा ने खेजड़ी का पौधा लगाकर इस मिशन को अपनी शुभकामनाएं दी। अग्रवाल का कहना है कि इस मिशन के तहत पूरे 10 लाख खेजड़ी के पौधे लगाए जाएंगे।

प्रेरणा

किसी भी काम को करने से पहले उस पर विवेक से विचार करें। - टाइटस मैक्सियस प्लैटस

संपादकीय

एथेनॉल हमें तेल-संकट से राहत दिला सकता है

देश की 1800 करोड़ लीटर एथेनॉल बनाने की वर्तमान क्षमता तेल-संकट से राहत दिला सकती है। भारत में एथेनॉल मक्का, चावल, गन्ने के रस और मोलेसेस (दो किस्म) से बनता है। ब्राजील दशकों पहले पेट्रोल में 30% एथेनॉल मिलाकर और केन्या एथेनॉल एटीएम बनाकर कुकिंग ईंधन संकट से बचने का रास्ता दिखा चुका है। भारत अपने परिवहन के लिए पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग (करीब 900 करोड़ लीटर) कर रहा है, जिसे 30% करने पर 400-500 करोड़ लीटर एथेनॉल की और जरूरत पड़ेगी। इसका लाभ यह होगा कि किसान का मक्का एथेनॉल बनाने के काम आएगा, यानी फसल विविधीकरण संभव हो सकेगा। खबर है कि नए चूल्हे बनाने पर शोध का काम कई संस्थाएं कर रही हैं। एथेनॉल एलपीजी से ज्यादा सुरक्षित और सस्ता है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत पेट्रोल की जगह शत प्रतिशत एथेनॉल (ई-100) पर भी जा सकता है और इसके लिए वर्तमान पेट्रोल पम्पों पर ही अलग से हाइड्रस (सजल) इकाई बनाई जा सकती है। वाहन यूजर्स कीमत देखकर दोनों विकल्पों में से कोई एक चुन सकते हैं। इसमें दो राय नहीं कि पिछले दो दशकों से भारत खाद्यान्न में न केवल आत्मनिर्भर हुआ है बल्कि उलटे अति-उत्पादन एक नया सिरदर्द बन गया है। चावल और गेहूं चूंकि मजबूत फसल हैं इसलिए किसान भारी खाद-पानी खर्च करके भी इनका उत्पादन कर रहा है। खंडा चावल का सबसे अच्छा विकल्प एथेनॉल बनाना ही है। हमारे यहां मक्का भी प्रचुर मात्रा में होता है।

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता

humarehanuman@gmail.com

जब भी विपत्ति आए, उसका अच्छे-से सामना करिएगा

मनुष्य के जीवन में अचानक जब कुछ होता है, तब उसकी परीक्षा होती है कि वो कितना समझदार है। कैसे उसका सामना करता है। आप कितने ही समर्थ व्यक्ति हों, लेकिन विपरीत परिस्थिति आपके हाथ में नहीं है। हां, उसको संभालना आपके हाथ में है। विपत्ति में कुछ लोग निखर कर कुंदन बन जाते हैं और कुछ कोयला रह जाते हैं। रामकथा में एक बहुत अच्छा उदाहरण है। राम को राजा बनना था लेकिन कैकेयी ने निर्णय पलट दिया और राम को बुलवाया। कैकेयी के महल में राम ने देखा कि दशरथ विचलित से लेटे हुए हैं। कैकेयी आवेश में है। ऐसा दृश्य राम ने पहली बार देखा। उनके लिए पंक्ति लिखी है- प्रथम दीख दुखु सुना न काउ। पहली बार कोई दुःख देखा। इससे पहले कभी दुःख सुना भी न था। लेकिन राम मन ही मन मुस्कराए और कहा- जो होता है, अच्छा ही होता है। और साबित भी कर दिया कि वनवासी राम इतने लोकप्रिय हुए कि जिन्होंने अयोध्या छोड़ी, वो लोगों के दिलों में पहुंच गए। तो जीवन में जब कुछ अचानक आए, विपरीत आए, श्रीराम को याद करके अच्छे-से उसका सामना करिएगा। • Facebook:Pt. Vijayshankar Mehta

शब्दों का जादू

खाना खाती औरतें

घर के आदमियों को दुनिया के बड़े जरूरी काम होते थे
वे आते, हांक लगाते, परोसी हुई थाली आती
वे चुपचाप खाना खाते, थाली में हाथ धोते
और दांत खोदते, खंखारते जरूरी कामों पर वापस चले जाते!

औरतें ऐसा नहीं करतीं।
औरतों के खाना खाने बैठने और खाना खाकर उठने से
घर के पहर बदल जाया करते हैं।

खाना खाती स्त्रियां हमारी गृहस्थियों की धूपघड़ियां होती हैं।

वे तब खातीं जब घर के कुत्ते-बिल्ली भी खाकर ऊंघने लगते थे।
वे अकेली रह जातीं इसलिए उनके साथ पूरी रसोई बाहर आती
बड़े भगोने, पतीले, कढ़ाही लेकर वे खाने बैठतीं।

कढ़ाही में खाने पर ब्याह में बारिश होने का भय बहुत वाजिब था
लेकिन ये औरतें ऐसे अधिकार से खातीं कि
इन्द्र देवता चुपचाप लोटे में बैठे उनको देखते रहते।
उस वक्त हमारी मांएं हमें देवताओं से भी ज्यादा रसूखदार लगतीं

जब तक मेरी इन पुरखिनों की आदिम भूख और प्यास की स्मृतियां
मेरे पास हैं, वे मेरे जीवन को कभी रीतने नहीं देंगी।

-एकता वर्मा, दिल्ली (मूल कविता के सम्पादित अंश)

भास्कर कविता उत्सव की शीर्ष 100 कविताओं में चयनित

पाठकों के पत्र

खानपान में मिलावट रुके

देश की कई खाद्य कंपनियां मिलावट में दोषी पाई जा रही हैं। मिलावट से मौतें होने पर भी इन पर कार्रवाई नहीं की जाती। जो कंपनियां विदेश में प्रतिबंधित है, वे भारत में खुलेआम सामान बेच रही हैं। सरकार को मिलावटखोरी पर पूर्णतः रोक लगानी चाहिए।
-आदित्य शेखर, इंदौर, मध्यप्रदेश

सड़कों पर अंधेरा गंभीर समस्या

सार्वजनिक स्थानों पर अपर्याप्त रोशनी गंभीर मुद्दा है। कामकाजी महिलाओं, कोचिंग छात्राओं को रात में अपर्याप्त रोशनी के कारण असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। हमारे यहां स्ट्रीट लाइटें मैनुअली संचालित हैं, जिससे समय पर प्रकाश नहीं हो पाता। प्रशासन को स्वचलित सोलर लाइटें लगानी चाहिए।
-विदुल शुक्ला, कानपुर, उत्तर प्रदेश

आप अपने पत्र editpage@dbcorp.in पर भेज सकते हैं

क्या आप जानते हैं

रेगिस्तान में 'गूंजते टीले'

चीन के अनोखे बादैन जारन मरुस्थल में 144 झीलें हैं। यहां 500 मीटर तक दुनिया के सबसे ऊंचे टीले भी हैं, जिन्हें 'सिंगिंग ड्यून्स' कहते हैं। हवा से मिट्टी के कणों के टकराने पर इनसे संगीत जैसी आवाज निकलती है।
7.26 लाख हेक्टेयर में फैला बादैन जारन विश्व धरोहरों में शामिल है।

सुर्खियों से आगे • आप ताकतवर हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन कुछ तो भी मत करिए...

तुम सौदागर तेल के, हम कोल्हू के बैल!

देश-दुनिया

नवनीत गुर्जर

navneet@dbcorp.in

कच्ची घाणी। अब तो इसके लिए भी आधुनिक तरीके, मशीनें आ गई हैं। लेकिन पहले कोल्हू होता था और कोल्हू का बैल। जी, हम सब कच्ची घाणी के या कोल्हू के बैल ही तो हैं! कोल्हू चलता था तो 'चक चूं' करता था। बैल बस, सारी उम्र चलता रहता था। साल, महीने गिने बिना। गोल-गोल घूमता फिरता था। गले की घंटी बजती रहती थी, जिससे उसे लगता था कि इस गोल-गोल दुनिया के सिवाय भी कुछ है। जैसे आवाज, घंटी की या शोर किसी और चीज का।

इसी धुन में, इसी भ्रम में, खींचता रहता था पुल्ली को। बीज सभी पिसते रहते थे। तेल निकलता रहता था। पीछे से चाबुक पड़ता था जब, खाल उधड़ जाती थी। कितने हजार मील चलता था, फिर भी वहीं पर। उसी जगह! मालिक तेल बाजार में बेचता था। बैल का कोई हिस्सा नहीं! यही तो है जिसका दुःख है। तेल किसी का। खाल किसी की। उसके लिए बस सूखी घास! यू ही तो चलता है दुनिया का कोल्हू, बैल बनाकर आदमी को! जोत दिया है खांचों में। रातें लम्बी होती जा रही है। सांसें सिकुड़ रही हैं। जैसे कोई होली में अभ्रक छिड़क गया हो!

अमेरिका वाले कोल्हू मालिक डोनाल्ड ट्रम्प ने अपनी जिद के कारण दुनियाभर को एक अजीब संकट में डाल दिया है। ईरान से युद्ध का हालांकि कोई ठोस कारण नहीं था लेकिन बिना उद्देश्य के हमला बोल दिया। ठीक है, आप ताकतवर हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन कुछ तो भी मत करिए। क्या मिला आपको? होर्मुज के कारण पूरी दुनिया परेशान है। उनके जहाज निकल नहीं पा रहे। उनकी भैंसे-गाएं अपने खूंटों से बंधी रंभा रही हैं। मतलब सैकड़ों जहाज, एलपीजी गैस और कच्चा तेल लादकर खड़े हुए हैं। उनके लिए कोई रास्ता नहीं। कोई जगह नहीं। जाएं तो जाएं कहां? किससे कहें? किसकी सुनें? कुछ समझ नहीं आ रहा।

दुनिया का थानेदार बनने या बने रहने की आकांक्षा या महत्वाकांक्षा ही है, जिसने ट्रम्प को आंदोलित किया होगा या इजराइल को उकसाया होगा। वरना तेल के सिवाय इस दुनिया में लालच ही क्या बचा है?

वैसे इजराइल अपना मकसद अच्छी तरह जानता है। वो अपना विस्तार करने में या विस्तार करने की दिशा में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। लेबनान पर हमले और उसकी जमीन हथियाने के मामलों से चीजों को समझा जा सकता है। लेकिन इस समूचे पुलिस कर्म में अमेरिका का क्या हित है? वैसे भी अमेरिका के लिए ईरान में तेल के सिवाय रक्खा ही क्या है? इजराइल तो हमेशा से लड़ता रहा है और लड़-लड़कर ही उसने जमीन हथियाई है लेकिन अमेरिका अपना अरबों का नुकसान करने के बावजूद इस युद्ध में शामिल क्यों है, ये समझ से परे है।

इधर भारत में हालांकि सरकार तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी तेल और रसोई गैस की किल्लत तो

अमेरिका इस युद्ध में क्यों?

अमेरिका के लिए ईरान में तेल के सिवाय रक्खा ही क्या है? इजराइल तो हमेशा से लड़ता रहा है और लड़-लड़कर ही उसने जमीन हथियाई है। लेकिन अमेरिका अपना अरबों का नुकसान करने के बावजूद युद्ध में क्यों है, समझ से परे है।

हर हाल में महसूस हो रही है। होने लगी है। अगर ईरान से युद्ध एक महीने और चला तो हो सकता है भारत में फिर से लॉकडाउन की नौबत आ जाए! हवाई यात्राएं बंद हो जाएं! सड़क पर वाहन चलाना सीमित हो जाए।

लेकिन भारत हार मानने वाला नहीं है। दुनियाभर में जब 2008 में मंदी आई थी तब भी भारत पर उसका असर लगभग शून्य रहा था। कोविड के वक्त भी दुनियाभर को हमने वैक्सीन दी। दरअसल, भारत की परम्पराएं, उसके रीति-रिवाज उसे हर हाल में जिंदा रखते हैं। यही वजह है कि दुनिया के किसी भी और किसी भी तरह के संकट का असर हम पर नगण्य होता है। घर आए मेहमान को या उसके बच्चे को पैसे-रुपए देना, भारत के सिवाय दुनिया में कहीं नहीं होता! इस इकोनॉमी का पर्याय या विकल्प भला दुनिया में और कहीं कहां है? हम अमेरिका की तरह पेंशन कार्ड तक से उधार लेकर चबा जाने वाले लोग नहीं हैं। हम बचत में माहिर हैं। बचत करना हमारे जीन में है। पेट काटकर भी पैसा बचाते हैं। यही वजह है जिसके कारण भारत को महान कहा जाता है। इसीलिए हम महान हैं भी।

इस तरफ मौसम पर आएं तो यहां युद्ध का तनाव तो दिख रहा है लेकिन बेमौसम बारिश ने सबकुछ थोड़ा आसान कर दिया है। ठंडा कर दिया है। मौसम, गर्मी का न सही, लेकिन बरसात का तो नहीं ही है। फिर भी मेह बरस रहा है। गर्मी के मुहाने ठंडक दस्तक दे रही है। रात को जब सोते हैं, पता नहीं चलता बारिश कब हुई, लेकिन सुबह जब सड़क गीली दिखती है तो समझ नहीं आता कि रात को बारिश हुई थी या सड़क को पसीना आया है!

इस लेख को मोबाइल पर सुनने के लिए **QR कोड** को स्कैन करें।

नजरिया • एआई के लिए एनर्जी की जरूरत पर सवाल

हमें लगता है कि एआई फ्री है जबकि सच्चाई कुछ और है

कृत्रिम मेधा

नीरज कौशल

कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर

nk464@columbia.edu

जनरेटिव एआई विस्मय और भय दोनों उत्पन्न करता है। आने वाला कल इसी का है, लेकिन वो कल कैसा होगा? कुछ पूर्वानुमान तो ऐसे परिदृश्य की ओर ले जाते हैं, जहां व्यापक सर्विलांस, भावनात्मक पहचान और ऑटोमेटेड कंटेंट जनरेशन की मदद से एआई समाज को नियंत्रित करेगा। लेकिन ऐसी बातों को एक तरफ रख भी दें तो यह तो सच है ही कि एआई हमारे संसार को बदल रहा है और आगे भी बदलता रहेगा।

वास्तव में, जीडीपी के संदर्भ में तो एआई पहले ही पश्चिमी दुनिया में वर्तमान को आकार देने लगा है और भारत में भी इसकी बड़ी उपस्थिति का अनुमान है। अमेरिका में, 2025 के पहले नौ महीनों में जीडीपी वृद्धि में एआई निवेशों का योगदान लगभग 40% तक रहा। अर्न्स्ट एंड यंग का अनुमान है कि एआई अगले सात वर्षों में स्किलिंग और शिक्षा में निवेश के माध्यम से भारतीय जीडीपी में 1.2 से 1.5 ट्रिलियन डॉलर का योगदान देगा। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन और मेटा ने अगले पांच वर्षों में डेटा केंद्रों और एआई-आधारित निवेशों के लिए 67.5 अरब डॉलर का वादा किया है। भारत के अपने औद्योगिक समूह- टाटा, रिलायंस और अदाणी भी पीछे नहीं हैं। अदाणी ने अगले 10 वर्षों में रिन्यूएबल ऊर्जा-संचालित, एआई-रेडी डेटा केंद्रों में 100 अरब डॉलर निवेश करने की योजना बनाई है।

ये आंकड़े जितने बड़े सुनाई देते हैं, वैश्विक स्तर पर अगले पांच वर्षों में अनुमानित निवेश की तुलना में वे नगण्य हैं। मैककिन्से एंड कम्पनी ने इसे 6.7 ट्रिलियन डॉलर आंका है। नए निवेशकों में से अधिकांश संभवतः प्रतिस्पर्धा में बाहर हो जाएंगे, लेकिन कुछ टिकेंगे और उत्पादकता बढ़ाएंगे। इन अकल्पनीय रूप से बड़े आंकड़ों से परे, बुनियादी सवाल यह है कि एआई का सामाजिक प्रभाव क्या होगा? क्या एआई का प्रसार उत्पादकता में व्यापक वृद्धि लाएगा या इसका उपयोग कुछ विशेष उद्योगों और समाज के कुछ वर्गों तक सीमित रहेगा? क्या हम एआई का उपयोग शिक्षा को इस तरह रूपांतरित करने के लिए कर पाएंगे कि उससे रोजगार-योग्य कौशल विकसित हों? या यह केवल मशीनों के जरिए नौकरियों का स्थान ले लेगा?

चैटजीपीटी या जेमिनाई का उपयोग करने वाले अधिकांश लोग एआई को एक ऐसी सुपरफास्ट मैकेनिक यूनिट के रूप में देखते हैं, जो इंटरनेट सर्च के त्वरित उत्तर प्रदान करती है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लिखती है, ग्रामर सुधारती है, समीक्षाएं और यहां तक कि लेख भी लिख देती है। अधिकांश यूजर्स इस सेवा के लिए कोई भुगतान नहीं करते। एआई के कुछ गंभीर यूजर्स ही इसके सब्स्क्रिप्शंस लेते हैं। इसलिए हमें लगता है कि यह हमारे और हमारे समाज के लिए मुफ्त है।

हम यह नहीं समझते कि यह एआई प्रणाली भारी मात्रा में बिजली की खपत करती है और भीमकाय हार्डवेयर का उपयोग करती है। इसलिए एआई को लेकर इस पूरे उत्साह के बीच हमें यह प्रश्न उठाना चाहिए कि क्या एआई ऐसे समाधान भी प्रदान करेगा, जो प्रदूषण को कम करें और ऊर्जा का संरक्षण करें? या फिर एनर्जी के लिए एआई की अतृप्त-भूख अभावों और प्रदूषण को और बढ़ाएगी?

एआई का मेडिकल फील्ड्स में व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। इलॉन मस्क ने अनुमान लगाया है कि 2030 तक एडवांस्ड एआई-संचालित रोबोट्स- विशेष रूप से टेस्ला का ऑप्टिमस- सर्वश्रेष्ठ मानव सर्जनों से भी बेहतर प्रदर्शन करने लगेंगे, जिससे पारंपरिक मेडिकल शिक्षा संभावित रूप से निरर्थक हो सकती है। लेकिन साथ ही, आशावादियों का यह तर्क भी है कि मनुष्य की सृजनात्मकता नए क्षेत्रों में रोजगार पैदा करेगी। टिकटॉक के रिसर्च-वैज्ञानिक शुपेंग चेन ने एक हालिया शोधपत्र में तर्क दिया है कि जहां एआई प्रचुर मात्रा में बुद्धिमत्ता लेकर आ रहा है, वहीं उसे तेजी से अपनाना उच्च स्तर पर लाखों पेशेवर व्हाइट कॉलर जॉब्स को अप्रासंगिक बना देगा। अमेरिकी अर्थव्यवस्था के आंकड़ों का उपयोग करते हुए चेन ने कहा है कि चूंकि व्हाइट कॉलर कर्मचारी उपभोक्ता-व्यय के आधे से अधिक हिस्से के लिए जिम्मेदार हैं, इसलिए एआई न केवल नौकरियों को प्रभावित करेगा, बल्कि उन वस्तुओं की मांग पर भी असर डालेगा, जिनका उत्पादन एआई कर रहा है। इससे ग्रोथ नहीं, बल्कि एक घोस्ट-इकोनॉमी उत्पन्न हो सकती है।

अधिकांश यूजर्स एआई के लिए कोई भुगतान नहीं करते। इसलिए हमें लगता है कि यह हमारे और हमारे समाज के लिए मुफ्त है। हम यह नहीं समझते कि यह एआई प्रणाली भारी मात्रा में बिजली की खपत करती है।

फिर भी, यदि एआई वास्तव में वैसी ही एक फोर्स है, जैसा कि उसके यूजर्स मानते हैं, तो इसे नियंत्रित करने का सुझाव देना व्यर्थ होगा। आशा यही है कि मनुष्य की सृजनात्मकता एआई की गति के साथ तालमेल बिठाते हुए उसके नकारात्मक परिणामों को न्यूनतम करने का प्रयास करेगी।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

स्पीक-अप • अब गावस्कर भी मुखर विरोधी हुए

भारतीय फ्रेंचाइजी को पाक खिलाड़ी क्यों लेने चाहिए?

क्रिकेट

मिन्हाज मर्चेंट

लेखक, प्रकाशक और सम्पादक

mmleditorial@gmail.com

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) आगामी 28 मार्च से शुरू हो रही है। आईपीएल में पाकिस्तानी क्रिकेटरों पर प्रतिबंध लगा हुआ है। दुनिया की सबसे अमीर स्पोर्ट्स लीग में से एक आईपीएल का मौजूदा बाजार मूल्य 18 अरब डॉलर है। इसकी तुलना में फुटबॉल की काफी पुरानी इंग्लिश प्रीमियर लीग (ईपीएल) की वैल्यू 30 अरब डॉलर की है।

साल दर साल आईपीएल की सफलता ने दुनिया भर में- ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से लेकर वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका तक- टी20 क्रिकेट लीगों को जन्म दिया है। इन लीग में कई फ्रेंचाइजी टीमों के मालिक भारतीय हैं, जिनमें से कइयों का आईपीएल टीम मालिकों से भी तालमेल है। हालांकि इन विदेशी लीग में भी भारतीयों के स्वामित्व वाली किसी फ्रेंचाइजी ने पाकिस्तानी क्रिकेटरों पर बोली नहीं लगाई। यह प्रतिबंध आधिकारिक भले न हो, लेकिन पूरी दुनिया में लागू है।

लेकिन पहली बार इस प्रतिबंध का उल्लंघन इंग्लैंड में होने जा रही 'द हंड्रेड' लीग में हुआ है। हर पारी में 100 गेंदों वाले इस टूर्नामेंट में ज्यादातर फ्रेंचाइजी टीमों के मालिक भारतीय हैं। इनमें से कई आईपीएल टीमों के भी मालिक हैं। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद टीम की मालकिन और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की करीबी रिश्तेदार काव्या मारन ने 'द हंड्रेड' में अपनी फ्रेंचाइजी टीम सनराइजर्स लीड्स के लिए पहली बार किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर को चुना है। उन्होंने पाकिस्तानी गेंदबाज अबरार अहमद को 1.90 लाख पाउंड (लगभग 2.34 करोड़ रुपए) में खरीदा।

तत्काल ही इसका विरोध शुरू हो गया। पूर्व भारतीय टेस्ट कप्तान सुनील गावस्कर सबसे तीखी प्रतिक्रिया देने वालों में थे। गावस्कर ने एक लेख में कड़े शब्दों में लिखा कि 'पाकिस्तानी खिलाड़ी को दी गई फीस- जिस पर वह अपनी सरकार को आयकर चुकाएगा और वो सरकार उससे हथियार खरीदेगी- अप्रत्यक्ष तौर पर भारतीय फौजियों और नागरिकों की मौत में योगदान देगी। इसी एहसास के कारण भारतीय संस्थाएं पाकिस्तानी कलाकारों और खिलाड़ियों को आमंत्रित करने के विचार से भी बचती हैं। भुगतान करने वाली इकाई भले भारतीय हो या उसकी कोई विदेशी शाखा, यदि उसका मालिक भारतीय है तो वह भारतीयों की मौत में योगदान दे रहा है।'

गावस्कर बेहद स्पष्टवादी हैं। लेकिन आम तौर पर उन्हें पाकिस्तान विरोधी नहीं माना जाता। उन्होंने वसीम अकरम के साथ कमेंट्री की है और पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर इमरान खान का भी समर्थन कर चुके हैं, जो अभी जेल में हैं। लेकिन जब गावस्कर जैसे कद के व्यक्ति ने आलोचना की तो यह खबर न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार में भी छपी, जो आमतौर पर क्रिकेट में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखता। अखबार ने गावस्कर के मुख्य तर्क को दोहराया कि किसी भारतीय क्रिकेट फ्रेंचाइजी द्वारा पाकिस्तानी खिलाड़ी को दिया गया पैसा अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल किया जाएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि 'भारत के महानतम क्रिकेटरों में से एक ने एक इंग्लिश टीम द्वारा पाकिस्तानी खिलाड़ी को साइन करने की आलोचना की है। उनका दावा है कि लेग स्पिनर अबरार अहमद द्वारा चुकाए गए टैक्स के जरिए यह पैसा पाकिस्तान की हथियार खरीद में काम आएगा और अप्रत्यक्ष तौर भारतीय सैनिकों या नागरिकों की मौत का कारण बन सकता है।'

गावस्कर पहले भी कह चुके हैं कि कई पाकिस्तानी क्रिकेटर हमेशा से भारत के खिलाफ रहे हैं। अबरार अहमद ने भारतीय वायुसेना का मजाक उड़ाया था।

अबरार अहमद ने भारतीय वायुसेना का मजाक उड़ाया था। लेकिन आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद टीम की मालकिन ने 'द हंड्रेड' लीग में अपनी फ्रेंचाइजी टीम सनराइजर्स लीड्स के लिए 2.34 करोड़ रुपए में अबरार को खरीदा है।

शाहिद अफरीदी तो आदतन भारत और भारतीय क्रिकेटरों के खिलाफ बयान देते रहते हैं। पूर्व पाकिस्तानी बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ ने सूर्यकुमार यादव को गाली तक दी थी। एशिया कप के एक मैच में हारिस रऊफ ने मैदान पर भारतीय सैन्य विमानों के गिरने संबंधी भड़काऊ इशारे किए थे।

गावस्कर का कहना है कि क्या 'द हंड्रेड' में भारतीय फ्रेंचाइजी मालिक भारत विरोधी खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए की फीस का इनाम देना चाहते हैं? बीसीसीआई ने यह कहते हुए पूरे विवाद से पल्ला झाड़ लिया है कि वह आईपीएल को संचालित करता है, लेकिन विदेशी लीग में निजी कंपनियों द्वारा संचालित फ्रेंचाइजी पर उनका कोई क्षेत्राधिकार नहीं। बीसीसीआई का कहना है कि उसे विदेशी लीग में हिस्सा लेने वाले भारतीय फ्रेंचाइजी मालिकों के विवेक पर भरोसा है कि वे आईपीएल की तरह पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अपनी टीम से बाहर रखेंगे। लेकिन काव्या मारन में यह विवेक नजर नहीं आया है। उनकी फ्रेंचाइजी का बहिष्कार हो, इससे पहले यह समझ उनमें आ जानी चाहिए।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

डिफ्रेंट एंगल • आने वाले समय में युद्ध केवल जमीन या तेल ही नहीं, बल्कि पानी के लिए भी हो सकते हैं...

मध्य पूर्व के संघर्ष में पानी अब हथियार भी है और निशाना भी

जल-प्रबंधन

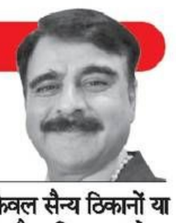

सुधींद्र मोहन शर्मा

पूर्व राष्ट्रीय नोडल अधिकारी, पेयजल मंत्रालय, भारत सरकार

मध्य पूर्व में चल रहा तनाव अब केवल सैन्य ठिकानों या ऊर्जा संसाधनों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि एक बेहद महत्वपूर्ण और जीवन देने वाला संसाधन पानी भी इस संघर्ष का हिस्सा बनता जा रहा है। ईरान द्वारा खाड़ी देशों की जल सुविधाओं को निशाना बनाने की चेतावनी ने साफ कर दिया है कि आने वाले समय में पानी न केवल एक हथियार बन सकता है, बल्कि निशाना भी।

खाड़ी क्षेत्र- जैसे सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान- प्राकृतिक रूप से बहुत शुष्क हैं। यहां बारिश बहुत कम होती है और नदियां-झीलें लगभग नहीं के बराबर हैं। ऐसे में इन देशों की सबसे बड़ी जरूरत पूरी करते हैं डिसेलिनेशन प्लांट। डिसेलिनेशन का मतलब है खारे पानी से नमक और अन्य अशुद्धियां हटाकर उसे पीने योग्य बनाना। यह काम मुख्य रूप से दो तरीकों से होता है। पहला है रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसमें समुद्री पानी को दबाव के साथ एक खास झिल्ली से गुजारा जाता है, जो नमक को रोक लेती है और साफ पानी को आगे जाने देती है। दूसरा तरीका है पानी को गर्म करके भाप बनाना और फिर उसे ठंडा करके शुद्ध पानी प्राप्त करना। इस तरह ये संयंत्र समुद्र के पानी को मीठे पानी में बदल देते हैं।

आज खाड़ी देशों में पानी की स्थिति पूरी तरह कृत्रिम स्रोतों पर निर्भर हो चुकी है। मध्य पूर्व क्षेत्र दुनिया की लगभग 45-50% डिसेलिनेशन क्षमता रखता है और प्रतिदिन लगभग 60-70 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी समुद्र से बनाता है। अनुमानतः खाड़ी देशों में करोड़ों लोग सीधे डिसेलिनेटेड पानी पर निर्भर हैं। इसके बावजूद क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्राकृतिक जल उपलब्धता बहुत कम है- औसतन 480 घन मीटर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष, जबकि वैश्विक औसत 5500 घन मीटर है। खाड़ी देशों के पास पानी का भंडार बहुत कम होता है- अधिकतर देशों के पास सिर्फ एक हफ्ते का पानी सुरक्षित रहता है।

डिसेलिनेशन के पहले यह क्षेत्र दुनिया के सबसे अधिक जल-संकट वाले क्षेत्रों में था। यहां 15 से अधिक देश अत्यधिक जल तनाव (80% से अधिक उपयोग) झेल रहे हैं। डिसेलिनेशन प्लांट्स बनने से पहले खाड़ी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता अत्यंत कम थी और जीवन मुख्यतः सीमित भूजल स्रोतों पर निर्भर था। कई क्षेत्रों में पानी इतना कम था कि बड़े शहरों का विकास संभव ही नहीं था। डिसेलिनेशन ने इस क्षेत्र को बसाने और विकसित करने में निर्णायक भूमिका निभाई। डिसेलिनेशन प्लांट्स समुद्र किनारे होते हैं और ईरान के काफी पास हैं, इसलिए इन्हें निशाना बनाना आसान है।

यदि इन प्लांट्स पर बड़े स्तर पर हमला होता है, तो पूरी शहरी आबादी प्रभावित हो सकती है और इसका असर केवल किसी एक शहर तक सीमित नहीं रहेगा। खाड़ी देशों की लगभग पूरी शहरी आबादी- करीब 10 करोड़ लोग- इससे सीधे प्रभावित होंगे। कुछ ही दिनों में पानी की कमी एक मानवीय संकट का रूप ले सकती है। पीने के पानी की कमी, उद्योग और फैक्ट्रियां बंद होना, बिजली उत्पादन पर असर, अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं में दिक्कत, यानी बिना सीधे लोगों पर हमला किए भी पूरे समाज को प्रभावित किया जा सकता है।

डिसेलिनेशन प्लांट्स पर हमला अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा असर डालेगा। खाड़ी की अर्थव्यवस्था पूरी तरह ऊर्जा + उद्योग + शहरीकरण पर आधारित है और डिसेलिनेशन और ऊर्जा क्षेत्र आपस में जुड़े हैं। सऊदी अरब अगले वर्षों में 80 अरब डॉलर तक का निवेश करने जा रहा है, लेकिन अगर पानी बंद हुआ तो अरबों डॉलर का निवेश और उत्पादन खतरे में पड़ने से क्षेत्रीय ही नहीं, वैश्विक अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होगी।

हाल में जब अमेरिका द्वारा ईरान के ऊर्जा ढांचे पर हमले की बात सामने आई, तो ईरान ने जवाब में खाड़ी देशों की जल सुविधाओं को नुकसान पहुंचाने की चेतावनी दी। संघर्ष के दौरान ऐसे संयंत्रों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं सामने भी आई हैं। इससे साफ है कि पानी अब युद्ध की रणनीति का हिस्सा बन रहा है। दुनिया मिलकर तय करे कि पानी को युद्ध से दूर रखा जाए- क्योंकि अगर पानी पर संकट आया, तो जीवन भी संकट में पड़ जाएगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

बिज़नेस भास्कर
Business Standard और TheEconomist की ख़बरों के साथ
फरीदाबाद, गुरुवार 26 मार्च, 2026

सोना कितना खरा! • गोल्ड रिजर्व की वैल्यू अब जीडीपी की 125%, गोल्ड लोन बाजार 4 साल में 4 गुना बढ़ा, इक्विटी मार्केट से 4 गुना बड़ा है ये भंडार

मजबूतीः भारत सोने के गहनों का सबसे बड़ा खरीदार बना, चीन को पीछे छोड़ा

भास्कर न्यूज | मुंबई

भारत अब 'ग्रेटर चाइना' को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ण आभूषण उपभोक्ता बन गया है। वित्त वर्ष 2025 में वैश्विक आभूषण मांग का करीब 30% हिस्सा अकेले भारत के नाम रहा, जो भारतीय बाजार की मजबूती और सोने के प्रति अटूट सांस्कृतिक लगाव को दर्शाता है। एसोचैम और रेटिंग एजेंसी इक्रा की रिपोर्ट के अनुसार, भारत और ग्रेटर चाइना (चीन, हांगकांग, मकाऊ और ताइवान) मिलकर दुनिया के कुल स्वर्ण आभूषण उपभोग का 55% हिस्सा कवर करते हैं। हालांकि, वित्तवर्ष 2025 में दोनों देशों की मांग में गिरावट देखी गई, लेकिन चीन में यह गिरावट अधिक तीव्र रही। शादियों और त्योहारों के दौरान सोने की अनिवार्य मांग ने भारत को चीन के मुकाबले बेहतर स्थिति में रखा।

भारत-ग्रेटर चीन में सोने की खपत

वित्त वर्ष	भारत	ग्रेटर चीन
2024	579	662
2025	539	448
2026 छमाही	278	164

खपत टन में

बदलाव.. निवेश मांग 74% बढ़ी

बाजार में एक बदलाव देखा जा रहा है। मांग अब 'उपभोग'से हटकर 'निवेश' की ओर बढ़ रही है। जहां एक ओर ऊंचे दामों ने गहनों की खरीदारी को प्रभावित किया है, वहीं निवेश के रूप में सोने का आकर्षण बढ़ा है। बार, सिक्कों और ईटीएफ में निवेश वित्त वर्ष 2025 में 74% और मौजूदा वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में 60% बढ़ा है।

समृद्धिः घरों में 445 लाख करोड़ का सोना, 5 लाख से कम आय वाले परिवारों में 68%

भारतीय घरों के पास अब 445 लाख करोड़ रुपए का सोना है। मार्च 2017 तक 103 लाख करोड़ रुपए का सोना था। यानी 2017-2024 के पूरे 7 वर्षों में 91% की वृद्धि हुई थी। इस स्वर्ण भंडार की वैल्यू जीडीपी की 125% है। इतना ही नहीं, घरेलू डिपॉजिट और इक्विटी के संयुक्त मूल्य से 75% अधिक है।

कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के मुताबिक यह डेटा समृद्धि को दिखाते हैं, लेकिन असल में यह भारतीय वित्तीय प्रणाली, फॉरेक्स रिजर्व और बैंकिंग तरलता पर गंभीर दबाव डाल रही है। वजह यह है कि सोने और कीमती धातुओं का शुद्ध आयात वित्त वर्ष 2011 से वित्त वर्ष 2026 के पहले 10 माह तक 500 अरब डॉलर रहा। यह एफपीआई (डेट+इक्विटी) के शुद्ध प्रवाह 200 अरब डॉलर का 2.5 गुना है। और एफपीआई और एफडीआई के कुल प्रवाह 600 अरब डॉलर का 85% है। यानी विदेशी निवेश से जो पैसा आता है, उसका बड़ा हिस्सा सोने के रूप में वापस बाहर चला जाता है। ऐसे में इसे इकोनॉमी से जोड़ना बेहद जरूरी है।

सोना किसके पास है?

5 लाख से कम आय वाले परिवारों के पास कुल सोने का 68% शेयर

आय वर्ग (Rs)	सोने में हिस्सेदारी (%)
<₹1,00,000	12%
₹1 लाख-2 लाख	20%
₹2 लाख- 5 लाख	36%
₹5 लाख- 10 लाख	21%
₹10 लाख- 20 लाख	9%
₹20 लाख+	2%

सोर्सः आईजीपीसी प्राइस सर्वे 2021

बड़ा मौकाः गोल्ड लोन पोर्टफोलियो 12 लाख करोड़, ये कुल वैल्यू का 2.8% ही

संकेतक	मूल्य	नोट
गोल्ड लोन एयूएफ	12 ट्रिलियन	तेजी से बढ़ रहा है
कुल ऋणों में हिस्सा	5.5%	अभी भी छोटा
रिटेल लोन में में हिस्सा	12%	बढ़ रहा है
2021 से 2025	3 से 12 ट्रिलियन	4 गुना वृद्धि

- 445 लाख करोड़ रुपए के सोने के मुकाबले गोल्ड लोन केवल 12 लाख करोड़ रुपए है। यानी सोने के कुल मूल्य का मात्र 2.8% हिस्सा ही 'उत्पादक' रूप में उपयोग हो रहा है। बाकी 97% से अधिक सोना अर्थव्यवस्था में निष्क्रिय पड़ा है।

सोना बनाम बैंक डिपॉजिट और इक्विटी

जनवरी 2026 तक भारतीय घरों की वित्तीय संपत्ति की तुलना

संपत्ति	मूल्य	हिस्सेदारी
बैंक डिपॉजिट	147	26%
घरेलू इक्विटी (निफ्टी 500)	106	19%
सोने का भंडार	445	55%

(मूल्य लाख करोड़ रुपए में)

भास्कर इन्फो

5 साल में महिलाओं के डीमैट खाते में 129% का उछाल

मुंबई | भारतीय निवेश बाजार की तस्वीर बदल रही है। महिलाएं अब सिर्फ सोने या एफडी (एफडी) तक सीमित नहीं हैं, बल्कि शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में भी अपनी धाक जमा रही हैं।

ऑनलाइन में सहज

साल 2021 के मुकाबले महिला निवेशकों के डीमैट खातों में 129% बढ़े।

64% इक्विटी ऑर्डर महिला एं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए खुद मैनेज कर रही हैं।

निवेशः 49% निवेश एकमुश्त में

कुल निवेश का बड़ा हिस्सा म्यूचुअल फंड्स में

49% लंपसम निवेश | 33% एसआईपी से

संकेतः लंबी अवधि की सोच और अनुशासन

कौन कर रहा है सबसे ज्यादा एसआईपी?

- 26–45 वर्ष एसआईपी में सबसे आगे
- 25 वर्ष से कम और 45+ वर्ष लंपसम निवेश ज्यादा पसंद

सोर्सः एक्सिस डायरेक्ट

भास्कर एनालिसिस 2 दिन में बीएसई लिस्टेड कंपनियों का एमकैप 16 लाख करोड़ बढ़ा

सेंसेक्स 1,205 अंक चढ़कर 75,273 पर, लेकिन जंग शुरू होने के बाद से अब भी 7.4% नीचे है

भास्कर न्यूज | मुंबई

शेयर बाजार में पिछले दो दिनों से जारी तेजी ने निवेशकों की झोली में 16 लाख करोड़ रुपए डाल दिए हैं। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने और कच्चे तेल की कीमतें गिरकर 100 डॉलर के करीब आने से तेजी को हवा मिली, जिससे बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी बीते दो सत्र में 3.5% से ज्यादा चढ़ चुके हैं। सेंसेक्स बुधवार को 1,205 अंक (1.6%) बढ़कर 75,273 पर बंद हुआ। इंट्रो डे के दौरान 75,849.76 का उच्चतम स्तर छुआ। निफ्टी 394 अंक (1.7%) की तेजी के साथ 23,300 के स्तर को पार कर 23,304 पर बंद हुआ। निफ्टी मिडकैप 100 में 2.2% और स्मॉलकैप 100 में 2.7% का उछाल आया। मार्केट के डर को मापने वाला इंडेक्स इंडिया विक्स 24.7 पर है, जो दर्शाता है कि बाजार में पूरी तरह से स्थिरता आने के लिए अभी सतर्कता जरूरी है। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के मुख्य निवेश रणनीतिकार वीके विजयकुमार के मुताबिक ईरान की ओर से 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज' को मालवाहक जहाजों के लिए खुला रखने का आश्वासन भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बड़ी खबर है। इससे डर कम हुआ है।

निफ्टी एनालिसिस | जब तक निफ्टी 22,640 के ऊपर, तब तक तेजी का नजरिया

निफ्टी 500 के 28 शेयर 200 दिन औसत से ऊपर

तकनीकी चार्ट पर बाजार में सुधार के स्पष्ट संकेत दिख रहे हैं। निफ्टी 500 की 28 कंपनियों ने अपने 200-दिवसीय मूविंग एवरेज को फिर से पार कर लिया है, जिसे लॉन्ग-टर्म तेजी का संकेत माना जाता है। इनमें एक्सिस बैंक, अपोलो हॉस्पिटल्स, बजाज ऑटो और डॉ. रेड्डीज जैसे बड़े शेयरों ने अपना 200 दिन का मूविंग एवरेज रिक्लेम किया। इन 28 शेयरों ने मार्च के अपने हालिया निचले स्तरों से 10% से 20% तक की रिकवरी दिखाई है। निफ्टी 50 इंडेक्स अभी भी अपने 200-दिवसीय औसत से करीब 7.4% नीचे ट्रेड कर रहा है निफ्टी के लिए अब 23,000-23,050 का स्तर मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, जबकि 23,600 अगला बड़ा रेजिस्टेंस (रुकावट) हो सकता है।

बुलिश डाइवर्जेंस से सुधार के संकेत, पर अलर्ट रहें

बाजार के चार्ट पर एक महत्वपूर्ण 'बुलिश आरएसआई डाइवर्जेंस' देखा गया है। सोमवार को जहां निफ्टी ने 22,471 का नया निचला स्तर बनाया, वहीं मोमेंटम इंडिकेटर आरएसआई ने हायर-लो बनाया। इसे ट्रेंड पलटने का शुरुआती संकेत माना जाता है। आरएसआई 'ओवरसोल्ड' जोन से बाहर निकलकर 38.90 पर आ गया है। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के अनुसार यदि तेजी जारी रहती है तो निफ्टी 4% उछलकर 23,800 के स्तर तक जा सकता है। एंजेल वन के अनुसार, 23,380 से 23,620 के बीच एक 'बेयरिश गैप' है, जो बढ़त को सीमित कर सकता है। गिरावट पर 22,880 पहला मजबूत सपोर्ट है। जब तक निफ्टी 22,640 के ऊपर बना है, तब तक तेजी का नजरिया बरकरार रहेगा।

जंग के बाद किस में कितनी गिरावट

सेंसेक्स	-7.4%
निफ्टी	-7.4%

सेक्टोरल सूचकांक	बदलाव
ऑयल एंड गैस	▼12.8%
रियल्टी	▼11.5%
बैंकैक्स	▼11.3%
ऑटो	▼11.0%
फाइनेंशियल सर्विसेज	▼10.2%
सर्विसेज	▼9.0%
कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी	▼8.6%
इंडस्ट्रियल्स	▼8.6%
एनर्जी	▼8.2%
हॉस्पिटल्स	▼7.5%
मेटल	▼7.3%
एफएमसीजी	▼7.0%
कंज्यूमर ड्यूरेबल	▼6.9%

विदेशी vs घरेलू निवेशक

किसने जीता बाजार का भरोसा

- **विदेशी निवेशक**
  1.06 लाख करोड़ की बिकवाली अब तक की सबसे मासिक सेलिंग
- **घरेलू निवेशक (डीआईआई)**
  1.24 लाख करोड़ की खरीदारी रिकॉर्ड खरीदारी मार्च में अब तक

एमके ग्लोबल | भारतीय बाजार अब 'फेयर वैल्यू' पर आ गए हैं

एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज की रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू शेयर बाजार अब ऊंचे वैल्यूएशन के दौर से निकलकर 'वाजिब' स्तर पर आ गया है। निफ्टी का पी/ई रेशियो वर्तमान में 20.2x पर है, जो इसके एक साल के औसत (22.3x) और लंबी अवधि के औसत (23.5x) से कम है। भारत का वैल्यूएशन अब ग्लोबल मार्केट्स के करीब है (जैसे नैस्डैक 33x, निक्केई 22x और डॉ जोन्स 20x) पर है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय बाजार अब ओवरप्राइस नहीं हैं, लेकिन वे एकदम सस्ते भी नहीं हैं। निफ्टी का 20x पीई स्तर मजबूत आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों के अनुमानों से समर्थित है।

लोकलसर्कल्स सर्वे | 13 बीमा कंपनियों में डार्क पैटर्न्स का खुलासा

ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म पर 10 में से 8 डिजिटल धोखेबाजी के शिकार

बिजनेस संवाददाता | नई दिल्ली

ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म से पॉलिसी खरीदना अब बहुत जोखिम भरा होता जा रहा है। लोकलसर्कल्स की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, हर 10 में से आठ ग्राहक ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म पर डार्क पैटर्न्स यानी डिजिटल धोखेबाजी का शिकार हो रहे हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्रिप्शन ट्रैप, नैगिंग, फोर्स्ड एक्शन और बेट एंड स्विच जैसे अनुचित तरीके अपनाए जा रहे हैं। सर्वे में देश के 341 जिलों के 87 हजार से ज्यादा बीमा धारकों ने अपनी परेशानियां साझा कीं। यह खुलासा हर उस व्यक्ति के लिए बेहद अहम है, जो मोबाइल या लैपटॉप से खुद ऑनलाइन बीमा खरीदता है।

रिपोर्ट बताती है कि पिछले 24 महीनों में पॉलिसी को कैंसल कराने में आने वाली दिक्कतों के मामले 61% से बढ़कर 80% हो गए हैं। कंपनियां ग्राहकों को सस्ते का लालच देकर फंसाती हैं और उनकी निजी जानकारी का गलत इस्तेमाल कर रही हैं।

मनमानीः 90% ग्राहकों को झेलने पड़ रहे अनचाहे कॉल्स, पुश नोटिफिकेशन

ऑनलाइन बीमा कंपनियां ग्राहकों को लगातार परेशान कर रही हैं। कंपनियां बार-बार कॉल, रिमाइंडर और पुश नोटिफिकेशन भेजती हैं। पिछले दो साल में ऐसे परेशान करने वाले मामले 86% से बढ़कर 90% पर पहुंच गए।

जालसाजीः 85% यूजर्स का निजी डेटा बिना सहमति हो रहा है इस्तेमाल

बीमा बेचने वाली साइट्स ग्राहकों से जबरन डेटा मांगती हैं। इस कारण कई बार लोगों के निजी डेटा का खुलेआम दुरुपयोग होता है। रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले दो साल में ग्राहकों के साथ हुई इस तरह की धोखाधड़ी के मामले 57% से तेजी से उछलकर 85% पर पहुंच गए।

धोखाधड़ीः 82% यूजर्स ने कहा शुरुआत में कम कीमत दिखा आकर्षित करते हैं

82% ने कहा कि ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म शुरुआत में कम कीमत दिखाकर ग्राहकों को आकर्षित करते हैं। और पॉलिसी खरीदते या रिन्यू कराते वक्त ज्यादा कीमत और शर्तें लगाते हैं, इनमें छिपे शुल्क भी शामिल हैं। 20 ऑनलाइन इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म्स की जांच में हर एक पर 2-4 डार्क पैटर्न्स मिले। ऐसे में डिजिटल माध्यम से बीमा खरीदते समय सतर्क रहने की जरूरत है।

सर्वे रिपोर्ट में ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी के वास्तविक मामले

कंपनी का नाम	डार्क पैटर्न	ग्राहक की शिकायत
स्टार हेल्थ	ड्रिप प्राइसिंग	23,269 के बजाय 23,957 वसूले गए।
गो डिजिट	बेट एंड स्विच	4 नवं. को पेमेंट किया, 28 जन. तक पॉलिसी नहीं मिली।
टर्टलमिंट	बेट एंड स्विच	प्रीमियम देने के बाद भी पॉलिसी डाक्यूमेंट जारी नहीं हुआ।
स्टार हेल्थ	बेट एंड स्विच	5 लाख का बीमा लिया, पर पॉलिसी 4 लाख की मिली
कवरफॉक्स	नेगिंग इमेल पर	जन्मदिन का बधाई संदेश बहुत ज्यादा बार मिला।
पॉलिसी बाजार	फोर्स्ड एक्शन	एक बार वेबसाइट विजिट की, कई बार कॉल आए।

बिजनेस ब्रीफ

सुनील मित्तल एयरटेल अफ्रीका का पद छोड़ेंगे

नई दिल्ली | सुनील मित्तल जुलाई 2026 में एयरटेल अफ्रीका के चेयरमैन पद से रिटायर होंगे। गोपाल विट्टल नए नॉन-एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का कार्यभार संभालेंगे। वहीं श्रावन भारती मित्तल को डिप्टी चेयरमैन नियुक्त किया गया है। सुनील भारती मित्तल साल 2019 से इस पद पर कार्यरत हैं।

लैपटॉप-पीसी निर्यात 5 साल में 18 गुना बढ़ा

नई दिल्ली | भारत से लैपटॉप और पर्सनल कम्प्यूटर (पीसी) का निर्यात 5 साल में 18 गुना बढ़ गया है। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-जनवरी के दौरान यह 106% बढ़कर करीब 6,286 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। कुल निर्यात का 55% हिस्सा अकेले यूएई को भेजा गया है।

ग्राउंड रिपोर्टः देशभर में सप्लाई और एक्सपोर्ट घटने की आशंका

मौसम की मार... लीची उत्पादन 70% गिरने की आशंका, दाम ऊंचे बने रहेंगे

बबीता माली/नवीन कुमार | मालदा/मुजफ्फरपुर

लीची के 'गढ़' कहे जाने वाले बिहार और बंगाल में इस साल मिठास गायब है। बागान लीची के सबसे बड़े 'अकाल' से जूझ रहे हैं। 42% हिस्सेदारी के साथ देश में अव्वल बिहार के मुजफ्फरपुर और दूसरे स्थान पर रहने वाले पश्चिम बंगाल (11%) के मालदा जिले में बेमौसम बारिश और बढ़ते तापमान ने उत्पादन पर ग्रहण लगा दिया है। मुजफ्फरपुर में जहां औसतन 1 लाख टन उत्पादन होता था, वहां इस बार केवल 30-35% ही कलियां आईं हैं, जिससे उत्पादन मात्र 30-35 हजार टन रहने की आशंका है। मौसम ने मालदा के 1553 हेक्टेयर में फैले बागानों की कमर तोड़ दी है। मालदा हॉर्टिकल्चर के डिप्टी डायरेक्टर सुमंत लायक बताते है, 'इस बार लीची के पेड़ में 55-60% ही कली आई है, जो सबसे कम उत्पादन का संकेत है। केवल 55-60% पेड़ों में ही कलियां आ सकीं। इस बार उत्पादन कम होगा तो कीमत ज्यादा होगी। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉ. विकास दास के अनुसार, दिसंबर में तापमान का सामान्य से अधिक होना और पौधों में फूल की जगह नई पत्तियों का निकलना इस साल उत्पादन घटने का मुख्य कारण है। दिल्ली, मुंबई और असम जैसे राज्यों में होने वाली सप्लाई पर गिरावट देखी जा सकती है।

लीची उत्पादन

बिहार	42%
पश्चिम बंगाल	11%
छत्तीसगढ़	8%
असम	8%
उत्तराखंड	2%

मालदा में 1,553 हेक्टेयर जमीन पर लीची की खेती, 1 लाख लोग जुड़े है

पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के बाद मालदा में सबसे ज्यादा लीची का उत्पादन होता है। मालदा में लगभग 1,553 हेक्टेयर जमीन पर लीची की खेती हो रही है। इससे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से 1 लाख से ज्यादा लोग जुड़े है। मालदा में मुख्य रूप से गुटी और बॉम्बई वैरायटी के लीची का उत्पादन होता है। पिछली बार 8,800 मैट्रिक टन लीची का उत्पादन हुआ था।

आईपीओ • जल्द लाने की तैयारी

जियोः 13 विदेशी निवेशक बेचेंगे 8-8% हिस्सेदारी

बिजनेस संवाददाता | मुंबई

मुकेश अंबानी की जियो प्लेटफॉर्म्स इसी हफ्ते बाजार नियामक सेबी के पास आईपीओ के शुरुआती दस्तावेज दाखिल कर सकती है। इस पब्लिक इश्यू के जरिए कंपनी के 13 बड़े विदेशी निवेशक अपनी 8-8% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में हैं। इनमें मेटा और गूगल जैसे दिग्गज हैं। जियो प्लेटफॉर्म्स के पास रिलायंस जियो का स्वामित्व है, जो ग्राहक संख्या के लिहाज से चाइना मोबाइल के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। मामले से जुड़े लोगों के अनुसार, यह कदम बाजार में लिस्टिंग की दिशा में एक बड़ी रणनीतिक शुरुआत है। कंपनी के कुल विदेशी निवेश में 13 निवेशकों का हिस्सा करीब 33% है। रॉयटर्स के मुताबिक, यदि सभी निवेशक अपनी होल्डिंग का 8% हिस्सा बेचते हैं, तो यह कुल शेयरों के 2.5% से अधिक होगा। फिलहाल रिलायंस और संबंधित निवेशकों ने इस मामले पर आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है।

महाराष्ट्र • संकट में प्याज उत्पादक

प्याज ₹900 क्विंटल, ये बीते साल से 50% कम

बिजनेस संवाददाता | नासिक

महाराष्ट्र में प्याज की गिरती कीमतों ने किसानों की कमर तोड़ दी है। प्याज की एशिया की सबसे बड़ी थोक मंडी लासलगांव में औसत भाव गिरकर 900 रुपए प्रति क्विंटल रह गया है। यह पिछले साल मार्च के औसत भाव 1,830 रुपए क्विंटल के मुकाबले करीब 50% कम है और 1,800 रुपए की उत्पादन लागत से भी आधा है। महाराष्ट्र राज्य प्याज उत्पादक संघ के अध्यक्ष भरत दिघोले ने राज्य सरकार से उन प्याज उत्पादकों को 1,500 रुपए प्रति क्विंटल का अनुदान देने की मांग की है, जिन्होंने पिछले छह महीनों के दौरान अपनी उपज उत्पादन लागत से कम दाम पर बेची है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। यह समिति दो-तीन महीनों में समाधान निर्धारित कर लागू करेगी। साथ ही, निर्यात बढ़ाने और बिचौलियों की मनमानी रोकने के लिए केंद्र सरकार से भी चर्चा की जाएगी।

उड़ान • ₹28,840 करोड़ मंजूर

आठ साल में देश में बनेंगे 100 एयरपोर्ट

बिजनेस संवाददाता | नई दिल्ली

देश में छोटे शहरों में मौजूद 100 पुरानी हवाई पट्टियों को आठ वर्षों में एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए 'उड़ान' योजना के संशोधित प्रारूप को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 28,840 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी गई। योजना 2035-36 तक लागू रहेगी। 100 एयरपोर्ट बनाने पर 12,159 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा हवाई टिकट की कीमतों को आम आदमी के बजट में रखने के लिए सरकार एयरलाइंस को 'वायबिलिटी गैप फंडिंग' देगी। 10 वर्षों में इसके लिए 10,043 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह सब्सिडी उन रूट पर दी जाएगी जहां यात्री कम होने के कारण किराया बढ़ने का डर रहता है। हवाई अड्डों के रख-रखाव के लिए 2,577 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। दूर-दराज, पहाड़ी इलाकों में कनेक्टिविटी के लिए 200 आधुनिक हेलीपैड बनाए जाएंगे।

TheEconomist बोत्सवानाः हीरों ने संवारी थी किस्मत, अब यही हीरा इकोनॉमी के लिए संकट बन रहा है

चमक फीकी, सबसे बड़ी डायमंड कंपनी डी बीयर्स की वैल्यू 80% घटी

भास्कर न्यूज | मुंबई/केप टाउन

कभी दक्षिण अफ्रीका के एक छोटे से देश बोत्सवाना की पहचान गरीबी और सूखे से थी, लेकिन 'डी बीयर्स' के हीरों ने इस देश की तकदीर बदल दी। आज वही बोत्सवाना एक ऐतिहासिक मुहाने पर है। दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित हीरा कंपनी 'डी बीयर्स' की मूल कंपनी एंग्लो अमेरिकन इसे बेचने की तैयारी में है। वहीं, बोत्सवाना जैसा छोटा सा देश इस कंपनी में हिस्सेदारी 15% से बढ़ाकर 25% या उससे अधिक करने पर विचार कर रहा है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला किसी 'इरेशनल रोमांस' जैसा हो सकता है, जो देश की अर्थव्यवस्था को और गहरे संकट में डाल देगा। हीरा बाजार की मौजूदा स्थिति डरावनी है। साल 2011 में डी बीयर्स की वैल्यू 12.75 अरब डॉलर थी, जो आज गिरकर महज 2.3 अरब डॉलर रह गई है। इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह लैब में बने सस्ते हीरे और अमेरिका-चीन जैसे बड़े बाजारों में शादियों (सगाई की अंगूठियों) के प्रति घटता क्रेज है। बोत्सवाना की खदानों से ही डी बीयर्स का 72% उत्पादन आता है, ऐसे में कंपनी का भविष्य सीधे तौर पर देश की जीडीपी से जुड़ा है। बोत्सवाना की अर्थव्यवस्था 'डच डिजीज' का शिकार हो चुकी है। इसका अर्थ है एक ही प्राकृतिक संसाधन पर अत्यधिक निर्भरता, जिससे अन्य उद्योग ठप हो जाते हैं। देश की जीडीपी का 25% और निर्यात का 80% हिस्सा हीरों से आता है।2023 से देश की विकास दर थम गई है और कर्ज का बोझ जीडीपी के मुकाबले दोगुना हो चुका है। साल 2024 में पहली बार पड़ोसी देश अंगोला ने उत्पादन के मामले में बोत्सवाना को पीछे छोड़ दिया है। बोत्सवाना को डर है कि यदि अंगोला ने डी बीयर्स को खरीदा, तो उसकी अपनी संप्रभुता खतरे में पड़ जाएगी। आईएमएफ ने बोत्सवाना को चेतावनी दी है कि मौजूदा वित्तीय संकट के बीच हिस्सेदारी बढ़ाना सही नहीं है। वहीं, इकोनॉमिस्ट कीथ जेफेरिस का तर्क है कि डी बीयर्स का सबसे मुनाफा देने वाला काम सिर्फ 'खनन' है, कटिंग और पॉलिशिंग जैसे बिजनेस में ज्यादा मार्जिन नहीं है। बोत्सवाना के राष्ट्रपति दुमा बोको के मुताबिक हम सिर्फ धरती की दौलत के संरक्षक नहीं हैं, हमें इसकी वैल्यू के निर्माता बनना होगा। हम इस पूरे इकोसिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं।डी बीयर्स के पूर्व हेड गैरेथ पेनी के मुताबिक "30 वर्षों के अनुभव में मैंने कभी ऐसा ग्राहक नहीं देखा जिसने हीरा सिर्फ इसलिए खरीदा क्योंकि वह चमक रहा था। मांग दोबारा पैदा करने के लिए इसे 'लग्जरी' के रूप में मार्केटिंग करनी होगी।'

आखिर क्यों फीकी पड़ रही डी बीयर्स की चमक

लैब बनाम नेचुरलः लैब में बने हीरे असली जैसे लगते हैं, लेकिन इनकी कीमत प्राकृतिक हीरों के मुकाबले 70% से 90% तक कम होती है।

वैल्यूएशन का खेलः पिछले 15 सालों में डी बीयर्स की ब्रांड वैल्यू में 10 बिलियन डॉलर की कमी आई है, जो किसी भी ग्लोबल लग्जरी ब्रांड के लिए सबसे बड़ी गिरावटों में से एक है।

'वन नेशन, वन स्टैंडर्ड': लाइसेंसिंग प्रक्रिया में एकरूपता आएगी

अब देश की दवा लाइसेंस प्रक्रिया को एक ही डोज, राज्यों की अलग व्यवस्था खत्म

एम. रियाज हाशमी | नई दिल्ली

देश में दवा लाइसेंसिंग की प्रक्रिया को एक समान बनाने की दिशा में केंद्र ने बड़ा बदलाव किया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की लाइसेंसिंग अथॉरिटी को गाइडेंस दस्तावेज जारी किया है, जिसमें दवाओं के निर्माण लाइसेंस के लिए 'डोजियर आधारित' प्रणाली लागू करने को कहा गया है। कंपनियों को लाइसेंस के लिए एक विस्तृत दस्तावेज (डोजियर) जमा करना होगा, जिसमें आवेदन फॉर्म, सहायक दस्तावेज, परीक्षण रिपोर्ट और तकनीकी जानकारी होंगी। इसी आधार पर लाइसेंस को मंजूरी, अस्वीकृति या अतिरिक्त स्पष्टीकरण का निर्णय होगा। यह व्यवस्था देशभर में लाइसेंसिंग प्रक्रिया में एकरूपता लाने और दवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा व प्रभावशीलता से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से लागू की जा रही है। लाइसेंस के लिए 41 बिंदुओं की चेकलिस्ट तय की गई है। पार्ट ए के तहत कंपनी पंजीकरण, जमीन, प्लांट, मशीनरी, तकनीकी स्टाफ व अनुमतियों की जानकारी। **पार्ट बी (दवा से जुड़ी जानकारी)**: मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया, गुणवत्ता व परीक्षण डेटा, स्थिरता रिपोर्ट, वैलिडेशन और बायो-इक्विवेलेंस से जुड़े दस्तावेज।

भास्कर एक्सप्लेनर

नई व्यवस्था के तहत नियमों में और क्या सख्ती?

ब्रैंड नेम पर नियंत्रणः प्रस्तावित नाम से बाजार में भ्रम नहीं होना चाहिए।

टेस्टिंग यूनिट स्वतंत्रः गुणवत्ता जांच के लिए अलग और स्वतंत्र व्यवस्था

बीई स्टडी अनिवार्यः बीसीएस II व IV श्रेणी की ओरल दवाओं के लिए जरूरी

अतिरिक्त उत्पाद पर राहतः पहले से स्वीकृत कैटेगरी में नया उत्पाद जोड़ने पर केवल 22 पॉइंट की जानकारी देनी होगी

संपादकीय

भोंदूबाबा आणि भोंदूपणाही संपवा!

नाशिकचा भोंदूबाबा अशोक खरात याची एकामागून एक दुष्कृत्य समोर येत असल्याने महाराष्ट्राचे समाजमन अक्षरश: हादरून गेले आहे. त्याचे पडसाद राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत उमटणे साहजिकच. शिव-शाहू-फुले-आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात एक असा भोंदूबाबा येतो काय, अनेकानेक प्रताप करतो काय आणि त्याच्या जाळ्यात राजकारणी, प्रशासनातील अधिकारी, महिला अडकतात काय, हे सगळेच महाराष्ट्राला काळिमा फासणारे आहे. महिलांचे लैंगिक शोषण त्याने कशा पद्धतीने केले याच्या ज्या कहाण्या समोर येत आहेत त्या पुरोगामी आणि प्रबुद्ध म्हणविणाऱ्या आपल्या समाजाला आत्मचिंतन करायला लावणाऱ्या तर आहेतच; पण असे सगळे प्रकार घडत असताना सरकारच्या संबंधित यंत्रणा, गृह खाते यांच्या ते लक्षात कसे आले नाही, हा प्रश्नही आहेच. वीसएक दिवसांपूर्वीच खरातच्या मुसक्या आवळायला पोलिसांनी कशी सुरुवात केली होती याची तपशीलवार माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली, पण गेली २० वर्षे या भोंदूबाबाचे असेच कारनामे सुरू होते, अश्लाघ्य प्रकार तो करत होता, त्यावेळी पोलिस काय करत होते याचे उत्तरही मिळाले पाहिजे. हे तर स्पष्टच आहे की त्या-त्यावेळी यंत्रणा हातात असलेले सरकार आणि प्रशासनातील बड्या व्यक्तींनी त्याला केवळ अभयच दिले नाही तर त्याचे प्रस्थ वाढण्यासाठी त्याला मदतच केली. हे करताना त्याच्या पायाशी लोळण घेतले. मधाच्या बाटल्या शक्तिवर्धक औषध म्हणून लाखो रुपयात तो विकायचा आणि ते घेणारेही अनेक जण होते. विकृतीच्या मार्गाने शक्तिवर्धन करण्याच्या नादात वाट्टेल तेवढा पैसा खर्च करण्याची तयारी असलेल्यांनी हा पैसाही अवैध मार्गानेच कमावलेला होता, हेही उघड आहे. शक्तिवर्धनाच्या मोहापायी होत असलेले हे सामाजिक अध:पतन हा खरा सामाजिक चिंता आणि चिंतनाचा विषय आहे. सरकार, नोकरशाहीमधील प्रभावशाली व्यक्तींना वश करणाऱ्या या अघोरी भोंदूबाबा अशोकच्या दुष्कृत्यांची पाळेमुळे खणून कठोरातील कठोर अशी कारवाई करण्याची गरज ही केवळ या घटनेपुरती मर्यादित नाही. या प्रकरणात त्याच्यासह त्याला सामील असलेल्यांना कठोर शिक्षा झालीच पाहिजे, अशा दृष्टीने तपासाची आणि प्रत्यक्ष कार्यवाहीची दिशा असली पाहिजे. अशी गैरकृत्ये करण्यास यापुढे कोणीही धजावणार नाही, असे अन्य भोंदूबाबा पुन्हा तयार होणार नाहीत, अशी जरब निर्माण होण्याची नितांत आवश्यकता आहे. आतापर्यंत भोंदूबाबा खरातची जी प्रकरणे समोर येत आहेत ती बघता जवळपास सर्वपक्षीय नेते त्याच्या चरणी लीन होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याच्याशी दुरान्वयानेही संबंध असलेल्यांनादेखील सोडणार नाही, अशी ग्वाही महाराष्ट्राला दिलेली आहे. राजकीय नेते सामील असतात अशी प्रकरणे यथावकाश दाबली जातात, असा अनुभव अनेक प्रकरणांमध्ये यापूर्वी आलेला आहे. भोंदूबाबा खरातच्या प्रकरणात हा कटू अनुभव येऊ नये, अशी अपेक्षा आहे. महिला आयोगाच्या अध्यक्षच त्याची पाद्यपूजा करायच्या. एक माजी राज्यमंत्री त्याला चरणस्पर्श करत असे, असा व्हिडीओदेखील फिरत आहे. विविध पक्षांच्या बड्या नेत्यांशी हा भोंदूबाबा चर्चा करत असल्याचे फोटो व्हायरल झालेले आहेत. एका मंत्र्याने या भोंदूबाबाला सरकारी पैशांतून मंदिर बांधून दिले. अनेकांना म्हणे हा बाबा राजकीय सल्ले द्यायचा. ज्या एकेक धक्कादायक बाबी समोर येत आहेत त्या बघता उद्या चालून काही 'आपल्यांवरही' कारवाई करण्याची वेळ या सरकारवर येऊ शकते. तसे आढळले तरी कोणाचाही मुलाहिजा न ठेवता कारवाई करणे हे मुख्यमंत्री व गृहमंत्री असलेले फडणवीस यांच्यासमोरील मोठे आव्हान असेल. कोणालाही सोडले जाणार नाही, अशी ग्वाही देत त्यांनी महाराष्ट्रातील जनतेला आश्वस्त तर केले आहे, पण प्रत्यक्ष वेळ येईल तेव्हाही त्यांनी हाच बाणा कायम ठेवावा अशी भोंदूबाबांच्या भयंकर कृत्यांमुळे ढवळून निघालेल्या समाजाला त्यांच्याकडून अपेक्षा आहे. भोंदूबाबा आणि भोंदूपणा अशा दोन्हींचाही कायमस्वरुपी बंदोबस्त करण्यासाठीची अत्यंत आश्वासक सुरुवात म्हणून या संपूर्ण प्रकरणाकडे सरकारने बघायला हवे आहे. कारण एक भोंदूबाबा तुरुंगात गेला, पण भोंदूपणा जिवंत राहिला तर त्याच्या गर्भातून अनेक भोंदूबाबा तयार होतात. व्यक्तींच्या पलीकडे अख्खी व्यवस्थाच अंधश्रद्धेचा हैदोस घालते तेव्हा तिला सरकारने वेसण घालणे समाजस्वास्थ्याच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. मोठ्या व्यक्तींची नावे आली की फाइल्स जड होत जातात आणि न्याय हलका होत जातो, असे यावेळी होऊ नये एवढेच!

सर्वांना एकाच कप्प्यात न बसवणे, हाच स्वधर्म!

एक देश, एक भाषा, एक धर्म, एक जात- अशा प्रकारे राष्ट्रीय एकात्मतेवर एकरूपतेचे कलम करणे भारताच्या स्वधर्माशी विसंगत ठरते, हे नक्की!

योगेंद्र यादव
राष्ट्रीय संयोजक, भारत जोडो अभियान, सदस्य, स्वराज इंडिया

याआधीच्या लेखांत आपण भारतीय प्रजासत्ताकाच्या स्वधर्माची तीन सूत्रे जाणून घेतली. आज या लेखात आपण संघराज्य (federalism) या चौथ्या सूत्राची चर्चा करू. भारत हा राज्यांचा संघ असेल असे राज्यघटनेच्या पहिल्याच अनुच्छेदात म्हटले आहे; परंतु इंग्रजीत 'फेडरेशन' नव्हे, तर 'युनियन ऑफ स्टेट्स' असे शब्द आहेत. या शब्दप्रयोगामागे देशाच्या फाळणीची पार्श्वभूमी होती. राज्यघटनेच्या निर्मितीवर फाळणीची पडछाया होतीच. तिची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी घटनाकार केंद्राला अबाधित अधिकार देऊ इच्छित होते. राष्ट्रीयता आणि प्रादेशिकता या संकल्पना आपल्या देशात घडीव युरोपीय साच्यानुसार नसाव्यात हा आग्रहही फेडरेशन हा शब्द टाळण्यामागे असावा.

भारत युरोपीय अर्थाने केंद्रीकृत किंवा अमेरिकन अर्थाने संघराज्यात्मकही नाही, हे आपले घटनाकार जाणून होते. भारतीय एकतेला समरूपतेची ओढ नाही किंवा विविधतेचे स्तोम नाही. 'युनियन'सारख्या लवचिक शब्दप्रयोगामुळे भारताची ही अनोखी घडण शाबूत राखण्याची आणि परस्परातील नाती आपल्या पद्धतीने निश्चित करण्याची मोकळीक आपल्याला लाभते. भारतीय प्रजासत्ताकाचे चौथे सूत्र या वेगळेपणातच दडलेले आहे.

भारतीय तत्त्वज्ञानाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याची नैतिक जाणीव कोणत्याही अढळ नियमांना यंत्रवत बांधलेली नाही. नैतिकता ही देश, काळ आणि पात्रसापेक्ष आहे. ही समज कोणा एकाच तात्त्विक किंवा धार्मिक परंपरेशी जोडलेली नाही. वैदिक काळापासून ते धर्मशास्त्रापर्यंत, बौद्ध, जैन तत्त्वज्ञानात, सूफी संतांपासून दारा शिकोहपर्यंत सर्वत्र हाच भाव आहे. त्यांच्या दृष्टीने विविधता हे मूल्य किंवा आदर्श नव्हे, तर एक सामाजिक वास्तव होते.

हाच भाव सामाजिक आणि राजकीय नियम किंवा कायदे एकारू देत नाही. प्रत्येक प्रदेशाचे आणि समुदायाचे वेगवेगळे आचार- व्यवहार, रीतीरिवाज असतात. सर्वांना एकाच कप्प्यात न बसवता या विविधतेचा सन्मान करायला हवा. शास्त्रे मौन बाळगतात तिथे सामाजिक मान्यताच मर्यादा ठरवते. नेहमी धर्मच संस्कारांचे स्रोत नसतात. काहीवेळा संस्कारही धर्माचे स्रोत बनतात. हा भाव आणि ही समज भारतीय प्रजासत्ताकाच्या पायाचा दगड आहे.

भारतीय राज्य हे केवळ एक आधुनिक, सर्वंकष सार्वभौम राज्य नाही. तो तर भारतीय राज्यसंस्थेचा दृश्य स्तर आहे. त्याच्या खाली इतिहासाचे अनेक पदर आहेत. यापूर्वी कोणतीही राजसत्ता भारतात कधीही पूर्णतः सार्वभौम नव्हती. प्राचीन काळी मोठ्यातल्या मोठ्या सम्राटाची सत्तासुद्धा मर्यादित असे. कायदे ठरवणारा तो एकटाच नसे. धार्मिक किंवा सामाजिक चालीरीतींत तो हस्तक्षेप करू शकत नसे.

राजाची सत्ता समाजाच्या सत्तेच्या बरोबरीने असे, त्याहून अधिक नसे. मुघलांचे राज्य आल्यानंतर राज्याची आर्थिक, लष्करी आणि संस्थात्मक क्षमता खूपच वाढली; परंतु मुघल बादशहांनाही आपले सार्वभौमत्व जमीनदार, स्थानिक राजे, धार्मिक संस्था आणि सामाजिक संघटनांबरोबर विभागून घ्यावे लागे.

राज्यसत्तेच्या या रचनेवर वासाहतिक राजवटीने आधुनिक राष्ट्र-राज्याचा थर चढवला. यामुळे आपल्या समाजाच्या आणि राजकीय सत्तेच्या स्वरूपात मूलगामी बदल झाले. भारतीय प्रजासत्ताकाचे औपचारिक कामकाज राष्ट्र-राज्याच्या आधुनिक पद्धतीनुसार चालते खरे; परंतु प्रत्यक्षात भारतीय सभ्यतेच्या सखोल घडणीने आधुनिक राष्ट्र, सार्वभौम राज्य आणि लोकशाही राजकारणाचा रागरंग पालटून टाकला आहे. एकछत्री, केंद्रीभूत, वर्चस्ववादी सत्ता ही आपल्या सभ्यतेची प्रवृत्ती नाही. त्यामुळे व्यवहारात आधुनिक राज्याची शक्ती नेहमी मर्यादितच राहिली आहे. विकेंद्रित सत्ता, सामायिक प्रभुत्व आणि युती आधारित सामर्थ्य हाच आपल्या समाजाचा स्वधर्म राहिला आहे.

भारतीय राज्यघटनेतील संघ किंवा युनियन या संकल्पनेकडे याच दृष्टिकोनातून पाहणे योग्य ठरेल. आपले संघराज्य अमेरिकेप्रमाणे अनेक सार्वभौम राज्यांनी स्वेच्छेने केलेल्या कराराची फलश्रुती मुळीच नाही. किंवा ते सोव्हिएत युनियनप्रमाणे अनेक राष्ट्रांचे मिळून झालेले बहुराष्ट्रीय 'राज्य'ही नाही. वसाहतिक सत्तेविरुद्ध केलेल्या संघर्षातून निर्माण झालेली एकजूट हा भारतीय प्रजासत्ताकाचा पाया आहे. या प्रजासत्ताकाच्या प्रादेशिक घटकांनी प्रौढ झाल्यानंतर परस्परसंबंध प्रस्थापित केलेले नाहीत. त्या साऱ्यांचा जन्म एकत्रच झाला आहे. येथे सत्तेची विभागणी याचा अर्थ केवळ कार्यकारी मंडळ, विधिमंडळ आणि न्यायपालिका यांच्या कार्याची विभागणी असा मुळीच नाही. सरकार आणि समाज यांच्यातही सत्तेची विभागणी असणे हा आपला स्वधर्म आहे. इथे स्वायत्ततेची व्याप्ती केवळ केंद्र आणि राज्य यांच्यापुरती मर्यादित न राहता ती पंचायत आणि वस्तीस्तरापर्यंत पोहोचायला हवी. इथली राष्ट्रीय एकात्मता ही अन्य भाषा आणि प्रादेशिक ओळखी पुसून टाकत नाही. इथल्या सर्व भाषिक आणि प्रादेशिक ओळखी भारतीयत्वापासून वेगळ्या नाहीत किंवा त्यावर अवलंबूनही नाहीत. भारतीयत्वाची ओळख हा या सर्व ओळखींचा मनोज्ञ संगम आहे.

भारतीय संघराज्याच्या मुळाशी वर्चस्व नाकारणारा एक अलिखित करार आहे. केंद्र सरकार किंवा भाषिक अथवा सांप्रदायिकदृष्ट्या बहुसंख्य समाज किंवा कोणताही सांस्कृतिक समूह आपले वर्चस्व गाजवू पाहणार नाही. म्हणून आपल्या सभ्यतेच्या मूळ प्रवृत्तीविरोधात, एक देश, एक भाषा, एक धर्म, एक जात- अशा प्रकारे राष्ट्रीय एकात्मतेवर एकरूपतेचे कलम करणे आपल्या स्वधर्माशी विसंगत ठरते.

yyopinion@gmail.com

अन्वयार्थ

कलकत्ता हायकोर्टात मुख्य न्यायाधीशांचा लाल गाऊन आणि विग

कलकत्ता हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश विशेष प्रसंगी पारंपरिक लाल गाऊन आणि पांढरा विग घालतात. ही वसाहतकालीन प्रथा अजूनही जपली जाण्यामागचे रहस्य!..

डॉ. खुशालचंद बाहेती
निवृत्त सहायक पोलिस आयुक्त व महाव्यवस्थापक- जनसंपर्क लोकमत

अनेक चित्रपटांत डोक्यावर पांढरा विग घातलेले न्यायाधीश आपण पाहिले आहेत. ब्रिटिश मॅजिस्ट्रेट लाल रंगाचा सोनेरी नक्षीदार लांब डगला घालायचे. प्रत्यक्षात भारतीय न्यायालयात आता विग घातलेले न्यायाधीश दिसत नाहीत; पण कलकत्ता उच्च न्यायालयात मात्र मुख्य न्यायाधीश विशेष प्रसंगीचा पोशाख म्हणून लाल रंगाचा गाऊन व लांब केसांचा विग अजूनही वापरतात.

यंदा जानेवारी महिन्यात न्यायमूर्ती सुजॉय पॉल यांनी कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली, तेव्हा ही वसाहतकालीन परंपरा पुन्हा चर्चेत आली. न्या. पॉल पारंपरिक लाल गाऊन आणि पांढऱ्या कुरळ्या केसांचा न्यायालयीन विग परिधान करून दिसले. मार्च २०२६ मध्ये न्या. पॉल यांनी आर. एन. रवी यांना पश्चिम बंगालचे राज्यपाल म्हणून शपथ दिली; तेव्हाही ते लाल गाऊन आणि विग घालून उपस्थित होते. भारतातील बहुतांश न्यायालयांनी ही प्रथा अनेक वर्षांपूर्वी बंद केली असली तरी कलकत्ता उच्च न्यायालयात काही विशिष्ट समारंभांमध्ये ती आजही पाळली जाते.

न्यायाधीशांनी विग घालण्याची परंपरा इंग्लंडमध्ये सतराव्या शतकात सुरू झाली. राजघराणे, उच्चवर्गीय अधिकारी आणि व्यावसायिक वर्गातील लोक विग वापरू लागले. याच काळात न्यायाधीश आणि वकील यांनीही औपचारिक पोशाखाचा भाग म्हणून विग वापरण्यास सुरुवात केली. १६८७ नंतर इंग्लंडमधील न्यायालयांमध्ये विग हा न्यायाधीश व वकिलांच्या पोशाखाचा स्थायी भाग बनला. विगची फॅशन पुढे कमी झाली, तरी न्यायव्यवस्थेने परंपरा आणि प्रतिष्ठेचे प्रतीक म्हणून ती कायम ठेवली. पारंपरिक न्यायालयीन विग हे साधारण पांढऱ्या किंवा राखाडी रंगाच्या घोड्याच्या केसांपासून तयार केले जातात. काही आधुनिक विग सिंथेटिक फायबरपासूनही बनवले जातात; मात्र पारंपरिक न्यायालयीन समारंभात आजही घोड्याच्या केसांपासून बनवलेल्या विगालाच अधिक प्रतिष्ठा दिली जाते.

विग वापरण्यामागे काही व्यावहारिक आणि प्रतीकात्मक कारणे होती. पहिले म्हणजे न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा आणि अधिकार दर्शवणे. विग आणि गाऊनमुळे न्यायाधीशांचा व्यक्तिगत नव्हे तर संस्थात्मक अधिकार अधोरेखित होतो. दुसरे कारण म्हणजे समानता आणि औपचारिकता.

सर्व न्यायाधीश आणि वकील एकसारखा पोशाख परिधान करत असल्याने न्यायालयातील औपचारिक वातावरण राखले जाते. या परंपरेची मुळे ब्रिटिश काळात आढळतात. हायकोर्ट ॲक्ट १८६१ अंतर्गत ब्रिटनच्या राणीला कलकत्ता, बॉम्बे आणि मद्रास येथे उच्च न्यायालये स्थापन करण्याचा अधिकार देण्यात आला होता. ही तीनही 'चार्टर्ड' उच्च न्यायालये ब्रिटिश काळातील सुप्रीम कोर्टाची थेट उत्तराधिकारी होती. त्यांची स्थापना भारतीय कायद्याअंतर्गत नव्हे, तर ब्रिटिश राजसत्तेच्या रॉयल चार्टर अंतर्गत करण्यात आली होती. म्हणूनच या न्यायालयांच्या समारंभिक परंपरा आणि पोशाख पद्धती इंग्लंडमधील उच्च न्यायालयांच्या प्रथांशी जवळून जोडलेल्या राहिल्या.

ब्रिटिश न्यायाधीश भारतात काम करताना विग आणि गाऊन घालत असत. पुढे भारतीय न्यायाधीशांनीही त्याच परंपरेचे पालन केले. त्यामुळे विग ही न्यायालयीन परंपरेचा भाग बनली. भारतामध्ये स्वातंत्र्यानंतर हळूहळू विग घालण्याची प्रथा बंद झाली. आज भारतीय न्यायाधीश आणि वकील प्रामुख्याने काळा गाऊन आणि गळ्यात पांढरा बँड इतकाच पोशाख वापरतात. मात्र कलकत्ता उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायाधीशांचा शपथविधी किंवा इतर विशेष प्रसंगी विग घालण्याची परंपरा अजूनही पाळली जाते. ही प्रथा न्यायालयाच्या ऐतिहासिक वारशाचा भाग म्हणून टिकवून ठेवण्यात आली आहे.

भारताबाहेर आजही काही न्यायालयांमध्ये- विशेषतः इंग्लंड आणि वेल्समधील फौजदारी न्यायालयांत - न्यायाधीश आणि वकील विग वापरतात. काही कॉमनवेल्थ देशांमध्येही ही परंपरा अजून अस्तित्वात आहे. काही जणांच्या मते, ही ब्रिटिश काळातील अनावश्यक वसाहतवादी परंपरा आहे आणि आधुनिक भारतात तिचे स्थान नाही. तर काहींच्या मते, ही न्यायव्यवस्थेच्या ऐतिहासिक सातत्याचे आणि परंपरेचे प्रतीक आहे.

जगभर

'प्रेम' करण्यासाठी चीनमध्ये विद्यार्थ्यांना स्पेशल सुट्टी !

वसंत ऋतूच्या आगमनाची चाहूल लागली की चीनमध्ये विद्यार्थ्यांना काही ठराविक काळासाठी सुट्टी दिली जाते. चीन सरकारनं यावेळी दोन आठवड्यांपूर्वीच वसंत ऋतूची सुट्टी जाहीर केली. सरकारच्या या घोषणेनंतर सिचुआन आणि ईस्ट जियांगसू राज्यांसोबतच सुझोउ आणि नानजिंग शहरांनी लगेचंच त्याचं अनुकरण केलं.

त्यानंतर सिचुआन येथील साउथ वेस्ट व्होकेशनल कॉलेज ऑफ एव्हिएशन विद्यापीठानंही लगोलग विद्यार्थ्यांना सुट्टी देऊ केली, पण त्यासाठी त्यांनी विद्यार्थ्यांना एक अटही घातली. ही जी सुट्टी तुम्हाला दिली आहे, त्याचा विनियोग चांगल्या कामासाठीच करा. इतरवेळी विद्यार्थ्यांना सुट्टीच्या काळात अभ्यासाचा किंवा नवीन काही स्किल्स शिकण्याचा सल्ला दिला जातो, पण या विद्यापीठानं विद्यार्थ्यांना बजावलं, या काळात सर्वत्र छान फुलं फुललेली असतात. वातावरण अतिशय सुंदर आणि आल्हाददायक असतं. या काळात तुम्ही फुलांचा आस्वाद घ्या, बागांमध्ये हिंडा, पण एकट्यानं नाही, आपल्या जोडीदारासोबत निसर्गाचा हा आनंद घ्या आणि भरपूर रोमान्स करा ! विद्यापीठानं यासाठी थेट नोटीसच काढली आणि त्यात लिहिलं, 'विद्यार्थ्यांनो, या काळात इतर कोणत्याही 'फालतू' गोष्टी करू नका, पुस्तकं, अभ्यास, वाचन.. यांसारख्या गोष्टीत निदान सध्या तरी आपला अमूल्य वेळ घालवू नका, त्याऐवजी आपापाल्या बॉयफ्रेण्ड, गर्लफ्रेण्डसोबत मौजमजा करा!. तुम्हाला कोणी जोडीदार नसेल, तर तातडीनं अशा जोडीदाराचा शोध घ्या आणि एकमेकांच्या सोबतीचा, सहवासाचा आनंद घ्या !'

सुटीच्या काळात तरुणांनी प्रेमात पडण्याची, रोमान्स करण्याची आणि अर्थातच मूल जन्माला घालण्याची त्यांनी जणू काही सक्तीच केली आहे. त्यासाठी विद्यापीठानं विद्यार्थ्यांना भरीव प्रोत्साहन दिलं आहे. एवढंच नाही, विद्यापीठाच्या बागा, उद्यानं

आणि अगदी एकांतही उपलब्ध करून दिला आहे !

देशाचा जन्मदर वाढावा यासाठीच हे केलं जात आहे. आपली लोकसंख्या वाढावी यासाठी चीन युद्धपातळीवर जे काही प्रयत्न करीत आहे, त्या प्रयत्नांचाच हा आणखी एक अभिनव मार्ग आहे.

रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, देशातील जन्मदर वाढविण्यासाठी हे केलं जात आहे. विद्यापीठानं आपल्या अधिकृत वीचॅट अकाउंटवरून या सुट्टीबद्दल माहिती दिली. त्यात 'विषय' या कॉलममध्ये 'विद्यार्थ्यांनी फुलं पाहणं आणि एकमेकांच्या सोबतीनं रोमान्सचा आनंद घेणं' असं नमूद केलं आहे. विद्यापीठातील सर्व शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांनी या काळात पुस्तकांपासून दूर राहण्याचं आवाहनही करण्यात आलं आहे.

चिनी अधिकाऱ्यांनी सांगितलं, विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांना ऑफ-सीझनमध्ये, जेव्हा पर्यटनस्थळांवर गर्दी कमी असते त्यावेळी अशा ठिकाणी फिरण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं जाईल. यासाठी त्यांना सशुल्क रजाही दिली जाईल. म्हणजेच या काळात तुम्ही जोडीदारासोबत मनमुक्त फिरा, प्रवास करा, मौज करा, ऑफिसमध्ये येऊन काहीही काम करू नका, सुट्टी घ्या, तरीही तुमचा पगार कापला जाणार नाही !

ऐश करण्यासाठीच ही सुट्टी त्यांना दिली जाणार आहे. जन्मदर सुधारण्यासाठी चिनी सरकारनं अशा प्रकारे प्रवास आणि मनोरंजनाला प्रोत्साहन देण्याचा नवा फंडा आता अंमलात आणायला सुरुवात केली आहे. चीनच्या या नव्या फंड्याला तरी तरुण बळी पडतात का, हा प्रश्नच आहे!

जनमन

पेन्शनरांना न्याय द्या, आश्वासनांचे नाटक नको

४७ लाख निवृत्तिधारकांना फक्त एक हजार रुपये पेन्शन मिळते आहे, अशी बातमी वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध झाली आहे. या एवढ्याशा तुटपुंज्या पेन्शनमध्ये काय होणार आहे? जगण्याचा खर्च त्यापेक्षा कितीतरी जास्त आहे. जगण्यालायक पेन्शन मिळत नसेल तर त्यांनी काय करावे? पेन्शनमध्ये वाढ करावी, जगण्यासाठी अत्यावश्यक असलेली किमान रक्कम तरी आम्हाला मिळावी, अशी मागणी कितीतरी वर्षांपासून निवृत्तीधारक करीत आहेत. पण, अजूनही त्याबाबत सकारात्मक पावले उचलली गेलेली नाहीत. ही मागणी करत करत काही जण हे जगण सोडून गेले, तर अनेक जण त्याच वाटेवर आहेत, तरीही काहीही होत नाही. याबाबत कायम नुसत्या वांझोट्या चर्चा!

लाखो निवृत्तिधारकांना निदान त्यांच्या जगण्यापुरते तरी निवृत्ती वेतन तुम्ही देणार नाही का? आश्वासनांच्या भोपळ्यावर आणि त्या आशेवर ज्येष्ठांनी किती दिवस वाट पाहायची? 'पेन्शन वाढणार', अशा बातम्या आतपर्यंत अनेकदा आल्या.

पण, ज्येष्ठांच्या तोंडाला कायम पाने पुसली गेली. प्रत्यक्ष बँकेत त्यांच्या खात्यामध्ये वाढीव पेन्शनची रक्कम जमा होत नाही, तोपर्यंत कोणत्याच गोष्टीची खात्री देता येत नाही. आमदार, खासदार, मंत्री, लाखो रुपये पेन्शन घेतात, सत्ताकाळात तर भरमसाठ मासिक वेतन, भत्ते, इतर सोयीसुविधा घेतात. पण, केवळ हजार रुपये पेन्शनवर ज्येष्ठ नागरिक कशी गुजराण करत असतील, हा विचार डोक्यात कसा येत नाही? निष्फळ चर्चा, आश्वासनांचा बॅण्डबाजा आणि सहानुभूतीचे खोटे खोटे नाटक आता पुरे झाले!

- राजेश कुलकर्णी, नाशिक

समकालीन महत्त्वाचे मुद्दे मांडणारी, नवी चर्चा सुरू करणारी वाचक-पत्रे या स्तंभामध्ये प्रसिद्ध केली जातील. आपली पत्रे येथे पाठवा : **janman@lokmat.com**

सेतू

संकटकाळात यूएईत विणला गेला माणुसकीचा सुरेख गोफ!..

पर्यटकांचा मुक्काम युद्धामुळे अचानक वाढला; पण त्यासाठी स्वयंसेवक पुढे आले. कोणी औषधांची, कोणी जेवणाची, तर कोणी राहण्याची सोय केली.

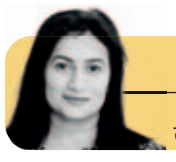

शिल्पा मोहिते
दुबईस्थित अभियंता तंत्रज्ञान, संस्कृती यावर लेखन

'यूएई'मध्ये तणावाची परिस्थिती निर्माण झाल्यापासून एक गोष्ट सतत जाणवते. ज्या बातम्यांमधून माणसांच्या मनात लपून बसलेल्या भीतीचं दर्शन घडतंय त्याच बातम्यांमधून माणसांच्या मनातल्या मानवतेचं दर्शनही घडतंय. युद्ध सुरू होण्याआधी माझी आई काही दिवस दुबईला आली होती. तिला मधुमेह आहे. येताना जेवढे दिवस राहायचं आहे तेवढे दिवस पुरतील एवढीच औषधं तिने आणली होती. युद्ध सुरू झालं. मुक्काम लांबला. स्थानिक डॉक्टरचं प्रिस्क्रिपशन नसेल तर इथे ती औषधं मिळत नाहीत. आता काय करायचं असा विचार करत असताना समोर आला तो एक सुरेख माणुसकीचा सेतू.

या सेतूच्या एका बाजूला भारत आणि महाराष्ट्र सरकारच्या मदतीने सुरू झालेली 'आयपीएफ' महा-हेल्पलाइन होती, तर दुसऱ्या बाजूला यूएई सरकारने केलेली मजबूत व्यवस्था. या उपक्रमात अनेक स्वयंसेवक, डॉक्टर, ट्रॅव्हल एजंट्स आणि विविध क्षेत्रांतील लोक एकत्र आले होते. दुबई आणि अबुधाबीतील मराठी डॉक्टरांना त्यात जोडण्यात आलं होतं. एक आजी अचानक आजारी पडल्या. त्यांना इथल्या इन्शुरन्स, सेकंड ओपिनियन अशा गोष्टींची साहजिकच माहिती नव्हती. अशा वेळी डॉक्टरांशी थेट संपर्क झाल्यामुळे त्यांना योग्य मार्गदर्शनही मिळालं.

या काळात लोकांच्या अडचणी साध्या तरी गंभीर होत्या. काही हाय बीपी, डायबेटिसचे रुग्ण, तर काही कॅन्सर पेशंटही होते. मुक्काम लांबल्यावर त्यांच्यासाठी वेळेत औषधांची व्यवस्था करणं,

डॉक्टरांशी संपर्क करून देणं हे सगळं या स्वयंसेवकांनी सुरळीत आणि कुठलाही बोभाटा न करता केलं. त्यामुळेच माझ्या आईचीही औषधं वेळेत मिळाली आणि आम्ही निश्चिंत झालो.

प्रवासासाठीही तीन विश्वासार्ह एजंट्स नेमून देण्यात आले. मार्जिन कमी ठेवा, अडकलेल्या लोकांना खात्रीशीर तिकिटं द्या, अशा स्पष्ट सूचना त्यांना देण्यात आल्या होत्या. सीनियर सिटिझन्स, लहान मुलं असलेली कुटुंबं.. असे वेगवेगळे गट तयार करण्यात आले. ही मंडळी पर्यटक म्हणून आली होती. त्यामुळे लांबलेल्या मुक्कामाचा भार झेपेल अशी सगळ्यांचीच आर्थिक परिस्थिती नव्हती; पण अनेक स्वयंसेवकांनी पुढाकार घेतला. कोणी घरून डबे पाठवले. कोणी राहण्याची सोय केली. कोणी या लोकांना प्रत्यक्ष भेटून त्यांना धीर दिला. या प्रयत्नांमागे 'युनायटेड महाराष्ट्र' हा एक मोठा प्लॅटफॉर्म उभा होता. त्यात सुमारे ३५ वेगवेगळ्या संस्था- महाराष्ट्र मंडळं, धार्मिक संस्था, व्यावसायिक गट, क्रीडा गट एकत्र आले होते. कोण अजमानमध्ये, कोण रास-अल-खैमामध्ये, कोण दुबईत, तर कोण अबुधाबीमध्ये.. या काळात डॉ. धीरज जैन यांनी एक आगळा आदर्श घालून दिला. डॉ. धीरज जैन मूळचे महाराष्ट्रातले. त्यांनी अजमानमधलं आपलं फार्महाऊस अडकलेल्या लोकांसाठी खुलं केलं आणि तब्बल ५०० लोकांसाठी बेड्सची सोय करण्यात आली. ही फक्त व्यवस्था नसून त्यांना तात्पुरतं 'घर' देण्याची भावना होती. लोकांना आणण्यासाठी आलिशान गाड्या पाठवण्यात आल्या, सकाळी योगा, जैन कुटुंबीयांबरोबर नाश्ता, जेवण, क्रिकेटचे सामने दाखवण्याचीही सोय केली गेली. या सगळ्या प्रयत्नांतून, बहुतेक सगळे लोक सुरक्षितपणे परत गेले. काहींचे सुखरूप पोहोचल्याचे कृतज्ञ निरोपही आले..

Shiloo75@gmail.com

सेतू : जगभरातील मराठी माणसांच्या जगण्यातले रूपरंग शोधणारा हा स्तंभ. तुम्ही स्वत:, तुमचे आप्त परदेशात राहात असाल, तर तुमचे अनुभव जरूर पाठवा. निवडक लेखनाला प्रसिद्धी. **ईमेल करा :** setu@lokmat.com

तिरकस आणि चौकस

गजानन घोंगडे

हे पत्र लोकमत मीडिया प्रा. लिमिटेडच्या वतीने मुद्रक व प्रकाशक **बालाजी मुळे** यांनी प्लॉट नं. ए - ८१८ इंडस्ट्रियल एरिया, एम.आय.डी.सी., महापे, नवी मुंबई येथे मुद्रित करून 'लोकमत', पृथ्वी पार्क, सेक्टर ३०, सानपाडा, नवी मुंबई कार्यालय - ४००७०५ येथून प्रसिद्ध केले. ● दूरध्वनी क्र : ०२२ ४६०४१७८४
● **मुंबई कार्यालय :** लोकमत मीडिया प्रा. लिमिटेड, तिसरा मजला, पारिजात हाउस, प्लॉट नं. १०७६, आपटे इंडस्ट्रियल इस्टेट, लक्ष्मीनरसिंग पपन मार्ग, डॉ. ई मोझेस रोडसमोर, गांधीनगर, वरळी, मुंबई, ४०००१८. ● दूरध्वनी क्र : ०२२- ४६०३५९३०, ०२२- ४७५०७९४६ ● **ठाणे कार्यालय :** वेस्टर्न व्ह्यू, श्री गजानन महाराज चौक, वारकरी भवनाजवळ, ठाणे, फोन : २५४४१९०५, २५३८१७७४ ● **नवी मुंबई कार्यालय :** पृथ्वी पार्क, सेक्टर ३०, सानपाडा, नवी मुंबई ४००७०५. फोन : ०२२ ४६०४१७८४ ● संस्थापक संपादक : **स्व. जवाहरलाल दर्डा** ● मानद संपादिका : **श्रीमती उषाताई दर्डा** ● चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड : **डॉ. विजय दर्डा** ● एडिटर इन चिफ : **राजेंद्र दर्डा** ● समूह संपादक : **विजय बाविस्कर**
● संपादक : **अतुल कुलकर्णी*** (*पी. आर. बी. कायद्यानुसार संपादकीय जबाबदारी यांची आहे.) 'लोकमत'मधील लेखांचे हक्क राखून ठेवले आहेत. लोकमत ® हे चिन्ह लोकमत मीडिया प्रायव्हेट लि. चे. व्यापारचिन्ह आहे.

नादाला लागाल तर तुमचे नामोनिशाण नष्ट करू

भोंदू खरातच्या संस्थेने अंनिसला दिला होत दम, काही वर्षांपूर्वी प्रकरण दाबण्यासाठी रिव्हॉल्व्हरचा दाखविला धाक

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नाशिक : सध्या भोंदू अशोक खरात याच्याविषयी पीडित महिलांच्या तक्रारी दाखल होत असून, त्याव्यतिरिक्त अनेकांनी आपल्याला धमक्या दिल्याच्या तक्रारीही केल्या आहेत. आता महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने देखील खरातने हे प्रकरण उघड करू नये यासाठी सुमारे वीस वर्षांपूर्वी धमक्या दिल्या होत्या, असा दावा केला आहे.

खरातने या धंद्यात जम बसविला, तेव्हा २००७ मध्ये 'अंनिस'कडे एक तक्रार आली होती. त्यानुसार 'अंनिस'चे कार्यकर्ते महेंद्र दातरंगे व प्रा. डॉ. सुदेश घोडेराव हे खरातच्या कार्यालयात गेले होते. तो करत असलेले कृत्य हे अंधश्रद्धायुक्त असून चुकीचे आहे, अशी जाणीव कार्यकर्त्यांनी त्याला करून दिली. त्यावर मी निवृत्त कॅप्टन आहे. माझ्याकडे रिव्हॉल्व्हर आहे, अशी धमकी त्याने कार्यकर्त्यांना दिली; पण कार्यकर्त्यांनी न घाबरता आव्हान दिले. त्यावर त्याने सावध राहा, अशी धमकी दिली होती. त्यावेळी भोंदू खरात त्याने त्याचे उपद्व्याप सुमारे तीन महिने बंद ठेवले होते. मात्र, काही दिवसांनी त्याने पुन्हा त्याचे कृत्य सुरू केल्याचे 'अंनिस'ने म्हटले आहे.

२०१३ मध्ये अंनिसचे सिन्नर येथील कार्यकर्ते अरुण घोडेराव यांच्याशी ईशान्येश्वर मंदिराच्या एका ट्रस्टीने वाद घालून धमकी दिली होती. तुम्ही अंनिसवाले अनेक भोंदूबाबांच्या मागे लागता; पण आमच्या नादाला लागाल तर तुमचे नामोनिशाण नष्ट करू, असे म्हणत धमकावले होते. यानंतरही 'अंनिस'कडे पीडित संपर्क करत होते; पण धाडसाने पुढे येऊन पोलिसांत तक्रार देण्यास ते घाबरत होते, असे कार्यवाह चांदगुडे यांनी माध्यमांना सांगितले.

'ब्रह्मसदन' या आलिशान बंगल्याची बुधवारी एसआयटीकडून तपासणी करण्यात आली.

एसआयटीकडून मिरगावातील ब्रह्मसदन बंगल्याची तपासणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नाशिक : महिला अत्याचार प्रकरणात अटकेत असलेल्या अशोक खरात याच्या सिन्नर तालुक्यातील मीरगाव येथील 'ब्रह्मसदन' या आलिशान बंगल्यावर विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) मंगळवारी (दि.२४) रात्री उशिरा तपासणी केली. न्यायालयात खरातला हजर केल्यानंतर एसआयटी पथक थेट मीरगाव येथे दाखल होत ईशानेश्वर मंदिर परिसरातील या बंगल्याची तपासणी करण्यात आली.

तपासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठिकाण मानल्या जाणाऱ्या या बंगल्याभोवती पथकाने परिसराची छाननी करत विविध बाबींची माहिती गोळा करण्याचा प्रयत्न केला.

पुराव्यांबाबत गोपनीयता

१ या कारवाईमुळे प्रकरणाच्या तपासाला वेग आला असून, पुढील काही दिवसांत अधिक धक्कादायक बाबी समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यापूर्वी स्थानिक पोलिसांनी याच बंगल्यावर झडती घेतली असता एक रिव्हॉल्व्हर व काही काडतुसे जप्त केल्याची माहिती समोर आली होती.

२ त्यामुळे या बंगल्याचा या प्रकरणाशी असलेला संबंध अधिक गडद झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर एसआयटीने केलेली तपासणी अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. नेमके काय आढळले, कोणते पुरावे हस्तगत करण्यात आले याबाबत गोपनीयता पाळली जात आहे.

भोंदूबाबा खरात विरोधात आता वन विभागही सरसावला

भोंदूबाबा अशोक खरातच्या लैंगिक शोषणाच्या गुन्ह्यांचा 'एसआयटी'कडून सखोल तपास केला जात आहे. दररोज खरातचे वेगवेगळे कारनामे उघड होत आहेत. सिन्नरच्या मिरगावात त्याने उभारलेल्या मंदिरात अघोरी प्रकारासाठी वन्य प्राण्यांची हत्या करून त्यांच्या अवयवांचा वापर केल्याचा सुद्धा संशय तपास पथकाला आहे. यामुळे आता त्या दिशेनेही तपास केला जात असून, नाशिक पश्चिम वन विभाग सुद्धा 'एसआयटी'च्या संपर्कात आहे.

भोंदू अशोक खरात याने त्याच्याकडे येणाऱ्या लोकांना हरणांची कस्तुरी देण्याचा प्रकार केल्याची चर्चा आहे. कस्तुरी त्याने कोठून व कशी मिळविली? याचा तपास करायचा असल्याचे सरकार पक्षाकडून न्यायालयात मंगळवारी सांगण्यात आले होते. तसेच हरणांची यासाठी शिकार केली गेली का? असाही संशय तपास पथकाला आहे. यामुळे आता भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम १९७२ नुसार भोंदू खरातविरुद्ध कलमवाढ केली जाते का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

खरातप्रकरणी कुरघोडीचे राजकारण सुरूच

भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणावरून विविध राजकीय नेत्यांकडून टीकेची झोड उठत आहे. विरोधी नेते सरकारला या मुद्द्यावरून कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करत आहेत, तर दुसरीकडे राष्ट्रवादी (अजित पवार)च्या रूपाली ठोंबरे यांनी रूपाली चाकणकर यांच्यावरील टीकास्त्र अव्याहत सुरू ठेवले आहे.

डझनभर मंत्री तुरुंगात जाण्याची शक्यता

महाराष्ट्रात जे काही सध्या चालले ते हास्यास्पद आहे. काही मंत्र्यांनीही खरातकडे अघोरी पूजा केली आहे. या प्रकरणी डझनभर मंत्री, दोन डझन अधिकारी तुरुंगात जातील.

हर्षवर्धन सपकाळ, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस

३८ आमदारांनी कापल्या करंगळ्या, चौकशी करा

देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्रिपदावरून दूर करण्यासाठी राज्यातील काही आमदारांनी अघोरी पूजेचा घाट घातला होता. ३८ आमदारांनी भोंदू अशोक खरातकडे जाऊन करंगळ्या कापल्या होत्या. त्याची चौकशी करा आणि खरात जिवंत राहील याची व्यवस्था करा.

जितेंद्र आव्हाड, आमदार, राष्ट्रवादी (शरद पवार)

भाजपच्याच नेत्याकडून ईशान्येश्वर मंदिराला निधी

सरकारने या संधीचा वापर करावा. खरातसंदर्भात जे पुरावे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आलेले आहेत, ते तपासले पाहिजे. भाजपच्याच एका नेत्याने ईशानेश्वर संस्थानसाठी दीड कोटीचा निधी दिला. खरे काय ते समोर येऊ द्या.

रोहित पवार, आमदार, राष्ट्रवादी (शरद पवार)

चाकणकर यांना प्रदेशाध्यक्षपदावरून हटवा

रूपाली चाकणकर यांना राष्ट्रवादी (अजित पवार)च्या महिला प्रदेशाध्यक्ष पदावरून हटवा. पक्षाच्या पुरोगामी चेहऱ्याला डाग लागला आहे. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना विनंती आहे.

रूपाली ठोंबरे पाटील, नेत्या, राष्ट्रवादी (अजित पवार)

चाकणकरांच्या हकालपट्टीसाठी महिला आघाडी मैदानात

भगूर (नाशिक) : भोंदू अशोक खरात याच्या ट्रस्टवर पदाधिकारी म्हणून काम करणाऱ्या राष्ट्रवादीच्या नेत्या रूपाली चाकणकर यांना राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदावरून पायउतार व्हावे लागले. आता त्यांची राष्ट्रवादी महिला आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्ष पदावरूनही हकालपट्टी करावी, अशी मागणी नाशिक जिल्हा राष्ट्रवादीच्या (अजित पवार) १३ तालुका अध्यक्षांनी केली आहे.

यासंदर्भात नाशिक जिल्हाध्यक्ष प्रेरणा बलकवडे यांनी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना भेटून निवेदन दिले आहे. पक्षाच्या महिला प्रदेशाध्यक्ष रूपाली चाकणकर अनेक वर्षांपासून महिलांचा छळ करणाऱ्या व्यक्तीचे त्या समर्थन करत आहेत. यामुळे राज्याच्या राजकारणात पक्षाच्या प्रतिमेचे कधीही न भरून येणारे नुकसान झाले आहे.

क्विक Update

पोस्ट कार्यालयांना बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी

परभणी/हिंगोली : राज्यातील पासपोर्ट व टपाल कार्यालयांना आरडीएक्स बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी देणारा ई-मेल बुधवारी दुपारी प्राप्त झाल्याने प्रशासनात खळबळ उडाली. दुपारी १२:१० वाजता सायनाईड मिश्रित १६ आरडीएक्स बॉम्बचा स्फोट होणार असल्याचा मेल पाठवण्यात आला होता. त्यामुळे काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. या पार्श्वभूमीवर परभणीसह हिंगोली आणि इतर भागातील सर्व पोस्ट कार्यालयांमध्ये बॉम्बशोधक व नाशक पथकाने श्वानाच्या मदतीने कसून तपासणी केली. मात्र, कोणतेही संशयास्पद किंवा आक्षेपार्ह वस्तू आढळून आली नाही. त्यामुळे प्रशासनाने सुटकेचा नि:श्वास सोडला असून, पुढील तपास सुरू आहे.

मंदिरात अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग

कडा : आष्टी तालुक्यातील राष्ट्रीय महामार्गावरील एका मंदिरात मंगळवारी सकाळी दर्शनासाठी आलेल्या अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग केल्याची धक्कादायक घटना घडली. "तू मला आवडतेस, तुझ्याशिवाय मी जगू शकत नाही; ही चिठ्ठी घेतली नाही तर तुला जिवे मारीन आणि मी स्वतःही आत्महत्या करीन," अशी धमकी देणाऱ्या नराधमाला आष्टी पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत.

कवडीचा भाव, टोमॅटो फेकले रस्त्यावर

जालना : कष्टाने पिकवलेल्या मालाला कवडीमोल भाव मिळत असल्याने शेतकरी हतबल झाला असून धारकल्याण (ता. जालना) येथील प्रयोगशील शेतकरी अमर काकडे यांनी २६ क्विंटल टोमॅटो रस्त्यावर फेकून दिला. यात त्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. काकडे नेहमीच शेतीत नवनवीन प्रयोग करत असतात. आर्थिक परिस्थिती सावरण्यासाठी त्यांनी मोठ्या आशेने एक एकर क्षेत्रावर टोमॅटोची लागवड केली होती.

शिर्डी येथील साई मंदिरात श्रीरामनवमी उत्सवानिमित्त करण्यात आलेली विविधरंगी फुलांची आकर्षक सजावट.

आई तुझं देऊळ साजतंय गुलाले डोंगरान...चैताचे महिन्यान

लोणावळा : कोकणातील कोळी, आगरी बांधवांसह महाराष्ट्रातील अनेकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या वेहेरगाव-कार्ला येथील एकवीरा देवीच्या चैत्री यात्रेनिमित्त कार्ला गडावर बुधवारी भाविकांची अलोट गर्दी झाली होती. पारंपरिक वाद्यांच्या गजरात पालखीचा मिरवणूक सोहळा उत्साहात पार पडला. संपूर्ण परिसर 'आई माउलीचा उदोऽऽउदो' अशा गजरात दुमदुमून गेला. लोणावळ्याजवळ कार्ला गडावर एकवीरा देवीचे मंदिर आहे. देवीच्या चैत्री यात्रेला मंगळवारी देवीचे माहेरघर असलेल्या देवघर येथील काळभैरवनाथ देवाच्या पालखी सोहळ्याने सुरुवात झाली. बुधवारी यात्रेचा मुख्य दिवस होता. पहाटेपासूनच हजारो भाविकांनी गड चढण्यास सुरुवात केली होती. एकवीरेचा जयघोष करत, भक्तांनी मंदिर परिसर दणाणून सोडला होता.

लाडक्या बहिणींना बिनव्याजी कर्ज

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : राज्यातील विविध महामंडळांच्या योजनांचे एकत्रीकरण करून त्या 'लाडकी बहीण'सारख्या योजनांशी जोडण्यात येणार आहेत. या माध्यमातून त्यांना बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधान परिषदेत केली.

वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळावर थेट कर्ज योजना सुरू करण्याबाबत आ. अभिजित वंजारी यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी आ. प्रवीण दरेकर यांनी उपप्रश्नाद्वारे व्हीजेएनटी महामंडळासह अन्य महामंडळांनी लाडकी बहीण योजनेला कर्ज योजना जोडून १ लाखाच्या व्याज परताव्याची सांगड घालावी, अशी विनंती केली.

डॉ. समीर कदम यांच्यावर लिंबगावात अंत्यसंस्कार

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नांदेड : 'एमजीएम'चे संस्थापक आणि विश्वस्त कुटुंबातील सदस्य तथा नवी मुंबई येथील 'एमजीएम' रुग्णालयातील सर्जन व एमजीएम वैद्यकीय महाविद्यालयाचे जनरल सर्जरी विद्याशाखेचे विभागप्रमुख डॉ. समीर सुधीरचंद्र कदम यांच्या पार्थिवावर मंगळवारी लिंबगाव (ता. जि. नांदेड) येथे महानुभाव पंथाच्या परंपरेने अंत्यसंस्कार करण्यात आले.

मुंबई येथून एअर ॲम्ब्युलन्सने नांदेड विमानतळावर डॉ. समीर यांचे पार्थिव आणण्यात आले. यानंतर नांदेडमधील भाग्यनगर येथील निवासस्थानी ते अंत्यदर्शनासाठी ठेवण्यात आले होते.

यावेळी डॉ. समीर यांची पत्नी डॉ. गायत्री कदम, मुलगा अभयसिंग कदम, वडील डॉ. सुधीरचंद्र कदम आणि मातोश्री, बंधू, वहिणी, पत्नी आणि पुत्र तसेच 'एमजीएम'चे अध्यक्ष माजी मंत्री कमलकिशोर कदम, लतिका कदम, एमजीएम विद्यापीठाचे कुलपती अंकुशराव कदम, अनुराधा कदम, विश्वस्त उज्ज्वल कदम, डॉ. नितीन कदम, एमजीएमचे उपाध्यक्ष डॉ. पी. एम. जाधव, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश रणजित भोसले, उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. के. कदम, एमजीएम आरोग्य विद्यापीठाचे कुलगुरु शशांक दळवी, एमजीएम विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. विलास सपकाळ, आ. बालाजीराव कल्याणकर आदी उपस्थित होते.

संमिश्र

३० लाख मुंबईकरांना दिलासा, फेरफार आता ऑनलाइन

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : मुंबई शहर जिल्ह्यातील मालमत्ताधारकांची मिळकत फेरफार प्रक्रिया पूर्णता ऑनलाइन करण्यात येणार आहे. यामुळे मुंबईतील सुमारे ३० लाख नागरिकांना सरकारी कार्यालयांत वारंवार चकरा मारण्याची गरज उरणार नाही, असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

मुंबई शहर व उर्वरित महाराष्ट्रातील प्रॉपर्टी कार्डच्या संगणकीय प्रणाली वेगवेगळ्या असल्यामुळे ही सुविधा मुंबईत नव्हती. मात्र, यातील तांत्रिक अडचणी दूर करून ही प्रक्रिया डिजिटल केली आहे. या नव्या प्रणालीअंतर्गत मुंबई शहरातील १९ महसूल विभाग व ४ नगररचना योजनांमधील सुमारे २७,८४७ प्रॉपर्टी कार्ड्स महाभूमी व जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.

खरेदीखत, वारसा हक्क, बक्षीसपत्र, भाडेपट्टा, गहाणखत, रोड सेटबॅक, आरक्षण व भूसंपादन अशा ४५ प्रकारच्या फेरफारांसाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याची सुविधा नागरिकांना मिळणार आहे. यामुळे आता घरबसल्या नागरिक अर्ज करू शकतील. मुंबई शहराच्या जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी हा गुंतागुंतीचा प्रकल्प राबवल्याबद्दल मंत्री बावनकुळे यांनी त्यांचे कौतुक केले.

हजार द्या किट घ्या; कामगारांच्या भांडी किटवर दलालांचा डल्ला

लोकमत एक्स्क्लूझिव्ह

सुमित डोळे
लोकमत न्यूज नेटवर्क

छत्रपती संभाजीनगर : सरकारतर्फे राबविण्यात येणारी भांडी किट योजना मोफत असताना काही मल्टिसर्व्हिसेस व ई-सेवा केंद्र चालक कामगारांकडून प्रतिकिट एक हजार रुपयांची वसुली करीत असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. 'लोकमत'च्या तपासणीत मुकुंदवाडी येथील केंद्रात पैसे घेतानाचा व्हिडीओ हाती लागला असून, यामुळे जिल्ह्यातील ई-सेवा व सीएससी केंद्र संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहेत.

२०२४ मध्ये राज्य सरकार महाराष्ट्र इमारत व बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळातर्फे नोंदणीकृत कामगारांसाठी भांडी योजना राबवत आहे. यात बांधकाम कामगारांना घरगुती वापरासाठी आवश्यक भांडी मोफत दिली जातात. मात्र शासनाने मोठ्या अपेक्षेने राबवलेल्या या योजनेला दलालांमुळे अल्पावधीतच ग्रहण लागले आहे.

एआय इमेज

कोणीही पैसे देऊ नये

अर्ज प्रक्रियेच्या अत्यल्प शुल्काव्यतिरिक्त या योजनेसाठी कुठलीही रक्कम, शुल्क नाही. ही योजना मोफत आहे. पैसे उकळले जात असतील तर कामगारांनी आमच्याकडे, तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे तक्रार करावी.

जी. बी. बोरसे, साहाय्यक कामगार आयुक्त

पहिला व्हिडीओ

प्रतिनिधी : शासनातर्फे मोफत आहे ना, हजार रुपये कशाचे घेताय?

एजंट : शासनातर्फे येत-जात सगळे दलालमध्ये असतात.

प्रतिनिधी : यांचा निधी, पगार असेल ना त्यांना?

एजंट : शासनाकडून फायदा होत नाही, मग घेतात पैसे.

प्रतिनिधी : हजार फार होताय हो, दोन-तीनशेत नाही का होणार?

एजंट : नाही.

व्हिडीओ दुसरा

प्रतिनिधी : गरीब आहोत आम्ही.

एजंट : सगळेच कुठे गरीब असतात.

प्रतिनिधी : आमचं जाऊद्या, खऱ्या गरिबांचे काय?

एजंट : बाकीच्यांचे पाहून घेऊ.

प्रतिनिधी : वरून मोफत आहे ना, पण हे सगळं. (पैसे देत)

एजंट : ट्रॅप तर नाही ना कुठला?

प्रतिनिधी : गोडाऊन चालकांना सरकार पैसे देत असेल ना?

एजंट : गोडाऊनवाले पैसे घेऊन बसलेत आधीच.

प्रतिनिधी : सर्वांना एक हजार रुपयेच आहेत का? का कोणाला कमी आहेत?

एजंट : सर्वांना बंधनकारक आहे. सगळ्यांचे वाटे आहेत यात. उघडले कशासाठी हे.

कोणाचा किती वाटा?

अर्ज भरून त्याची प्रिंट देऊन गोदामावर पाठवले जाते. गोदामावरील दलाल फॉर्मचा एक भाग काढून घेत पुन्हा केंद्रावर जाण्यास सांगतो.

ई-सेवा केंद्र, मल्टिसर्व्हिसेसवरील एजंट, केंद्र चालक १ हजार रुपयांची मागणी करतो.एजंटच्या दाव्यानुसार १०० रुपये त्याचे शुल्क, ६०० रुपये इतरांचे व ३०० रुपये गोदाम चालकाला द्यावे लागतात. त्यानंतरच किट मिळते.

जमिनीच्या मोबदल्यात कपात करता येणार नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नवी दिल्ली : जमीन संपादनाचा मोबदला आणि त्यावरील व्याज देणे हे केवळ आर्थिक बोजाचे कारण पुढे करून टाळता येणार नाही, असा शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला.

'न्याय्य मोबदल्याची घटनात्मक हमी कोणत्याही आर्थिक कारणास्तव कमी केली जाऊ शकत नाही,' अशा कडक शब्दांत सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाची (एनएचएआय) पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली.

प्रकरण काय?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०२५ मधील निर्णयानुसार, अधिग्रहित जमिनींसाठी शेतकऱ्यांना ९ टक्के व्याज आणि नुकसान भरपाई मिळणे अपेक्षित होते. तर प्राधिकरणाचा दावा होता की, हा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केल्यास त्यांच्यावर तब्बल २९,००० कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा पडेल.

न्यायालयाने म्हटले काय?

न्यायालयाने प्राधिकरणाचा हा दावा फेटाळताना स्पष्ट केले की, केवळ आर्थिक दायित्वाचा आकडा मोठा आहे म्हणून मूळ निर्णयाचा फेरविचार करता येणार नाही.

कार्यालये रिकामी करा; काँग्रेसला नोटीस

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नवी दिल्ली : काँग्रेस पक्षाला लुटियन्स दिल्लीतील २४, अकबर रोड आणि ५, रायसीना रोड येथील कार्यालये २८ मार्चपर्यंत रिकामी करण्याबाबत नोटीस देण्यात आली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. इस्टेट विभागाकडून ही अंतिम नोटीस देण्यात आली असून, १९७८ पासून ताब्यात असलेली जुनी पक्ष कार्यालये सोडण्याची वेळ येण्याची शक्यता आहे.

सध्या पक्षाचे मुख्यालय अकबर रोड येथील कार्यालयात असून, इंडियन यूथ काँग्रेसचे कामकाज रायसीना रोड येथून चालते. सूत्रांनी सांगितले की, ही नोटीस काही दिवसांपूर्वी देण्यात आली असून पक्षाला एक आठवड्याचाही अवधी देण्यात आलेला नाही.

माता-बाल आरोग्याला चालना; ३६ जिल्ह्यांत तपासणी मोहीम

मुंबई : महाराष्ट्रात माता व बाल आरोग्य संवर्धनासाठी विविध अभिनव उपक्रम यशस्वीपणे राबविण्यात येत असून, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला अधिक बळकट करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलण्यात येत असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली खारघर, नवी मुंबई येथील सिडकोच्या जागेवर श्री सत्य साई संजीवनी केंद्र उभे राहिले आहे. या केंद्राचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. संजीवनी केंद्रामार्फत मुख्यमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यातील सर्व ३६ जिल्ह्यांमध्ये राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) अंतर्गत टू-डी-इको शिबिरांचे आयोजन केले. या शिबिरांद्वारे विविध जिल्हा रुग्णालयांमध्ये हृदयरोग तज्ज्ञांकडून एकूण २,५०७ टू-डी-इको तपासण्या करण्यात आल्या, तसेच जन्मजात हृदयरोग (सीएचडी) उपचारासाठी राज्यभरातील ३,२२६ बालकांवर संजीवनी केंद्र येथे उपचार करण्यात आले. तसेच पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर आणि सातारा जिल्ह्यातील जावळी या आदिवासी बहुल तालुक्यांना दत्तक घेऊन तेथे विशेष आरोग्य उपक्रम राबविले. रायगड जिल्ह्यातील पनवेल, विदर्भातील चंद्रपूर, यवतमाळ आणि नागपूर जिल्ह्यांमध्ये बालकांमधील जन्मजात हृदयरोग तपासणीसाठी मेगा शिबिरे, वीटभट्टी कामगारांच्या मुलांसाठी आरोग्य प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत.

लक्ष्य को ही अपना जीवन-कार्य समझो, हर क्षण उसी का चिंतन करो और उसी के सहारे जीवित रहो।

- स्वामी विवेकानंद

इंसाफ की खातिर

किसी भी आपराधिक वारदात में पीड़ित को न्यायपालिका पर भरोसा होता है कि उसे न्याय जरूर मिलेगा। मगर इंसाफ तभी मिल पाता है, जब मामले की गंभीरता के मद्देनजर जांच-पड़ताल की जाए और अदालत में पुख्ता साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएं। यह काम जांच एजंसियों का होता है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि पुलिस या अन्य जांच एजंसियों के अधिकारी संगीन मामलों को भी गंभीरता से नहीं लेते हैं और हल्की धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हैं। इसके पीछे या तो जांच अधिकारियों की लापरवाही होती है या फिर किसी बाहरी दबाव की वजह से मामले को कमजोर करने की मंशा छिपी होती है। हरियाणा के गुरुग्राम में पिछले माह एक मासूम बच्ची के यौन उत्पीड़न के मामले में भी पुलिस का ऐसा ही रवैया सामने आया है। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को कड़ा संज्ञान लेते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए और मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एक विशेष जांच दल गठित करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कहा कि इस मामले में पुलिस का रवैया शर्मनाक और असंवेदनशील रहा है, जो न्यायिक प्रक्रिया के लिए चिंताजनक है।

यह बात छिपी नहीं है कि सामान्य आपराधिक घटना में भी प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए पीड़ित पक्ष को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि कानून में अब शून्य पुलिस प्राथमिकी दर्ज कराने का प्रावधान है, इसके बावजूद अक्सर ऐसी खबरें आती रहती हैं कि घटनास्थल का किसी दूसरे थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने का हवाला देकर पुलिसकर्मी प्राथमिकी दर्ज करन से इनकार कर देते हैं। कई बार तो पुलिस के साथ जांच प्रक्रिया से जुड़े अन्य संस्थाओं के पदाधिकारियों का गठजोड़ भी सामने आता है। गुरुग्राम मामले में भी इस तरह की बातें सामने आई हैं। पुलिस ने पाक्सो (यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम के तहत दर्ज प्राथमिकी में गंभीर धारा लगाने की बजाय हल्की धारा लगाकर अपराध को कमतर दिखाने की कोशिश की। सर्वोच्च न्यायालय ने बच्ची के बयान पर अपना पक्ष पूरी तरह से बदलने के लिए एक निजी अस्पताल की चिकित्सक को भी फटकार लगाई और कहा कि उनका यह व्यवहार शर्मनाक है।

इसमें दोराय नहीं कि किसी भी अपराध में पीड़ित को इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी पुलिस और दूसरी संबंधित जांच एजंसी की होती है। मगर राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की एक रपट पर गौर करें, तो वर्ष 2018 से 2022 के दौरान बलात्कार के मामलों में दोषसिद्धि की दर 27-28 फीसद के बीच दर्ज की गई थी। वर्ष 2023 में यह दर घटकर 23 फीसद से भी कम रह गई। यानी बलात्कार के मामलों में कड़े कानूनी प्रावधानों का असर आरोपियों को सजा दिलाने में नजर नहीं आ रहा है। इसके पीछे मामलों की जांच में देरी, सबूतों का अभाव या गवाहों के मुकर जाने जैसे कई कारण हो सकते हैं, मगर इसके लिए सीधे तौर पर जवाबदेही पुलिस की ही बनती है। शीर्ष अदालत ने गुरुग्राम मामले में स्थानीय बाल कल्याण समिति के सदस्यों की भूमिका पर भी सवाल उठाए और कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा कि क्यों न उन्हें पद से हटा दिया जाए। अदालत ने पुलिस के साथ-साथ समिति के आचरण को भी कठघरे में खड़ा किया। बहरहाल, उम्मीद की जानी चाहिए कि न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी और पीड़ित बच्ची एवं उसके परिवार को जल्द इंसाफ मिलेगा।

समय की पाबंदी

कुछ माह पहले जब लंबी दूरी की रेलगाड़ियों का किराया बढ़ाया गया था, तब यह उम्मीद थी कि यात्रियों की सुविधाओं और उनकी दिक्कतों पर भी ध्यान दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। अब सरकार के एक नए फैसले ने यात्रियों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। नए नियमों के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति रेलगाड़ी के रवाना होने के निर्धारित समय से आठ घंटे पहले अपना टिकट रद्द कराता है, तो उसे कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा। जबकि पहले यह समय सीमा चार घंटे की थी। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को निजी कारणों से अंतिम समय में यात्रा रद्द करनी पड़ती है, मगर अब ऐसा करना जेब पर भारी पड़ेगा। हालांकि, सरकार का दावा है कि इससे प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों को सीट पाने के ज्यादा अवसर मिलेंगे और इससे टिकटों की कालाबाजारी पर भी रोक लगेगी। मगर सवाल है कि टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं निकाला जा सकता था, जिससे आम यात्रियों को आपात स्थिति में टिकट रद्द कराने पर वित्तीय नुकसान न झेलना पड़े?

यह निराशाजनक ही है कि रेलगाड़ियों के संचालन से लेकर सुविधाओं में व्यवस्थागत खामियों को दूर करने के बजाय यात्रियों के हितों को हाशिये पर रखा जा रहा है। इसमें दोराय नहीं कि लंबी दूरी की यात्रा के लिए रेलगाड़ियां आम आदमी की जीवन रेखा मानी जाती हैं। मगर इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि रेलवे के आधुनिकीकरण की कवायद के बीच यात्रियों की बुनियादी सुविधाओं में सुधार करने को आज भी प्राथमिकता नहीं दी जाती है। रेलगाड़ियों में किफायती और सुरक्षित खान-पान के अभाव से लेकर साफ-सफाई की शिकायतें कम नहीं हो रही हैं। इन समस्याओं का समाधान करने के बजाय ऐसे नियम लागू किए जा रहे हैं, जिससे यात्रियों की परेशानी और बढ़ गई है। राजस्व बढ़ाने की रेलवे की चिंता वाजिब हो सकती है, लेकिन उसे इस बात पर भी गंभीरता से विचार करना होगा कि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है।

डिजिटल विकास के समांतर चुनौतियां

भारत वैश्विक डिजिटल अवसंरचना के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। इस क्षेत्र में यहां अरबों डालर के निवेश की संभावना जताई जा रही है। मगर यह निवेश डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए जितना आशाजनक दिखता है, उतना ही जल और ऊर्जा संसाधनों के लिए चिंता का कारण भी बनता जा रहा है।

योगेश कुमार गोयल

दुनिया में दोराय नहीं कि डिजिटल क्रांति ने मानव जीवन को एक नई दिशा दी है। इसने गति और संपर्क की सुविधा का विस्तार किया है, लेकिन इस चमकदार तकनीकी संसार के पीछे एक अदृश्य संकट भी आकार ले रहा है। कृत्रिम मेधा, 'क्लाउड कंप्यूटिंग' और डेटा विस्तार के साथ-साथ दुनिया भर में डेटा सेंटरों का जाल तेजी से फैल रहा है। भारत भी इस वैश्विक दौड़ का प्रमुख केंद्र बन रहा है। दुनिया की दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनियां भारत में 'एआइ लैब' और 'डेटा सेंटर' स्थापित करने के लिए अरबों डालर का निवेश कर रही हैं। ऐसे में देश तेजी से वैश्विक डिजिटल अवसंरचना के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। विभिन्न घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा देश में डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए अरबों डालर के निवेश की संभावना जताई जा रही है। मगर यह निवेश भारत की तकनीकी महत्त्वाकांक्षाओं और डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए जितना आशाजनक दिखता है, उतना ही देश के जल और ऊर्जा संसाधनों के लिए गहरी चिंता का कारण भी बनता जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस उद्योग के लिए पानी और बिजली की निर्बाध आपूर्ति की जरूरत होती है, जिससे भविष्य में नई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं।

हाल ही में गूगल ने अपनी पर्यावरण रपट जारी की है, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कृत्रिम मेधा यानी एआइ और डेटा सेंटर बिजली एवं पानी की मांग तेजी से बढ़ा रहे हैं। इसके अनुसार, गूगल डेटा सेंटरों ने 6.1 अरब गैलन पानी का उपयोग किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 17 फीसद अधिक था। गूगल के मुताबिक, वर्ष 2030 तक बिजली की मांग भी चौदह गुना तक बढ़ सकती है। डेटा सेंटर सुनने में भले ही महज डिजिटल ढांचा लगें, लेकिन वास्तव में यह एक ऐसा विशाल संयंत्र हैं, जिन्हें चलाने के लिए निरंतर बिजली और पानी की आवश्यकता होती है। हजारों सर्वर चौबीसों घंटे चलते हैं और भीषण गर्मी पैदा करते हैं। इस गर्मी को नियंत्रित करने के लिए 'कूलिंग सिस्टम' में स्वच्छ पानी जाता है। आज जब हम स्मार्टफोन पर वीडियो काल करते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं या एआइ से कोई सवाल पूछते हैं, तब अनजाने में हम धरती के जल संसाधनों पर भी दबाव बढ़ा रहे होते हैं। दुनिया के कई हिस्सों से यह चेतावनी पहले ही सामने आ चुकी है कि डेटा सेंटर किस तरह स्थानीय जल संकट को जन्म दे रहे हैं।

वर्ष 2018 में अमेरिका के जार्जिया राज्य के न्यूटन काउंटी में एक सोशल मीडिया कंपनी की ओर से 7.5 करोड़ डालर की लागत से एक बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा ने स्थानीय लोगों में उम्मीदों की नई लहर जगा दी थी। रोजगार, आर्थिक विकास और क्षेत्रीय समृद्धि के सपने बुने गए। शुरुआती वर्षों में इन उम्मीदों को बल भी मिला, लेकिन यह खुशी ज्यादा समय तक टिक नहीं सकी। कुछ ही वर्षों बाद हालात पलट गए। एक रपट ने चौंकाने वाला सच उजागर किया कि इस डेटा सेंटर के कारण आसपास के कुएं सूखने लगे और घरों तक पानी की आपूर्ति बाधित हो गई। जांच में सामने आया कि एआइ आधारित यह सेंटर प्रतिदिन करीब पांच लाख गैलन पानी खपत कर रहा था, जो काउंटी के कुल दैनिक जल उपयोग का लगभग दस फीसद था। परिणाम यह हुआ कि जहां पहले सौ फीट पर पानी मिल जाता था, वहां अब तीन सौ फीट खुदाई के बाद भी पानी नहीं मिल रहा। इस जल संकट ने स्थानीय लोगों में विस्थापन का भय पैदा कर दिया। एआइ और डेटा सेंटरों में पानी की जरूरत केवल उन्हें शीतल करने तक सीमित नहीं है। एआइ आधारित प्रोसेसिंग में कई गुना अधिक 'कंप्यूटिंग पावर' लगती है, जिससे बिजली की खपत भी बढ़ जाती है।

> भारत जिस 'डिजिटल विकास' का सपना देख रहा है, वह तभी टिकाऊ होगा, जब उसमें पर्यावरणीय विवेक भी शामिल हो। डाटा सेंटरों के लिए हरित और पारदर्शी नियम बनाए जाने की जरूरत है। केवल निवेश और तकनीकी क्षमता ही नहीं, जल और ऊर्जा की दीर्घकालिक उपलब्धता भी नीति का केंद्र बिंदु होनी चाहिए। ऐसा न हो कि डिजिटल प्रगति की दौड़ में हमारे जल और ऊर्जा स्रोतों पर दबाव लगतार बढ़ता जाए, जो भविष्य में बड़ा संकट पैदा कर दे। प्रश्न केवल यह नहीं है कि भारत डिजिटल विकास के पथ पर कितनी तेजी से आगे बढ़ेगा, बल्कि यह भी है कि इसके लिए वैकल्पिक संसाधन कैसे तलाशे जाएं।

बिजली उत्पादन चाहे कोयला आधारित हो, परमाणु हो या तापीय, लगभग हर तरीके में पानी की बड़ी भूमिका होती है। इंटरनेशनल एनर्जी एजंसी के अनुसार, एआइ से किया गया एक सवाल सामान्य 'आनलाइन सर्च' के मुकाबले कई गुना अधिक ऊर्जा खपत करता है। यानी हर डिजिटल सुविधा के पीछे पानी और बिजली की दोहरी मांग छिपी है। कैलिफोर्निया और टेक्सास में हुए अनुसंधान में पाया गया कि चैटजीपीटी-तीन माडल से दस से पचास सवालों के उत्तर देने में लगभग आधा लीटर पानी लगता है। पानी की जरूरत इस पर भी निर्भर करती है कि उत्तर कितना लंबा है, कहां प्रोसेस हो रहा है और गणना में किन चीजों को शामिल किया गया है।

भारत पहले ही दुनिया के उन देशों में शामिल है, जहां भू-जल का अत्यधिक दोहन हो रहा है। कई सरकारी और अंतरराष्ट्रीय रपटों में चेतावनी दी गई है कि आने वाले वर्षों में देश के सैकड़ों जिले गंभीर जल संकट का सामना कर सकते हैं। ऐसे समय में यदि डेटा सेंटरों के लिए भू-जल का अनियंत्रित इस्तेमाल बढ़ता है, तो यह स्थिति और भयावह हो सकती है। विडंबना यह है कि ग्रेटर नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और बंगलुरु इत्यादि जिन क्षेत्रों में डेटा सेंटर स्थापित हो रहे हैं, वहां पहले से ही पानी की उपलब्धता दबाव में है। स्थानीय समुदायों में यह चिंता बढ़ रही है कि कहीं डिजिटल विकास उनकी बुनियादी जरूरतों को पीछे न धकेल दे।

एक समस्या यह भी है कि कई प्रमुख डेटा सेंटर अपनी पर्यावरण रपटों में पानी के उपयोग का पूरा और स्पष्ट ब्योरा सार्वजनिक नहीं करते। इससे नीति-निर्माताओं और आम नागरिकों के लिए यह समझना मुश्किल हो जाता है कि वास्तव में यह उद्योग जल संसाधनों पर कितना दबाव डाल रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में अपेक्षाकृत नरम पर्यावरणीय नियम और स्वनियमन का माडल भी विदेशी कंपनियों को यहां निवेश के लिए आकर्षित करता है। सस्ती बिजली, श्रम और जमीन के साथ-साथ जल-पर्यावरणीय शर्तें भारत को डेटा सेंटरों के लिए 'सस्ता ठिकाना' बना रही हैं। डेटा सेंटरों का प्रभाव केवल जल और ऊर्जा के संसाधनों तक सीमित नहीं है, बल्कि इनसे भारी मात्रा में कार्बन डाइआक्साइड गैस का उत्सर्जन भी होता है, इलेक्ट्रानिक कचरा पैदा होता है और स्थानीय तापमान पर भी असर पड़ता है।

हालांकि तस्वीर पूरी तरह निराशाजनक भी नहीं है। तकनीकी विशेषज्ञों का कहना है कि यदि सही दिशा में निवेश और नीति-निर्माण किया जाए, तो डेटा सेंटरों का जल प्रभाव काफी हद तक कम किया जा सकता है। भारत जिस 'डिजिटल इंडिया' का सपना देख रहा है, वह तभी टिकाऊ होगा, जब उसमें पर्यावरणीय विवेक भी शामिल हो। डाटा सेंटरों के लिए सख्त और पारदर्शी नियम बनाए जाने की जरूरत है। केवल निवेश और तकनीकी क्षमता ही नहीं, जल और ऊर्जा की दीर्घकालिक उपलब्धता भी नीति का केंद्र बिंदु होनी चाहिए, अन्यथा खतरा यह है कि कहीं डिजिटल प्रगति की दौड़ में हम अनजाने में अपनी नदियों, तालाबों और भू-जल पर दबाव न बढ़ा दें। अब प्रश्न केवल यह नहीं है कि भारत कितनी तेजी से डिजिटल विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा, बल्कि यह भी है कि क्या वह इस प्रगति को पानी, पर्यावरण और भविष्य की पीढ़ियों के अधिकारों के साथ संतुलित कर पाएगा। सच यही है कि डेटा जितना बढ़ेगा, धरती का पानी उतना ही घटेगा और इसी सच्चाई को समझना आज की सबसे बड़ी जरूरत है।

स्मृतियों के रंग

महिमा सामंत

जीवन को ध्यान से देखा जाए, तो वह घटनाओं से नहीं, स्मृतियों से बनता है। जो घट चुका है, वह केवल अतीत नहीं बनता। वह हमारे भीतर कहीं ठहर जाता है। हम आगे बढ़ते रहते हैं, समय अपनी गति से चलता रहता है, पर स्मृतियां हमारे साथ चलती हैं, कभी छाया बनकर, कभी प्रकाश बनकर। वे शोर नहीं मचातीं, लेकिन हमारे निर्णयों, हमारे व्यवहार और हमारे भावों को चुपचाप आकार देती रहती हैं। जीवन की इस लंबी यात्रा में स्मृतियां ही वे रंग हैं, जो हमारे भीतर एक अदृश्य चित्र रचती हैं- कभी उजली, कभी गहरी, कभी हल्की, कभी भारी, लेकिन हमेशा अर्थपूर्ण।

बचपन की स्मृतियां उस चित्र की सबसे कोमल परत होती हैं। वे दिन, जब जीवन सरल था और मन निष्कपट। सुबह स्कूल जाने से पहले मां की आवाज और उसके जवाब में 'बस पांच मिनट' की मासूम जिद। खोई हुई पेंसिल पर बहाए गए आंसू और शिक्षक की एक मुस्कान, जो सब कुछ ठीक कर देती थी। गर्मी की छुट्टियों में नानी के घर की सुबहें, आंगन में नंगे पांव दौड़ना और शाम को खेल से लौटते समय मां की पुकार- ये स्मृतियां आज भी मन को उसी तरह सुकून देती हैं, जैसे कभी दिया करती थीं।

दुनिया मेरे आगे

> कुछ यादें जीवन की सबसे गहरी परतों में छिपी होती हैं। प्रिय व्यक्ति को खोने का दुख, टूटे हुए रिश्ते या ऐसा दर्द जिसे शब्द नहीं मिलते। बाहर से मुस्कुराते हुए भीतर खालीपन ढोना, त्योहारों में भी मन का भारी रह जाना- ये अनुभव कठिन होते हैं, लेकिन निरर्थक नहीं।

समय के साथ स्मृतियों का स्वर बदलने लगता है। विद्यार्थी जीवन में भविष्य को लेकर जन्म लेते सपने, पहली बार मंच पर बोलते समय कांपती आवाज, परीक्षा से पहले की बेचैन रातें- ये अनुभव भीतर कहीं स्थायी निशान छोड़ जाते हैं। हर कोशिश सफल नहीं होती, हर उम्मीद पूरी नहीं होती, लेकिन कोशिश करने का साहस हमारे भीतर जड़ें जमा लेता है। जैसे किसी पेड़ को फल देने से पहले मजबूत जड़ों की जरूरत होती है, वैसे ही ये अनुभव हमें धीरे-धीरे मजबूत बनाते हैं।

जीवन में मित्रता की स्मृतियां हमेशा हल्की धूप की तरह महसूस होती हैं। कालेज की कैंटीन में साझा की गई एक काफी, बिना वजह खींची गई तस्वीरें, देर रात तक चलने वाली बातचीत- ये पल जीवन को सहज बना देते हैं। कठिन समय में बिना सवाल पूछे साथ खड़ा दोस्त या उदासी में अचानक आया खुशखबरी का संदेश- ये छोटी-सी चीजें जीवन को रोशन कर देती हैं। समय और दूरी भले ही लोगों को अलग कर दे, लेकिन उनकी हंसी की गूंज स्मृतियों में हमेशा बनी रहती है।

कुछ स्मृतियां मौन में पनपती हैं। वे क्षण, जब शब्द कम और विचार अधिक होते हैं। बस की खिड़की से बाहर देखते हुए पुराने दिनों में खो जाना, किसी को फोन करने की इच्छा होकर भी न कर पाना, देर रात पुराने संदेशों को बार-बार पढ़ना- ये स्मृतियां शोर नहीं करतीं, लेकिन भीतर बहुत कुछ कह जाती हैं। यही मौन कई बार हमें स्वयं से मिलवाता है। और फिर जीवन हमें उन स्मृतियों से भी परिचित कराता है, जो पीड़ा लेकर आती हैं। किसी अपने की कठोर बात, बहुत चाहा हुआ अवसर हाथ से निकल जाना, या सही होते हुए भी अपनी बात न सुना पाना- इन क्षणों में दर्द गहरा होता है। लगता है जैसे सब कुछ बिखर गया हो, लेकिन समय के साथ वही पीड़ा हमें मजबूत बनाती है। वह हमें सावधान होना सिखाती है, अपनी कीमत पहचानना सिखाती है। ये स्मृतियां हमें तोड़ती नहीं, बल्कि गढ़ती हैं।

कुछ यादें जीवन की सबसे गहरी परतों में छिपी होती हैं। प्रिय व्यक्ति को खोने का दुख, टूटे हुए रिश्ते, या ऐसा दर्द जिसे शब्द नहीं मिलते। बाहर से मुस्कुराते हुए भीतर खालीपन ढोना, त्योहारों में भी मन का भारी रह जाना- ये अनुभव कठिन होते हैं, लेकिन निरर्थक नहीं। अंधेरा ही हमें प्रकाश का मूल्य समझाता है। इन्हीं स्मृतियों से संवेदनशीलता जन्म लेती है और भीतर एक नई शक्ति आकार लेती है। यह अंत नहीं होता, बल्कि भीतर से फिर उठ खड़े होने की शुरुआत होती है। जैसे-जैसे जीवन आगे बढ़ता है, स्मृतियां जिम्मेदारी का रूप लेने लगती हैं। पहली बार घर के खर्च की चिंता, बड़ों की सेहत की जिम्मेदारी, या परिवार के लिए अपनी इच्छाओं को पीछे रखना- ये अनुभव जीवन की वास्तविकता से परिचय कराते हैं। पहली तनख्वाह से घर के लिए कुछ लाने की खुशी या थकान के बावजूद कर्तव्य निभाने के संतोष की स्मृति हमें जमीन से जोड़े रखती हैं।

कुछ स्मृतियां ऐसी होती हैं, जो समय के साथ और अधिक मूल्यवान होती जाती हैं। मां का निस्वार्थ त्याग, पिता की बिना कहे दी गई सुरक्षा, शिक्षक का एक विश्वासभरा वाक्य, या कठिन समय में किसी अनजान व्यक्ति की मदद। धीरे-धीरे समझ आता है कि जीवन की सच्ची संपत्ति पद, पैसा या उपलब्धियां नहीं, बल्कि यही स्मृतियां हैं, जो मन में कभी फीकी नहीं पड़तीं।

जीवन वास्तव में एक विशाल चित्र है और उसे रंग देती हैं हमारी स्मृतियां। उजाला भी, छाया भी। केवल सुख की हर रंग आवश्यक है- यादें नहीं, दुख की स्मृतियां भी हमें पूर्ण बनाती हैं।

हम स्मृतियों को चुन नहीं सकते। वे जीवन की यात्रा में स्वयं जुड़ती जाती हैं। कुछ को हम सहेजकर रखते हैं, कुछ को भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी स्मृति पूरी तरह मिटती नहीं। कभी-कभी हम कहते हैं कि यह याद नहीं चाहिए, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर वही स्मृति हमें सही दिशा दिखाती हुई मिलती है। बिना पीड़ा के संवेदना अधूरी है, बिना मौन के आत्म-परिचय असंभव। जब सभी रंग एक साथ होते हैं, तभी जीवन का चित्र संपूर्ण बनता है। और शायद जीवन का अर्थ भी वहीं से शुरू होता है।

शक्ति का संतुलन

मध्यपूर्व में शक्ति संतुलन कुछ प्रमुख महाशक्तियों के हितों और उनके साझेदार देशों के आसपास केंद्रित रहा है। इन देशों की ताकत सैन्य क्षमता, ऊर्जा संसाधनों, अर्थव्यवस्था, भू-राजनीतिक स्थिति और कूटनीतिक प्रभाव से तय होती है। इस क्षेत्र में अमेरिका का प्रभाव पिछले कई दशकों से अंतरराष्ट्रीय राजनीति का एक महत्त्वपूर्ण पहलू रहा है। विशाल तेल संसाधन और सामरिक शक्ति के कारण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही अमेरिका इस क्षेत्र में अपनी आर्थिक और सैन्य उपस्थिति को मजबूत करता रहा। उसने क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए कई देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी विकसित की है। मध्यपूर्व में अमेरिका का बढ़ता प्रभाव क्षेत्रीय संकटों का एक प्रमुख कारण माना जाता है। अमेरिका ने अपने सामरिक, आर्थिक और राजनीतिक हितों के लिए इस क्षेत्र की राजनीति में लगातार हस्तक्षेप किया है। इससे स्थानीय शक्ति संतुलन प्रभावित हुआ है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को आशंका है कि यदि ईरान परमाणु हथियार क्षमता हासिल कर लेता है, तो मध्यपूर्व में शक्ति संतुलन बदल सकता है।

- शाहिद हाशमी, अमेठी

गौरैये की फिक्र

गौरैया कभी हमारे घर-आंगन की पहचान हुआ करती थी। आज वह अपने अस्तित्व की आखिरी लड़ाई लड़ रही है। यह चिड़िया मानव के करीब रहना पसंद करती है, लेकिन शहरीकरण, पेड़ों की कमी, मोबाइल टावरों का बढ़ते जाल और पर्यावरणीय बदलावों ने इसके प्राकृतिक आवास को नष्ट कर दिया है। इससे इसकी संख्या में भारी कमी देखी जा रही है। आज बहुत कम गौरैया शेष रह गई हैं। यह मनुष्य की मित्र है और वह उसके आसपास ही घोंसला बना कर रहती आई है। गौरैया को बचाने के लिए हमें विशेष प्रयास करने होंगे। घरों की छतों और आंगन में पानी एवं दाना रखना चाहिए। उनके लिए कृत्रिम घोंसले बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। ये छोटे-छोटे कदम बड़े बदलाव का आधार बन सकते हैं। गौरैया के संरक्षण के लिए केवल गोष्ठियां और कार्यशालाएं आयोजित करना काफी नहीं, हमें जमीनी स्तर पर काम करना होगा।

- हिमांशु शेखर, गयाजी

ईंधन का संकट

ईरान तथा इजराइल-अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध से सभी चिंतित हैं। दुनिया भर की नजर मध्यपूर्व पर है, जहां हालात दिन-प्रति-दिन बिगड़ते जा रहे है। होर्मुज जलमार्ग से जहाजों की आवाजाही पर युद्ध की छाया है। इसका प्रभाव कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति पर पड़ा है। भारत में भी इसका असर नजर आ रहा है। रसोई गैस की कमी देश भर में देखी जा रही है। लोग चिंतित हैं कि अगर संकट बढ़ा, तो स्थिति से कैसे निपटेंगे। सबसे ज्यादा प्रभावित प्रवासी मजदूर वर्ग है, जो अपने घर से दूर किसी दूसरे शहर में रोजगार के लिए गए हैं। उन्हें रसोई गैस की किल्लत में जैसे-तैसे गुजारा करना पड़ रहा है। जमाखोरी और कालाबाजारी ने समस्या और जटिल कर दी है। कहीं-कहीं तो दोगुनी-तिगुनी कीमत देने पर भी रसोई गैस नहीं मिल रही। सरकार को इस पर गंभीरता से ध्यान देना होगा कि अगर आम लोग महंगे दाम में रसोई गैस खरीदेंगे, तो उनकी बाकी जरूरतें कैसे पूरी होंगी?

- अभिषेक जैसवाल, मैंहर, मप्र

समानता का सवाल

भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। इसका अर्थ है कि किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन व्यवहार में अक्सर इसका उल्टा देखने को मिलता है। चुनाव आते ही कई राजनीतिक दल जाति और धर्म के आधार पर लोगों को बांट कर अपना वोट बैंक मजबूत करने में लग जाते हैं। इस तरह की राजनीति समाज में दूरी और अविश्वास बढ़ाती है। कई बार कानून और नीतियों को भी लोग अपने-अपने नजरिए से देखने लगते हैं। जैसे नागरिकता संशोधन कानून को लेकर एक वर्ग में धर्म के आधार पर चिंता देखने को मिली थी, वहीं यूजीसी से जुड़े फैसलों को लेकर कुछ जाति और वर्गों में असंतोष नजर आया। ऐसे में लोगों को चाहिए कि वे धर्म से ऊपर उठ कर ऐसे प्रतिनिधि चुनें, जो विकास पर ध्यान दें।

- मो नैयर आजम, सीतामढ़ी

तथ्य

अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की रपट 'भारत में कामकाज की स्थिति-2026' में कहा गया है कि भारत में 20 से 29 वर्ष के बेरोजगार युवाओं में स्नातकों की संख्या पिछले दो दशकों में दोगुनी से अधिक हो गई है। 2023 में लगभग 67 फीसद बेरोजगार युवा स्नातक थे, जबकि 2004 में यह आंकड़ा केवल 32 फीसद था। इस दौरान हर साल करीब 50 लाख नए स्नातक जुड़े, लेकिन रोजगार के अवसर केवल 28 लाख को ही मिले, जिनमें से मात्र 17 लाख को स्थायी वेतनभोगी नौकरी मिली। रपट ने स्पष्ट किया कि शिक्षा बढ़ने के बावजूद रोजगार की गति उसके अनुरूप नहीं बढ़ी है।

एनसीईआरटी : कक्षा 10-11 की नई किताबें 2027-28 से बदलेगी

स्कूल शिक्षा में बड़े बदलाव के तहत एनसीईआरटी ने नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पाठ्यक्रम और किताबों को लेकर अहम जानकारी दी है। इसके मुताबिक कक्षा 10 और 11 के लिए नई किताबें सत्र 2027-28 से लागू होंगी, जबकि 2026-27 सत्र में इन कक्षाओं के छात्र पुरानी किताबों से ही पढ़ाई जारी रखेंगे। एनसीईआरटी ने बताया कि बदलाव चरणबद्ध तरीके से लागू किए जा रहे हैं। कक्षा 1 से 8 तक की नई किताबें पहले ही तैयार की जा चुकी हैं और ये प्रिंट के साथ-साथ डिजिटल रूप में भी उपलब्ध हैं। इन पुस्तकों को राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2023 के आधार पर तैयार किया गया है, ताकि पढ़ाई को अधिक व्यावहारिक और छात्र-केंद्रित बनाया जा सके।

सूचनापट्ट

आइआइएसईआर

इंडियन इंस्टीट्यूट्स आफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च (आइआइएसईआर) ने पांच अप्रैल 2026 से आइआइएसईआर एप्टीट्यूड टेस्ट 2026 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 13 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। सामान्य/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 2,000 रुपए और आरक्षित श्रेणी व दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 1,000 रुपए है। विदेशी उम्मीदवारों के लिए शुल्क 12,000 रुपए है। पात्रता के लिए 2024, 2025 में 12वीं उत्तीर्ण या 2026 में परीक्षा दे रहे अभ्यर्थियों का जीव विज्ञान, रसायन, गणित और भौतिक विज्ञान में कम से कम तीन विषयों में न्यूनतम 60 फीसद अंक होना जरूरी है। सुधार की विंडो 16 से 18 अप्रैल तक खुलेगी। परीक्षा 7 जून को कंप्यूटर आधारित होगी।

अंतिम तिथि : 13 अप्रैल, 2026

यूपीटीईटी

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी) 2026 को लेकर महत्त्वपूर्ण सूचना जारी की है। प्राथमिक (कक्षा 1 से 5) और उच्च प्राथमिक (कक्षा 6 से 8) स्तर के लिए परीक्षा की अधिसूचना 20 मार्च 2026 से आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। आनलाइन पंजीकरण और आवेदन प्रक्रिया 27 मार्च 2026 से शुरू होगी, जबकि आवेदन और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 26 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई है। आवेदन में संशोधन तथा शुल्क समायोजन की अंतिम तिथि 1 मई 2026 तय की गई है। इस बार अभ्यर्थियों के लिए एक बार पंजीकरण व्यवस्था लागू की गई है, जिसे पूरा करना अनिवार्य होगा। परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई 2026 को आयोजित की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थियों को दिशा-निर्देश ध्यानपूर्वक पढ़कर ही आवेदन करना चाहिए।

अंतिम तिथि : 26 अप्रैल, 2026

केवीएस प्रवेश

केंद्रीय विद्यालय संगठन ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बालवाटिका और कक्षा 1 में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभिभावक अब अपने बच्चों के लिए केवल आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 20 मार्च 2026 से शुरू होकर 2 अप्रैल 2026 रात 11:59 बजे तक चलेगी। आवेदन करने के लिए केवीएस के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करना आवश्यक है और बच्चे व अभिभावक से जुड़ी सभी जानकारी सावधानीपूर्वक भरनी होगी। गलत जानकारी देने पर आवेदन निरस्त हो सकता है। बालवाटिका प्री-प्राइमरी और कक्षा 1 प्राथमिक स्तर के लिए है। कक्षा 2 से ऊपर (कक्षा 11 को छोड़कर) में प्रवेश आफलाइन रिक्त सीटों के आधार पर होगा।

अंतिम तिथि : 2 अप्रैल, 2026

आइआइटी दिल्ली

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने वर्ष 2026 के लिए ग्रीष्मकालीन शोध फेलोशिप हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन प्रक्रिया 16 मार्च से शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 3 अप्रैल 2026 निर्धारित है। यह आठ सप्ताह का कार्यक्रम 13 मई से 13 जुलाई 2026 तक चलेगा, जिसमें चयनित विद्यार्थी विशेषज्ञ शिक्षकों के मार्गदर्शन में शोध कार्य करेंगे। इसमें वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने अभियांत्रिकी स्नातक के दो वर्ष पूरे कर लिए हों या परास्नातक के प्रथम सत्र में न्यूनतम 70 फीसद अंक प्राप्त किए हों। चयनित छात्रों को प्रति सप्ताह 2000 रुपए भत्ता, यात्रा व्यय तथा आवास-भोजन की सुविधा दी जाएगी।

अंतिम तिथि : 3 अप्रैल, 2026

यूपीएससी फार्मासिस्ट

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने फार्मासिस्ट भर्ती 2026 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 29 मार्च 2026 निर्धारित की गई है। यह भर्ती उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अंतर्गत फार्मासिस्ट के कुल 560 पदों को भरने के लिए आयोजित की जा रही है। आयोग के अनुसार आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इस भर्ती में वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने प्रारंभिक पात्रता परीक्षा 2025 में भाग लिया है और जिनके पास वैध स्कोरकार्ड है। चयन मुख्य परीक्षा के लिए पीईटी स्कोर के आधार पर किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता के रूप में उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से फार्मेसी में डिप्लोमा होना चाहिए और उत्तर प्रदेश राज्य फार्मेसी परिषद में पंजीकरण जरूरी है। आवेदन शुल्क सभी वर्गों के लिए 25 रुपए रखा गया है।

अंतिम तिथि : 29 मार्च, 2026

आपूर्ति श्रृंखला : युवा रोजगार का भविष्य

विशेषज्ञ की कलम से

भारत की अर्थव्यवस्था जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, उसमें एक अदृश्य लेकिन बेहद महत्त्वपूर्ण भूमिका है आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की। यह वह व्यवस्था है जो किसी भी उत्पाद की पूरी यात्रा तय करती है। कच्चे माल की खरीद से लेकर तैयार वस्तु को ग्राहक तक पहुंचाने तक। इसी पूरी प्रक्रिया को सुचारु रूप से चलाने का काम करता है लाजिस्टिक तंत्र। यानी, अगर आपूर्ति श्रृंखला एक योजना है, तो लाजिस्टिक उसका क्रियान्वयन है। दोनों एक-दूसरे के बिना अधूरे हैं। राष्ट्रीय लाजिस्टिक नीति भी इसी समन्वय को मजबूत करने पर जोर देती है, ताकि देश में तेज, सस्ता और विश्वसनीय परिवहन एवं वितरण तंत्र विकसित हो सके।

आज भारत का लाजिस्टिक क्षेत्र 22 से 25 मिलियन लोगों को रोजगार दे रहा है और 2030 तक इसमें 47 लाख नए रोजगार जुड़ने की संभावना है। भारत का लाजिस्टिक्स बाजार वर्तमान में लगभग 250-350 अरब अमेरिकी डालर का है। तेजी से बढ़ते ई-कामर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश और सरकारी योजनाओं के कारण इसमें मजबूत वृद्धि हो रही है। अगले दो वर्षों में यह बाजार बढ़कर लगभग 400-450 अरब डालर तक पहुंचने की संभावना है, जो अर्थव्यवस्था को और गति देगा।

> आज भारत का लाजिस्टिक क्षेत्र 22 से 25 मिलियन लोगों को रोजगार दे रहा है और 2030 तक इसमें 47 लाख नए रोजगार जुड़ने की संभावना है।

कैसे जुड़े हैं दोनों क्षेत्र

आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पूरी रणनीति बनाता है-कितना उत्पादन होगा, कहां भंडारण होगा और किस बाजार में माल भेजना है। इसके बाद लाजिस्टिक उस योजना को जमीन पर उतारता है-यानी माल की ढुलाई, गोदाम प्रबंधन और समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करता है। इस तरह, जहां आपूर्ति श्रृंखला 'सोच' है, वहीं लाजिस्टिक 'कार्रवाई' है।

क्यों चुनें यह क्षेत्र

हर उद्योग, चाहे वह विनिर्माण हो, खुदरा व्यापार, रक्षा या आनलाइन व्यापार- सभी की रीढ़ लाजिस्टिक है। कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पाद को ग्राहक तक पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया इसी पर निर्भर करती है। यदि यह तंत्र रुक जाए तो पूरा व्यवसाय ठप हो सकता है। इसलिए इस क्षेत्र में कुशल लोगों की हमेशा मांग रहती है। साफ है कि आने वाले समय में लाजिस्टिक क्षेत्र ग्तेजी से बढ़ता करिअर विकल्प बन सकता है।

प्रमुख पाठ्यक्रम और योग्यता

इस क्षेत्र में करिअर बनाने के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण की एक स्पष्ट दिशा है। स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों के लिए उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना आवश्यक है। वहीं, स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश पाने के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री जरूरी होती है। कुछ उच्चस्तरीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर की प्रवेश परीक्षाओं में सफलता भी आवश्यक होती है। इन परीक्षाओं में सीएटी, एक्सएटी, सीएमएटी, एमएटी, स्नैप, एटीएमए और एनएमएटी जैसे विकल्प शामिल हैं। शैक्षिक पाठ्यक्रम भी इस क्षेत्र में करिअर बनाने की तैयारी के लिए विविध हैं। छात्रों के लिए प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, स्नातक डिग्री, स्नातकोत्तर डिप्लोमा और एमबीए जैसे विकल्प उपलब्ध हैं। विशेष रूप से आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और आजिस्टिक में विशेषज्ञता वाले एमबीए पाठ्यक्रमों में छात्रों को संचालन प्रबंधन, भंडारण, माल सूची नियंत्रण, गुणवत्ता प्रबंधन और आपूर्ति श्रृंखला विश्लेषण जैसे विषयों में व्यावहारिक अनुभव दिया जाता है।

युवाओं के लिए अवसर

लाजिस्टिक केवल सामान ढुलाई तक सीमित नहीं है। इसमें योजना बनाना, भंडारण, खरीद, वितरण और विश्लेषण जैसे कई महत्त्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। प्रमुख भूमिकाओं में आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधक, गोदाम प्रबंधक, परिवहन विश्लेषक, माल सूची प्रबंधक, खरीद प्रबंधक और सलाहकार जैसी नौकरियां शामिल हैं। युवाओं में समस्या समाधान की क्षमता, समय प्रबंधन, टीम वर्क और दबाव में काम करने की योग्यता होना जरूरी है।

- आशीष झा, *करिअर परामर्शदाता*

जानें-सीखें

एक अप्रैल से पैन के बदलेंगे नियम, जानें पूरी प्रक्रिया

यदि आपने अभी तक पैन नहीं बनवाया है, तो यह समाचार आपके लिए महत्त्वपूर्ण है। आयकर विभाग की वर्तमान व्यवस्था के अनुसार अभी केवल आधार के माध्यम से घर बैठे पैन बनवाया जा सकता है। लेकिन एक अप्रैल 2026 से नियमों में परिवर्तन होने जा रहा है, जिसके बाद यह प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक जटिल हो सकती है।

वर्तमान में पैन बनवाने के लिए किसी अतिरिक्त प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। केवल आधार संख्या और उससे जुड़े चल मोबाइल नंबर के माध्यम से पहचान सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर कुछ ही समय में पैन प्राप्त किया जा सकता है। यह सुविधा पूरी तरह घर बैठे, बिना किसी शुल्क के और अत्यंत सरल है। इसलिए जानकारों का कहना है कि लोगों को इस अवसर का लाभ तुरंत उठा लेना चाहिए। नए नियम लागू होने के बाद पैन बनवाने के लिए अतिरिक्त प्रमाण प्रस्तुत करने पड़ सकते हैं, जिनमें जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज शामिल हो सकते हैं। इससे न केवल प्रक्रिया लंबी हो सकती है, बल्कि लोगों को अधिक औपचारिकताएं भी पूरी करनी पड़ेंगी। 'एक्स' पर सीएससी ई-गवर्नेंस द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, एक अप्रैल 2026 से पैन बनवाने के लिए केवल आधार पर्याप्त नहीं होगा। आवेदकों को अब जन्म तिथि और पहचान के लिए अतिरिक्त प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। इनमें जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, दसवीं की अंकतालिका या प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र, पासपोर्ट जैसे दस्तावेज शामिल हो सकते हैं।

आवेदन की प्रक्रिया क्या है

पैन बनवाने की प्रक्रिया बहुत सरल है। इसके लिए आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर त्वरित पैन सेवा का विकल्प चुनना होगा। इसके बाद नया पैन प्राप्त करें पर जाकर अपनी 12 अंकों की आधार संख्या दर्ज करें। इसके पश्चात आधार से जुड़े चल मोबाइल नंबर पर एक गुप्त संकेत संख्या प्राप्त होगी। उसे दर्ज करते ही आपकी जानकारी अपने आप भर जाएगी। सत्यापन के बाद जैसे ही आप प्रेषित करेंगे, थोड़ी ही देर में आपका पैन तैयार हो जाएगा, जिसे आप तुरंत प्राप्त भी कर सकते हैं। पावर स्किल्स की सबसे खास बात यह है कि ये किसी एक काम या क्षेत्र तक सीमित नहीं होतीं, बल्कि हर नौकरी, प्रोजेक्ट और इंडस्ट्री में समान रूप से उपयोगी होती हैं। कार्नेगी फाउंडेशन की 1918 की एक प्रसिद्ध रिपोर्ट भी यही बताती है कि किसी पेशेवर की सफलता में ज्यादा योगदान उसके व्यक्तित्व और संवाद कौशल का होता है, जबकि तकनीकी ज्ञान की भूमिका अपेक्षाकृत कम होती है। इसी कारण आज के नियोक्ता ऐसे पेशेवरों को ज्यादा महत्व देते हैं, जिनके पास मजबूत पावर स्किल्स हों, क्योंकि यही कौशल संगठन की प्रगति और बेहतर प्रदर्शन में अहम भूमिका निभाते हैं।

युवा शक्ति डेस्क

जागरूकता

वाराणसी के नमो घाट पर 'फिट इंडिया मूवमेंट' के अंतर्गत आयोजित साइकिल रैली में भाग लेते प्रतिभागी।

युवाओं के लिए सफलता का मूल मंत्र : समझ, संतुलन और सहयोग

परामर्श

आज के समय में केवल ज्ञान या धन अर्जित करना ही सफलता की गारंटी नहीं है। यदि आप जीवन और कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको लोगों और काम के बीच सही संतुलन बनाना सीखना होगा। इसके लिए भावनाओं को समझने की क्षमता, नैतिक दृष्टि और दूसरों के साथ मिलकर काम करने का गुण अत्यंत आवश्यक है। यही वे मानवीय गुण हैं, जो आपको एक अच्छा मार्गदर्शक और जिम्मेदार व्यक्ति बनाते हैं।

सबसे पहले बात करते हैं परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने की। बदलते समय के साथ चलना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसका अर्थ केवल बदलाव को स्वीकार करना नहीं, बल्कि नई परिस्थितियों में सही सोच विकसित करना, त्वरित और उचित निर्णय लेना तथा उसी अनुसार कार्य करना है। आज का युवा अनेक चुनौतियों, बाजार के उतार-चढ़ाव और नई तकनीकों का सामना कर रहा है। जो व्यक्ति इन परिवर्तनों को अवसर के रूप में देखता है, वही आगे बढ़ता है। अब बात आती है मिल-जुलकर काम करने की। दूसरों की भावनाओं को समझना और उनका सम्मान करना एक महत्वपूर्ण गुण है।

जब आप अपने साथियों की बात ध्यान से सुनते हैं, उनके दृष्टिकोण को समझते हैं और उनकी परिस्थितियों का सम्मान करते हैं, तब विश्वास का वातावरण बनता है। इससे न केवल संबंध मजबूत होते हैं, बल्कि कार्यस्थल पर सकारात्मकता और सहयोग भी बढ़ता है।अंत में, समान अवसर और सम्मान का महत्व समझना जरूरी है। हर व्यक्ति अलग है, उसकी सोच और अनुभव अलग हैं। जब आप सभी को बराबरी का अवसर देते हैं और खुले मन से उनकी बात सुनते हैं, तब नए विचार जन्म लेते हैं और बेहतर निर्णय संभव होते हैं।

सीबीएसई : 10वीं के विद्यार्थियों की दूसरी परीक्षा मई में

जरूरी जानकारी

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा दसवीं के विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2026 की दूसरी बोर्ड परीक्षा से जुड़ी महत्त्वपूर्ण जानकारी जारी की है। इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को अपने अंकों में सुधार करने का एक अतिरिक्त अवसर देना है। अब वे छात्र जो अपने परिणाम से संतुष्ट नहीं हैं, अधिकतम तीन विषयों में दोबारा परीक्षा दे सकेंगे। यह परीक्षा मई 2026 में आयोजित की जाएगी, जिससे छात्रों को बिना अधिक दबाव के बेहतर प्रदर्शन का मौका मिल सके।

बोर्ड ने उम्मीदवारों की सूची जमा करने की प्रक्रिया को तीन चरणों में विभाजित किया है। पहला चरण 18 मार्च से 31 मार्च 2026 तक चलेगा। दूसरा चरण परिणाम घोषित होने के बाद पांच दिनों तक खुला रहेगा। तीसरे चरण में परिणाम जारी होने के सात दिन बाद दो दिनों की विलंब शुल्क अवधि दी जाएगी। सभी विद्यालयों को निर्धारित समय के भीतर शुल्क जमा कर प्रक्रिया पूरी करनी होगी, क्योंकि अंतिम तिथि के बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

परीक्षा शुल्क भी निर्धारित किया गया है। भारत में पढ़ने वाले छात्रों के लिए प्रति विषय 320 रुपए शुल्क रखा गया है। नेपाल के छात्रों के लिए यह शुल्क 1100 रुपए प्रति विषय और अन्य देशों के छात्रों के लिए 2200 रुपए प्रति विषय तय किया गया है। यदि कोई छात्र निर्धारित समय में आवेदन नहीं कर पाता है, तो उसे 2000 रुपए का अतिरिक्त विलंब शुल्क देना होगा। बोर्ड ने विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए हैं कि वे छात्रों और अभिभावकों को इस नई व्यवस्था की सही जानकारी दें। साथ ही यह भी समझाएं कि किन छात्रों के लिए दूसरी परीक्षा देना लाभदायक रहेगा। परीक्षा केंद्र सीमित होने के कारण कुछ छात्रों को नजदीकी शहरों में जाकर परीक्षा देनी पड़ सकती है।

> पहला चरण 31 मार्च तक। दूसरा चरण परिणाम घोषित होने के बाद पांच दिनों तक खुला रहेगा। तीसरे में परिणाम जारी होने के सात दिन बाद दो दिनों की विलंब शुल्क अवधि दी जाएगी।

पात्रता के अनुसार, वही छात्र इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं जिन्होंने पहली परीक्षा में कम से कम तीन विषयों में भाग लिया हो। सुधार परीक्षा के लिए उत्तीर्ण होना आवश्यक है, जबकि कंपार्टमेंट श्रेणी के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। वहीं, जो छात्र तीन या अधिक विषयों में असफल रहे हैं या आवश्यक पुनः परीक्षा श्रेणी में आते हैं, वे इस अवसर का लाभ नहीं उठा सकेंगे।

जेईई मुख्य सत्र-2 परीक्षा तिथियों में बदलाव, नई समय-सारिणी जारी

राष्ट्रीय परीक्षा एजंसी (एनटीए) ने जेईई मेन सत्र-2 की परीक्षा तिथियों में संशोधन करते हुए नई तारीखों की घोषणा कर दी है। साथ ही अभ्यर्थियों के लिए सिटी सूचना पर्ची भी जारी कर दी गई है, जिससे वे अपनी परीक्षा के शहर की जानकारी पहले ही प्राप्त कर सकें। अब यह परीक्षा 2 अप्रैल से 8 अप्रैल 2026 के बीच आयोजित की जाएगी, जबकि पहले इसकी अवधि 2 से 9 अप्रैल तक निर्धारित थी। परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी।नई समय-सारिणी के अनुसार, बीई और बीटेक (पेपर 1) की परीक्षाएं 2, 4, 5, 6 और 8 अप्रैल को होंगी, जबकि बीआर्क और बीप्लानिंग (पेपर 2) की परीक्षा 7 अप्रैल 2026 को आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी अपनी सिटी सूचना पर्ची आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन संख्या और पासवर्ड के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं।

यह पर्ची केवल परीक्षा शहर की जानकारी देती है, ताकि उम्मीदवार पहले से यात्रा और ठहरने की तैयारी कर सकें। परीक्षा देश के विभिन्न शहरों के साथ विदेश के 15 शहरों में भी आयोजित की जाएगी। प्रवेश पत्र जल्द जारी होगा, जिसमें परीक्षा केंद्र, समय और आवश्यक निर्देश दर्ज होंगे। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र ले जाना अनिवार्य है, जबकि सिटी पर्ची केवल जानकारी के लिए होती है।

2021 चुनाव में हिंदू-मुसलिम ध्रुवीकरण का तृणमूल को मिला था फायदा

ध्रुवीकरण का मुद्दा बरकरार, बदल गई भाषा

जनसत्ता ब्यूरो

पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा में एक बार फिर मतदाताओं को सांप्रदायिक आधार पर बंटते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इस बार इसकी भाषा अलग है। 2021 के विधानसभा चुनाव में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) की आशंका से मतदाताओं में तीखे मतभेद उभरकर सामने आए थे। इस बार विशेष गहन संशोधन (एआइआर) के इर्द गिर्द मौजूदा राजनीतिक घूम रही है। इसके साथ ही 'अल्पसंख्यक तुष्टिकरण' और 'घुसपैठ' जैसे पुराने मुद्दों पर भी कुछ जगहों पर चर्चा है।

पश्चिम बंगाल, एक ऐसा राज्य है जहां 2011 की जनगणना के अनुसार 27 फीसद से अधिक मुसलिम आबादी है। ऐसे में बंगाल के अल्पसंख्यक-बहुल जिले एक बार फिर चुनावी नतीजों में अहम भूमिका निभा सकते हैं। जानकारों का कहना है कि 2021 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर गौर करें तो यह शायद दशकों में सांप्रदायिक आधार पर प्रदेश का सर्वाधिक ध्रुवीकृत चुनाव माना जा सकता है। इस तरह के ध्रुवीकरण को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के पक्ष में

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव

25 फीसद से अधिक मुसलिम आबादी वाली 80 फीसद सीट पर हासिल की थी जीत।

2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य में 27 फीसद से अधिक आबादी।

एक बार फिर चुनावी नतीजों में अल्पसंख्यक-बहुल सीटें निभा सकती हैं अहम भूमिका।

निर्णायक भूमिका के तौर पर अहम माना गया था। मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, बीरभूम, दक्षिण 24 परगना, नदिया, हावड़ा, उत्तर 24 परगना और कूचबिहार समेत प्रदेश के नौ जिलों में मुसलिमों की आबादी 25 फीसद से अधिक है। पिछले चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 160 में से 127 सीटें जीतीं, जो करीब 80 फीसद की सफलता दर है। भाजपा को 32 सीट मिली थी, जिनमें करीब 50 फीसद सीट कूचबिहार और नदिया जिले की थीं। इसके उलट, 25 फीसद से कम मुसलिम आबादी वाले 14 अन्य जिलों में तृणमूल का प्रदर्शन अपेक्षाकृत सफलता दर की थी, हालांकि सत्तारूढ़ दल ने भाजपा से अच्छी बढ़त बनाए रखी।

इन जिलों में तृणमूल ने 134 में से 86 विधानसभा सीट (64 फीसद) पर जीत हासिल की थी जबकि भाजपा को 47 सीटें मिलीं। इनमें बर्धमान, पश्चिम बर्धमान, कोलकाता, हुगली, पूर्व मेदिनीपुर, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, पश्चिम मेदिनीपुर, झाड़ग्राम, बांकुरा, पुरुलिया, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और दक्षिण दिनाजपुर शामिल हैं।

तृणमूल कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, बंगाली क्षेत्रीयतावाद और उम्मीदवारों के चयन में रणनीतिक सूझबूझ की बदौलत एक पिछले चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की। पार्टी ने 2021 के चुनावों में 294 में से 213 सीट पर जीत दर्ज की थी, जिसमें कुल 48 फीसद मत मिले थे।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी एक महिला-केंद्रित राजनीतिक छवि बरकरार रखते हुए 'कन्याश्री' और 'लक्ष्मी भंडार' जैसी योजनाओं को तवज्जो देते हुए अपेक्षाकृत ज्यादा संख्या में महिला उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा।

इन वजहों से तृणमूल कांग्रेस को सभी समुदायों की महिला मतदाताओं को अपने पक्ष में एकजुट करने में मदद की। इससे पहले 2016 और 2021 के चुनावों की तुलना से पता चलता है कि तृणमूल कांग्रेस ने मुसलिम उम्मीदवारों की संख्या 54 से घटाकर करीब 45 कर दी। खास तौर पर उन निर्वाचन क्षेत्रों में जहां भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनावों में मजबूत प्रदर्शन किया था।

हलचल

असम विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए बुधवार को गुवाहाटी में ईवीएम से मतदान कराने का अभ्यास करते चुनाव अधिकारी।

बंगाल में पूजा करने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है : नवीन

भाजपा नेता नितिन नवीन ने पश्चिम बंगाल में धार्मिक गतिविधियों की अनुमति को लेकर दोहरे मानदंड अपनाए जाने का आरोप लगाते हुए बुधवार को कहा कि राज्य में नमाज अदा करने की पूरी आजादी है लेकिन पूजा आयोजित करने या पंडाल लगाने के लिए अदालत से अनुमति लेनी पड़ती है।

नवीन ने कोलकाता के बाहरी इलाके में स्थित दक्षिणेश्वर मंदिर में पूजा-अर्चना करने के बाद पत्रकारों से कहा कि यह स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है।नितिन नवीन ने कहा कि यहां नमाज अदा करने की अनुमति है लेकिन पूजा करने और पंडाल लगाने के लिए हाई कोर्ट से अनुमति मांगनी पड़ती है। नवीन ने कहा कि मैंने दक्षिणेश्वर में पूजा की और राज्य के लोगों के कल्याण तथा 'विकसित बंगाल' एवं 'सोनार बांग्ला' के निर्माण के लिए देवी से प्रार्थना की।

भाजपा खाता भी नहीं खोल पाएगी : कांग्रेस

कल्याणकारी योजनाओं से संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा को मिलेगी जीत

केरल

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बुधवार को दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) केरल में खाता नहीं खोल पाएगी और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कर्नाटक और तेलंगाना की तर्ज पर यूडीएफ (संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा) द्वारा प्रस्तावित कल्याणकारी गारंटी इस दक्षिणी राज्य में भी सफल साबित होंगी। वेणुगोपाल ने कहा कि यह केवल एक धारणा थी कि भाजपा केरल में यूडीएफ के लिए खतरा है, क्योंकि हाल के स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा को नाममात्र की सफलता मिली।

कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल ने कहा कि यह महज एक धारणा है। कुछ भी ठोस नहीं है। अभी दो महीने पहले ही स्थानीय निकाय चुनाव हुए थे। उन्हें कितने जिला पंचायत सदस्य मिले? उन्होंने कहा कि उन्हें कितनी नगरपालिकाएं मिलीं? नाममात्र की। कुछ भी ठोस नहीं है। केरल में भाजपा का खाता भी नहीं खुल सकता। जब उनसे पूछा गया कि क्या कर्नाटक और तेलंगाना विधानसभा चुनावों के दौरान किए गए कल्याणकारी वादे, जहां कांग्रेस विजयी रही, केरल में कारगर साबित होंगे, तो वेणुगोपाल ने हां में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने पांचों वादों की घोषणा करने से पहले गहन शोध किया था, जिनमें सभी महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा और कालेज जाने वाली छात्राओं को 1,000 रुपए की मासिक सहायता शामिल है। वेणुगोपाल ने

कहा कि पार्टी ने राज्य की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण किया और ये वादे इसलिए किए क्योंकि केरल जैसे प्रगतिशील राज्य में भी महिलाएं बेहद कष्ट झेल रही हैं। उन्होंने कहा कि आपको समझना होगा, जब भी वे खेतों में काम करने जाती हैं - चाहे वे कृषि मजदूर हों, मनरेगा कार्यकर्ता हों, काजू मजदूर हों या मछुआरा हों - आप देख सकते हैं कि उन पर कितना बोझ होता है। उन्होंने कहा कि उनका जीवन दयनीय हो गया है। यूडीएफ का मानना है कि हमें केरल की महिलाओं का समर्थन करना चाहिए। इसीलिए केरल की महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा चाहिए। दूसरे, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए 25 लाख रुपए का बीमा है और कल्याण पेंशन बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दी जाएगी। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में पूछे जाने पर वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी की यह परंपरा नहीं है कि वह कहीं भी किसी मुख्यमंत्री का चेहरा पेश करे। उन्होंने कहा कि यह चुनाव किसी को भी केरल का मुख्यमंत्री बनाने के बारे में नहीं है। 2016 में भी, पिनराई विजयन को केरल में एलडीएफ के मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में पेश नहीं किया गया था।

उन्होंने कहा कि इन बातों की चिंता ना करें। चुनाव के बाद, कांग्रेस तुरंत एक मुख्यमंत्री का चयन करेगी और वह अन्य लोगों के साथ मिलकर राज्य का संचालन करेगा। अलप्पुझा संसदीय क्षेत्र से सांसद वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी केरल में सार्वजनिक जीवन में बदलाव और सुशासन चाहती है और यही यूडीएफ राज्य की जनता से वादा कर रहा है। उन्होंने कहा कि यही सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने दावा किया कि राज्य के लोग बदलाव की तलाश में हैं क्योंकि वे पिछले 10 वर्षों से एलडीएफ शासन के अधीन कष्ट झेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह एलडीएफ सरकार जनविरोधी सरकार बन गई है। वेणुगोपाल ने कहा कि अब लोग सरकार में बदलाव चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि हर क्षेत्र, युवा, महिलाएं, किसान और मजदूर, सभी इस सरकार के रवैये से नाखुश हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार में व्यापक भ्रष्टाचार है और पर्यटन विभाग से वर्गीकरण प्रमाण पत्र के बिना लगभग 200 बार को लाइसेंस जारी किए जाने का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि यह भ्रष्टाचार का स्पष्ट मामला है। वेणुगोपाल ने शबरिमला सोना गायब होने के मुद्दे का भी उल्लेख किया और कहा कि यह एक और मुद्दा है जिसने राज्य के लोगों को शासन में बदलाव की मांग करने के लिए प्रेरित किया है।

द्रमुक महिला विरोधी, तृणमूल कांग्रेस गरीबों पर अन्याय करने वाली : सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में अप्रैल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बुधवार को लोकसभा में इन दोनों प्रदेशों की सरकारों पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि द्रमुक सरकार महिला विरोधी है, वहीं तृणमूल कांग्रेस की सरकार गरीबों के साथ अन्याय कर रही है। उन्होंने सदन में वित्त विधेयक, 2026 पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बयान का उल्लेख किया और कहा कि द्रमुक सरकार महिलाओं के खिलाफ है और इस बार महिलाओं का समर्थन उसे नहीं मिलेगा। उनका कहना था कि महिला आरक्षण विधेयक का विरोध किया जा रहा है। सीतारमण ने आरोप लगाया कि तमिलनाडु की द्रमुक सरकार महिलाओं के खिलाफ है। उसे महिलाओं का समर्थन नहीं मिलेगा। जब कुछ विपक्षी दलों ने आपत्ति जताई तो वित्त मंत्री ने कहा कि यह शर्मनाक है कि विपक्षी दलों के लोग द्रमुक के समर्थन में खड़े हैं। द्रमुक सदस्यों के सदन में मौजूद नहीं रहने को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि जब भी मैं बोलती हूं तो द्रमुक के सदस्य सदन में नहीं बैठते हैं। यह पहली बार नहीं हुआ है। तृणमूल कांग्रेस भी ऐसा ही करती है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने मंगलवार को केंद्र से जून में संसद का विशेष सत्र बुलाने का अनुरोध किया ताकि परिसीमन, सीट वृद्धि और राज्यों के प्रतिनिधित्व के वर्तमान हिस्से को तीस वर्षों तक जारी रखने की गारंटी के लिए संवैधानिक संशोधन पारित किए जा सके। (ए)

जनसंपर्क

गुवाहाटी मध्य में बुधवार को असम जातीय परिषद (एजेपी) की उम्मीदवार कुन्की चौधरी चुनाव प्रचार करती हुईं।

'कांग्रेस नेतृत्व केरल में अगले मुख्यमंत्री का फैसला करेगा'

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश चेन्निथला ने कहा है कि केरल में कांग्रेस के पास राज्य का नेतृत्व करने में सक्षम कई नेता हैं और यही पार्टी की ताकत है, जबकि सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) के पास मुख्यमंत्री पद के लिए केवल पिनराई विजयन का ही चेहरा है।

चेन्निथला ने एक साक्षात्कार के दौरान इस बात से इनकार नहीं किया कि वह मुख्यमंत्री पद के एक दावेदार हैं। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस की पहली प्राथमिकता विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करना है और जीत के बाद पार्टी नेतृत्व यह तय करेगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए।

यह पूछे जाने पर कि पार्टी बिना मुख्यमंत्री पद के चेहरे के चुनाव क्यों लड़ रही है, कांग्रेस की कार्यकारी समिति के सदस्य ने कहा कि हम किसी को भी मुख्यमंत्री के रूप में पेश नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी के साथ हाल ही में हुई बैठक में सभी मुद्दों पर चर्चा की थी। अपने निर्वाचन क्षेत्र हरिपाद में चुनाव प्रचार करते हुए चेन्निथला ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष (मल्लिकार्जुन खरगे) और राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्राथमिकता चुनाव जीतना है, और मुख्यमंत्री पद का फैसला बाद में

चेन्निथला ने एक साक्षात्कार के दौरान इस बात से इनकार नहीं किया कि वह मुख्यमंत्री पद के एक दावेदार हैं।

किया जाएगा। जब चेन्निथला से पूछा गया कि क्या वह केरल के मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनने की आकांक्षा रखते हैं, तो उन्होंने कहा कि यह उम्मीदवारों की आकांक्षा का सवाल नहीं है। हमारे पास एक दर्जन नेता हैं जो राज्य का नेतृत्व करने में सक्षम हैं। यही कांग्रेस पार्टी की ताकत है। उन्होंने कहा कि माकपा के पास केवल एक ही चेहरा है- पिनराई विजयन, जबकि कांग्रेस के पास ऐसे कई नेता हैं जो मुख्यमंत्री बनने के योग्य हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या कांग्रेस महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल और केरल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष वीडी सतीशन उन्हें संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में समर्थन देंगे।

केरल : एलडीएफ विधायक प्रतिभा पर यूडीएफ नेता की विवादित टिप्पणी, छिड़ा विवाद

केरल के अलप्पुझा में संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) के एक नेता ने कायमकुलम की मौजूदा विधायक और नौ अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) की उम्मीदवार यू. प्रतिभा पर निशाना साधते हुए दावा किया कि प्रतिभा तीसरी बार इस सीट से जीत हासिल करने के लिए अपनी वाक्पटुता और सुंदरता का इस्तेमाल कर रही हैं।

इंडियन यूनियन मुसलिम लीग के नेता और यूडीएफ की कायमकुलम इकाई के संयोजक ए इरशाद ने एक चुनावी सभा के दौरान प्रतिभा पर जनता के लिए कोई काम न करने का आरोप भी लगाया। लीग नेता ने प्रतिभा पर विधायक के रूप में मिलने वाली विभिन्न निधियों का अपने निर्वाचन क्षेत्र के हित में उपयोग न करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि विधायक ने जनता के प्रतिनिधि के रूप में कुछ भी नहीं किया है। अब वह (प्रतिभा) वाक्पटुता व सुंदरता का इस्तेमाल करके जीत हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। इरशाद ने लोगों से यूडीएफ उम्मीदवार एम लिजू को वोट देने का आग्रह किया ताकि प्रतिभा को तीसरी बार इस निर्वाचन क्षेत्र से जीतने से रोका जा सके। (ए)

ओवैसी-कबीर गठबंधन की अल्पसंख्यकों को साधने की कोशिश

सर्वेश कुमार

पश्चिम बंगाल में सत्ता हासिल करने की दौड़ में नए गठबंधन से सियासी समीकरण बदलने के कयास लगाए जा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर के एक साथ होने से तृणमूल कांग्रेस के लिए मुश्किलें कुछ बढ़ सकती हैं। हालांकि सियासी मामलों के जानकारों का कहना है 2026 के चुनाव में इसका असर कम हो सकता है, लेकिन भविष्य में पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस गठबंधन के मायने अलग हो सकते हैं।

बंगाल

आगामी विधानसभा चुनाव में मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर और मालदा सरीखे जिलों की कुछ सीटों पर तृणमूल को मतों का नुकसान हो

तीन जिलों में तृणमूल कांग्रेस की चुनौतियां बढ़ीं

आगामी विधानसभा चुनाव में मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर और मालदा सरीखे जिलों की कुछ सीटों पर तृणमूल को मतों का नुकसान हो सकता है, लेकिन कितनी सीटों पर जीत में तब्दील करने में गठबंधन को सफलता मिलती है, इसका फैसला मतदान की तारीख तक तमाम दलों की रणनीति और प्रचार की बदौलत जनता के बीच अपनी पैठ बनाने पर निर्भर है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआइएमआइएम और हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी (एजेयूपी) ने आधिकारिक तौर पर गठबंधन की घोषणा कर दी।

सकता है, लेकिन कितनी सीटों पर जीत में तब्दील करने में गठबंधन को सफलता मिलती है, इसका फैसला मतदान की तारीख तक तमाम दलों की रणनीति और प्रचार की बदौलत जनता के बीच अपनी पैठ बनाने पर निर्भर है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से बुधवार को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआइएमआइएम और हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी (एजेयूपी) ने आधिकारिक तौर पर गठबंधन की घोषणा कर दी। ओवैसी ने न केवल भाजपा और तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा। प्रदेश में 23 और 29 अप्रैल को मतदान होने वाला है। इस बीच हुमायूं कबीर और ओवैसी के बीच गठबंधन, आने वाले वर्षों में तमाम राजनीतिक दलों को नए सिरे से रणनीतिक समीकरण बनाने के लिए मजबूर कर सकती हैं। जानकारों का कहना है कि इस गठबंधन से प्रदेश के सियासी जंग में एक बात तो तय है कि अल्पसंख्यक मतों का कुछ हद तक बंटवारा होगा। माना जा रहा है कि भाजपा को इसका फायदा होगा, लेकिन कुछ सीटों पर तृणमूल कांग्रेस की दूसरे दलों पर जीत का अंतर कम हो सकता है।

राजनीतिक मामलों के जानकार बिश्वनाथ चक्रवर्ती ने इस गठबंधन को लेकर कहा, मध्य वर्गीय मुसलिम नेतृत्व के समर्थन से अपनी भागीदारी बढ़ाने की सोच के साथ यह गठबंधन आगे बढ़ रहा है।

जयलक्ष्मी के आंतरिक तौर पर नुकसान पहुंचाने के आरोप अनुचित : उषा विजयन

मानंतवाडी विधानसभा सीट से संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) की उम्मीदवार उषा विजयन ने बुधवार को कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पी के जयलक्ष्मी द्वारा स्थानीय पार्टी नेताओं के एक वर्ग के खिलाफ लगाए गए आंतरिक रूप से नुकसान पहुंचाने के हालिया आरोपों को अनुचित करार दिया। विजयन ने कहा कि हालांकि, मौजूदा हालात में ऐसे आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए थे, लेकिन इससे यूडीएफ और भी अधिक एकजुट हो गया है। जयलक्ष्मी ने मंगलवार को अपनी ही पार्टी के कुछ स्थानीय नेताओं के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए और कहा कि पिछले चुनावों में उनकी हार उन्हीं नेताओं द्वारा की गई साजिश के कारण हुई थी। नौ अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले वेल्लामुंडा में आयोजित संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) के सम्मेलन में उन्होंने दावा किया कि पार्टी के कुछ नेताओं ने 2016 और 2021 के विधानसभा चुनावों में मानंतवाडी निर्वाचन क्षेत्र में उनके खिलाफ काम किया था। (ए)

डिजिटल ठगी

देश की राजधानी दिल्ली आज सिर्फ राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र ही नहीं, बल्कि साइबर और वित्तीय अपराधों का भी बड़ा केंद्र दिखाई दे रही है। प्रतिदिन औसतन 50 लाख रुपये की ठगी के मामलों का सामने आना न केवल चौंकाने वाला है, बल्कि यह कानून-व्यवस्था और डिजिटल सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करता है। यह आंकड़े एक दैनिक अखबार में प्रकाशित किये गए हैं जो चौंकाने वाले दिख रहे हैं। वर्ष 2025 में 184 मामले दर्ज किये गए हैं, लगभग 70,64,80,424 रूपये (30 जून तक) तक ठग लिए गये हैं। इससे पिछले वर्ष 2024 में 1,591 मामले दर्ज हुए और 8,17,64,85,471 रूपये ठग लिए गए। आज ठगी से कैसे बचे ? अभी गैस की क्या कमी हुई ठगों ने इस आपदा को अवसर बना लिया। इस डिजिटल युग में ठगी के बढ़ते जाल से कैसे निजात मिलेगी तो विशेषज्ञों का कहना है कि जागरुकता और सतर्कता सावधानी जरूरी है। दिल्ली जैसी राजधानी में दिल्ली पुलिस अच्छा कार्य कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में तकनीक के विस्तार के साथ ठगी के तरीके भी बेहद परिष्कृत हो गए हैं। पहले जहां जेबकतरी और साधारण धोखाधड़ी आम थी, वहीं अब ऑनलाइन फ्रॉड, फर्जी कॉल, अपडेट के नाम पर ठगी, और निवेश के झांसे जैसे अपराध तेजी से बढ़े हैं। आम नागरिक, विशेषकर बुजुर्ग और डिजिटल रूप से कम जागरूक लोग, इन ठगों का आसान शिकार बन रहे हैं। दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियां लगातार जागरूकता अभियान चला रही हैं, लेकिन अपराधियों की चतुराई और तकनीकी दक्षता कई बार इन प्रयासों पर भारी पड़ती है। अपराधी अक्सर विदेशी सर्वर, फर्जी सिम कार्ड और डिजिटल वॉलेट्स का इस्तेमाल कर अपनी पहचान छिपा लेते हैं, जिससे जांच और गिरफ्तारी में कठिनाई आती है। यह स्थिति कई स्तरों पर चिंता पैदा करती है। पहला, आम जनता का डिजिटल लेनदेन पर विश्वास कमजोर होता जा रहा है। दूसरा, देश की आर्थिक सुरक्षा पर इसका असर पड़ता है। तीसरा, कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता और संसाधनों पर भी प्रश्न उठते हैं। समाधान के लिए बहुस्तरीय रणनीति आवश्यक है। सबसे पहले, साइबर अपराध से निपटने के लिए पुलिस बल को अत्याधुनिक तकनीक और प्रशिक्षण से लैस करना होगा। दूसरे, बैंकों और डिजिटल पेमेंट कंपनियों को अपनी सुरक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाना होगा। तीसरे, स्कूलों और सामाजिक मंचों के माध्यम से डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि लोग ठगी के नए-नए तरीकों से परिचित हो सकें। इसके अलावा, सरकार को सख्त कानून और त्वरित न्याय व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी, ताकि अपराधियों में डर पैदा हो। साथ ही, आम नागरिकों को भी सतर्क रहना होगा—अनजान कॉल, लिंक या ऑफर पर भरोसा करने से पहले पूरी जांच करना जरूरी है। हाल के महीनों में दिल्ली पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया। पुलिस आयुक्त के निर्देश पर संयुक्त आयुक्त रजनीश गुप्ता के नेतृत्व में ऑपरेशन साई-हॉक के तहत दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में बड़े पैमाने पर छापेमारी की गई। इस ऑपरेशन का उद्देश्य उन कॉल सेंटरों और गिरोहों को नेस्तनाबूद करना था जो फर्जी केवाईसी, लॉटरी और निवेश के नाम पर लोगों को लूटते हैं। इस कार्रवाई के बाद साइबर अपराधों की दर में गिरावट दर्ज की गई। अब जांच टीम के विस्तार से इस पकड़ को और मजबूत किया जा सकेगा। यह समझना होगा कि डिजिटल युग में सुरक्षा केवल सरकार या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो यह ठगी का जाल और भी व्यापक रूप ले सकता है, जिससे न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक विश्वास भी प्रभावित होगा। यह आंकडे तो दिल्ली के है देश भर में यह ठगी का आंकडा बड़ा भी हो सकता है। लेकिन सतर्कता सावधानी जरूरी है। डिजिटल युग ने जहां हमारी जिंदगी को आसान बनाया है, वहीं ठगों के लिए नए रास्ते भी खोल दिए हैं। आज मोबाइल, इंटरनेट और ऑनलाइन बैंकिंग के बढ़ते उपयोग के साथ डिजिटल ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हर दिन आम लोग अपनी मेहनत की कमाई साइबर अपराधियों के जाल में फंसा रहे हैं। ऐसे में यह सवाल बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि डिजिटल ठगी से कैसे बचा जाए और इस समस्या पर प्रभावी नियंत्रण कैसे हो। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि डिजिटल ठगी केवल तकनीकी समस्या नहीं, बल्कि जागरूकता की कमी का परिणाम भी है। ठग अक्सर फर्जी कॉल, मैसेज, ईमेल या लिंक के माध्यम से लोगों को भ्रमित करते हैं। आपका बैंक खाता बंद हो जाएगा, केवाईसी अपडेट करें, लॉटरी लगी है —जैसे लालच और डर पैदा करने वाले संदेश लोगों को जल्दी फैसले लेने पर मजबूर कर देते हैं। इसी जल्दबाजी का फायदा अपराधी उठाते हैं।इस समस्या से निजात पाने का पहला और सबसे प्रभावी उपाय है—जागरूकता। आम नागरिकों को यह समझना होगा कि कोई भी बैंक या सरकारी संस्था कभी भी फोन या मैसेज के जरिए पासवर्ड या नहीं मांगती। ऐसे किसी भी अनुरोध को तुरंत नजरअंदाज करना चाहिए। साथ ही, अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचना और केवल आधिकारिक वेबसाइट या ऐप का ही उपयोग करना जरूरी है।

स्त्री परमसत्ता: शक्ति के रूप में ब्रह्माण्ड की अभिव्यक्ति

डॉ. प्रभांशु ओझा
सहायक प्रोफेसर
हंसराज कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय

''इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में केवल मैं ही विद्यमान हूँ; मेरे अतिरिक्त दूसरा कौन है''—यह उद्घोषणा उस सत्ता की है जिसे सनातन परम्परा शक्ति या देवी के रूप में स्वीकार करती है। इस कथन की गहराई केवल उसके अद्वैत भाव में नहीं, बल्कि इस तथ्य में है कि यह एक स्त्री स्वर में व्यक्त हुआ है। जहाँ अनेक धार्मिक परम्पराएँ ईश्वर को पुरुष रूप में कल्पित करती हैं, वहीं भारतीय चिन्तन में परम सत्ता को स्त्री रूप में देखना केवल एक प्रतीकात्मक आग्रह नहीं, बल्कि एक व्यापक दार्शनिक प्रतिपादन है जिसमें सम्पूर्ण जगत को स्त्री-तत्त्व की अभिव्यक्ति माना गया है। यहाँ देवी कोई सीमित, पृथक, अलौकिक सत्ता नहीं, बल्कि वही ऊर्जा है जो चेतना के रूप में, प्रकृति के रूप में और समस्त अनुभवों के रूप में हमारे सामने उपस्थित है।

भारतीय धार्मिक अनुभव में देवी की सर्वव्यापकता का जो स्वरूप उभरता है, वह ''या देवी सर्वभूतेषु'' जैसे मन्त्रों में स्पष्ट दिखाई देता है, जहाँ देवी को केवल शुभ, कोमल और मंगलकारी तत्त्वों तक सीमित नहीं किया गया, बल्कि उन्हें चेतना, बुद्धि, स्मृति, श्रद्धा, शान्ति और करुणा के साथ-साथ भूख, प्यास, निद्रा, छाया और भ्रान्ति तक में प्रतिष्ठित बताया गया है। यह दृष्टि एक अत्यंत गहन दार्शनिक संकेत देती है कि इस जगत में ऐसा कोई भी तत्त्व नहीं है जहाँ देवी का अभाव हो। यहाँ तक कि जो अवस्थाएँ मनुष्य सामान्यतः नकारात्मक मानता है, वे भी उसी सार्वभौम शक्ति की अभिव्यक्तियाँ हैं। इस प्रकार संसार का प्रत्येक आयाम—चाहे वह प्रकाश हो या अन्धकार—देवी की उपस्थिति से ही अर्थपूर्ण है। इस विचारधारा में सृष्टि और सृष्टा के बीच कोई कठोर विभाजन नहीं है; देवी स्वयं जगत हैं और साथ ही उस जगत का आधारभूत चैतन्य भी हैं। वेदों में इस दृष्टि के बीज अत्यंत प्राचीन रूप में मिलते हैं। आदिति को अनन्त और सर्वव्यापी कहा गया है, जो केवल देवताओं की माता नहीं, बल्कि स्वयं सम्पूर्ण विश्व का विस्तार हैं। वे आकाश भी हैं, पृथ्वी भी हैं और उन सबके पार भी हैं। इसी प्रकार वाक्, जो स्वयं को सृष्टि की अधिष्ठात्री के रूप में उद्घोषित करती हैं, यह बताती हैं कि ज्ञान, व्यवस्था और सृजन की मूल चेतना स्त्री रूप में ही कल्पित की गई है। इन वैदिक प्रतिपादनों में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि देवी किसी पुरुष देवता की आश्रिता नहीं हैं; वे स्वतन्त्र सत्ता हैं, जो अपने बल से सृष्टि को उत्पन्न और संचालित करती हैं। यह विचार आगे चलकर पुराणों और तांत्रिक परम्पराओं में और भी स्पष्ट रूप से विकसित होता है, जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और शिव तक देवी की शक्ति के बिना निष्क्रिय माने जाते हैं।

इस दर्शन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि देवी को केवल करुणामयी माता के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे पूर्ण सत्य के रूप में देखा गया है जो सृजन और संहार दोनों को अपने भीतर समाहित करता है। ''ॐ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी'' जैसे स्तोत्रों में देवी के विविध नाम उनके विरोधाभासी प्रतीत होने वाले स्वरूपों को उद्घाटित करते हैं—वे कल्याणकारी भी हैं और संहारक भी, कोमल भी हैं और उग्र भी, क्षमा भी हैं और काल भी। इस प्रकार देवी का स्वरूप किसी एक आयाम में सीमित नहीं है, बल्कि वह जीवन और जगत की सम्पूर्णता का प्रतीक है। दशमहाविद्याओं की परम्परा में यह समग्रता और भी तीव्रता से व्यक्त होती है, जहाँ सौन्दर्य, ज्ञान, समृद्धि, शून्यता, भूख, भय और मृत्यु जैसे सभी तत्त्व देवी के विभिन्न रूपों में व्यक्त होते हैं। यहाँ यह स्पष्ट होता है कि भारतीय चिन्तन सत्य को केवल सुखद और स्वीकार्य रूपों तक सीमित नहीं करता, बल्कि वह उन पक्षों को भी स्वीकार करता है जो मनुष्य के लिए असहज या भयावह हो सकते हैं।

देवी के उग्र रूपों को लेकर आधुनिक संवेदनशीलता में जो असमंजस दिखाई देता है, वह इस बात से उत्पन्न होता है कि हम प्रकृति के यथार्थ को स्वीकार करने में संकोच करते हैं। प्रकृति केवल सौन्दर्य और सृजन का स्थल नहीं है; वह विनाश, संघर्ष और निरन्तर परिवर्तन का भी क्षेत्र है। जीवन स्वयं जीवन पर आश्रित है और इस प्रक्रिया में भक्षण, क्षय और मृत्यु अनिवार्य हैं। भूकम्प, बाढ़ और तूफान जैसी घटनाएँ यह स्मरण कराती हैं कि सृष्टि में एक ऐसा आयाम भी है जो मानवीय संवेदनाओं से परे है। देवी के उग्र और रक्तपायी रूप इसी यथार्थ के प्रतीक हैं। यह उस साहस का द्योतक है जिसके साथ प्राचीन भारतीय चिन्तन ने जीवन को उसकी सम्पूर्णता में स्वीकार किया, बिना उसे किसी कृत्रिम नैतिकता के अनुसार ढालने का प्रयास किए।

इस व्यापक दार्शनिक दृष्टि का सामाजिक प्रभाव भी अत्यंत गहरा रहा है। जब परम सत्ता को ही स्त्री रूप में देखा जाता है, तब स्त्री को स्वभावतः हीन या गौण मानने का कोई आधार नहीं रह जाता। भारतीय समाज में विभिन्न स्तरों पर देवी की उपस्थिति—कुलदेवी, ग्रामदेवी, नगरदेवी और राष्ट्र की अधिष्ठात्री शक्तियों के रूप में—यह दर्शाती है कि स्त्री-तत्त्व केवल घरेलू जीवन तक सीमित नहीं, बल्कि सार्वजनिक और राजनैतिक जीवन में भी प्रतिष्ठित रहा है। लक्ष्मी के रूप में समृद्धि, सरस्वती के रूप में ज्ञान और दुर्गा के रूप में शक्ति की कल्पना यह बताती है कि जीवन के सभी महत्वपूर्ण आयाम स्त्री के साथ जोड़े गए हैं। इतिहास में भी अनेक उदाहरण मिलते हैं जहाँ स्त्रियों ने शासन, साहित्य, आध्यात्म और युद्ध—सभी क्षेत्रों में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई। यह केवल सामाजिक संयोग नहीं, बल्कि उस सांस्कृतिक चेतना का परिणाम है जिसमें स्त्री को शक्ति का मूर्त रूप माना गया।भारतीय शाक्त दृष्टि में ब्रह्माण्ड को स्त्री स्वरूप में देखना केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं, बल्कि एक गहन दार्शनिक और अस्तित्वगत समझ है। यहाँ स्त्री और पुरुष के बीच कोई द्वन्द्व नहीं, बल्कि एक ऐसी एकात्मता है जिसमें पुरुष तत्त्व भी अन्ततः शक्ति में ही समाहित हो जाता है। देवी केवल ''माता'' नहीं हैं, बल्कि वह सम्पूर्ण सत्ता हैं—सृष्टि, स्थिति और संहार की अधिष्ठात्री। इस दृष्टि में जीवन के सभी आयाम—चाहे वे सुखद हों या दुःखद—एक ही परम सत्य के विभिन्न रूप हैं। यही समग्रता इस दर्शन को अद्वितीय बनाती है और यही वह आधार है जो स्त्री को केवल सामाजिक भूमिकाओं तक सीमित न रखकर उसे परम सत्ता के रूप में प्रतिष्ठित करता है। ऐसी दृष्टि आज के समय में न केवल दार्शनिक रूप से प्रासंगिक है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें जीवन, प्रकृति और मानव अस्तित्व को अधिक व्यापक और समावेशी दृष्टि से देखने की प्रेरणा देती है।

भारतीय चिन्तन में शक्ति की कल्पना अत्यन्त व्यापक और गहन है। यहाँ शक्ति केवल किसी देवी-देवता की सहायक सत्ता नहीं, बल्कि सम्पूर्ण सृष्टि की मूल प्रेरक शक्ति मानी गई है। यदि ब्रह्म को निष्क्रिय चेतना कहा जाए, तो शक्ति उसकी सक्रिय अभिव्यक्ति है—वही ऊर्जा जो सृष्टि को उत्पन्न करती है, उसका पालन करती है और समय आने पर उसका संहार भी करती है। इसीलिए तांत्रिक परम्परा में कहा गया है—''शिवः शक्त्या युक्तः''—अर्थात शक्ति के बिना शिव भी निष्क्रिय हैं। इस दृष्टि से सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड एक गतिशील ऊर्जा-प्रवाह है, जो निरन्तर परिवर्तनशील होते हुए भी एक ही मूल सत्ता से जुड़ा हुआ है। भारतीय परम्परा में शक्ति की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि यह समझा गया कि जीवन की प्रत्येक क्रिया—चाहे वह विचार हो, कर्म हो या सृजन—शक्ति के बिना संभव नहीं है। मनुष्य के भीतर जो चेतना, साहस, करुणा और सृजनशीलता है, वह उसी शक्ति का अंश है। अतः शक्ति की उपासना केवल बाह्य देवी की पूजा नहीं, बल्कि अपने भीतर स्थित ऊर्जा को जागृत करने का एक आध्यात्मिक प्रयास है। यही कारण है कि शक्ति-पूजा को आत्मविकास और आत्मबोध से भी जोड़ा गया है। जब मनुष्य शक्ति की उपासना करता है, तो वह अपने भीतर के आलस्य, भय और अज्ञान को दूर करने का संकल्प भी करता है।

शक्ति के विभिन्न रूपों की व्याख्या भारतीय संस्कृति की विशेषता है, जहाँ जीवन के प्रत्येक पक्ष को किसी न किसी देवी के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। दुर्गा को शक्ति और संरक्षण का प्रतीक माना गया, जो अधर्म और अन्याय का नाश करती हैं। काली समय और संहार की प्रतीक हैं, जो अहंकार और अज्ञान का अंत करती हैं। लक्ष्मी समृद्धि और संतुलन की अधिष्ठात्री हैं, जो जीवन में ऐश्वर्य और स्थिरता लाती हैं। सरस्वती ज्ञान, कला और विवेक की देवी हैं, जो मनुष्य को बौद्धिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध करती हैं। इन सभी रूपों के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया कि जीवन केवल एक आयाम में नहीं चलता, बल्कि उसमें शक्ति, ज्ञान, समृद्धि और परिवर्तन—सभी की आवश्यकता होती है।इसके अतिरिक्त, दशमहाविद्याओं की परम्परा में शक्ति के और भी सूक्ष्म और गूढ़ रूपों का वर्णन मिलता है, जहाँ देवी को सौम्य और उग्र दोनों रूपों में स्वीकार किया गया है। यह इस बात का संकेत है कि भारतीय चिन्तन ने जीवन के किसी भी पक्ष को नकारा नहीं, बल्कि उसे समझने और स्वीकार करने का प्रयास किया। यहाँ तक कि भय, दुःख, शून्यता और विनाश जैसे अनुभवों को भी देवी के रूप में देखा गया, ताकि मनुष्य उनसे भागे नहीं, बल्कि उन्हें समझकर उनसे ऊपर उठ सके।

नवरात्र के नौ दिन हमें स्मरण कराते हैं कि जीवन के प्रत्येक आयाम—चाहे वह संघर्ष हो या शान्ति, ज्ञान हो या शक्ति, सृजन हो या परिवर्तन—सब उसी आद्याशक्ति के विविध रूप हैं। जब हम नवदुर्गा के भिन्न-भिन्न स्वरूपों की उपासना करते हैं, तब वस्तुतः हम अपने ही जीवन के विभिन्न स्तरों को साधने का प्रयत्न कर रहे होते हैं। यह साधना हमें यह बोध कराती है कि शक्ति कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही सुप्त रूप में विद्यमान है, जिसे जागृत करने की आवश्यकता है।

युद्ध के दौर में खाद्यान्न भंडार की शक्ति

डा. जयंतीलाल भंडारी

इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि अनाज बर्बाद होने से बचाने के लिए देश में 2028 तक सहकारी क्षेत्र में 700 लाख टन अनाज भंडारण की नई क्षमता विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना को तेजी से कारगर क्रियान्वयन की डगर पर आगे बढ़ाया जाए। उम्मीद करें कि सरकार और किसान कृषि को निर्यात उन्मुख बनाएंगेङ्क

हाल ही में 13 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9.3 करोड़ से अधिक किसानों को 18640 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि की पीएम- किसान सम्मान निधि की 22 वीं किस्त जारी करते हुए कहा कि किसान और कृषि परिवेश भारत की शक्ति बन गए हैं। यह उल्लेखनीय है कि इस समय पश्चिम एशिया में युद्ध के बीच जहां भारत के रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन और रिकॉर्ड खाद्य प्रसंस्करण उत्पाद देश के आम आदमी के लिए राहत और अर्थव्यवस्था की ताकत बन गए हैं, वहीं 1 अप्रैल से लागू होने वाले वर्ष 2026-27 के आम बजट के तहत देश की कृषि को उन्नत और निर्यात उन्मुख बनाने की प्रभावी पहल की गई है। गौरतलब है कि दुनिया के तेजी से खुलते हुए कृषि बाजारों और खाद्यान्न की बढ़ती वैश्विक मांग के मद्देनजर भारत के द्वारा कृषि को निर्यात उन्मुख बनाए जाने से किसानों की आर्थिक सशक्तता के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नया अध्याय लिखा जा सकेगा। 21वीं सदी के इस दौर में कृषि क्षेत्र को नई ऊर्जा के साथ आगे ले जाना सरकार की प्राथमिकता है। बजट 2026-27 में कृषि क्षेत्र के लिए 162671 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7 प्रतिशत अधिक है। सरकार तकनीक और कृषि हितप्रद नीति के माध्यम से किसानों को केवल 'अन्नदाता' ही नहीं, बल्कि 'निर्यातकर्ता' बनाने की दिशा में काम कर रही है। खाद्य तेल और दलहन पर राष्ट्रीय मिशन और प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन सहित सभी कृषि क्षेत्रों को मजबूत किया जा रहा है।

ऐसे में उच्च मूल्य वाले कृषि क्षेत्र को बड़े पैमाने पर बढ़ाने से ही हम अपनी खेती को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में बदल सकते हैं और दुनिया में भारत से बड़े पैमाने पर कृषि निर्यात बढ़ा सकते हैं। इस समय भारत दुनिया का सातवां सबसे बड़ा कृषि उत्पादों का निर्यातक देश है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि जहां देश का रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन देश के आम आदमी के लिए भोजन की गारंटी है, वहीं दुनिया के कई जरूरतमंद देशों के करोड़ों लोगों के लिए खाद्यान्न आपूर्ति का आधार भी है। पिछले वर्ष 2024-25 में भारत में 35.70 करोड़ टन खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है और इस वर्ष 2025-26 में इससे भी अधिक खाद्यान्न उत्पादन की संभावना है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के पास केंद्रीय पूल में अप्रैल 2026 तक लगभग 182 लाख टन गेहूं उपलब्ध हो जाने का अनुमान है। इस समय देश के 80 करोड़ से अधिक कमजोर वर्ग के लोगों को निशुल्क खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि 2008 की वैश्विक मंदी में भी भारत की अर्थव्यवस्था खाद्यान्न ताकत के कारण बहुत कम प्रभावित हुई। इतना ही नहीं छह साल पहले कोरोना से जंग में देश के खाद्यान्न भंडार देश के लिए हथियार बन गए थे और भारत ने जरूरतमंद देशों को खाद्यान्न का निर्यात भी किया। अब एक बार फिर इस समय जब ईरान और इजराइल-अमेरिका युद्ध से दुनिया में खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ रही हैं और खाद्यान्न आपूर्ति में व्यवधान है, तब भारत का रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन और रिकॉर्ड खाद्य प्रसंस्करण उत्पाद एक मजबूत हथियार दिखाई दे रहे हैं और भारत नए खाद्यान्न निर्यात आदेशों की पूर्ति के लिए तत्पर दिखाई दे रहा है। पिछले माह फरवरी 2026 में भारत ने 25 लाख टन गेहूं का निर्यात भी सुनिश्चित किया है। निःसंदेह कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार और देश के दीर्घकालिक विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है।

ऐसे में उच्च मूल्य वाले कृषि क्षेत्र को बड़े पैमाने पर बढ़ाने से ही हम अपनी खेती को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में बदल सकते हैं और दुनिया में भारत से बड़े पैमाने पर कृषि निर्यात बढ़ा सकते हैं। इस समय भारत दुनिया का सातवां सबसे बड़ा कृषि उत्पादों का निर्यातक देश है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि जहां देश का रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन देश के आम आदमी के लिए भोजन की गारंटी है, वहीं दुनिया के कई जरूरतमंद देशों के करोड़ों लोगों के लिए खाद्यान्न आपूर्ति का आधार भी है। पिछले वर्ष 2024-25 में भारत में 35.70 करोड़ टन खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है और इस वर्ष 2025-26 में इससे भी अधिक खाद्यान्न उत्पादन की संभावना है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के पास केंद्रीय पूल में अप्रैल 2026 तक लगभग 182 लाख टन गेहूं उपलब्ध हो जाने का अनुमान है। इस समय देश के 80 करोड़ से अधिक कमजोर वर्ग के लोगों को निशुल्क खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि 2008 की वैश्विक मंदी में भी भारत की अर्थव्यवस्था खाद्यान्न ताकत के कारण बहुत कम प्रभावित हुई।

खासतौर से विगत कुछ वर्षों में कृषि क्षेत्र व छोटे किसानों की मजबूती के लिए कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं। 'पीएम किसान सम्मान निधि' और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) जैसे कई कार्यक्रमों से देश का कृषि क्षेत्र लगातार मजबूत हुआ है। अब तक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्राप्त हुई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के बीमा दावों का निपटारा किया गया है। संस्थागत ऋण कवरेज 75 प्रतिशत से अधिक हो गया है। देश के गांवों में अप्रैल 2020 से शुरू की गई पीएम स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीणों को उनकी जमीन का कानूनी हक देकर उनके आर्थिक सशक्तिकरण का नया अध्याय लिखा जा रहा है। गांवों में बैंक शाखाओं की संख्या मार्च 2010 के 33378 से बढक़र दिसंबर 2024 तक 56579 हो गई। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, सहकारी समितियों और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह, ग्रामीण बैंकिंग व्यवस्था आदि प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि इस समय भारत दुनिया की नई खाद्य टोकरी और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रतिबद्ध देश के रूप में रेखांकित हो रहा है। इस समय भारत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नवाचार, स्थिरता और सुरक्षा के वैश्विक मानक स्थापित कर रहा है। पिछले 10 वर्षों के दौरान, भारत ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए व्यापक सुधार शुरू किए हैं। भारत खाद्य प्रसंस्करण में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई), प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकरण, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना जैसी बहुआयामी पहलों के माध्यम से पौष्टिक दुनिया के निर्माण के सपने को साकार करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के तहत पिछले दस वर्षों में 50 हजार करोड़ रुपए से अधिक का एफडीआई प्राप्त हुआ है और भारत की खाद्य प्रसंस्करण क्षमता 15 गुना से अधिक बढक़र दो सौ लाख टन से अधिक हो गई है। देश के कुल कृषि निर्यात में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की हिस्सेदारी 13.7 से बढक़र करीब 24 प्रतिशत हो गई है।

साथ ही भारत का खाद्य प्रसंस्करण बाजार आकार वर्ष 2025-26 में 535 अरब डॉलर की ऊंचाई तक पहुंचना अनुमानित है। निश्चित रूप से रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन और रिकॉर्ड खाद्य प्रसंस्करण उत्पाद भारत की नई आर्थिक शक्ति बन गए हैं। ऐसे में इन्हें निर्यात उन्मुख बनाकर भारत निर्यात की कमाई व वैश्विक खाद्य आपूर्ति में और प्रभावी भूमिका निभा सकता है। भारत के पास खाद्यान्न उत्पादन और खाद्य प्रसंस्करण वस्तुओं का उत्पादन और निर्यात बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं। भारत जहां विश्व में चावल, दूध, जूट और मसाला उत्पादन में पहले क्रम पर है, वहीं गेहूं, कपास, गन्ना, मूंगफली, फल व सब्जियों के उत्पाद में दूसरे क्रम पर है। भारत के पास विविध जलवायु है और भारत कृषि-जलवायु क्षेत्रों के मामले में समृद्ध है। ऐसे में भारत को निर्यात आधारित खेती, फसल विविधीकरण और खेती में आधुनिक तकनीक के एकीकरण के साथ आगे बढना होगा। भारतीय कृषि उत्पादों की गुणवत्ता, ब्रांडिंग और मानकों के सभी पहलुओं पर काम किया जाना होगा।

चूंकि भारत में अभी भी अनाज, दाल व तिलहन के उत्पादन का स्तर तो मौसम पर निर्भर ही होता है, ऐसे में क्षेत्रवार और फसलवार आधार का व्यापक अध्ययन करते हुए सिंचाई की व्यवस्था की नई नीति तैयार की जाना लाभप्रद होगी। इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि अनाज बर्बाद होने से बचाने के लिए देश में 2028 तक सहकारी क्षेत्र में 700 लाख टन अनाज भंडारण की नई क्षमता विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना को तेजी से कारगर क्रियान्वयन की डगर पर आगे बढ़ाया जाए। उम्मीद करें कि सरकार और किसान कृषि को निर्यात उन्मुख और प्रतिस्पर्धी बनाकर वैश्विक बाजार से जोडने की राह पर आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करें कि भारत रिकॉर्ड खाद्यान्न भंडार से आम आदमी की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए दिखाई देगा।

बुलेट ट्रेन
परियोजना में लगे पंख

भारत आज एक ऐसे दौर से गुजर रहा है,जहाँ विकास की परिभाषा केवल सड़कों,पुलों और भवनों तक सीमित नहीं रही,बल्कि वह गति, समन्वय और सुविधा के समग्र अनुभव में परिवर्तित हो चुकी है। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के मिशन मोड़ व अश्वनी वैष्णव के विजन में इसी बदलती सोच का सबसे सशक्त प्रतीक बनकर उभरी है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण बुलेट ट्रेन की परियोजना में पंख लग गए है ।सर्व विदित रहे कि देश की बहुप्रतीक्षित बुलेट ट्रेन परियोजना,जो केवल एक तेज रफ्तार रेल सेवा नहीं,बल्कि आधुनिक शहरी जीवन शैली का आधार बनने की दिशा में अग्रसर है ।आपको बता दें कि बुलेट ट्रेन स्टेशनों को जिस दृष्टिकोण से विकसित किया जा रहा है,वह अपने आप में एक नई अवधारणा को जन्म देता है ।अब स्टेशन केवल यात्रा के प्रारंभ और अंत का स्थान नहीं रहेंगे,बल्कि वे शहर की परिवहन व्यवस्था के साथ एकीकृत होकर आधुनिक शहरी नेटवर्क का महत्वपूर्ण हिस्सा बनेंगे ।मल्टी- मॉडल इंटीग्रेशन (एमएमआई) की यह अवधारणा यात्रियों को बिना किसी व्यवधान के एक परिवहन माध्यम से दूसरे माध्यम में सहज रूप से स्थानांतरित होने की सुविधा प्रदान करेगी ।इस योजना के तहत स्टेशन परिसर और उसके आसपास के क्षेत्रों का व्यापक विकास किया जा रहा है ।बस,टैक्सी,निजी वाहन और अन्य सार्वजनिक परिवहन साधनों को एक ही स्थान पर सुव्यवस्थित ढंग से जोड़ने का प्रयास,भारतीय शहरों की लंबे समय से चली आ रही परिवहन अव्यवस्था को दूर करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। यह केवल यात्रा को आसान नहीं बनाएगा, बल्कि समय की बचत,ईंधन की खपत में कमी और पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा ।सुत्रो के अनुसार स्टेशन प्लाज़ा को जिस प्रकार से डिजाइन किया जा रहा है,वह आधुनिक शहरी सौंदर्य और कार्यकुशलता का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। यहाँ के चौड़े और सुरक्षित फुटपाथ, सुव्यवस्थित पिकअप एवं ड्रॉप ऑफ जोन,पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था, उन्नत संकेत प्रणाली,आधुनिक स्ट्रीट लाइटिंग और सीसीटीवी आधारित सुरक्षा व्यवस्था - ये सभी सुविधाएँ मिलकर यात्रियों को एक सुरक्षित,सुविधाजनक और विश्वस्तरीय अनुभव प्रदान करेंगी। साथ ही,लैंडस्केपिंग और वृक्षारोपण के माध्यम से इन क्षेत्रों को हरित और पर्यावरण अनुकूल बनाने का प्रयास भी सराहनीय है। यदि हम इस परियोजना की प्रगति पर दृष्टि डालें,तो स्पष्ट होता है कि यह केवल कागजों तक सीमित योजना नहीं,बल्कि धरातल पर तेजी से आकार लेती हुई वास्तविकता है ।सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन पर स्टील स्ट्रक्चर और रूफ शीटिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है और अब फिनिशिंग कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है ।प्लेटफॉर्म और कॉन्कोर्स क्षेत्र में फ्लोरिंग,क्लैडिंग और अन्य आंतरिक कार्यों की प्रगति इस बात का संकेत देती है कि यह स्टेशन शीघ्र ही अपनी अंतिम रूपरेखा में दिखाई देगा। बिलिमोरा स्टेशन पर भी निर्माण कार्य उल्लेखनीय गति से आगे बढ़ रहा है ।रेल और प्लेटफॉर्म स्तर की स्लैब कास्टिंग पूरी हो चुकी है और संरचनात्मक स्टील का कार्य भी समाप्त हो गया है ।अब आर्किटेक्चरल फिनिशिंग और एमईपी कार्यों के माध्यम से इसे आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है ।आणंद स्टेशन की प्रगति विशेष रूप से उल्लेखनीय है ।यहाँ न केवल स्लैब कास्टिंग और रूफ संरचना का कार्य पूरा हो चुका है,बल्कि लिफ्ट और एस्केलेटर भी स्थापित किए जा चुके हैं ।यह दर्शाता है कि यात्रियों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए इस परियोजना को किस गंभीरता से क्रियान्वित किया जा रहा है।

पाठकगण अपने विचार responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भेज सकते हैं।

गंभीर स्वास्थ्य संकट बनते जा रहे सड़क हादसे

महिलाओं के हक में

भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) की महिला अधिकारियों को पूरी पेंशन देने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश उन अधिकारियों के लिए बड़ी राहत के साथ-साथ स्त्रियों के हक में एक सार्थक सामाजिक संदेश भी है. उन महिला अधिकारियों ने अपनी सेवा से हटाये जाने को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल कर उन्हें न्याय दिया है. यानी अब उन महिला सेनाधिकारियों को 20 साल की सेवा के बराबर पेंशन पाने का हकदार माना जायेगा. अदालत का यह आदेश हालांकि एक 'अस्थायी उपाय' के रूप में ही आया है, क्योंकि पेंशन का लाभ केवल वर्दीधारी पुरुषों और महिलाओं को 20 वर्ष की सेवा पूरी करने पर ही मिलता है. पर सुप्रीम कोर्ट ने उन महिला अधिकारियों के संघर्ष को समझा और उनके हक में फैसला सुनाया, तो यह निश्चित रूप से एक बड़ी बात है. पूरा मामला दरअसल एसएससी के तहत नियुक्त उन महिला अधिकारियों की याचिकाओं से जुड़ा था, जिन्होंने स्थायी कमीशन दिये जाने की मांग की थी. एसएससी के तहत नियुक्त अधिकारी का कार्यकाल 10 वर्ष का होता है, जिसे चार वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है. उसके बाद योग्यता के आधार पर स्थायी कमीशन दिया जाता है और स्थायी कमीशन न मिलने पर सेवा छोड़नी होती है. उन महिला अधिकारियों ने स्थायी कमीशन न मिलने पर पहले आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल (एएफटी) का रुख किया था. बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां इन अधिकारियों ने याचिका दायर कर कहा था कि स्थायी कमीशन देने के मामले में पुरुषों के मुकाबले उनके साथ भेदभाव हो रहा है. इनमें से कुछ महिला अधिकारी तो ऑपरेशन सिंदूर का भी हिस्सा रही थीं. महिला अधिकारियों की तरफ से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद केंद्र सरकार की तरफ से महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने में भेदभाव किया गया. शीर्ष अदालत ने अपनी टिप्पणियों में कहा कि अवसरों की कमी ने महिला अधिकारियों की योग्यता और करियर की प्रगति को प्रभावित किया और उन्हें गलत तरीके से लंबी अवधि के करियर के लिए 'अनफिट' माना गया. यानी महिलाओं को स्थायी कमीशन न देना उनकी योग्यता की कमी नहीं, बल्कि व्यवस्था में मौजूद भेदभाव का नतीजा था. सुप्रीम कोर्ट ने बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि सेना में पुरुष अधिकारियों का एकाधिकार नहीं हो सकता और वे यह उम्मीद नहीं कर सकते कि सभी खाली पद पुरुषों के लिए ही होंगे.

शॉर्ट सर्विस कमीशन की महिला सेनाधिकारियों को पूरी पेंशन देने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश उन संघर्षरत अधिकारियों के लिए बड़ी राहत के साथ स्त्रियों के हक में एक सार्थक सामाजिक संदेश भी है.

सुदीप लखटकिया
एनएसजी के पूर्व महानिदेशक और पूर्व जॉएंट कमिश्नर ऑफ ट्रैफिक पुलिस, हैदराबाद सिटी
editor@thebillionpress.org

वर्ष 2023 में देश में 4.8 लाख सड़क दुर्घटनाओं में 1.72 लाख लोगों की मौत हुई और 4.6 लाख से अधिक लोग घायल हुए. हमारे पास बेहतर सड़कें, स्मार्ट निगरानी तकनीक और सख्त दंड हैं, जिनसे दुर्घटनाएं कम होनी चाहिए थीं. पर देश में सड़क पर होने वाली मौतों का आंकड़ा सड़क नेटवर्क के विस्तार के साथ बढ़ रहा है. इस पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है. हमारी सड़कें असुरक्षित हैं, क्योंकि हमने सड़क हादसों से सबक नहीं सीखे. उच्च सड़क दुर्घटना दर के साथ भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता.

भारत के पास लगभग 1.5 लाख किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जो तेजी से बढ़ रहे हैं और पूरे देश में सड़क परिवहन की स्थिति को बदल चुके हैं. लेकिन यह आधुनिक बुनियादी ढांचा पहले से कहीं अधिक लोगों की जान सड़क दुर्घटनाओं में ले रहा है. उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 2023 में भारत में 4.8 लाख सड़क दुर्घटनाओं में 1.72 लाख लोगों की मौत हुई और 4.6 लाख से अधिक लोग घायल हुए. हमारे पास बेहतर सड़कें, स्मार्ट निगरानी तकनीक और सख्त दंड हैं, जिनसे दुर्घटनाएं कम होनी चाहिए थीं.

लेकिन अपने यहां सड़क पर होने वाली मौतों का आंकड़ा सड़क नेटवर्क के विस्तार के साथ लगभग समानुपाती रूप से बढ़ रहा है, जिससे सड़क दुर्घटनाएं एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट का रूप लेती जा रही हैं. इस पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है. हम एक जटिल समस्या का सामना कर रहे हैं, जिसने ज्ञान के क्षरण को जन्म दिया है. यह एक ऐसी स्थिति है, जहां आंकड़े तो मौजूद हैं, लेकिन उनसे सीख नहीं ली जा रही. हमें पता है कि क्या गलत है, फिर भी हमारी सड़कें असुरक्षित हैं, क्योंकि हमने सड़क हादसों से सबक नहीं सीखे. सड़क सुरक्षा तब बिगड़ती है जब वाहन चालकों, पैदल यात्रियों और व्यवस्था संभालने वाले अधिकारियों का समुदाय सीखना और सुरक्षित व्यवहार अपनाना बंद कर देते हैं. साक्ष्य आधारित प्रवर्तन का धीरे-धीरे कमजोर होना और संस्थागत सीख की कमी असुरक्षित प्रथाओं को बढ़ावा देती है. इससे एक ऐसी संस्कृति बनती है, जो समय के साथ-साथ और खराब होती जाती है. ऐसी व्यवस्था में वही लोग सुरक्षा से समझौता करते हैं, जो आखिरकार इससे सबसे अधिक प्रभावित होते हैं और सड़कों पर घायल या मृत हो सकते हैं. सुरक्षा का एक पहलू सीधे सरकार की दृष्टि से जुड़ा है. जब राजनीतिक दबाव साक्ष्यों पर हावी हो जाता है, तब योजनाकार दुर्घटनाओं के आंकड़ों को नजरअंदाज करने लगते हैं. वैसे में, नियमों के उल्लंघनों को सामान्य मान लिया जाता है, समाज उन्हें स्वीकार कर लेता है और इसके परिणामस्वरूप सड़क पर बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती हैं. अपने यहां सरकारों के पास सड़क दुर्घटनाओं का विशाल आंकड़ा है, फिर भी इंजीनियरिंग, प्रवर्तन और सार्वजनिक स्वास्थ्य को अलग-अलग खांचों में बांटकर देखा जाता है.

ऐसी स्थिति में, सड़क सुरक्षा को मजबूत करने का पहला कदम यातायात उल्लंघनों पर सख्त दंड लागू करना होना चाहिए. ट्रैफिक चालान, जैसा कि आम बोलचाल में कहा जाता है, नियमों के उल्लंघनों को आर्थिक रूप से हतोत्साहित करने और उन्हें भविष्य की प्रशासनिक या कानूनी कार्रवाई के लिए दर्ज किये जाने का माध्यम है. इसमें कोई शक नहीं कि देश में कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने उल्लंघनों की सटीक पहचान और चालान जारी करने की क्षमता में काफी सुधार किया है. लेकिन चालान की वसूली उस गति से नहीं बढ़ी है. यही कारण है कि सड़क अनुशासन और सुरक्षा पर असर पड़ा है. देश के कुछ शहरों में तो जुर्माना वसूली की दर पांच फीसदी तक ही है. जबकि चालान के भुगतान में देरी या भुगतान न करने के प्रति शून्य सहिष्णुता होनी चाहिए. न लिये जाने वाले जुर्माने उल्लंघनों को बढ़ावा देते हैं. कानून की गरिमा उसके सही और पूर्ण कार्यान्वयन में है. समय पर चालान की वसूली नियमों के प्रभावी पालन का अंतिम चरण है और यह जोखिम को रोकने में सहायक हो सकता है. इससे सभी सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षित व्यवहार को बढ़ावा मिलेगा. आदर्श रूप से नियमों का उल्लंघन करने वाले हर व्यक्ति को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए. जैसा कि ट्रैफिक पुलिस के आंकड़ों से पता चलता है. दिल्ली में 2025 तक निजी चालकों के खिलाफ लगभग 2.5 करोड़ और वाणिज्यिक चालकों के खिलाफ करीब 20 लाख चालान लंबित हैं. ये आंकड़े उस आम धारणा को चुनौती देते हैं कि केवल वाणिज्यिक चालक ही नियमों का उल्लंघन करते हैं. लगभग तीन करोड़ लंबित मामलों में से एक-तिहाई तेज गति से वाहन चलाने और लगभग 48 लाख मामले अवैध पार्किंग से संबंधित हैं, जो सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण हैं. हाल ही में पुणे में एक हाई-प्रोफाइल सड़क दुर्घटना के बाद यह तथ्य सामने आया कि आरोपी के कई चालान लंबित थे. यदि समय पर उससे जुर्माना वसूला गया होता, तो शायद जानें बचायी जा सकती थीं. यह उस 'ब्रोकन विंडो सिंड्रोम' की ओर संकेत करता है, जिसके अनुसार छोटे अपराधों को नजरअंदाज करने से बड़े अपराधों को बढ़ावा मिलता है. स्पष्ट है कि यातायात उल्लंघनों के जुर्माने की वसूली एक आसान उपाय है, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण इसमें ढील दी जाती है, जिससे भुगतान में देरी, छूट या माफी मिल जाती है. इस संदर्भ में तेलंगाना सरकार का यह बयान सराहनीय है कि ऐसे मामलों में कोई आम माफी नहीं दी जायेगी. यदि देश में यह नया चलन बनता है, तो इससे नियमों के उल्लंघनों और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी.

बेशक दंड एक पहलू है, जिस क्षेत्र में आसानी से सुधारा लाया जा सकता है, लेकिन हमें अन्य जटिल मुद्दों पर भी ध्यान देना होगा, जैसे ड्राइविंग टेस्ट की प्रक्रिया, लाइसेंस जारी करना, सड़कों का रखरखाव, मरम्मत की गुणवत्ता, कमजोर ट्रैफिक इंजीनियरिंग और सड़क संकेतों की खराब व्यवस्था. देश में जिस आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस जारी हो जाते हैं, वह भी चिंता का विषय है. यदि परीक्षा की गंभीरता कम हो जाये, तो फिर उसका महत्व ही क्या रह जाता है? इसके अलावा, भले ही सड़कें अच्छी हों, लेकिन बिना चेतावनी के डायवर्जन, मरम्मत कार्य और अपर्याप्त संकेतक तेज गति वाले यातायात के लिए नये खतरे पैदा करते हैं. खराब या गलत तरीके से लगाये गये संकेत भी इस समस्या को बढ़ाते हैं. यह सब मिलकर दिखाता है कि प्रणाली कई स्तरों पर विफल हो रही है. हमें ऐसे समग्र समाधान की आवश्यकता है, जो पूरे तंत्र में काम करे. एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव बीमा और चालान प्रणाली को जोड़ने का है, जिसमें अधिक उल्लंघनों पर बीमा प्रीमियम बढ़ाने का प्रावधान हो. इसके लिए तकनीक आधारित सख्त प्रवर्तन की आवश्यकता होगी, जिससे हर उल्लंघनकर्ता को दंडित किया जा सके. बार-बार उल्लंघन करने पर ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द होना चाहिए, जैसा कि विकसित देशों में होता है. भारत उच्च सड़क दुर्घटना दर के साथ विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता. सड़क सुरक्षा एक महत्वपूर्ण विकास संकेतक है और हमें इसे उसी रूप में देखना चाहिए, ताकि आधुनिक सड़क नेटवर्क का पूरा लाभ उठाते हुए हम सुरक्षित और तेज भविष्य की ओर बढ़ सकें.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में वृद्धि की आस

मधुरेन्द्र सिन्हा
वरिष्ठ पत्रकार
madhurendra.sinha6@gmail.com

संसद की श्रम एवं रोजगार समिति ने कहा है कि इपीएफ 95 स्कीम के तहत 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन राशि अपर्याप्त है और इसे सम्मानजनक स्तर तक बढ़ाने की जरूरत है. उधर इपीएफओ दावा कर रहा है कि इस मद में लाखों करोड़ रुपये खर्च होंगे और यह सरकार के बजटीय सहयोग के बिना संभव नहीं है. अब मामला केंद्र सरकार के पाले में है, जो इस पर फैसला करेगी.

अमेरिका और यूरोप के विकसित देशों में सरकारें सामाजिक सुरक्षा पर काफी खर्च करती हैं, जिसका नतीजा होता है कि नागरिकों का बुढ़ापा अच्छे से कट जाता है. भारत में सामाजिक सुरक्षा एक मिश्रित व्यवस्था है, जिसमें कर्मचारी या अन्य अपनी ओर से योगदान करते हैं तथा सरकार भी उसमें अपनी ओर से योगदान करती है. इससे एक बड़ी रकम उनकी वृद्धावस्था में उन्हें नियमित रूप से मिलती रहती है. लेकिन कुछ ऐसे भी प्रावधान हैं जिनमें कर्मचारी नौकरी के दौरान अपनी ओर से योगदान करता रहता है, लेकिन सरकार की ओर से उसे कोई योगदान नहीं मिलता है. इसका नतीजा होता है कि पेंशन के रूप में दी जाने वाली राशि बहुत कम या नगण्य होती है.

ऐसी ही एक पेंशन योजना चर्चा और कर्मचारियों द्वारा आलोचना का विषय है. वर्ष 1995 में कई निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए ऐसी ही एक योजना शुरू की गयी थी, जिसे इपीएफ 95 का नाम दिया गया था. इसमें कर्मचारी अपनी नौकरी के दौरान योगदान करते हैं और सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें एक निश्चित राशि, जो बहुत ही कम है, हर महीने दी जाती है. इसे लेकर काफी आंदोलन हुए और मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया. बाद में केंद्र सरकार ने इसकी न्यूनतम राशि बढ़ाकर 1,000 रुपये महीना कर दी. पर यह राशि भी काफी कम थी और कर्मचारी अपने-अपने स्तर पर इसे बढ़ाने के लिए आवाज उठाते रहे. अब संसद की श्रम एवं रोजगार समिति ने कहा है कि इपीएफ 95 स्कीम के तहत 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन राशि अपर्याप्त है और इसे सम्मानजनक स्तर तक बढ़ाने की जरूरत है. यहां यह बताना भी जरूरी है कि विभिन्न राज्यों में वृद्धावस्था पेंशन हर महीने कम से कम 2,000 रुपये है. दिल्ली में यह राशि 2,500 रुपये तक है और हरियाणा में यह 3,200 रुपये प्रतिमाह है. इसी तरह, विधवा पेंशन की राशि दिल्ली में 2,500 रुपये प्रतिमाह है और ये सभी लाभार्थियों के योगदान के बिना मिलती हैं. सरकार ही इनका सारा खर्च उठाती है. इसी तरह, महिलाओं के लिए बनी सम्मान योजनाओं में, जिन्हें कई नामों से बुलाया जाता है, इसी तरह की राशि हर महीने दी जाती है. ऐसे में, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के साथ ऐसा व्यवहार आश्चर्यजनक है.

श्रम, वस्त्र एवं कौशल विकास से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की 'अनुदान मांगों (2026-27)' पर अपनी 15वीं रिपोर्ट में कहा है कि महंगाई बढ़ने के बावजूद कर्मचारी पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रतिमाह काफी समय से अपरिवर्तित है. समिति ने साक्ष्यों पर गौर करने के दौरान पाया कि पेंशनधारकों, विशेषकर वृद्ध और आर्थिक रूप से कमजोर लाभार्थियों को होने वाली वित्तीय कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग के साथ अनेक प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं. समिति ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के इस प्रतिवेदन पर भी गौर किया है कि भारत सरकार इस योजना के लिए पहले से ही वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है. इसके तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के वर्तमान में कार्यरत सदस्यों के लिए 1.16 प्रतिशत का योगदान और 1,000 रुपये प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित करने के लिए प्रदान की गयी बजटीय सहायता शामिल है. संसदीय समिति ने मांग की है कि मंत्रालय कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन की तत्काल और व्यापक समीक्षा करे. समिति का यह भी सुझाव है कि मंत्रालय योजना के लिए बजटीय सहायता बढ़ाने की संभावना तलाशे, ताकि पेंशनधारकों को वर्तमान जीवन यापन लागत के अनुरूप उचित न्यूनतम पेंशन प्राप्त हो सके और योजना के अंतर्गत आने वाले लाखों सेवानिवृत्त श्रमिकों को अधिक सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता प्रदान की जा सके.

रिपोर्ट के अनुसार, यह देखा गया है कि अनुबंध पर काम करने वाले अनेक श्रमिक नियमित श्रमिकों के समान कार्य करते हैं, लेकिन कार्यस्थल पर दुर्घटनाओं के बाद राहत और मुआवजा प्राप्त करने में अक्सर देरी का सामना करते हैं. इसे देखते हुए समिति ने सिफारिश की है कि ऐसे श्रमिकों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा और कर्मचारी भविष्य निधि जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत समय पर 'कवरेज' सुनिश्चित की जाये. समिति ने केंद्र और राज्य सरकारों से अनुपालन की निगरानी और मुआवजे का शीघ्र वितरण सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था स्थापित करने को भी कहा है. वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि काफी समय पहले भारत सरकार के श्रम सचिव ने इसे बढ़ाकर न्यूनतम 2,000 रुपये करने की सिफारिश की थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ. इसी तरह, कोश्यारी समिति ने भी 2013 में इसे 3,000 रुपये करने तथा महंगाई के अनुरूप इसे समायोजित करने की अनुशंसा की थी, लेकिन वही ढाक के तीन पात वाली स्थिति रही. उनका कहना था कि पेंशन फंड में दस लाख करोड़ रुपये अतिरिक्त जमा हैं और इस पर एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का खर्च नहीं आयेगा, जबकि इपीएफओ दावा कर रहा है कि इस मद में लाखों करोड़ रुपये खर्च होंगे. उसका यह भी कहना है कि यह सरकार के बजटीय सहयोग के बिना संभव नहीं है. अब मामला केंद्र सरकार के पाले में है, जो इस पर फैसला करेगी.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

देश दुनिया

ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग से लाभान्वित हो सकते हैं भारत-नेपाल

नेपाल ने अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने के लिए लंबे समय से अपने पड़ोसी देशों और अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के बीच एक बारीक संतुलन बनाये रखा है. आज के नये राजनीतिक परिदृश्य में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) के कंधों पर नेपाल की भू-राजनीतिक स्थिति का लाभ उठाकर सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देने और एक विश्वसनीय तथा स्थिर क्षेत्रीय शक्ति के रूप में राष्ट्र की प्रतिष्ठा को मजबूत करने का दायित्व है. यद्यपि, 1950 की शांति एवं मैत्री संधि नेपाल और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों की नींव बनी हुई है, फिर भी दोनों देशों के बीच सहयोग का दायरा औपचारिक राजनयिक सीमाओं से परे और 'रोटी-बेटी' संबंध से कहीं अधिक व्यापक है. आरएसपी के चुनावी घोषणापत्र के अनुसार, उसने विकास कूटनीति को प्राथमिकता दी है और संतुलित एवं गतिशील कूटनीति अपनाने का संकल्प लिया है. ऐसे में आने वाले वर्षों में नेपाल की विदेश नीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, जिसमें आर्थिक लक्ष्यों और सामाजिक-आर्थिक साझेदारी पर विशेष ध्यान होगा, विशेषकर भारत के साथ संबंधों में. उत्पादक और पारस्परिक लाभ वाले व्यापार संबंध के लिए आरएसपी के सामने निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने, व्यावहारिक वार्ता करने और अनौपचारिक और अवैध व्यापारों पर अंकुश लगाने के लिए नियामकीय निगरानी को कड़ा करने की जरूरत है. भारत के लिए नेपाल अपनी बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का एक भरोसेमंद स्रोत है. खाड़ी क्षेत्र की स्थिति से उत्पन्न ऊर्जा अस्थिरता को देखते हुए दोनों देश इस क्षेत्र में गहन सहयोग से अत्यधिक लाभान्वित हो सकते हैं. एक मजबूत और स्थिर सरकार के साथ नया नेतृत्व भारत के विकास पथ का अनुकरण कर सकता है. एक मजबूत नेतृत्व द्वारा संचालित विकसित और समृद्ध नेपाल ही नेपाली जनता की हमेशा से आकांक्षा रही है, इसका भारत के लिए भी समान महत्व है. **-रवींद्र राजभंडारी**

THE KATHMANDU POST

बोधि वृक्ष

भक्ति, ध्यान और प्रेम

अनेक साधक के मन में एक प्रश्न बार-बार उठता है कि आखिर साधना की वास्तविक उपलब्धि क्या है? क्या यह केवल कुछ आध्यात्मिक अनुभवों तक सीमित है, या फिर यह जीवन को गहरे स्तर पर बदल देती है? भारतीय संत परंपरा कहती है कि साधना का सबसे बड़ा फल है परम सत्ता के प्रति गहरा और स्वाभाविक प्रेम. जब साधक के भीतर ईश्वर के प्रति ऐसा आकर्षण उत्पन्न हो जाता है, जो किसी नियम, भय या सामाजिक दबाव से नहीं, बल्कि हृदय की सहज भावना से जन्म लेता है, तब वह भक्ति की उच्च अवस्था में प्रवेश करता है. इसे ही रागात्मक या स्वाभाविक भक्ति कहा गया है. इस अवस्था में साधक के लिए ईश्वर का स्मरण कोई कर्तव्य नहीं रह जाता, बल्कि उसके जीवन की सहज धड़कन बन जाता है. इस भाव को समझने के लिए प्रकृति की ओर देखना पर्याप्त है. विशाल समुद्र में असंख्य लहरें उठती हैं. वे कुछ समय के लिए अलग दिखाई देती हैं, लेकिन वास्तव में वे समुद्र से अलग नहीं होतीं. अंततः वे उसी समुद्र में लौट जाती हैं, जहां से उनका उद्भव हुआ था. इसी प्रकार, यह संपूर्ण सृष्टि भी एक अनंत चेतना से उत्पन्न होकर उसी में विलीन होने की ओर अग्रसर है. कई संत कवियों के अनुसार, परम सत्ता कोई दूर बैठी शक्ति नहीं है, बल्कि आनंद और प्रेम का अनंत स्रोत है.

इसी कारण इस जगत की प्रत्येक गति में एक लय और संगीत छिपा हुआ है. आध्यात्मिक साधना का एक महत्वपूर्ण अनुभव इसी सूक्ष्म लय से जुड़ा हुआ माना गया है. जब साधक नियमित साधना के माध्यम से अपने मन को शांत और सूक्ष्म बनाता है, तब उसे भीतर एक अनोखी ध्वनि का अनुभव होने लगता है. यह ध्वनि बाहरी कानों से सुनाई देने वाली नहीं होती, बल्कि चेतना के भीतर अनुभव की जाती है. जब साधक इस दिव्य ध्वनि का अनुभव करने लगता है, तब उसकी साधना में एक नया उत्साह और गहराई आ जाती है. इस अवस्था में साधना बोझ नहीं रहती, बल्कि आनंदमय यात्रा बन जाती है. यही वह बिंदु है जहां भक्ति, ध्यान और प्रेम एक दूसरे में मिल जाते हैं.

-श्री श्री आनंदमूर्ति

कुछ अलग

युवाओं की पसंद बनते माइक्रो ड्रामा

मुकुल श्रीवास्तव
टिप्पणीकार
srivastava_mukul@lkouniv.ac.in

आज का युवा सब कुछ शॉर्ट फॉर्म में चाह रहा है. ऐसे में लंबी फीचर फिल्में और टीवी धारावाहिक धीरे-धीरे हाशिये पर जा रहे हैं. रील्स देखते-देखते उसकी ध्यान अवधि में लगातार कमी आ रही है. नतीजा, घंटे भर के सीरियल पर गौर करना अब बड़ी चुनौती हो गयी है. इस बदलते परिदृश्य को समझते हुए कंटेंट निर्माताओं ने हमारे सामने एक नया विकल्प, 'माइक्रो ड्रामा', पेश किया है. इसमें सस्पेंस भी है, इमोशन भी और क्लाइमेक्स भी.

माइक्रो ड्रामा, जिसे लोग वर्टिकल माइक्रो वेबसीरीज भी कहते हैं, असल में स्मार्टफोन के लिए बनी एक नयी कंटेंट स्टाइल है. ये छोटे-छोटे एपिसोड होते हैं, जिनकी समय अवधि एक से दो मिनट होती है. खास बात यह है कि ये वीडियो हॉरिजॉन्टल नहीं, पोर्ट्रेट मोड में बनाये जाते हैं, ताकि इन्हें मोबाइल स्क्रीन पर आसानी से देखा जा सके. हर एपिसोड तेज रफ्तार, डायलॉग और ट्विस्ट से भरा होता है, ताकि देखने वाले को अगली कड़ी देखने का मन हो जाये. अमेरिका और चीन जैसे देशों में यह नया कंटेंट फॉर्मेट बाजार का रूप ले चुका है. भारत में भी इस माइक्रो ड्रामा फॉर्मेट ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिये हैं. रील टीवी, पॉकिट टीवी, रील शॉर्ट, फ्लिकरील्स जैसे कई प्लेटफॉर्म भी इस नये शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट में उतरे हैं. जी, टीवीएफ, एमएक्स प्लेयर जैसे बड़े एंटरटेनमेंट प्लेयर भी इसमें काफी निवेश कर रहे हैं. जी ने हाल ही में अपना वर्टिकल एप बुलेट लॉन्च किया है. कंसल्टिंग फर्म बर्नस्टीन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत में दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों के इंटरनेट यूजर्स महीने में औसतन 35-40 जीबी डाटा का उपयोग करते हैं. जबकि मेट्रो शहरों में यह आंकड़ा 30 जीबी से भी कम है. ऐसे में माइक्रो ड्रामा बनाने वाले एप्स इन शहरों के लोगों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं. जैसे अलग-अलग भारतीय भाषा, संस्कृति और ऐसी कहानियां, जिससे कोई भी जुड़ जाये. इससे छोटे शहरों और कस्बों में माइक्रो ड्रामा अच्छी लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं.

ये ड्रामा बड़े बजट, बड़े सेट या बड़े एक्टर्स के मोहताज नहीं होते हैं. बस अच्छी कहानी और कुछ ठीक-ठाक कलाकारों से भी काम चल जाता है. इसलिए कंटेंट इंडस्ट्री और प्लेटफॉर्म इस तरह के कंटेंट पर अच्छा-खासा निवेश कर रहे हैं. यह ड्रामा न सिर्फ क्रिएटर्स और प्लेटफॉर्म को नये अवसर दे रहा है, बल्कि दर्शकों की बदलती आदतों को भांपकर मनोरंजन का नया फॉर्मेट भी परोस रहा है. छोटे एपिसोड, तेज और सस्पेंस भरी कहानी और मोबाइल फ्रेंडली डिजाइन ने इसे डिजिटल दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया है.

आपके पत्र

मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के आदर्श

कल रामनवमी है. इसी दिन अयोध्या में भगवान श्रीराम का अवतरण हुआ था. जीवनपर्यंत उन्होंने धर्म का पालन किया और मर्यादित जीवन जीते रहे. पितृ भक्त होने के साथ ही, अपने से बड़ों का सम्मान और छोटों को अपार स्नेह उनके स्वभाव का हिस्सा था. अपने इन्हीं सदाचरणों के कारण वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाये. हमें भी भगवान श्रीराम के आदर्शों को आत्मसात कर धर्म की राह पर चलने और मर्यादित जीवन जीने की आवश्यकता है.

अचला श्रीवास्तव, रांची

स्वस्थ जीवनशैली अपनाने की जरूरत

खान-पान की गलत आदत, निष्क्रियता और वायु प्रदूषण के कारण हमारे देश पर गैर-संचारी रोगों का बोझ बढ़ता जा रहा है. बड़े-बूढ़े ही नहीं, बल्कि बच्चे व युवा भी आज मोटापा, अवसाद, मधुमेह, अस्थमा, हृदयरोग समेत अनेक बीमारियों से जूझ रहे हैं. थोड़ी सी सक्रियता, खान-पान व अपनी दिनचर्या में बदलाव लाकर हम इन बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं. देश के बच्चे व युवा स्वस्थ रहें, इसके लिए बड़ों को अपनी जीवनशैली को स्वस्थ व संतुलित बनाने की जरूरत है. ताकि हमारे बच्चे हमारा अनुकरण करें और स्वस्थ बने रहें.

राम बिलास महतो, बोकारो

पोस्ट करें : प्रभात खबर, 15 पी, इंडस्ट्रियल एरिया, कोकर, रांची 834001 ■ **फैक्स करें :** 0651-2544006 ■ **मेल करें :** eletter@prabhatkhabar.in पर ■ ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है.

एडमिशन अलर्ट

एविएशन में करें एमबीए

संस्थान : राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी, अमेठी, यूपी.
कोर्स : एमबीए-एविएशन मैनेजमेंट/ एविएशन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट/ एविएशन फाइनेंस. **योग्यता :** बैचलर डिग्री.
आवेदन : ऑनलाइन आवेदन करें.
अंतिम तिथि : 31 मार्च, 2026.
विवरण देखें : https://rgnau.ac.in/

एग्रीबिजनेस में पीजीडीएम

संस्थान : आइआइपीएम, बेंगलुरु.
कोर्स : पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट- एग्रीबिजनेस एंड प्लांटेशन मैनेजमेंट.
योग्यता : न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ एग्रीकल्चर एवं अलाइड साइंस में बैचलर डिग्री. कैट/सीमैट/ मैट का स्कोर.
प्रवेश : अकादमिक प्रदर्शन, जीडी व पीआइ.
आवेदन : ऑनलाइन आवेदन करना है.
अंतिम तिथि : 31 मार्च, 2026.
विवरण देखें : https://iipmb.edu.in/online-application-2026-27/

एसइसीएल से करें अप्रेंटिस

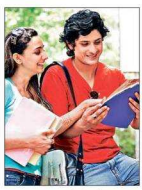

साउथ इस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसइसीएल) ने अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम 2026-27 के तहत ग्रेजुएट अप्रेंटिस एवं टेक्नीशियन अप्रेंटिस के कुल 1600 पदों पर आवेदन मांगे हैं.
योग्यता : ग्रेजुएट अप्रेंटिस पदों के लिए संबंधित विषय में 3 या 4 वर्षीय फुलटाइम रेगुलर इंजीनियरिंग/ सामान्य स्नातक डिग्री प्राप्त करनेवाले आवेदन कर सकते हैं. टेक्नीशियन अप्रेंटिस पदों के लिए संबंधित इंजीनियरिंग शाखा में 3 वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त करनेवाले आवेदन के पात्र हैं. बारहवीं के बाद डिप्लोमा के दूसरे वर्ष में सीधा प्रवेश लेनेवाले लेटरल एंट्री के अभ्यर्थी, जिनके पास 2 साल का डिप्लोमा है, वे भी आवेदन के पात्र हैं.
आयु सीमा : आवेदन करनेवाले अभ्यर्थी की आयु 31 मार्च, 2026 तक न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए.
चयन प्रक्रिया : शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों के मेरिट के आधार पर चयन किया जायेगा.
स्टाइपेंड : ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 12,300 रुपये और टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए 10,900 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड दिया जायेगा.

अंतिम तिथि : 31 मार्च

सबसे पहले एनएटीएस 2.0 पोर्टल पर पंजीकरण करना है. इसके बाद एसइसीएल की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन करना होगा.
विवरण देखें : https://secl-cil.in

दसवीं पास युवाओं के लिए
कांस्टेबल बनने का मौका

सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ने ग्रुप-सी नॉन-गजेटेड श्रेणी में कांस्टेबल के विभिन्न पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. गृह मंत्रालय के अधीन आनेवाले इस बल ने कांस्टेबल ड्राइवर, वेटरनरी समेत विभिन्न पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं.
शैक्षणिक योग्यता : मान्यताप्राप्त संस्थान से 10वीं (मैट्रिक) पास होने के साथ संबंधित ट्रेड में आइटीआइ सर्टिफिकेट, डिप्लोमा प्राप्त करनेवाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं. ड्राइवर पद के लिए दसवीं पास होने के साथ भारी वाहन ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है. वहीं, वेटरनरी के लिए 10वीं में मुख्य विषय के रूप में विज्ञान और एक वर्ष का पशु चिकित्सा अनुभव (वांछनीय) है. विस्तार से जानने के लिए अधिसूचना देखें.
आयु सीमा : न्यूनतम आयु 18 वर्ष है. अधिकतम आयु सीमा पद के अनुसार 23 से 27 वर्ष के बीच रखी गयी है. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में सरकारी नियमानुसार के अनुसार छूट दी जायेगी.
वेतनमान : चयनित उम्मीदवारों को पे-मैट्रिक्स लेवल-3 के तहत 21,700 से 69,100 रुपये प्रतिमाह मूल वेतन मिलेगा. इसके अलावा महंगाई भत्ता, राशन मनी, हाउस रेंट अलाउंस व अन्य सुविधाएं भी देय होंगी.
चयन प्रक्रिया : उम्मीदवारों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षण, 100 अंकों की कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और ट्रेड टेस्ट एवं विस्तृत चिकित्सा परीक्षा के आधार पर किया जायेगा.

कुल पद	827
कांस्टेबल	
ड्राइवर (केवल पुरुष)	553
वेटरनरी	34
गार्डनर	41
वाटर कैरियर	5
कॉबलर	25
टेलर	41
वॉशरमैन	74
बारबर	43
वेटर	3
कारपेंटर	7
नर्सिंग अर्दली	1

अंतिम तिथि
20 अप्रैल, 2026

ऐसे करें आवेदन : इच्छुक उम्मीदवार www.ssbrectt.gov.in या applyssb.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. सामान्य, इडब्ल्यूएस और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये है, जबकि एससी/ एसटी, भूतपूर्व सैनिकों और महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन निःशुल्क है.
विवरण देखें : https://applyssb.com/SSB_CT_25/applicationAfterIndex

इंडियन मेरीटाइम यूनिवर्सिटी में एडमिशन की करें तैयारी

एडमिशन स्टोरी

इंडियन मेरीटाइम यूनिवर्सिटी ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के विभिन्न कोर्स में एडमिशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. आप इन कोर्सेज में प्रवेश लेकर आगे की राह बना सकते हैं...

मेरीटाइम इंडस्ट्री के लिए योग्य पेशेवर तैयार करनेवाले देश के प्रमुख संस्थान भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय (आइएमयू) में एडमिशन शुरू हैं. इस विश्वविद्यालय के कुल छह कैंपस हैं, जो चेन्नई, कोच्चि, कोलकाता, मुंबई पोर्ट, नवी मुंबई एवं विशाखापट्टनम में स्थित हैं.

कोर्स, जिनमें ले सकते हैं प्रवेश

बीटेक : नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशन इंजीनियरिंग/ नेवल आर्किटेक्चर एंड शिप बिल्डिंग/ मरीन इंजीनियरिंग में.
बीएससी : नॉटिकल साइंस, डिप्लोमा- नॉटिकल साइंस.
बीबीए : लॉजिस्टिक्स, रिटेलिंग एवं इ-कॉमर्स/ मेरीटाइम लॉजिस्टिक्स (अप्रेंटिसशिप एंबेडेड).
एमटेक : नेवल आर्किटेक्चर एवं ओशन इंजीनियरिंग/ ड्रेजिंग एवं हार्बर इंजीनियरिंग/ एनवायर्नमेंटल इंजीनियरिंग/ मरीन टेक्नोलॉजी में.
पीजीडी : मरीन इंजीनियरिंग में.
एमबीए : इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट/ पोर्ट एंड शिपिंग मैनेजमेंट/ मेरीटाइम मैनेजमेंट में.

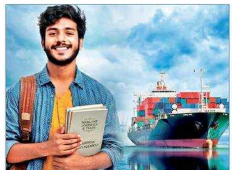

अंतिम तिथि : 24 अप्रैल, 2026

आवेदन प्रक्रिया : यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है.
विवरण देखें : https://www.imu.edu.in/imunew/admissions-2026-27

एडमिशन के लिए योग्यता

बीटेक, बीएससी एवं एक वर्षीय डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस के लिए न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों में पीसीएम से बारहवीं करनेवाले आवेदन कर सकते हैं. बीबीए के लिए बारहवीं पास होने के साथ दसवीं एवं बारहवीं में इंग्लिश में न्यूनतम 50 फीसदी अंक जरूरी हैं. एमबीए के लिए ग्रेजुएट अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं. कोर्स के अनुसार योग्यता की जानकारी नोटिफिकेशन से प्राप्त करें.

एंट्रेंस से बनेगी आगे की राह

यूजी कोर्स (बीबीए के अतिरिक्त) में प्रवेश आइएमयू-सीइटी 2026 रैंक/ सीयूइटी (यूजी) 2026 स्कोर के आधार पर मिलेगा, लेकिन प्रवेश में प्राथमिकता आइएमयू-सीइटी रैंक वाले उम्मीदवारों को दी जायेगी. बीबीए प्रोग्राम में एडमिशन बारहवीं में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर दिया जायेगा.

एमबीए प्रोग्राम में एडमिशन के लिए आइएमयू-सीइटी 2025/ 2026 रैंक/ कैट 2025 स्कोर/ मैट (सितंबर/दिसंबर)2025/ (फरवरी/मई) 2026 के स्कोर/ सीमैट 2025-26 के स्कोर के आधार पर आवेदन कर सकते हैं. एमटेक में एडमिशन की राह आइएमयू-सीइटी 2026 की रैंक/ गेट, सीयूइटी पीजी, पीजी सीइटी 2026 के स्कोर से बनेगी. एंट्रेंस टेस्ट यानी आइएमयू-सीइटी 24 मई, 2026 को आयोजित होगा.

स्मार्टर इंडिया लॉजिकल रीजनिंग एंड एप्टिट्यूड स्कॉलरशिप-2026

यह स्कॉलरशिप छात्रों की लॉजिकल रीजनिंग, एनालिसिस एवं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को निखारने के साथ पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है.
पात्रता : किसी भी स्ट्रीम (आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स आदि) के छात्र इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. कामकाजी पेशेवर भी आवेदन के पात्र हैं. आवेदक की आयु 13 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
लाभ : प्रथम श्रेणी पर चयनित अभ्यर्थी को 1,00,000 रुपये एवं अमेरिका की एक करियर एक्सपोजर विजिट, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करनेवाले को 50,000 रुपये व अंतरराष्ट्रीय सिफारिश पत्र के साथ एक वर्चुअल यूएस मिनी-प्रोजेक्ट, अन्य 20 प्रतिभागियों को 10,000 रुपये और शीर्ष 50 फाइनलिस्ट को साक्षात्कार, प्रमाणपत्र और एक डायरेक्टरी लिस्टिंग एवं राउंड-2 के प्रतिभागियों को राउंड पूरा करने का प्रमाणपत्र दिया जायेगा.
चयन प्रक्रिया : अभ्यर्थियों का चयन ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट एवं इंटरव्यू के माध्यम से होगा.

अंतिम तिथि
10 अप्रैल, 2026

ऐसे करें आवेदन : ऑनलाइन आवेदन करना है.
विवरण देखें : www.b4s.in/awsar/LROS1

झारखंड

सिटी बाइट्स

ट्रेन की चपेट में आने से महिला व बच्ची की मौत

घाटशिला. घाटशिला थाना अंतर्गत काशिदा के समीप बुधवार दोपहर डाउन रेलवे ट्रैक (संख्या 211/26-21) पर अज्ञात महिला और उसकी लगभग 6 माह की बच्ची की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गयी. दोनों के शव क्षत-विक्षत अवस्था में ट्रैक पर बिखरे मिले. घटना की सूचना मिलते ही घाटशिला पुलिस और आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने क्षत-विक्षत शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए घाटशिला अनुमंडल अस्पताल भेजा. पुलिस ने बताया कि महिला की अनुमानित उम्र 30 से 35 वर्ष और बच्ची छह माह की है. फिलहाल शवों की पहचान नहीं हो सकी है. इस कारण शवों को जमशेदपुर के शीत गृह में सुरक्षित रखा गया है. यदि अगले 72 घंटों के भीतर मृतकों की शिनाख्त नहीं हो पाती है, तो प्रशासन द्वारा नियमानुसार अंतिम संस्कार कर दिया जायेगा. घाटशिला पुलिस और आरपीएफ इस बात की जांच कर रही है कि यह एक दुर्घटना है या आत्महत्या.

घटनास्थल की जांच करती पुलिस.

बाइक पेड़ से टकरायी, दो युवकों की मौत

मनोहरपुर. मनोहरपुर प्रखंड के छोटानागरा थानांतर्गत तेतलीघाट गांव के समीप बुधवार शाम की करीब 7:00 बजे सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गयी. वहीं एक युवक घायल हो गया. मृतकों की पहचान टोंटोगढ़ा गांव निवासी लुकून चांपिया (19) और मानकी लागुरी (20) के रूप में हुई है. दुर्घटना में रोया पूर्ति (22) गंभीर रूप से घायल हो गया है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने तीनों को मनोहरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पहुंचाया. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, तीनों युवक एक बाइक पर सवार होकर मनोहरपुर से अपने गांव टोंटोगढ़ा लौट रहे थे. तेतलीघाट के पास उनकी बाइक अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा गयी. तीनों युवक बाइक से छिटककर पास पड़ी एक सूखी लकड़ी पर जा गिरे, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आयीं. बताया जाता है कि तीनों ने हेलमेट नहीं पहना था. अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने लुकून और मानकी को मृत घोषित कर दिया. वहीं, रोया पूर्ति की नाजुक स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है.

7 लाख की साइबर ठगी का आरोपी गिरफ्तार

जादूगोड़ा. दिल्ली पुलिस की टीम ने बुधवार को जादूगोड़ा थाना के इचड़ा गांव से शातिर साइबर अपराधी को धर दबोचा. गिरफ्तार आरोपी की पहचान राज भगत के रूप में हुई है. दिल्ली पुलिस उसे रिमांड पर अपने साथ ले गयी है. पुलिस के अनुसार राज भगत पर हिमांशी अनुज नामक महिला से करीब 7 लाख रुपये की ऑनलाइन ठगी करने का आरोप है. इस संबंध में पश्चिम दिल्ली साइबर थाना में 16 मार्च 2026 को प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. इस छापेमारी में आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार किया गया.

सड़क हादसे में एक युवक की मौत व दो घायल

पेटरवार. पेटरवार-तेनु मुख्य पथ पर पेटरवार थाना क्षेत्र में ओरदाना गांव के पास सड़क दुर्घटना में पतकी पंचायत के रांगामाटी गांव निवासी प्रसादी गंझू के पुत्र 24 वर्षीय सुरेश कुमार भोगता की मौत हो गयी. दो युवक गंभीर रूप से घायल भी हो गये. घटना मंगलवार रात लगभग दस बजे की है. सुरेश कुमार भोगता, सुमित कुमार भोगता और रमेश कुमार भोगता एक बाइक से पेटरवार से घर लौट रहे थे. इसी दौरान एक अज्ञात वाहन ने धक्का मार दिया.

विष्णुगढ़ में नाबालिग की दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या

प्रतिनिधि, विष्णुगढ़ (हजारीबाग)

विष्णुगढ़ में 12 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म कर बर्बरतापूर्वक हत्या करने का मामला सामने आया है. पुलिस ने बुधवार को नाबालिग का शव घर से करीब 200 मीटर दूर बांस की झाड़ियों से बरामद किया. दरिंदों ने दुष्कर्म के बाद नाबालिग के प्राइवेट पार्ट को भी क्षति पहुंचायी. घटना से लोगों में आक्रोश है. इसकी सूचना पाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और नाबालिग के कपड़े, चप्पल, खून के नमूने सहित कई साक्ष्य जब्त किये हैं. मृतका की मां ने दोषियों को कड़ी सजा देते हुए फांसी देने की मांग की है.

मंगला जुलूस देखने निकली थी नाबालिग : नाबालिग के भाई ने बताया कि गांव में मंगलवार की शाम मंगला जुलूस निकला था. उसकी बहन जुलूस देखने गयी थी. गांव के भ्रमण के बाद जुलूस करीब नौ बजे समाप्त हुआ. जुलूस खत्म होने के बाद नाबालिग के घर नहीं लौटने घरवाले उसे खोजने निकले. रात करीब दो बजे तक नाबालिग की सहेलियों व उसके परिचित के घर पर पता लगाया गया. लेकिन उसकी कोई सूचना नहीं मिली. सुबह नाबालिग के गुम होने की जानकारी चौकीदार को दी गयी. गांव वालों ने बताया कि गांव के बाहर ईंट बनाने का काम चल रहा है. गांव क ही एक युवती ईंट मजदूरों के लिए खाना पहुंचाने जा रही थी. इसी दौरान युवती को नाबालिग का शव बांस की झाडी के पास दिखा.

डॉग स्क्वायड की टीम जांच करती हुई.

नाबालिग के पिता महाराष्ट्र में प्रवासी मजदूर : गांववालों ने बताया कि नाबालिग का परिवार काफी गरीब है. माता-पिता मजदूरी कर जीवनयापन करते हैं. उसके पिता मुंबई (महाराष्ट्र) के चिपलौंग में मजदूरी करते हैं. इधर एसडीपीओ बैजनाथ प्रसाद में कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जायेगा.

नाबालिग से दुष्कर्म व वीडियो वायरल करने के दो दोषियों को 20-20 साल जेल की सजा

प्रतिनिधि, सरायकेला

सरायकेला

- कोर्ट ने 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया, नहीं भरने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा होगी

नाबालिग छात्रा का यौन शोषण और उसका वीडियो बनाकर वायरल करने के मामले में बुधवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाशंकर सिंह की अदालत ने आरोपी रोहित प्रमाणिक और कुणाल दास को दोषी करार दिया. उन्हें 20-20 वर्ष का कारावास की सजा सुनायी. दोनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा होगी.

ब्लैकमेल कर बनाया था वीडियो : यह मामला 1 सितंबर, 2022 का है. 12वीं की छात्रा कोचिंग से लौट रही थी. सहपाठी रोहित प्रमाणिक उसे जबरन चांडिल डैम स्थित शीशमहल के पास एक खंडहर में ले गया. वहां उसने छात्रा को गला दबाकर जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया. इस दौरान रोहित का दोस्त कुणाल दास भी वहां मौजूद था, जिसने अपने मोबाइल में वीडियो बना लिया. बाद में दोनों आरोपियों ने वीडियो के जरिये छात्रा को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और अंततः उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

मां की शिकायत पर दर्ज हुई थी प्राथमिकी : घटना का खुलासा तब हुआ, जब पड़ोस के एक व्यक्ति ने पीड़िता की मां को वह वीडियो दिखाया. मां के पूछताछ करने पर बेटी ने आपबीती सुनायी, जिसके बाद चांडिल थाना में मामला दर्ज कराया गया. अदालत ने पॉक्सो एक्ट और अन्य धाराओं के तहत सुनवाई करते हुए धारा 14 में 6 वर्ष (2 हजार जुर्माना) और धारा 323 में 2 वर्ष (5 हजार जुर्माना) की भी सजा सुनायी है. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.

180 किमी प्रति घंटा की स्पीड से चली स्पेशल ट्रेन

प्रतिनिधि, झुमरीतिलैया

- डीडीयू (मुगलसराय) से प्रधानखांटा तक हुआ विंडो ट्रेलिंग स्पीड ट्रायल
- हाजीपुर जोन के जीएम ने खुद की मॉनिटरिंग, डीआरएम भी रहे मौजूद

पूर्व-मध्य रेलवे की ओर से बुधवार को दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन (डीडीयू) से प्रधानखांटा तक विशेष ट्रेन द्वारा स्पीड ट्रायल किया गया.

जानकारी के अनुसार, हावड़ा से नयी दिल्ली के बीच सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाने की तैयारी चल रही है. बंगाल, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले ग्रैंड कोड सेक्शन इस रेल मार्ग का अहम हिस्सा है. ग्रैंड कोड सेक्शन का चयन 180 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से स्पीड ट्रायल के लिए किया गया है. ट्रायल के दौरान कोडरमा स्टेशन से भी होकर ट्रेन गुजरी. इस पल के कई लोग गवाह बने और वीडियो बनाया. बता दें कि जीएम और डीआरएम की मौजूदगी में पिछले साल चार अप्रैल को भी डीडीयू से धनबाद तक स्पीड ट्रायल किया गया था. उस समय 160 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चली. वापसी में धनबाद से डीडीयू के बीच भी स्पीड ट्रायल पूरा हुआ था. 160 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही ट्रेन ने तीन घंटे 55 मिनट में धनबाद से डीडीयू की 400 किमी दूरी कर ली थी, जबकि धनबाद से गया तक 200 किमी का फासला एक घंटे 57 मिनट में ही तय हो गया था. अब ट्रेन 180 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी, तो इस रूट पर एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचने का समय और कम हो जायेगा. पूर्व-मध्य रेल हाजीपुर जोन के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह की मौजूदगी में हुए ट्रायल के दौरान डीडीयू से गया तक डीडीयू के डीआरएम तथा गया से धनबाद तक धनबाद के डीआरएम अखिलेश मिश्र भी मौजूद थे. विंडो ट्रेलिंग स्पीड ट्रायल के दौरान ट्रैक में किये गये सुधार समेत अन्य प्रगति की जानकारी अधिकारियों ने ली.

वंदे भारत ट्रेन में घटिया खाना की शिकायत पर ₹60 लाख का जुर्माना

प्रमुख संवाददाता, जमशेदपुर

- पटना-टाटा वंदे भारत एक्सप्रेस में 15 मार्च की घटना, यात्री की शिकायत पर रेलवे ने की कार्रवाई
- रेलवे ने आइआरसीटीसी पर 10 लाख व सर्विस प्रोवाइडर कंपनी पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और स्वास्थ्य से समझौता करने वालों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है. पटना-टाटानगर वंदे भारत एक्सप्रेस में घटिया भोजन परोसे जाने की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए रेल मंत्रालय ने आइआरसीटीसी और संबंधित सर्विस प्रोवाइडर पर कुल 60 लाख रुपये का जुर्माना ठोका है.

जानकारी के अनुसार, 15 मार्च को ट्रेन नंबर 21896 पटना-टाटानगर वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर कर रहे एक यात्री ने भोजन की गुणवत्ता को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी. यात्री ने खाने के मानक और स्वाद को बेहद खराब बताया था. शिकायत मिलते ही रेल मंत्रालय ने जांच के आदेश दिये. जांच में अनियमितता की पुष्टि होने के बाद रेलवे ने आइआरसीटीसी पर 10 लाख और भोजन तैयार करने वाली सर्विस प्रोवाइडर कंपनी पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. वहीं, कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट भी तुरंत प्रभाव से समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया गया है. रेल मंत्रालय ने सोशल मीडिया के माध्यम से कार्रवाई को सार्वजनिक किया.

यात्री को परोसा गया था कीड़ा युक्त दही : पटना-टाटानगर वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे रितेश कुमार ने परोसे गये अमूल दही में कीड़ा होने की बात कही. इस पर ट्रेन के स्टाफ ने कीड़े को "केसर" बताया. रितेश ने इसकी शिकायत रेलवे से की, जिसपर रेलवे ने संज्ञान लिया.

सेना ने विस्फोट कर दोनों बम को नष्ट किया, 100 मीटर ऊंचा धुएं का गुबार उठा

बहरागोड़ा

- सुवर्णरेखा नदी तट पर 10 फीट गहरा गड्ढा खोदकर बालू के बोरे से ढंकने के बाद कराया गया विस्फोट

प्रतिनिधि, बहरागोड़ा

पूर्वी सिंहभूम जिला के बहरागोड़ा स्थित पानीपड़ा-नागुड़साई के पास सुवर्णरेखा नदी तट पर मिले द्वितीय विश्व युद्ध के दो जीवित बमों को बुधवार को भारतीय सेना ने सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया. यूएसए एएनएम 64 मार्का वाले अमेरिकी निर्मित बमों को सेना के विशेषज्ञों ने आधे-आधे घंटे के अंतराल पर दो अलग-अलग स्थानों पर 10-10 फीट गहरे गड्ढे खोदकर विस्फोट के जरिये डिफ्यूज किया. विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि धमाके की गूंज दूर तक सुनाइ्र दी और नदी की रेत के साथ आग व धुएं का गुबार करीब 100 मीटर की ऊंचाई तक आसमान में उठा.

विस्फोट के बाद उठता धुएं का गुब्बार.

डेटोनेटर से एक किमी दूर से किया नियंत्रित : भारतीय सेना के कैप्टन आयुष कुमार सिंह के नेतृत्व और लेफ्टिनेंट कर्नल धर्मेंद्र सिंह के दिशा-निर्देशों के तहत इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया. सुरक्षा के मद्देनजर विस्फोट स्थल से 1000 मीटर के दायरे में घेराबंदी कर दी गयी थी. बंगाल-झारखंड सीमा पर लोगों के प्रवेश को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया था. कलाइकुंडा एयरबेस को सूचित करने के बाद सेना ने लगभग 1 किमी की सुरक्षित दूरी से डेटोनेटर के माध्यम से 227 किलोग्राम वजनी बमों में विस्फोट कराया. किसी भी अनहोनी से बचने के लिए बमों को गड्ढे में रखकर बालू की बोरियों से ढंका गया था.

तीन दिनों की तैयारी के बाद मिली सफलता : उल्लेखनीय है कि ये बम 17 मार्च को नदी तट पर मिले थे, जिसके बाद एसएसपी की पहल पर सेना को सूचित किया गया था. पिछले तीन दिनों से सेना की टीम इस ऑपरेशन की तैयारी में जुटी थी. जानकारों का कहना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये बम गिराये गये होंगे, जो दशकों से नदी की रेत में दबे हुए थे.

पारिवारिक विवाद में पिता ने बेटे की कर दी हत्या, पत्नी पर हमला

रामगढ़ (दुमका). दुमका जिला के रामगढ़ थाना क्षेत्र के साधुडीह गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आयी है. एक पिता ने अपने ही 10 वर्षीय पुत्र की हत्या कर दी, जबकि पत्नी पर भी जानलेवा हमला किया. मृतक की पहचान कुशल कुमार उर्फ क्रांति कुमार के रूप में हुई है. पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है. मृतक की मां पूजा देवी ने बताया कि जरमुंडी थाना क्षेत्र के लगवा ठाड़ी निवासी पति संजय कामती से उसकी शादी हुई थी. उसे ससुराल में प्रताड़ित किया जाता था, जिस कारण वह मायके साधुडीह में रह रही थी. बताया जाता है कि आरोपी बुधवार को गांव पहुंचा और पत्नी पर केस वापस लेने का दबाव बनाने लगा. उसने बेटे से भी मां के खिलाफ बयान देने को कहा. बेटे के इनकार करने पर आरोपी ने उस पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गयी.

Your Time Is Most Valuable Thing.

I will not let you down 🙏

I GIVE YOU MY GUARANTEE, THIS PURCHASE WILL BE WORTH IT.

📚Indian Newspapers:

1) Times of India
2) Hindustan Times
3) Business line
4) The Indian Express
5) Economic Times
6) The Hindu
7) Live Mint
8) Financial Express
9) Business standard
+All Editorial PDFs

Uploding starts from 5AM

🎈Access to all this In Just 19 Rupees [lifetime Validity]

Click below to

Join

📚International Newspapers Channel

📚 Magazine Channel (National & International)

अमर उजाला

प्रवाह

7 साल बेमिसाल

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक

स्थापना : 18 अप्रैल 1948 • आगरा

नई दिल्ली ■ बृहस्पतिवार, 26 मार्च 2026

जहां चिकित्सा की कला से प्रेम किया जाता है, वहां मानवता से प्रेम खुद-ब-खुद पैदा हो जाता है। - हिप्पोक्रेट्स

वैश्विक भू-राजनीतिक संकटों के बावजूद आरबीआई की रिपोर्ट का यह कहना आश्वस्तकारी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में बाहरी झटकों को सहन करने की क्षमता पहले से बढ़ी है। जरूरत चुनौतियों के बरक्स इन क्षमताओं को बढ़ाने की है, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था अधिक स्थिर व आत्मनिर्भर बन सके।

चुनौतियों के बरक्स

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का अपनी ताजा रिपोर्ट में बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं को रेखांकित करते हुए यह संकेत देना कि भारतीय अर्थव्यवस्था की बाहरी झटकों को सहन करने की क्षमता पहले की अपेक्षया मजबूत हुई है, एक जटिल, किंतु आश्वस्तकारी आर्थिक वातावरण की ओर इशारा है। रिपोर्ट बताती है कि पश्चिम एशिया में तनाव ने वैश्विक ऊर्जा व वित्तीय बाजारों में स्वाभाविक ही अस्थिरता बढ़ा दी है। कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और उर्वरकों की आपूर्ति में आई रुकावटों की गंभीरता इससे ही समझी जा सकती है कि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी वैश्विक तेल बाजार की तारीख में इसे सबसे बड़ा आपूर्ति-व्यवधान बता रही है। जाहिर है कि इन स्थितियों में शेयर बाजार कमजोर हो गए हैं और उभरते बाजारों की मुद्राओं पर अवमूल्यन का दबाव भी बढ़ता दिख रहा है। भारत कच्चे तेल की अपनी कुल जरूरत का 85 फीसदी से अधिक और प्राकृतिक गैस की जरूरत का 40 फीसदी से अधिक आयात करता है। लिहाजा, इन स्थितियों का हम पर असर होना लाजिमी है। लेकिन, इन चुनौतियों के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था ने उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया है। घरेलू मांग में मजबूती के चलते 2025-26 के लिए जीडीपी वृद्धि दर मजबूत बनी हुई है। केंद्रीय बैंक की रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि शहरी व ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में उच्च खपत, रिकॉर्ड कृषि उत्पादन और मजबूत ऑटोमोबाइल बिक्री को देखते हुए आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने के संकेत ही मिल रहे हैं। हालांकि, रिपोर्ट में महंगाई को लेकर कुछ चिंताएं जरूर जताई गई हैं, जो जनवरी की तुलना में फरवरी में बढ़ी तो है ही, ईंधन आपूर्ति में व्यवधान के चलते इसमें और बढ़ोतरी की आशंका भी पैदा हो गई है। गनीमत है कि सरकारी खर्च पर नियंत्रण और केंद्रीय बैंक के उपायों की वजह से अर्थव्यवस्था फिलहाल पर्याप्त तरल बनी हुई है, लेकिन इस सच से भी आंखें नहीं मूंदी जा सकतीं कि वित्तीय बाजार वैश्विक झटकों से अछूते नहीं रहे हैं। विदेशी पोर्टफोलियो के बहिर्वाह के चलते रुपये पर दबाव बढ़ा है, तो व्यापार घाटे में बढ़ोतरी से देश का चालू खाता घाटा भी कुछ बढ़ा है। अच्छी बात यह है कि इन हालात में भी भारतीय रिजर्व बैंक साफ तौर पर कह रहा है कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार बाहरी झटकों से बचाव के लिए पर्याप्त है, जो एक हद तक व्यापक आर्थिक स्थिरता का ही प्रमाण है। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट का संकेत यही है कि खतरे मौजूद हैं, लेकिन देश में उनसे निपटने की क्षमता भी विकसित हुई है। जरूरत इसकी है कि इस क्षमता को और मजबूत बनाया जाए, तभी भविष्य में हम एक अधिक स्थिर व आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के रूप में पहचाने जा सकेंगे।

जब दवा ही मर्ज बन जाए

सेमाग्लूटाइड नामक औषधि को तेजी से वजन घटाने के समाधान के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। लेकिन, इससे मरीज एक ऐसे चक्र में फंस रहे हैं, जहां एक दवा दूसरी दवा के लिए बाजार बनाती है। इस संदर्भ में, चिकित्सा संगठन भी अप्रत्यक्ष और गलत भूमिका निभाते नजर आते हैं।

आजकल अखबारों की सुर्खियों में एक दवा है- सेमाग्लूटाइड, जिसका पेटेंट खत्म हो चुका है। भारत में मूलतः डायबिटीज के इलाज के लिए स्वीकृत यह दवा, वजन घटाने में भी सहायक मानी जाती है। लेकिन भारतीय उपभोक्ता बाजार की प्रवृत्ति को भांपते हुए, इस दवा को अब 'अफोर्डेबल वजन घटाने वाली दवा' के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।

निश्चित रूप से आज भारत मोटापे और उससे जुड़ी मेटाबोलिक बीमारियों- जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, फैटी लिवर और डिस्लिपिडेमिया के बढ़ते बोझ से जूझ रहा है। लगभग हर चौथा भारतीय मोटापे का शिकार है। हर दस में से एक वयस्क मधुमेह से पीड़ित है, जबकि तीन में से एक को उच्च रक्तचाप है। बड़ी संख्या में लोगों में फैटी लिवर की समस्या भी है। इससे भी अधिक चिंता की बात है कि बच्चों में मोटापा और वजन तेजी से बढ़ रहा है। इन सबके कारण भी ज्ञात हैं। अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों का बढ़ता प्रसार, शहरी जीवनशैली के कारण घटती शारीरिक सक्रियता, खुले स्थानों की कमी, लगातार तनाव, शराब का सेवन और अपर्याप्त नींद, ये सभी इस संकट को जन्म दे रहे हैं। इसके साथ ही, भारतीयों में एक आनुवंशिक प्रवृत्ति भी है, जिसमें दिखने में पतले होने के बावजूद शरीर में वसा अधिक होती है। इसे भारतीयों की 'थिन-फैट' प्रवृत्ति कहा जाता है।

डॉ. चंद्रकांत लहारिया
वरिष्ठ चिकित्सक एवं स्वास्थ्य नीति विशेषज्ञ

ऐतिहासिक रूप से, एक ऐसे समाज में, जहां लंबे समय तक कुपोषण रहा, वहां अधिक वजन को कभी समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। इसलिए, जब पिछले दो दशकों में मोटापा बढ़ा, तो इस पर चर्चा अपेक्षाकृत धीमी और संकोचपूर्ण रही। फिर दवाओं का दौर आया। पिछले वर्ष वजन घटाने की एक नई दवा भारतीय बाजार में आई और तेजी से बिकने वाली दवाओं में शामिल हो गई। इसकी सफलता ने न केवल चिकित्सकीय मांग को उजागर किया, बल्कि एक बड़े और लाभकारी बाजार के उभरने का संकेत भी दिया। अब जब सेमाग्लूटाइड कम कीमत पर उपलब्ध है, तो इसे तेजी से वजन घटाने के समाधान के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। बीते एक वर्ष में एक और चिंताजनक प्रवृत्ति उभरी है। प्रिस्क्रिप्शन दवाओं का सीधा विज्ञापन प्रतिबंधित है, पर दवा कंपनियां 'सरोगेट विज्ञापन' के माध्यम से इस सीमा को पार करती रहीं। मोटापे को केंद्र में रखते हुए दवा कंपनियों के नाम से अखबारों में पूरे पन्ने के विज्ञापन, शहरों में बड़े-बड़े होर्डिंग, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स द्वारा अप्रत्यक्ष प्रचार और प्रायोजित लेख-ये सभी जनमानस को प्रभावित करते हैं। यह धीरे-धीरे जन अपेक्षाओं और चिकित्सकीय व्यवहार को प्रभावित करता है। सरकारी नियामक एजेंसियों ने इन्हें अनदेखा किया और जब तक इस पर रोक लगी, तब तक दवा कंपनियों का उद्देश्य पूरा हो चुका था। ऐसे माहौल में, वैज्ञानिक प्रगति और व्यावसायिक हितों के बीच की रेखा धुंधली लगती है।

नई दवाओं को अक्सर ही क्रांतिकारी समाधान के रूप में पेश किया जाता है, जबकि उनके दुष्प्रभाव पर कम ध्यान दिया जाता है। इससे मोटापा जैसी जटिल समस्याएं भी दवाओं से आसानी से हल होने वाली प्रतीत होती हैं। अब जैसे कि सेमाग्लूटाइड और अन्य जीएलपी-1 आधारित दवाएं केवल चर्बी ही नहीं घटातीं, बल्कि मांसपेशियों को भी कमजोर कर सकती हैं, जिसे सारकोपेनिया कहा जाता है। सारकोपेनिया सिर्फ सैद्धांतिक चिंता नहीं रही, बल्कि शोध और वास्तविक अनुभव इसे प्रमाणित करते हैं। लेकिन वजन घटाने के उत्साह में इस जोखिम को नजरअंदाज किया जाता है। परिणामस्वरूप, व्यक्ति का वजन तो कम होता है, पर उसकी ताकत और दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। लेकिन फार्मा कंपनियों के लिए यह सिलसिला यहीं नहीं रुकता।

इन दवाओं के एक साइड इफेक्ट 'सारकोपेनिया' के इलाज के लिए नई दवाओं का परीक्षण किया जा रहा है। आने वाले कुछ वर्षों में, जब लोग इन दवाओं का इस्तेमाल करेंगे, तो उनका मोटापा तो कम हो जाएगा, लेकिन सारकोपेनिया के इलाज के लिए नई दवाएं लेने की जरूरत पड़ सकती है। भारत की नियामक व्यवस्था पहले ही अत्यधिक चिकित्साकरण को बढ़ावा दे चुकी है। दरअसल, मोटापे का इलाज दवाओं में नहीं, बल्कि जीवनशैली में है। हम एक ऐसे चक्र को देख रहे हैं, जहां एक दवा दूसरी दवा के लिए बाजार बनाती है और हर नया समाधान पिछले के दुष्प्रभावों को संभालने के लिए आता है। इस संदर्भ में, चिकित्सा संगठन भी अप्रत्यक्ष व गलत भूमिका निभाते नजर आते हैं।

आजकल क्लिनिकल दिशानिर्देश तेजी से अपडेट हो रहे हैं और नई दवाओं को जल्दी शामिल किया जा रहा है। इससे उनका व्यापक उपयोग और व्यावसायिक सफलता लगभग सुनिश्चित हो जाती है। ऐसे में, सवाल उठता है कि क्या ये सिफारिशें हमेशा ठोस साक्ष्यों पर आधारित होती हैं। दूसरी ओर, मोटापे के सबसे बड़े कारणों में से एक अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों के विस्तार पर कम ध्यान दिया जाता है। भारत में इस क्षेत्र की वृद्धि तेज रही है। ये उत्पाद लोगों की खान-पान की आदतों को बदल रहे हैं, पर नीतिगत स्तर पर ठोस कदम अब भी सीमित हैं। हम एक विरोधाभासी व्यवस्था में जी रहे हैं। एक उद्योग ऐसी जीवनशैली को बढ़ावा देता है, जो बीमारियां पैदा करती है। दूसरा उद्योग उन बीमारियों के इलाज के लिए दवाएं बेचता है। और फिर एक उद्योग दवाओं के दुष्प्रभावों के इलाज के लिए तैयार हो रहा होता है। बाजार के नजरिये से यह लाभकारी है, पर सार्वजनिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह असंतुलित है। मूल प्रश्न यह है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं-क्या हम एक स्वस्थ समाज बना रहे हैं या एक अधिक दवा-निर्भर समाज? स्वास्थ्य की अवधारणा को पुनः स्थापित करने के लिए दृष्टिकोण बदलना होगा।

दवाएं महत्वपूर्ण हैं, पर वे मूलभूत उपायों का विकल्प नहीं हो सकतीं। संतुलित आहार, नियमित शारीरिक गतिविधि, पर्याप्त नींद और तनाव प्रबंधन को प्राथमिकता देनी होगी। दवाओं के लाभ के साथ उनके जोखिमों पर भी पारदर्शिता जरूरी है। स्वास्थ्य के चिकित्साकरण को रोकने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हैं। स्वास्थ्य की तलाश में दवा और बाजार-निर्भरता के एक और चक्र की शुरुआत हो जाए, तो हम स्वास्थ्य के वास्तविक अर्थ से भटक सकते हैं। एंटी-ओबेसिटी दवाएं अंतिम समाधान नहीं हैं, बल्कि एक संकेत है कि चिकित्साकरण हमारे जीवन में कितनी गहराई तक प्रवेश कर चुका है। यह समय है ठहरकर सोचने का और स्वास्थ्य को पुनः परिभाषित करने का, इससे पहले कि दवाएं ही इसे परिभाषित करने लगें।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

अनाइस नीन

जीवन का असली रहस्य यह है कि हम इसे ऐसे जिएं, जैसे हम खुद भी कल हों या न हों। जब हम ऐसा सोचते हैं, तब काम को अधूरा नहीं छोड़ते, रिश्तों को नजरअंदाज नहीं करते, और हर पल को पूरी शिद्दत के साथ जीते हैं।

कल का कोई भरोसा नहीं

हम अक्सर एक सुरक्षित और सीमित दायरे में जीते रहते हैं, अपने चारों ओर एक नाजुक-सा खोल बना लेते हैं, और मान लेते हैं कि यही जीवन है। फिर अचानक कोई किताब पढ़ते हैं या यात्रा करते हैं और तब हमें एहसास होता है कि हम वास्तव में जी नहीं रहे, बल्कि हम तो सुषुप्त अवस्था में हैं। इस स्थिति के संकेत बहुत आसानी से समझे जा सकते हैं। पहला संकेत है-बेचैनी। दूसरा, और ज्यादा गंभीर संकेत है-जीवन में खुशी का खत्म हो जाना। यह स्थिति देखने में भले ही साधारण लगे, लेकिन धीरे-धीरे यह खतरनाक बन जाती है। एक जैसी जिंदगी, लगातार ऊब और उत्साह की कमी,

ये सब मिलकर इन्सान को अंदर ही अंदर खत्म करने लगते हैं। लाखों लोग इसी तरह जीते रहते हैं, या यों कहें कि धीरे-धीरे जीना छोड़ देते हैं, और उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनके जीवन से असली खुशी और जीवंतता कब गायब हो गई। वे दफ्तरों में काम करते हैं, परिवारों के साथ पिकनिक मनाते हैं। सब कुछ सामान्य चलता रहता है। फिर अचानक कोई चीज उन्हें झकझोर देती है-कोई इन्सान, कोई किताब या कोई गीत। वह उन्हें जैसे नींद से जगा देता है और उन्हें जीवन का असली एहसास करा देता है। हालांकि, एक सच यह भी है कि कुछ लोग कभी जाग ही नहीं पाते।

जीवन का असली रहस्य यह है कि हम इसे ऐसे जिएं, जैसे कल का कोई भरोसा न हो, जैसे हम खुद भी कल यहां हों या न हों। जब हम ऐसा सोचते हैं, तब टालने की आदत अपने आप खत्म होने लगती है। हम काम को अधूरा नहीं छोड़ते, रिश्तों को नजरअंदाज नहीं करते, और हर पल को पूरी शिद्दत के साथ जीते हैं। इस विचार ने मुझे हर मिलने वाले, हर परिचय, हर संवाद के प्रति अधिक सतर्क बना दिया। यह अनुभूति आज के समय में दुर्लभ हो गई है और दिन-ब-दिन दुर्लभ होती जा रही है, क्योंकि अब हम एक तेज और सतही गति में जी रहे हैं। आज हम मानते हैं कि हम अधिक लोगों, देशों, स्थानों के संपर्क में हैं। लेकिन यह एक भ्रम है, जो हमें हमारे पास मौजूद व्यक्ति से गहराई से जुड़ने से वंचित कर देता है। जब तकनीक इन्सानों के बीच की जगह लेने लगती है, और हमें लगता है कि हम लाखों लोगों से जुड़े हुए हैं, तब असल में हम अंदर से और ज्यादा अकेले हो जाते हैं। हमारी सच्ची भावनाएं, गहरे रिश्ते और एक-दूसरे को समझने की क्षमता भी धीरे-धीरे कम होने लगती है।

जीवन की असली समृद्धि अपने आसपास के लोगों को महसूस करने और उनसे दिल से जुड़ने से होती है। जीवन का वह संगीत, वह ऊर्जा, वह चेतना, जो हमें केवल जागृत होकर ही अनुभव होती है, वही जीवन को सच्चा बनाती है। यह अनुभव तभी मिलता है, जब हम सच में जागरूक होकर जीते हैं। अगर हम हर दिन, हर पल और हर व्यक्ति का ध्यान रखें, तो साधारण और उबाऊ लगने वाली जिंदगी में भी हमें सच्ची खुशी मिल सकती है।

-द डायरी ऑफ अनाइस नीन-4 के अनूदित अंश

आज कुछ नया करें

सूत्र

जीवन का असली अर्थ तब ही महसूस होता है, जब हम हर क्षण जागरूक होकर जीते हैं, हर व्यक्ति और अनुभव के साथ पूरी संवेदनशीलता से जुड़ते हैं, कल के अनिश्चित होने को स्वीकार करते हैं, और अपनी दिनचर्या, ऊब और तर्कसंगत जीवन की सीमाओं से बाहर निकलकर कुछ नया करने की कोशिश करते हैं।

दूसरा पहलू

उत्तर प्रदेश के कासगंज का नदरई पुल ब्रिटिश वास्तुकला का नायाब नमूना तो है ही, यहां कुछ ऐसा भी हुआ, जिससे सहम उठे लोग।

डेढ़ सौ साल पुराना पुल, मगरमच्छ और डॉक्टर डेथ

भला किसी पुल की भी कोई कहानी हो सकती है? ऐसा लगता तो नहीं, लेकिन आगरा-बरेली राजमार्ग पर कासगंज में नदरई पुल की दास्तां अनोखी ही है। यह पुल अतीत को वर्तमान से जोड़े हुए है। लगभग डेढ़ सदी के इतिहास को समेटे इस पुल को देखने आज भी देश-विदेश से पर्यटक आते हैं। ब्रिटिश इंजीनियरिंग की अनोखी मिसाल इस पुल को आयरलैंड की कॉर्क यूनिवर्सिटी के तकनीकी सहयोग से ब्रिटिश अभियंता विलियम गुड ने बनाया था।

इस विशाल पुल को बनाने में लोहे का इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि मेहराब की तकनीक इस्तेमाल की गई है। इस जलसेतु (एक्वाडक्ट) को बनाने में चार वर्ष लगे। जलसेतु का काम गुरुत्वाकर्षण के जरिये पानी को ऊंचाई से ढलान पर पहुंचाना होता है। यह पुल चर्चा में तब आया, जब डॉक्टर डेथ के नाम से कुख्यात देवेंद्र शर्मा को पुलिस ने मई, 2025 में गिरफ्तार किया। वर्ष 2002 से 2004 के बीच देवेंद्र पर 125 लोगों की किडनी निकालकर बेचने और उनकी हत्या करने का आरोप था। लाशों को ठिकाने लगाने के लिए डॉक्टर डेथ ने इसी पुल का सहारा लिया। बताया जाता है कि वह ऐसा इसलिए करता था, ताकि मगरमच्छ शवों को खा जाएं और किसी को कुछ पता न चले। पुल की सबसे खास बात है कि ऊपर हजारा (निचली गंगा) नहर और लगभग 100 फीट नीचे काली नदी बहती है। स्थानीय लोग इसे झाल या नदरई का पुल कहते हैं। पुल 15 मेहराबों पर टिका है, जो एक हजार फीट से अधिक फैली हुई हैं। पुल लगभग 20 मीटर चौड़ा है। इसे थामे रखने वाले स्तंभ (पिलर) ईंटों के बने हैं। तब कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं होता था, पर बाद में कई जगह सीमेंट से मरम्मत की गई। उस समय ईंटों को जोड़े रखने के लिए चूने और गुड़, दाल के मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता था। दिलचस्प बात यह है कि पुल आज भी शान से खड़ा है। इसमें कोई लीकेज या समस्या नहीं है। आमतौर पर किसी भी पुल को 100 साल बाद उपयोग के लिए बंद कर गिरा दिया जाता है, पर इसके साथ ऐसा नहीं है। पुल की मेहराबों के ऊपर कोठरी और बुर्जियां बनी हैं, जिनसे सीढ़ियों के जरिये नीचे काली नदी तक जाया जा सकता है, पर इनमें से ज्यादातर कूड़े व गंदगी के कारण बंद हैं। काली नदी भी सूख चुकी है।

भूपेंद्र कुमार

डॉक्टर डेथ के नाम से कुख्यात सीरियल किलर देवेंद्र शर्मा ने लाशों को ठिकाने लगाने के लिए इसी पुल का सहारा लिया था।

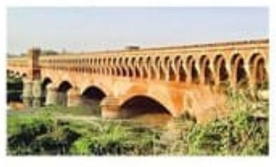

वह ऐसा इसलिए करता था, ताकि मगरमच्छ शवों को खा जाएं और किसी को कुछ पता न चल सके। स्थापना के सैकड़ों वर्षों बाद भी पुल शान से खड़ा है। इसमें कोई लीकेज या अन्य समस्या नहीं है।

पुल की वास्तुकला कमाल की है। इसके नीचे सुरंगों का पूरा जाल है। पर, अब इनका कोई उपयोग नहीं है। तो क्या यहां अब भी मगरमच्छ रहते हैं? स्थानीय ग्रामीण रमेश कहते हैं-हां बिल्कुल, वे खेतों तक में आ जाते हैं, कई बार मवेशियों और लोगों को पानी में खींच भी चुके हैं। सीरियल किलर डॉक्टर डेथ ने भी तो आखिर मगरमच्छों की वजह से ही इस जगह को चुना था। यह पुल बहते पानी के अलावा अंग्रेजों व डॉक्टर डेथ की क्रूरता का भी साक्षी है।

आंकड़े

एशिया का वर्चस्व

आंकड़ों के अनुसार, चीन और भारत मिलकर विश्व की कुल वास्तविक जीडीपी का लगभग 43.6 फीसदी हिस्सा वहन करते हैं।

चीन	26.6
भारत	17.0
अमेरिका	9.9
इंडोनेशिया	3.8
तुर्किये	2.2

आंकड़े देशों के वैश्विक जीडीपी में योगदान के, प्रतिशत में। | स्रोत : अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ)

चैत्र नवरात्र की रामनवमी का गहरा आध्यात्मिक महत्व है। इसी दिन भगवान विष्णु ने श्रीराम के रूप में जन्म लेकर धर्म की पुनः स्थापना का संकल्प लिया।

श्रीहरि का राम रूप

अंतर्यात्रा

संकलित

चैत्र नवरात्र की पूर्णाहुति और भगवान श्रीराम के जन्मोत्सव, रामनवमी का भारतीय संस्कृति में गहरा आध्यात्मिक महत्व है। पौराणिक मान्यताओं और *वाल्मीकि रामायण* के अनुसार, अयोध्या के राजा दशरथ अत्यंत प्रतापी और न्यायप्रिय शासक थे, किंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। अपनी व्यथा को लेकर वह अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के पास गए। गुरुदेव ने उन्हें 'पुत्रकामेष्टि यज्ञ' करने का परामर्श दिया। इस महान यज्ञ के संपादन के लिए विशेष रूप से ऋषि ऋष्यशृंग को आमंत्रित किया गया।

सरयू नदी के तट पर अत्यंत भव्य अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। यज्ञ की पूर्णाहुति के समय, स्वयं अग्नि देव साक्षात प्रकट हुए। उनके हाथों में स्वर्ण पात्र था, जिसमें दिव्य 'खीर' (पायस) थी। अग्नि देव ने राजा दशरथ से कहा कि यह खीर उनकी पत्नियों के लिए है, जिसके सेवन से उन्हें तेजस्वी पुत्रों की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने उस दिव्य प्रसाद का वितरण अपनी तीनों रानियों में किया। इसके फलस्वरूप, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को माता कौशल्या ने भगवान राम को जन्म दिया। उसी समय कैकेयी ने भरत और सुमित्रा ने लक्ष्मण व शत्रुघ्न को जन्म दिया।

रावण जैसे शक्तिशाली राक्षस के अत्याचारों से देवता और ऋषि-मुनि त्रस्त थे। तब भगवान विष्णु ने मानव रूप (श्रीराम) में अवतार लेकर धर्म की पुनः स्थापना का संकल्प लिया। श्रीराम का जन्म इसी दिव्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ था।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 26 मार्च, 1954

पूर्वी बंगाल में तनाव की स्थिति

पूर्वी बंगाल में तनाव की स्थिति
दमन का दौर तेजी से शुरू
लीगियों ने धमकियां देना शुरू किया

चटगांव की कर्नाफुली पेपर मिल में हुए बलवे के फलस्वरूप पूर्वी बंगाल राइफल्स के सैनिक क्षेत्र में पहरा दे रहे हैं। पूर्वी बंगाल में भारी औद्योगिक अशांति मची हुई है। बेकारी से तंग आकर लोग कानून को अपने हाथ में लेने तक के लिए आमादा हो गए हैं।

श्रम न्यायालयों से न्याय की आशा

श्रम न्यायालयों में पीठासीन अधिकारियों के रिक्त पद व उदासीन भर्ती प्रक्रिया ने न्याय को एक अंतहीन प्रतीक्षा में बदल दिया है।

रवि श्रीवास्तव

मुद्दा

संविधान में श्रमिकों के हितों की रक्षा का संकल्प लिया गया है। आजादी के बाद औद्योगिक विवादों को समय से निस्तारित करने के लिए जहां औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 लागू हुआ, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में श्रमिकों के वादों को समय से निस्तारित करने के लिए उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के साथ-साथ इसकी नियमावली को भी लागू किया गया। इसमें व्यवस्था की गई कि श्रमिकों के विवादों का एक निर्धारित समयसीमा में निस्तारण किया जाएगा।

इस अधिनियम के अंतर्गत श्रम न्यायालय और औद्योगिक न्यायाधिकरण में पीठासीन अधिकारियों की नियुक्तियों के विषय में एक उच्च स्तरीय समिति के गठन का प्रावधान किया गया। वहीं औद्योगिक न्यायाधिकरणों/श्रम न्यायालयों में पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति हेतु जो पात्रता की शर्तें रखी गई हैं, उनमें सेवारत/सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों/उच्चतर न्यायिक सेवा व राज्य न्यायिक सेवा के

अधिकारीगण/भारतीय प्रशासनिक सेवा/श्रम सेवा के अधिकारीगण या राज्य सिविल सर्विस के अधिकारी चयन हेतु पात्र होते हैं। पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति तीन वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने की तिथि (जो भी पहले हो) तक के लिए की जाती है।

उत्तर प्रदेश में कुल 20 श्रम न्यायालयों की स्थापना की गई है, जबकि छह औद्योगिक न्यायाधिकरण स्थापित किए गए हैं। इनके गठन का प्रमुख उद्देश्य श्रमिकों को सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय प्रदान करना है। लेकिन वास्तविकता में ये अदालतें श्रमिकों के लिए न्याय की राह आसान बनाने के बजाय देरी का प्रतीक बन गई हैं। लाख कोशिशों के बावजूद वादों के निस्तारण में कोई सुधार नहीं दिख रहा है। वादों के निस्तारण में 10-12 वर्ष का समय लग रहा है। इसकी अनेक वजहें हैं।

इन श्रम न्यायालयों अथवा न्यायाधिकरणों में पीठासीन अधिकारियों की बेहद कमी है, जबकि कई अवसरों पर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को यह निर्देश दिया है कि किसी भी श्रम न्यायालय अथवा औद्योगिक न्यायाधिकरणों में पीठासीन अधिकारी का पद एक भी दिन के लिए रिक्त नहीं रखा जाएगा। पिछले कुछ वर्षों में यह देखने में आया है कि उत्तर प्रदेश के पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति अन्य आयोगों और ट्रिब्यूनल में भी हो गई। इसका परिणाम यह हुआ कि इन पीठासीन अधिकारियों की प्राथमिकता बदल गई।

श्रम कानून अन्य कानूनों से थोड़ा अलग है। श्रम वादों के निस्तारण की प्रक्रिया में कई चरण होते हैं। प्रशासनिक/न्यायिक सेवा से जो अधिकारी पीठासीन अधिकारी के रूप में आते हैं, वे सामान्यतः उम्र के अंतिम पड़ाव, अर्थात 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद आते हैं। शासन की मंशा स्पष्ट है कि इनकी विद्वता और अनुभवों का लाभ उठाते हुए श्रम वादों का निस्तारण कराया जाए। लेकिन उन्हें एक से दो वर्ष का समय श्रम वादों को समझने में लग जाता है। जब तक वादों को समझते हैं, तब तक उनका कार्यकाल पूरा होने का समय आ जाता है। नतीजतन, लंबित मामलों का ढेर लग जाता है। इसके अलावा, शासन द्वारा ऐसा कोई तंत्र विकसित नहीं किया गया है कि संलग्न तंत्र में निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो सके। इसके लिए शासन स्तर पर निरंतर योजनाबद्ध नीतिगत प्रयास व नियमित अनुश्रवण की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रदेश में न्यायिक प्रशासनिक/श्रम सेवा में कार्य करने वाले अधिकारियों की कमी नहीं है। इसलिए इन न्यायालयों में ऐसे अधिकारियों की ही नियुक्ति की जाए, जिन्हें श्रम वादों के निस्तारण में व्यापक अनुभव हो, ताकि वे गुणवत्तापूर्ण निर्णय समयसीमा में दे सकें।

उत्तर प्रदेश में कामकाजी श्रमिकों की संख्या करोड़ों में है। किसी श्रमिक का अपने मालिकान/सेवायोजक से विवाद होता है, तो सबसे पहले वह श्रम कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करता है। सामान्यतः विवाद का निस्तारण तीन माह के अंदर हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा न होने पर वह टूट-सा जाता है।

श्रम न्यायालयों/औद्योगिक न्यायाधिकरणों में पीठासीन अधिकारियों के चयन से संबंधित भर्ती का विज्ञापन नहीं दिया जाता या आवेदन सार्वजनिक रूप से आमंत्रित नहीं किए जाते। इसके अलावा, इन न्यायालयों का इन्फ्रास्ट्रक्चर भी आधुनिक बनाए जाने की आवश्यकता है। अभिलेखों के उचित रखरखाव की पर्याप्त व्यवस्था किए जाने के साथ-साथ नियमित कर्मचारियों की स्थायी भर्ती की जानी चाहिए। पीठासीन अधिकारियों को न्यायिक प्रक्रिया/निर्णय दिए जाने हेतु समय-समय पर अद्यतन श्रम वादों से अवगत होने के संबंध में अनिवार्य प्रशिक्षण दिए जाने चाहिए एवं उनके निर्णयों की गुणवत्ता के न्यायिक परीक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। वादों के निस्तारण हेतु शासन स्तर से एक समयबद्ध प्रक्रिया बनाई जाए।

संचार क्रांति के युग में जब ई-कोर्ट और श्रम न्याय सेतु पोर्टल विकसित किए जा चुके हैं, तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि श्रमिक/सेवायोजक को वादों की अद्यतन जानकारी एक दिन पूर्व मिल सके।

सोने-चांदी में लौट सकती है तेजी, फिर मिलेगा कमाई का मौका

11,250 रुपये महंगी हुई चांदी, सोने में 4,900 का उछाल

मुंबई। मजबूत वैश्विक संकेतों के बीच बुधवार को सोना और चांदी की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला। सोना 4,900 रुपये चढ़कर लगभग 1.49 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। चांदी 11,250 रुपये बढ़कर करीब 2.41 लाख रुपये प्रति किलो पहुंच गई। बाजार के जानकारों के मुताबिक यह तेजी वैश्विक स्तर पर हालात सुधरने की उम्मीद, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और डॉलर के कमजोर होने के कारण आई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोना करीब 4,550 डॉलर प्रति औंस और चांदी 72 डॉलर प्रति औंस के आसपास पहुंच गई। पूरे महीने के हिसाब से दोनों धातुओं पर अभी भी दबाव बना हुआ है। मार्च महीने में अब तक सोना करीब 13 फीसदी गिर चुका है। एमसीएक्स के आंकड़ों के अनुसार 2 मार्च को सोना करीब 1,69,300 रुपये था, जो 25 मार्च तक करीब 1,44,339 रुपये रह गया। चांदी की कीमत करीब 2,36,686 रुपये प्रति किलो पहुंची। पूरे महीने में यह 20 फीसदी से ज्यादा गिर चुकी है। कामा ज्वैलरी के प्रबंध निदेशक कॉलिन शाह ने कहा कि पश्चिम एशिया में हो रहे घटनाक्रमों पर नजर रखना और उसके अनुसार निर्णय लेना आवश्यक है, क्योंकि बाजार अस्थिर दौर से गुजर रहे हैं। एजेंसी

इसलिए बना हुआ है दबाव

पश्चिम एशिया युद्ध के चलते बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता, निवेशकों की बदलती सोच, डॉलर की मजबूती और बढ़ती ब्याज दरें।

घरों में पड़ा है 10 लाख करोड़ रुपये का सोना

नई दिल्ली। भारत के घरों में करीब 10,000 अरब डॉलर (10 लाख करोड़ रुपये) का सोना रखा है। इस सोने के भंडार को वित्तीय प्रणाली में लाया जाना चाहिए। संसद की वित्त पर स्थायी समिति के सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी ने बुधवार को एसोचैम के एक कार्यक्रम में कहा, भौतिक रूप से सोना जमा रखने से आर्थिक वृद्धि में उसकी भूमिका सीमित रह जाती है। इस सोने को काम पर लगाने से भारत की आयात पर निर्भरता कम हो सकती है और चालू खाते के घाटे पर दबाव घट सकता है।

■ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मुख्य कारोबार विकास अधिकारी श्रीराम कृष्णन ने कहा कि भारत के घरों तथा मंदिरों में मिलाकर कुल 50,000 टन सोना है। इसका बड़ा हिस्सा औपचारिक वित्तीय प्रणाली से बाहर है। उन्होंने सरकार से इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स (ईजीआर) के माध्यम से सोने के वित्तीयकरण में आने वाली बाधाओं को दूर करने का आग्रह किया। एजेंसी

बढ़ी आभूषणों की मांग

नई दिल्ली। रेटिंग एजेंसी इक्रा लिमिटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जितिन मक्कड़ का मामना है कि पिछले दो वित्त वर्ष में सोने की कीमतों में

लगभग 30-30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसके कारण सोने को वित्तीय प्रणाली में लाने पर चर्चा हो रही है। कीमतों में तेज बढ़ोतरी के बावजूद आभूषणों की मांग मजबूत बनी हुई है। प्रमुख खुदरा विक्रेताओं ने दो अंक की राजस्व वृद्धि दर्ज की है। वित्त वर्ष 2024-25 तथा 2025-26 में खुदरा दुकानों की संख्या में लगभग 20 फीसदी का इजाफा हुआ है। एजेंसी

जियो के आईपीओ में आठ फीसदी हिस्सेदारी बेच सकते हैं बड़े निवेशक

अगले सप्ताह सेबी के पास दाखिल हो सकते हैं दस्तावेज

नई दिल्ली। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स जल्द ही शेयर बाजार में उतरने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, जियो प्लेटफॉर्म्स अपने आने वाले आईपीओ से पहले बड़े विदेशी निवेशकों से बात कर रही है। कंपनी चाहती है कि ये निवेशक अपने हिस्से का करीब 8 फीसदी शेयर बेचें। आईपीओ की प्रक्रिया से जुड़े सूत्रों ने बताया कि प्रत्येक निवेशक की करीब 8 फीसदी हिस्सेदारी की बिक्री होगी।

जिन बड़े निवेशकों से बातचीत चल रही है, उनमें मेटा (लगभग 9.99 फीसदी हिस्सेदारी) और गूगल (7.73 फीसदी हिस्सेदारी) जैसे बने नाम शामिल हैं। खाड़ी देशों के पब्लिक इनवेस्टमेंट फंड, मुबादला और अबुधाबी इनवेस्टमेंट अथॉरिटी ने भी जियो प्लेटफॉर्म्स में निवेश किया है। जियो प्लेटफॉर्म्स की टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो यूजर्स की संख्या के लिहाज से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। जियो प्लेटफॉर्म्स आईपीओ के लिए इस हफ्ते ड्राफ्ट पेपर्स फाइल कर सकती है। बड़े विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी बेचने की योजना से बाजार में काफी हलचल होने की उम्मीद है। एजेंसी

__भारत का सबसे बड़ा आईपीओ :__ जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपीओ भारत की सबसे बड़े सार्वजनिक पेशकश में से एक हो सकता है। रिलायंस जियो का आईपीओ पूरी तरह ऑफर फॉर सेल होगा। यह कंपनी लिस्ट कराने की पुरानी रणनीति है। इसमें कंपनी नया फंड नहीं जुटाती। कंपनी के मौजूदा निवेशक ही आईपीओ में अपने शेयर दूसरे निवेशकों को बेचते हैं।

न्यूज डायरी

ट्रेजरी बिल नीलामी पर रिजर्व बैंक की सख्ती

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को ट्रेजरी बिल (टी-बिल) की नीलामी में पेश सभी बोलियां खारिज कर दीं। जानकारी के मुताबिक, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि निवेशकों ने पिछले नीलामी स्तरों से 0.05-0.10 प्रतिशत अधिक रिटर्न की मांग की, जबकि बैंकिंग प्रणाली में नकदी की स्थिति नाजुक बनी हुई थी। नीलामी में 91-दिन, 182-दिन और 364-दिन के टी-बिल शामिल थे। एजेंसी

रमण मूर्ति बने सेबी के पूर्णकालिक सदस्य

नई दिल्ली। सरकार ने केवी रमण मूर्ति को तीन साल के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है। अन्य तीन पूर्णकालिक सदस्य अमरजीत सिंह, कमलेश चंद्र वार्ष्णेय और संदीप प्रधान हैं। रमण मूर्ति 1991 बैच के भारतीय रक्षा लेखा सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। वह रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्य कर चुके हैं। एजेंसी

भारत-जापान में 16,420 करोड़ रुपये का समझौता

नई दिल्ली। भारत सरकार ने मंगलवार को जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के साथ 16,420 करोड़ रुपये की चार परियोजनाओं के लिए समझौते किए। इनमें पंजाब में बागवानी को बढ़ावा देने की योजना और मुंबई मेट्रो लाइन परियोजना शामिल हैं। समझौते पर आर्थिक मामलों के संयुक्त सचिव आलोक तिवारी और जेआईसीए इंडिया के मुख्य प्रतिनिधि ताकेउची ताकुरो ने दस्तखत किए। एजेंसी

हर तीसरे भारतीय पर साइबर हमले का खतरा

नई दिल्ली। कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाले हर तीसरे भारतीय को साइबर अटैक का सामना करना पड़ता है। जनवरी से दिसंबर 2025 के बीच 6.46 करोड़ से अधिक साइबर हमले रोके गए। साइबर सुरक्षा कंपनी कैस्परस्काई की रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट छोड़ने के बाद भी सुरक्षा की गारंटी नहीं है। भारत शीर्ष 80 देशों में शामिल है, जहां साइबर हमलों का खतरा सबसे ज्यादा है। एजेंसी

मित्तल छोड़ेंगे एयरटेल अफ्रीका चेयरमैन का पद

नई दिल्ली। एयरटेल अफ्रीका ने बुधवार को घोषणा की कि सुनील भारती मित्तल जुलाई, 2026 में कंपनी की वार्षिक आम बैठक के बाद निदेशक मंडल के चेयरमैन पद से सेवानिवृत्त हो जाएंगे। गोपाल विट्टल को गैर-कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया गया है, जबकि श्राविन भारती मित्तल डिप्टी चेयरमैन का पदभार संभालेंगे। एजेंसी

पश्चिम एशिया में संघर्ष विराम की संभावना से तेल की कीमतों में गिरावट

कच्चे तेल की कीमत पर होर्मुज जलडमरूमध्य पर ईरान के बदलते रवैये का भी असर

न्यूयार्क। अमेरिका द्वारा ईरान को युद्ध खत्म करने के लिए 15 बिंदुओं का प्रस्ताव भेजे जाने की खबरों के बाद बुधवार को कच्चे तेल की कीमतों में करीब 4 फीसदी की गिरावट आई। ब्रेंट क्रूड करीब 3.8 फीसदी गिरकर 100.53 डॉलर प्रति बैरल और अमेरिकी डब्ल्यूटीआई क्रूड लगभग 3.9 प्रतिशत गिरकर 88.78 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने अमेरिका का प्रस्ताव ईरान तक पहुंचाया है। कहा जा रहा है कि बातचीत पाकिस्तान या तुर्की में हो सकती है, हालांकि ईरान ने सीधे बातचीत से इनकार किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक ठोस प्रगति नहीं होती तब तक तेल बाजार में उतार-चढ़ाव बना रहेगा।

इस बीच युद्ध के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल और गैस की सप्लाई लगभग ठप हो गई है। यहां से दुनिया की करीब 20 फीसदी आपूर्ति होती है। इससे रोजाना करीब 2 करोड़ बैरल तेल की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने इसे अब तक का सबसे बड़ा सप्लाई संकट बताया है। सऊदी अरब ने नुकसान की भरपाई के लिए यानबू बंदरगाह से तेल निर्यात बढ़ाकर करीब 40 लाख बैरल प्रतिदिन कर दिया है।

दूसरी ओर भारत ने भी कई साल बाद ईरान से कच्चे तेल की पहली खेप खरीदी है, क्योंकि अमेरिका ने अस्थायी रूप से प्रतिबंधों में ढील दी है। वहीं जापान ने बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए अतिरिक्त तेल भंडार जारी करने की मांग की है। अमेरिका के आंकड़ों के अनुसार उसके कच्चे तेल के भंडार में भी 6.9 मिलियन बैरल की बढ़ोतरी हुई है। तेल की कीमतों पर रूस-यूक्रेन युद्ध का असर भी दिखा। यूक्रेन के ड्रोन हमलों के बाद रूस के बाल्टिक बंदरगाहों पर तेल लोडिंग रोक दी गई, कुल मिलाकर वैश्विक तनाव के बीच तेल बाजार में भारी अस्थिरता बनी हुई है और आगे कीमतों में और उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। एजेंसी

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में प्रगति हो रही है। अमेरिका ने युद्ध खत्म करने के लिए 15 सूत्रीय योजना भी भेजी है। इससे बाजार में उम्मीद बनी कि जल्द ही युद्ध खत्म हो सकता है।

इसलिए गिर रहा कच्चा तेल

कच्चे तेल की कीमत पर होर्मुज जलडमरूमध्य पर ईरान के बदलते रवैये का भी असर हुआ है। ईरान ने कहा है कि गैर-शत्रु जहाज यहां से गुजर सकते हैं। इससे सप्लाई सुधरने की उम्मीद बढ़ी है। होर्मुज जलडमरूमध्य से दुनिया की करीब 20 फीसदी तेल और गैस आपूर्ति होती है। उधर सऊदी अरब ने अपने यानबू पोर्ट से तेल निर्यात बढ़ाया है।

भारत अप्रैल में खरीदेगा 6 करोड़ बैरल रुसी तेल

ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत अप्रैल में 6 करोड़ बैरल रूसी तेल खरीदेगा। यह मध्य पूर्व में आपूर्ति में आई रुकावटों का सामना करने के लिए एक बड़ा कदम है। अमेरिका से मिली छूट की वजह से मैंगलोर रिफाइनरी जैसी बड़ी कंपनियां फिर से रूसी कच्चे तेल की ओर लौट रही हैं। देश वेनेजुएला से भी तेल की खरीद बढ़ा रहा है। इससे आपूर्ति से जुड़ी चिंताएं कम हुई हैं।

आगे का नजरिया : विशेषज्ञों के मुताबिक, अभी युद्ध पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है इसलिए बाजार में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है।

■ **युद्धविराम सफल होगा या नहीं, इस पर संदेह बना हुआ है। अमेरिका में तेल और पेट्रोल का स्टॉक बढ़ा है, इससे कीमतों पर दबाव पड़ सकता है।**

कच्चे तेल में नरमी से शेयर बाजार में लगातार दूसरे सत्र में दिखी तेजी

■ सेंसेक्स 1,205 अंक चढ़ा, निफ्टी में 1.72 फीसदी की बढ़त

मुंबई। भारतीय शेयर बाजारों ने बुधवार को लगातार दूसरे दिन मजबूती दिखाई। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लगभग करीब 2% उछलकर बंद हुए। बीएसई सेंसेक्स 1,205 अंक चढ़ गया, जबकि एनएसई निफ्टी में 394 अंकों की तेजी रही। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की उम्मीद के बीच कच्चे तेल के दाम में कमी और वैश्विक बाजारों में मजबूती के साथ घरेलू शेयर बाजार बढ़त में रहे। एशिया के अन्य बाजारों में, दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की, चीन का शंघाई कम्पोजिट और हांगकांग का हैंग सेंग बढ़त के साथ बंद हुए।

तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 1,205 अंक यानी 1.63 प्रतिशत बढ़कर 75,273.45 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 1,781.31 अंक चढ़कर 75,849.76 अंक पर पहुंच गया था। इस तेजी से निवेशकों को 11 लाख करोड़ का फायदा हुआ। पचास शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 394.05 अंक यानी 1.72 प्रतिशत बढ़कर 23,306.45 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी मिडकैप में 2.34 फीसदी, जबकि स्मॉलकैप में 2.49 फीसदी की बढ़त देखी गई।

जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के विनोद नायर ने कहा, वैश्विक जोखिम धारणा में सुधार और शांति की उम्मीद बढ़ने से शेयर बाजारों में तेजी बनी रही। अमेरिका और ईरान के बयान में विरोधाभास के बावजूद तेल की कीमत 100 डॉलर से नीचे आ गई जिसका बाजार ने स्वागत किया। सेंसेक्स मंगलवार को 1,372.06 अंक बढ़कर 74,068.45 अंक पर बंद हुआ था, जबकि निफ्टी 399.75 अंक चढ़कर 22,912.40 अंक पर रहा था। शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने बुधवार को 1,805.37 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। वहीं, घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 5,429.78 करोड़ के शेयर खरीदे। ब्यूरो

प्रमुख इंडेक्स का हाल

निफ्टी नेक्स्ट 50	2.02% की बढ़त
निफ्टी बैंक	2.1% ऊपर
निफ्टी फाइनेंस	2.35% उछाल
निफ्टी मिड सेलेक्ट	2.04% आगे
निफ्टी आईटी	0.08% तेजी
सबसे अधिक बढ़ने वाले शेयर	
अल्ट्राटेक सीमेंट	4.12%
बजाज फाइनेंस	3.82%
लार्सन और टूब्रो	3.80%
टाइटन	3.50%
इंटरग्लोब एविएशन	3.46%
सबसे कमजोर प्रदर्शन (गिरावट)	
टेक महिंद्रा	1.66%
पावर ग्रिड	1.37%
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज	-0.86%
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स	0.27%

आज बंद रहेगा शेयर बाजार

राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज एनएसई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई गुरुवार, 26 मार्च 2026 को श्रीराम नवमी के अवसर पर बंद रहेंगे। 26 मार्च को इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव्स और सिक्योरिटीज लेंडिंग और बॉरोइंग (एलएसबी) सेगमेंट में ट्रेडिंग पूरी तरह बंद रहेगी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सुबह का सेशन बंद रहेगा, जबकि शाम 5:00 बजे से रात 11:55 बजे तक ट्रेडिंग चलेगी।

बायबैक से शेयर बेचने पर 12 फीसदी सरचार्ज लगेगा

नया नियम एक अप्रैल से होगा लागू, छोटे निवेशकों पर बढ़ेगा टैक्स का बोझ

नई दिल्ली। एक अप्रैल से कंपनियों को बायबैक यानी पुनर्खरीद में शेयर बेचने पर होने वाले कैपिटल गेन पर 12 फीसदी सरचार्ज देना होगा। ये बदलाव बुधवार को पारित फाइनेंस बिल 2026 में किए गए हैं। अब व्यक्तिगत और कॉरपोरेट दोनों निवेशकों पर एक समान 12 फीसदी सरचार्ज लगेगा। पहले सरचार्ज इनकम के आधार पर अलग-अलग था।

नया नियम एक अप्रैल से लागू होगा। एक अहम बदलाव यह भी है कि अब आयकर विभाग की इलेक्ट्रॉनिक मंजूरी को सिर्फ तकनीकी कमी (जैसे डिजिटल हस्ताक्षर का न होना) के आधार पर अमान्य नहीं किया जाएगा। टैक्स विशेषज्ञ संदीप झुनझुनवाला ने कहा, इससे छोटे और मध्यम निवेशकों के लिए टैक्स का बोझ बढ़ेगा। बायबैक के जरिये पैसा निकालना अब महंगा हो जाएगा। इससे निवेशक डिविडेंड जैसे विकल्पों की ओर जा सकते हैं। हालांकि जिन निवेशकों की आय एक करोड़ से ज्यादा है, उनके लिए सरचार्ज 15 फीसदी से घटकर 12 फीसदी हो जाएगा। जिन कंपनियों की आय एक करोड़ तक है, उनके लिए पहले सरचार्ज नहीं था। अब उन्हें भी 12 फीसदी सरचार्ज देना होगा। इससे बायबैक प्रक्रिया और महंगी हो सकती है। ब्यूरो

बायबैक क्या होता है : शेयर बायबैक एक कॉरपोरेट प्रक्रिया है जिसमें कंपनी अपने ही शेयरधारकों से अपने शेयर वापस खरीदती है। यह आमतौर पर बाजार मूल्य से अधिक कीमतपर किया जाता है। इसका उद्देश्य बाजार में शेयरों की संख्या को कम करना और मूल्य को सहारा देना है।

सरकार ने आरबीआई से मार्च 2031 तक महंगाई 4 फीसदी रखने को कहा

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आरबीआई को निर्देश दिया है कि वह खुदरा महंगाई दर को मार्च 2031 तक 4 फीसदी पर बनाए रखे। इसमें 2 फीसदी ऊपर या नीचे की सीमा तय की गई है, यानी महंगाई 2 से 6 फीसदी के बीच रह सकती है। इससे पहले सरकार ने 2016 में पहली बार भारतीय रिजर्व बैंक को यही लक्ष्य दिया था। बाद में इसे 2026 तक बढ़ाया गया था। दूसरी बार इसे आगे बढ़ाकर 2031 तक कर दिया गया है। जरूरत पड़ने पर केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में बदलाव कर सकता है। इससे आम लोगों की जेब और खर्च पर सीधा असर पड़ेगा। एजेंसी

भारत में बढ़ रहे रोजगार के अवसर कंपनियां कर रहीं वेतन में बदलाव

रोजगार का आकलन करने वाली फर्म टीमलीज सर्विसेज की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में नौकरी के मौके बढ़ने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही (अप्रैल से सितंबर) में रोजगार लगभग 4.7 फीसदी बढ़ सकता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि यह बढ़ोतरी खासतौर पर ई-कॉमर्स, टेक स्टार्टअप, हेल्थकेयर, फार्मा और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलेगी। ब्यूरो

किन सेक्टरों में ज्यादा बढ़ोतरी

8.9% ई-कॉमर्स और टेक स्टार्टअप

7% हेल्थकेयर और फार्मा

6.6% मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर

40% मौके आईटी में सबसे अधिक

फाइनेंस सेक्टर में 39 फीसदी लोगों को रोजगार

किस तरह की कंपनियां ज्यादा भर्ती करेंगी

74% बड़ी कंपनियां नई भर्ती की योजना बना रही हैं

मध्यम आकार की 57% कंपनियां नए लोगों को काम देंगी

38% छोटी कंपनियां भी नौकरियों के मौके प्रदान करेंगी, 64% कंपनियों ने कहा कि रोजगार लागत बढ़ी है

2026-27 में 7.1% रहेगी विकास दर एसएंडपी ने बढ़ाया भारत के लिए अनुमान

नई दिल्ली। रेटिंग एजेंसी एसएंडपी ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि यानी जीडीपी का अनुमान बढ़ाकर 7.1 फीसदी कर दिया है।

एजेंसी के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में निजी खपत, निवेश और निर्यात मुख्य भूमिका निभाएंगे। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष की वजह से ऊर्जा की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे देश की वित्तीय स्थिति पर दबाव पड़ सकता है। एशिया-प्रशांत क्षेत्र पर अपनी नवीनतम रिपोर्ट में एसएंडपी ने कहा कि नए भू-राजनीतिक तनाव और लगातार बने व्यापार संबंधी अनिश्चितता के जोखिम से भारत पर वस्तु कीमतों, व्यापार मात्रा एवं पूंजी प्रवाह में उतार-चढ़ाव के माध्यम से असर पड़ सकता है।

यदि कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी रहती हैं तो भारत में ईंधन की कीमतें बढ़ सकती हैं, ताकि सब्सिडी लागत को नियंत्रित किया जा सके। एजेंसी

डॉलर के मुकाबले रुपया 20 पैसे टूटकर 93.96 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा

मुंबई। रुपया बुधवार को 20 पैसे टूटकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर 93.96 पर आ गया। विदेशी पूंजी की भारी निकासी और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव से निवेशक चिंतित हैं। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, डॉलर के कमजोर रुख और घरेलू शेयर बाजारों में सकारात्मक धारणा के बावजूद स्थानीय मुद्रा को कोई राहत नहीं मिल सकी। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया, डॉलर के मुकाबले 93.94 पर खुला। अंत में यह 93.96 के सर्वकालिक निचले स्तर पर बंद हुआ। एजेंसी

गिरावट रोकने के लिए आगे आया रिजर्व बैंक

मुंबई। भारतीय रुपये की गिरावट रोकने को रिजर्व बैंक ने बाजार में दखल देकर इसे संभालने की कोशिश की। डॉलर की भारी मांग के कारण रुपया कमजोर होकर लगभग 93.96 तक पहुंच गया। इसके बाद आरबीआई ने सरकारी बैंकों के जरिए डॉलर बेचकर रुपये को गिरने से रोकने की कोशिश की। रिजर्व बैंक स्पॉट और फॉरवर्ड दोनों बाजारों में दखल दे रहा है। एजेंसी

बिल में एलपीजी या गैस सरचार्ज न जोड़ें होटल व रेस्तरां : सरकार

सीसीपीए ने कहा, नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

नई दिल्ली। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने बुधवार को होटलों और रेस्तरां को चेताया कि वे अपने बिल में अतिरिक्त शुल्क, जैसे एलपीजी चार्ज, गैस सरचार्ज न जोड़ें। प्राधिकरण ने कहा कि यह गलत है और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जाएगी। सीसीपीए ने इसे उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 के तहत अनुचित व्यापार गतिविधियां बताया। केवल लागू कर ही मेन्यू में लिखी कीमत में जोड़े जा सकते हैं। कोई भी अतिरिक्त चार्ज चाहे उसका नाम कुछ भी हो, सेवा शुल्क या अतिरिक्त शुल्क माना जाएगा और इसके लिए कार्रवाई की जा सकती है।

प्राधिकरण ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 10 के तहत निर्देश दिया गया है कि ऐसे कोई भी शुल्क स्वतः नहीं लगाए जाएंगे। उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीसीपीए ने स्पष्ट किया कि ईंधन, एलपीजी, बिजली और अन्य खर्चे जैसे कच्चे माल की लागत कारोबार चलाने की लागत का हिस्सा हैं और इन्हें मेन्यू आइटम की कीमत तय करते समय शामिल किया जाना चाहिए। एजेंसी

डब्ल्यूटीओ बैठक में छोटे किसानों व मत्स्य उद्योग के हितों पर होगा भारत का जोर

जब दुनिया विभिन्न भू-राजनीतिक कारणों से उथल-पुथल का सामना कर रही है, भारत डब्ल्यूटीओ को मजबूत बनाने पर जोर देगा

नई दिल्ली। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की कैमरून बैठक में भारत का जोर छोटे किसानों और मत्स्यपालकों की आजीविका और आर्थिक हितों की आवाज बुलंद करने पर होगा। यह बैठक 26 मार्च से चार दिनों के लिए कैमरून के याउंदे में होगी। विकासशील देशों के लिए डिजिटल व्यापार जैसे नए क्षेत्रों में नीति बनाने की स्वतंत्रता इस मंत्री स्तरीय बैठक में भारत की मुख्य प्राथमिकता होगी। इस बैठक में 166 सदस्य देशों के वाणिज्य मंत्री शामिल होंगे। इनमें भारत, चीन और अमेरिका प्रमुख हैं। बैठक में कृषि, ई-कॉमर्स और मत्स्य उद्योग से जुड़े वैश्विक व्यापार मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत का नेतृत्व वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल करेंगे। उनकी टीम में वाणिज्य विभाग और जेनेवा में भारत के स्थायी मिशन के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। भारत का मुख्य फोकस खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, छोटे किसानों और मत्स्यपालकों के रोजगार की रक्षा के साथ डिजिटल व्यापार और नई तकनीकों में विकासशील देशों के लिए स्वतंत्रता बनाए रखना होगा। ब्यूरो

विकास के लिए निवेश सुविधा

भारत ऐसे प्रयासों का समर्थन करता है जो विकासशील देशों में निवेश बढ़ाएं। पिछली बैठक में भारत ने चीन के नेतृत्व वाले आईडीएफ प्रस्ताव का विरोध किया था। यह प्रस्ताव सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी होगा।

क्या होंगे बैठक के मुख्य प्रस्ताव

बैठक के मुख्य प्रस्ताव होंगे- कृषि, ई-कॉमर्स, मत्स्य उद्योग, निवेश, डब्ल्यूटीओ सुधार और डिजिटल ट्रेड। भारत अन्य मुद्दों को भी उठाएगा, जिनमें ई-कॉमर्स ट्रांसमिशन पर 28 साल की रोक को जारी रखना, मत्स्य पालन सब्सिडी और विकास के लिए निवेश सुविधा समझौते का प्रस्ताव शामिल है। डब्ल्यूटीओ के सदस्य देश ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए टैरिफ से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा कर सकते हैं।भारत बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को मजबूत करने वाली सुधारों का समर्थन करेगा, लेकिन विकासशील देशों के हितों को केंद्र में रखेगा। डिजिटल अर्थव्यवस्था तेजी से बदल रही है, खासकर कृत्रिम मेधा और नई तकनीकों के युग में। भारत का कहना है कि देशों को नई तकनीकों का लाभ लेने के लिए नीतियों में स्वतंत्रता चाहिए।

25 वर्षों तक सब्सिडी पर रोक की मांग कर सकता है भारत

भारत सार्वजनिक भंडारण के स्थाई समाधान की मांग करेगा। देश के 99.4 फीसदी किसान कम आय वाले हैं और नयूनतम समर्थन मूल्य पर निर्भर हैं। इस व्यवस्था का समाधान किसानों के जीवन और खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक है। इसके अलावा भारत ने मत्स्य उद्योग सब्सिडी पर बातचीत और संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। इसके तहत मत्स्य उत्पादन में अग्रणी देशों को मछली पकड़ने की क्षमता को धीरे-धीरे घटाने की बात कही गई है। साथ ही, इस क्षेत्र में कम से कम 25 वर्षों के लिए सब्सिडी पर रोक हो।

चिंतन

ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल करना हो अगला कदम

आर्थिकी
सतीश सिंह

अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच युद्ध भड़कने के बाद एक बात पूरी दुनिया को समझ में आ गई है कि अब उन्हें अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए 'आउट ऑफ बॉक्स' सोच की जरूरत है। इस युद्ध ने वैश्विक ऊर्जा चर्चा का रुख निर्णायक रूप से आत्मनिर्भरता की ओर मोड़ दिया है। यूरोप, यूनाइटेड किंगडम और जापान जैसे देशों ने अपने घरेलू ऊर्जा स्रोतों को सुरक्षित करने की दिशा में कदम तेज कर दिए हैं, जबकि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) ने चेतावनी दी है कि यह व्यवधान लंबा खिंच सकता है और संरचनात्मक रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। आपूर्ति में कमी और बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान का असर बाजारों पर संघर्ष खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक बना रह सकता है। इसी परिदृश्य में भारत भी ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में अपने प्रयास तेज कर रहा है। शायद यही हमारे लिए सबसे अच्छा विकल्प भी है। अधिक आक्रामक तरीके से ड्रिलिंग करने की मौजूदा पहल 2025 और 2026 की शुरुआत से ही गति पकड़ चुकी थी, जिसे अब भू-राजनीतिक दबावों ने और तेज कर दिया है। इस बदलाव का सबसे स्पष्ट संकेत ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी) से मिला है, जिसकी हालिया पहल दिखाती है कि भारत अब केवल इरादों से आगे बढ़कर बड़े पैमाने पर क्रियान्वयन की दिशा में बढ़ रहा है। ओएनजीसी द्वारा लगभग 20 अरब डॉलर का वैश्विक टेंडर जारी कर गहरे समुद्र में ड्रिलिंग रिग्स किराए पर लेने का फैसला भारत की अपस्ट्रीम रणनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। इस योजना का विशाल आकार और केवल 80 दिनों में रिग्स जुटाने की शर्त भारत के अन्वेषण इतिहास में शायद ही कभी देखी गई तत्परता को दर्शाती है। यह कार्यक्रम उत्पादन वाले और नए (फ्रंटियर) दोनों तरह के बेसिन को कवर करता है। ओएनजीसी कृष्णा-गोदावरी बेसिन में गतिविधि बढ़ा रहा है और साथ ही अंडमान के अल्ट्रा-डीपवॉटर क्षेत्रों में भी प्रवेश कर रहा है, जिन्हें लंबे समय से संभावनाशील लेकिन कम खोजे गए क्षेत्र माना जाता रहा है। बीपी, एक्सॉनमोबिल, टोटलएनर्जीज और पेट्रोब्रास जैसी वैश्विक कंपनियों के साथ साझेदारी यह दर्शाती है कि भारत जटिल समुद्री क्षेत्रों में तेजी से परिणाम पाने के लिए तकनीक और विशेषज्ञता आयात करने को तैयार है। यह केवल ड्रिलिंग गतिविधि का विस्तार नहीं, बल्कि एक रणनीतिक उछाल है। डीपवॉटर अन्वेषण महंगा और अनिश्चित होता है, लेकिन इसमें बड़े भंडार मिलने की संभावना होती है, जो भारत के ऊर्जा संतुलन को बदल सकती है। अरबों डॉलर का निवेश यह दिखाता है कि ऊर्जा सुरक्षा अब राष्ट्रीय प्राथमिकता बन चुकी है। सरकार अब रसोई गैस (एलपीजी) पर निर्भरता कम करने के लिए एथेनॉल का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए एथेनॉल बेस्ड कुकिंग स्टोव (चूल्हे) बनाने पर काम हो रहा है। हालांकि यह प्रोजेक्ट अभी बेहद शुरुआती चरण में है। सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल बढ़ाना भी इस दिशा में अहम कदम हो सकता है। हालांकि इसमें भी समस्या सप्लाई चेन की ही है। हम ईवी के लिए अभी बड़े पैमाने पर चीन व अन्य देशों पर निर्भर हैं। ऐसे में ऊर्जा सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भता ही सर्वोत्तम विकल्प है। वैश्वीकरण के मौजूदा दौर में जब दुनिया सप्लाई चेन के लिए एक-दूसरे पर आश्रित हो गई है तो भी जरूरी है कि ऐसे स्रोतों का विविधीकरण करके किसी एक पर ही निर्भर न रहा जाए।

कमजोर और कमतर होता रुपया

इस महीने की शुरुआत में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 92 के स्तर पर था। 1947 में एक डॉलर की कीमत 4 रुपये थी, जो 2022 में घटकर 80 रुपये हो गई और अब यह कमजोर होकर 93 रुपये के स्तर पर आ गया है। केवल 3 वर्षों में रुपया डॉलर के मुकाबले 13 रुपये कमजोर हुआ है। युद्ध के कारण निवेशकों के बीच डर का माहौल है, जिससे एशियाई बाजार और भारतीय शेयर बाजार जैसे सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट आई है। हालांकि, भारत की अर्थव्यवस्था अभी मजबूत है, लेकिन यदि युद्ध जारी रहता है तो रुपये और कमजोर होंगे और भारत को कई आर्थिक स्तरों पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।

बीस मार्च को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपने सबसे निचले स्तर 93.24 पर पहुंच गया, जो बाद में सुधरकर 93.12 के स्तर पर आ गया। इस गिरावट का कारण कच्चे तेल का बढ़ता आयात बिल और विदेशी निवेशकों का भारतीय बाजार से लगातार पैसा निकालना है। इस महीने की शुरुआत में रुपया 92 के स्तर पर था। 1947 में एक डॉलर की कीमत 4 रुपये थी, जो 2022 में घटकर 80 रुपये हो गई और अब यह कमजोर होकर 93 रुपये के स्तर पर आ गया है। केवल 3 वर्षों में रुपया डॉलर के मुकाबले 13 रुपये कमजोर हुआ है।

अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष के कारण कच्चे तेल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगातार बढ़ रही हैं। खाड़ी देशों में ईरान के हमलों से अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमतें 110 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर चली गई हैं। भारत अपनी कुल जरूरत का 85% कच्चा तेल रूस, इराक, सऊदी अरब, अमेरिका और यूएई से आयात करता है, लेकिन फिलहाल अमेरिका के कारण रूस से तेल की आपूर्ति सामान्य नहीं हो पा रही है। इससे भारत की मुश्किलें बढ़ रही हैं। ध्यान दें कि कच्चे तेल का भुगतान डॉलर में किया जाता है। तेल की कीमतें बढ़ने से डॉलर की मांग भी बढ़ी है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ रहा है और रुपया कमजोर हो रहा है। तेल की कीमतें बढ़ने से हवाई यात्रा, परिवहन और जरूरी वस्तुओं की कीमतें भी भारत में बढ़ रही हैं। 22 मार्च 2026 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 709.76 अरब अमेरिकी डॉलर के स्तर पर था। कच्चे तेल की कीमत बढ़ने की वजह से डॉलर अधिक खर्च हो रहा है, साथ ही रिजर्व बैंक रुपये को स्थिर रखने के लिए डॉलर की लगातार बिक्री कर रहा है, क्योंकि वैश्विक तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण भारतीय मुद्रा पर दबाव बना हुआ है। इन कारणों से 13 मार्च 2026 को समाप्त सप्ताह में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 7.052 अरब डॉलर की तेज गिरावट दर्ज की गई थी। उससे पहले, 6 मार्च 2026 को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार में 11.68 अरब डॉलर की बड़ी गिरावट हुई थी। उल्लेखनीय है कि फरवरी 2026 के मध्य में, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 725 अरब डॉलर से अधिक के अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। वैश्विक अनिश्चितता और डर के कारण, मार्च तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने लगभग 8 अरब डॉलर, यानी करीब 83,000 करोड़ रुपये, भारतीय शेयर बाजार से निकाल लिए हैं। रुपये के कमजोर होने के कारण, विदेशी निवेशक अपने पैसे सुरक्षित रखने के लिए भारत जैसे उभरते बाजार से पैसा निकालकर अमेरिकी बॉन्ड्स में निवेश कर रहे हैं। इस बिकवाली से रुपये कमजोर हो रहा है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज वह समुद्री मार्ग है, जिसके माध्यम से दुनिया का 20 फीसदी और भारत का लगभग आधा तेल गुजरता है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के कारण इस रूट पर आपूर्ति में बाधा का खतरा बना हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक इस समुद्री मार्ग की स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती, तब तक रुपये की कीमत में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा। रुपये की कमजोरी के कई दुष्परिणाम हैं। इसकी कमजोर स्थिति से भारत में आयात महंगे हो जाएंगे, जैसे क्रूड ऑयल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम, जिनमें मोबाइल और लैपटॉप भी शामिल हैं। आयात महंगा होने से देश के चालू खाते का घाटा बढ़ेगा। जिन कंपनियों ने विदेश से कर्ज लिया है, उन्हें चुकाने के लिए ज्यादा रकम खर्च करनी पड़ेगी। इससे विदेश में पढ़ाई का खर्च भी बढ़ेगा, और यह भारत की आर्थिक विकास दर को प्रभावित कर सकता है। लगातार बढ़ती कच्चे तेल की कीमत महंगाई को बढ़ाएगी और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगी। इससे भारतीय रिजर्व बैंक के लिए नीतिगत ब्याज दरों में कटौती करना भी मुश्किल हो जाएगा, जिससे बचत में कमी, बैंकों को सस्ती पूंजी की किल्लत, कर्ज दर में वृद्धि, आर्थिक गतिविधियों में कमी, महंगाई में वृद्धि और विकास दर में गिरावट आएगी। रुपये की कमजोरी के कुछ फायदे भी हैं, जैसे कि इससे निर्यातकों को लाभ होता है। आईटी, फार्मा और ऑप्टिकल उद्योग की कंपनियों को उनके उत्पाद या सेवाओं के लिए डॉलर में भुगतान मिलता है। जब ये डॉलर को रुपये में बदलते हैं, तो उन्हें अधिक रुपये मिलते हैं। भारत में विदेशी पर्यटकों के लिए यात्रा करना सस्ता हो जाएगा, जिससे स्थानीय पर्यटन क्षेत्र को फायदा होगा। विदेशों में काम करने वाले भारतीय अपने परिवारों को जो पैसा भेजते हैं, वह अधिक रुपये में मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक कच्चे तेल की कीमतें 110-115 डॉलर से ऊपर हैं और विदेशी निवेशक बेचवाली कर रहे हैं, रुपये कमजोर बना रहेगा। यदि वैश्विक माहौल में कोई सुधार नहीं होता, तो यह 94 के स्तर को भी पार कर सकता है।

किसी भी देश की मुद्रा का मूल्य मुख्य रूप से उसके अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग और आपूर्ति पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, यदि भारत को अधिक सामान जैसे कच्चा तेल मंगवाना हो तो उसे अधिक डॉलर की आवश्यकता होगी। इस मांग के बढ़ने पर डॉलर की कीमत बढ़ेगी और वह महंगा हो जाएगा, जिससे रुपया कमजोर हो जाएगा। मुद्रा की कीमत का निर्धारण देश की महंगाई दर, ब्याज दरें और विदेशी निवेशकों का भरोसा भी करता है। जब महंगाई कम रहेगी तो आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा और अर्थव्यवस्था स्थिर रहने पर विदेशी निवेशक भारत में निवेश करेंगे, जिससे डॉलर की आमद बढ़ेगी और रुपया मजबूत होगा। आसान शब्दों में, दुनिया में जिस मुद्रा की मांग अधिक और आपूर्ति कम होगी, उसकी कीमत भी उतनी ही अधिक होगी।

अंत में कहा जा सकता है कि रुपये की कमजोरी के फायदे कम और नुकसान ज्यादा हैं। युद्ध के कारण निवेशकों के बीच डर का माहौल है, जिससे एशियाई बाजार और भारतीय शेयर बाजार जैसे सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट आई है। वैश्विक अनिश्चितता के कारण विदेशी निवेशक शेयर बाजार में बिकवाली कर रहे हैं, जिससे देश में निवेश घट रहा है, क्योंकि भारत में विदेशी निवेशकों का अहम योगदान है। इसके अतिरिक्त, इससे भारत में उर्वरक, तेल और रसोई गैस की कमी हो गई है। शिपिंग मार्गों में रुकावट से कई जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति पर प्रभाव पड़ा है। इन बाधाओं से महंगाई बढ़ी है, व्यापार घाटा बढ़ रहा है और विदेशी मुद्रा भंडार कम हो रहा है। वर्तमान स्थिति में सरकार को उर्वरक की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किसानों को सब्सिडी देनी पड़ेगी, क्योंकि भारत में उर्वरक का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है। इससे राजकोषीय दबाव का खतरा बढ़ रहा है। हालांकि, भारत की अर्थव्यवस्था अभी मजबूत है, लेकिन यदि युद्ध जारी रहता है तो रुपये और कमजोर होंगे और भारत को कई आर्थिक स्तरों पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।

(लेखक एसबीआई मुंबई में एजीएम हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर दे सकते हैं।

रामनवमी पर विशेष

मुनीष भाटिया

आध्यात्मिक चेतना और दर्शन के शाश्वत प्रतीक हैं श्रीराम

मानव जीवन एक सतत यात्रा है-सत्य, प्रेम और आत्मबोध की यात्रा। इस यात्रा में राम एक मार्गदर्शक प्रकाश की तरह हमारे साथ रहते हैं। वे केवल इतिहास या ग्रंथों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के अंतर्मन में बसने वाली वह चेतना है, जो हमें सही और गलत का भेद सिखाती है। उनका नाम केवल धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा नहीं, बल्कि जीवन को सार्थक बनाने की अनुभूति है। आज का समाज अनेक विभाजनों में बंट चुका है-जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के आधार पर। इन विभाजनों ने मानवता की मूल भावना को कमजोर कर दिया है। लेकिन राम का जीवन हमें यह सिखाता है कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने अपने आचरण से यह सिद्ध किया कि सच्चा धर्म वही है, जो सबको साथ लेकर चले। शबरी के प्रेम से सिक्त बेर स्वीकार करना, निषादराज को आत्मीय मित्र बनाना और हनुमान जैसे भक्त को हृदय से लगाना-ये सभी प्रसंग यह दर्शाते हैं कि राम के लिए कोई भी ऊंच-नीच या भेदभाव नहीं था। वे समरसता और समानता के सच्चे प्रतीक हैं। राम को "मर्यादा पुरुषोत्तम" इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जीवन के हर संबंध और हर भूमिका में मर्यादा का पालन किया। चाहे वह पुत्र के रूप में पिता के वचन का पालन हो, राजा के रूप में प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व, या एक मित्र के रूप में निष्ठा-हर स्थान पर उन्होंने आदर्श स्थापित किए। आज जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं और स्वार्थों के कारण मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहा है, तब राम का जीवन हमें अनुशासन और संयम का महत्व याद दिलाता है। उन्होंने चौदह वर्षों का वनवास सहर्ष स्वीकार कर यह सिद्ध किया कि कर्तव्य और वचन की मर्यादा सर्वोपरि होती है। राम का जीवन इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य अपने कर्मों और आचरण से ही महान बनता है। वे हमें यह समझाते हैं कि "पुरुष" से "पुरुषोत्तम" बनने की यात्रा बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता, सत्यनिष्ठा और कर्तव्यपरायणता से तय होती है। जब व्यक्ति लोभ, मोह, अहंकार और वासना जैसे बंधनों से मुक्त होकर निष्काम भाव से कर्म करता है, तभी वह अपने वास्तविक स्वरूप के निकट पहुंचता है। राम का यह संदेश हमें आत्मोन्नति की ओर प्रेरित करता है। मानव की सबसे बड़ी चुनौती उसकी अनियंत्रित इच्छाएं हैं, जो उसे भ्रम और पतन की ओर ले जाती हैं। इसके विपरीत, रावण का चरित्र यह दर्शाता है कि ज्ञान और शक्ति होते हुए भी यदि व्यक्ति अपने अहंकार और वासना पर नियंत्रण नहीं रखता, तो उसका विनाश निश्चित है। इस प्रकार राम और रावण का अंतर केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक मूल्यों का अंतर है। राम का सबसे महत्वपूर्ण संदेश "निष्काम कर्म" का है- ऐसा कर्म, जिसमें फल की अपेक्षा न हो। जब व्यक्ति बिना स्वार्थ के अपना कर्तव्य निभाता है, तो वह न केवल मानसिक शांति प्राप्त करता है, बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा बनता है। आज का मनुष्य भौतिक सुख-सुविधाओं की दौड़ में इतना व्यस्त हो गया है कि उसने आंतरिक संतोष और शांति को पीछे छोड़ दिया है। राम का मार्ग हमें सादगी, संतुलन और आत्मिक संतोष की ओर लौटने का आह्वान करता है। सत्य और धर्म राम के जीवन के मूल आधार रहे हैं। उन्होंने हर परिस्थिति में सत्य का साथ दिया, चाहे वह कितना ही कठिन क्यों न हो। यह हमें सिखाता है कि सच्चाई का मार्ग भले ही चुनौतीपूर्ण हो, लेकिन अंततः वही स्थायी विजय का मार्ग है। इसी संदर्भ में आज के समय में राम के आदर्शों की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है।

आधुनिक जीवन की भागदौड़, प्रतिस्पर्धा और मानसिक तनाव के बीच व्यक्ति स्वयं से दूर होता जा रहा है। ऐसे में राम का जीवन हमें आत्मचिंतन की ओर प्रेरित करता है। वे सिखाते हैं कि बाहरी सफलता के साथ-साथ आंतरिक संतुलन भी आवश्यक है। यदि मन अशांत है, तो कोई भी उपलब्धि हमें संतुष्टि नहीं दे सकती। इसलिए राम का मार्ग केवल नैतिकता का ही नहीं, बल्कि मानसिक शांति और संतुलन का भी मार्ग है। इसके अतिरिक्त, राम का जीवन नेतृत्व और सामाजिक उत्तरदायित्व का भी अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। उन्होंने राजा के रूप में सदैव प्रजा के हित को सर्वोपरि रखा। आज के नेतृत्वकर्ता यदि राम के इस गुण को अपनाएं, तो समाज में न्याय और विश्वास की स्थापना हो सकती है। राम हमें यह भी सिखाते हैं कि सच्चा नेतृत्व वही है, जो त्याग, सेवा और समर्पण पर आधारित हो, न कि केवल सत्ता और अधिकार पर। अंततः, राम कोई दूरस्थ आदर्श नहीं, बल्कि हमारे भीतर जागृत होने वाली वह चेतना हैं, जो हमें एक बेहतर मनुष्य बनने की प्रेरणा देती है। उनका संदेश सरल है-सत्य का अनुसरण करो, धर्म का पालन करो, और मानवता को सर्वोपरि रखो। यही जीवन का सार है, और यही सच्चे अर्थों में राम को जीना है।

(लेखक स्वतंत्र स्तंभकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

धैर्य के साथ करें आत्ममूल्यांकन

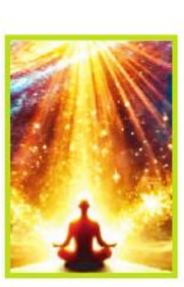

संकलित
दर्शन

प्रकृति हमेशा एक मार्गदर्शक के रूप में हमें प्रेरित व उत्साहित करती रहती है। हर पेड़, पौधे, फूल, पत्ती का एक मौन संदेश हुआ करता है और वह है कि स्वयं को निरंतर गतिमान और संतुलित रखने के लिए धैर्य चाहिए। पेड़ों पर मंजरी या बौर आने के तुरंत बाद ही तो फल नहीं आ जाता। हौले-हौले ही यह प्रक्रिया सम्पन्न होती है। माटी, हवा और पानी से जिस तरह एक पौधा धीरज रखकर खुद को पुष्पित और पल्लवित करता है, हमें भी ऐसा ही जीवन दर्शन अपनाना चाहिए। महर्षि अरविंद अपने पास आने वाले जिज्ञासु को यह मंत्र देते थे कि मनुष्य अपने सारे जीवन का वास्तुकार स्वयं ही है। हम अपनी रुचि और सोच-विचार के हिसाब से दिनचर्या तय करते हैं। अपने तौर तरीके से दिन बिताते हैं। सब सामान्य रहता है, तो हम खुश रहते हैं। लेकिन इस दिनचर्या में कुछ जरा-सा भी कुछ अनचाहा हुआ नहीं कि हम सिर पीटने लगते है। हमारा धैर्य डोल जाता है। हमारी पसंद से बने हुए जीवन की हलचल और हिचकोले हमें विचलित कर देते हैं। हम गलती से भी आत्म अवलोकन नहीं करते।हम अपनी भूमिका न देखकर किसी और पर दोष मढ़ देते हैं। ऐसा प्रदर्शित करते हैं कि इस हालत के लिए उनके अलावा सब ही जिम्मेदार हैं। आरोप लगाने और खुद साफ बच जाने के इस पल में हम चतुराई से यह सच छिपा जाते हैं कि कर्म का नियम कुछ और ही है। कर्म का सिद्धांत यह साफ कहता है कि हमारे हर दुख कष्ट आदि के लिए हम ही जिम्मेदार हैं, कोई दूसरा नहीं।

श्रमरहित पराश्रित जीवन विकास के द्वार बंद करता है

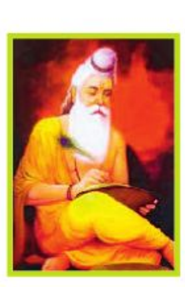

संकलित
प्रेरणा

महर्षि वेदव्यास ने एक कीड़े को तेजी से भागते हुए देखा। उन्होंने उससे पूछा- हे क्षुद्र जंतु, तुम इतनी तेजी से कहाँ जा रहे हो? उनके प्रश्न ने कीड़े को चोट पहुंचाई और वह बोला- हे महर्षि, आप तो इतने ज्ञानी हैं। यहां क्षुद्र कौन है और महान कौन? क्या इस प्रश्न और उसके उत्तर की सही-सही परिभाषा संभव है? कीड़े की बात ने महर्षि को निरुत्तर कर दिया। फिर भी उन्होंने उससे पूछा- अच्छा यह बताओ कि तुम इतनी तेजी से कहाँ जा रहे हो? कीड़े ने कहा- मैं तो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा हूं। देख नहीं रहे, पीछे से कितनी तेजी से बैलगाड़ी चली आ रही है। कीड़े के उत्तर ने महर्षि को चौंकाया। वे बोले, तुम तो इस कीट योनि में पड़े हो। यदि मर गए तो तुम्हें दूसरा और बेहतर शरीर मिलेगा। इस पर कीड़ा बोला- महर्षि, मैं तो इस कीट योनि में रहकर कीड़े का आचरण कर रहा हूँ, परंतु ऐसे प्राणी असंख्य हैं, जिन्हें विधाता ने शरीर तो मनुष्य का दिया है, पर वे मुझसे भी गया-गुजरा आचरण कर रहे हैं। कीड़े की बातों में महर्षि को सत्यता नजर आई। वे सोचने लगे कि वाकई जो मानव जीवन पाकर भी देहासक्ति और अहंकार से बंधा है, जो ज्ञान पाने की क्षमता पाकर भी ज्ञान से विमुख है, वह कीड़े से भी बदतर है। महर्षि ने कीड़े से कहा- नन्हें जीव, चलो हम तुम्हारी सहायता कर देते हैं। कीड़ा बोला- किंतु मुनिवर श्रमरहित पराश्रित जीवन विकास के द्वार बंद कर देता है। कीड़े के कथन ने महर्षि को ज्ञान का नया संदेश दिया।

राम की मूर्ति को अंतिम रूप

महाराष्ट्र के नागपुर में चल रहे नवरात्रि उत्सव के दौरान राम नवमी से पहले एक कलाकार भगवान राम की मूर्ति को अंतिम रूप दे रहा है।

आज की पाती

परमात्मा बेईमानी-चालाकी सब देखते हैं

दुनिया की नजर से बचकर हम चालाकियां और बेईमानियां कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे कर्मों का लेखा-जोखा रख रहा है, उससे हम कुछ नहीं छुपा सकते। हम सब जानते हैं कि भगवान कण-कण में विराजमान हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग इस अटल सच्चाई को नजरअंदाज करते हुए बेईमानी और अन्य गलत कामों को करने से परहेज नहीं करते, बेशक उन्होंने बुरे कर्मों का नतीजा भुगता ही क्यों न हो, लेकिन फिर भी वो दुनिया से नजर बचाकर बेईमानी और चालाकी करने से बाज नहीं आते। परमात्मा हमारी अंतरात्मा पर भी नजर रखता है, वो हमारी सोच, मन, मस्तिष्क में क्या चल रहा है, उसको भी देखता है। परमात्मा की नजर में हमारे कर्म रिकॉर्ड होते हैं।

– विजय देवागंन, कुम्हारी

ट्रेंड

शांति और स्थिरता पर चर्चा

राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर पश्चिम एशिया की स्थिति पर विचारों का उपयोगी आदान-प्रदान हुआ। भारत तनाव कम करने और जल्द से जल्द शांति बहाल करने का समर्थन करता है। हमने शांति और स्थिरता के प्रयासों के संबंध में संपर्क में रहने पर सहमति जताई।

- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

ट्रांसजेंडर विधेयक

भाजपा सरकार का ट्रांसजेंडर व्यक्ति संशोधन विधेयक ट्रांसजेंडरों के संवैधानिक अधिकारों और पहचान पर खुला हमला है। यह प्रतिगामी विधेयक ट्रांसजेंडर लोगों से उनकी स्वयं की पहचान करने का अधिकार छीन लेता है, जो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लंघन है।

- राहुल गांधी, सांसद, कांग्रेस

आईपीडी टावर की उपेक्षा

जयपुर के महिला चिकित्सालय (सांगानेरी गेट) में बन रहा आईपीडी टावर भी आज भाजपा सरकार की उपेक्षा का शिकार है। हमारी कांग्रेस सरकार ने फरवरी 2023 में इस प्रोजेक्ट का काम शुरू किया था।

- अशोक गहलोत, पूर्व सीएम, राजस्थान

बिहार में अपराध

बिहार में अपराधियों का काम अब पुलिस कर रही है। दारू पीकर दरोगा किसी को भी गोली मार देता है और दरोगा का कुछ नहीं बिगड़ता। ये भ्रष्ट असामाजिक तत्व हमारे लोगों के संयम और अनुशासन को कमजोरी ना समझे।

-तेजस्वी यादव, पूर्व डिप्टी सीएम, बिहार

करंट अफेयर

ईरान में छिड़ी जंग से ज्यादा परेशान ये मुल्क

ईरान में अमेरिका और इजरायल की ओर से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। ईरान के तेल कुएं हों या फिर गैस फील्ड, सभी को अमेरिका और इजरायल ने टारगेट किया है। वहीं ईरान ने भी संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर और बहरीन समेत कई ऐसे देशों पर हमले किए हैं, जहां से बड़ी संख्या में तेल और गैस की सप्लाई दुनिया भर में की जाती है। इस जंग ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को भी बाधित किया है, जहां से दुनिया का करीब 20 फीसदी तेल कारोबार होता है। इसके चलते भारत समेत कई देशों में तेल और गैस का संकट पैदा हो गया है। इसकी वजह है कि भारत ने अपनी तेल की जरूरतों को डाइवर्सिफाई किया है। वहीं पाकिस्तान, जापान, थाइलैंड और कोरिया जैसे देशों को ज्यादा परेशानी है। एक रिपोर्ट के अनुसार खाड़ी देशों से अपनी जरूरत का सबसे ज्यादा तेल आयात पाकिस्तान करता है। इसके बाद दूसरा नंबर जापान, तीसरा थाईलैंड और चौथा साउथ कोरिया का है। इसके बाद 5वां नंबर भारत का आता है। साफ है कि ईरान में चल रही जंग से भारत के मुकाबले कहीं ज्यादा परेशान पाकिस्तान है। इस संकट के चलते एक तरफ सप्लाई पर असर पड़ा है तो वहीं कच्चे तेल के दाम भी 100 डॉलर के ऊपर लगातार बने हुए हैं।

ऑफ बीट

कई ग्लुटेन मुक्त उत्पादों में कैलोरी-शर्करा अधिक

अमेरिकी उपभोक्ता अक्सर ग्लुटेन-मुक्त उत्पादों के लिए अधिक भुगतान करते हैं, फिर भी ये उत्पाद आमतौर पर ग्लुटेन युक्त विकल्पों की तुलना में कम प्रोटीन और अधिक शर्करा एवं कैलोरी प्रदान करने वाले होते हैं। वर्तमान में कई ग्लुटेन-मुक्त उत्पादों में फाइबर, प्रोटीन और आवश्यक पोषक तत्वों की कमी होती है। इसके अलावा, ग्लुटेन-मुक्त उत्पादों में आमतौर पर ग्लुटेन युक्त अन्य उत्पादों की तुलना में अधिक शर्करा पाई जाती है। ग्लुटेन-मुक्त आहार के लंबे समय तक सेवन का संबंध 'बॉडी मास इंडेक्स' (बीएमआई) में वृद्धि और पोषण संबंधी कमियों से है। ग्लुटेन-मुक्त उत्पाद को अमेरिका में ऐसे उत्पाद के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनमें ग्लुटेन प्रति 10 लाख में 20 भाग से कम या उसके बराबर होता है। लेकिन ग्लुटेन-मुक्त उत्पाद में बड़े पैमाने पर गेहूं, राई, जौ और कभी-कभी जई की कमी होती है, जबकि ये सभी 'रबीनॉक्सिलन' के समृद्ध स्रोत हैं जो एक महत्वपूर्ण स्टार्च रहित पॉलीसेकेराइड है। अरबीनॉक्सिलन कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है, जिसमें लाभकारी आंत बैक्टीरिया को बढ़ावा देना, पाचन को बढ़ाना, रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना और संतुलित आंत माइक्रोबायोटा का समर्थन करना शामिल है।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।

नितिन नवीन ने पश्चिम बंगाल प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण सांगठनिक बैठकें की

पश्चिम बंगाल चुनाव जनता में टीएमसी के भय बनाम भाजपा के भरोसे के बीच होगा: नवीन

भाजपा अध्यक्ष बोले, बंगाल की जनता टीएमसी के गुंडों और ममता बनर्जी की वसूली सरकार से मुक्ति चाहती है

हरिभूमि ब्यूरो ▶▶ नई दिल्ली

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बुधवार को कोलकाता में अपने पश्चिम बंगाल प्रवास के दूसरे और अंतिम दिन नबद्वीप ज़ोन बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कई महत्वपूर्ण सांगठनिक बैठकें की और बंगाल विधान सभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा की माइक्रो लेवल तैयारियों की समीक्षा की तथा पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशानिर्देश दिए। कार्यक्रम के दौरान पश्चिम बंगाल भाजपा के चुनाव प्रभारी व केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, राष्ट्रीय महामंत्री एवं पश्चिम बंगाल के प्रभारी सुनील बंसल, बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे, सह प्रभारी अमित मालवीय, पूर्व सांसद लॉकेट चटर्जी सहित अन्य वरिष्ठ नेता व पदाधिकारी उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि यह पूरा चुनाव केवल दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित है - तृणमूल सरकार के कुशासन से भय और जनता का भाजपा के सुशासन पर भरोसा। यह चुनाव टीएमसी के भय के वातावरण से बाहर निकलने का चुनाव है, क्योंकि जनता अब पूरी तरह से उस डर से मुक्त होना चाहती है। टीएमसी के गुंडे, तथाकथित कार्यकर्ता और उनकी सरकार वसूली, भ्रष्टाचार और अराजकता की सरकार चला रहे हैं, उससे अब राज्य की जनता मुक्ति चाहती है। जनता उस भय के वातावरण से बाहर आना चाहती है और उसे यह भी स्पष्ट रूप से पता है कि यदि उसे इस स्थिति से निकलना है तो उसका भरोसा केवल भारतीय जनता पार्टी पर है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, उसके कार्यकर्ता और स्थानीय नेतृत्व पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और जनता को विश्वास है कि वही सोनार बंगाल के सपने को साकार कर सकते हैं।

नवीन ने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोग टीएमसी सरकार के भ्रष्टाचार, वसूली, भय और अराजकता के माहौल से मुक्ति चाहते हैं। भाजपा ही सुरक्षा, रोजगार और सम्मान सुनिश्चित कर सकती है। भाजपा के कमल का निशान पश्चिम बंगाल को विकास, सुरक्षा और 'सोनार बंगाल' की दिशा में आगे ले जाने का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भाजपा की ताकत उसके समर्पित कार्यकर्ता हैं, जो 'राष्ट्र प्रथम' के भाव से काम करते हैं। पार्टी के कार्यकर्ता मेहनत और परिश्रम के साथ हर बूथ तक पहुंचेंगे और 4 मई को राज्य में भाजपा की सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि कमल का निशान, इस राज्य को विकास के पैमाने पर आगे बढ़ाने, राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने और 'सोनार बंगाल' के सपने को साकार करने का प्रतीक है। यह कमल का फूल निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल को 'विकसित पश्चिम बंगाल' बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

नवीन ने कहा कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ता एक-एक बूथ की संरचना खड़ी करने में जुटे हैं और पिछले चार-पांच वर्षों में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद पश्चिम बंगाल में संगठन को मजबूत किया है, वह अत्यंत सराहनीय है। पिछले चार-पांच वर्षों में विपरीत परिस्थितियों में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा की गई मेहनत अब रंग ला रही है और आज जनता उनके साथ खड़ी है। पश्चिम बंगाल का एक-एक व्यक्ति इस परिवर्तन की लहर में कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा होकर संघर्ष करने के लिए तैयार है।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव

भाजपा ने आरजी कर रेप पीड़िता की मां को बनाया उम्मीदवार

भाजपा ने 19 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की

हरिभूमि ब्यूरो ▶▶ नई दिल्ली

भाजपा ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट बुधवार को जारी की। इस लिस्ट में 19 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। भाजपा ने आरजी कर रेप पीड़िता की मां रत्ना देबनाथ को भी टिकट दिया है। पीड़िता की मां पानीहाटी से चुनाव लड़ेंगी। हरिपाल से मधुमिता घोष को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इंग्लिश बाजार से अमलन भादुरी को टिकट मिला है। कूचबिहार दक्षिण से रथीन्द्र नाथ बोस को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं, राजगंज से दिनेश सरकार को चुनाव लड़ने का मौका मिला है।

शांतिपुर से स्वपन दास को प्रत्याशी बनाया गया है। हावड़ा मध्य से बिप्लब मंडल, इस्लामपुर से चित्रजीत रॉय, नलहाटी से अनिल सिंह को टिकट मिला है। सिंगूर से अरूप कुमार दास और सैंथिया से कृष्णा कांत साहा चुनाव लड़ेंगे। कूचबिहार दक्षिण से रथीन्द्र नाथ बोस, राजगंज (अजा) से दिनेश सरकार (हराधन सरकार), इस्लामपुर से चित्रजीत रॉय, हेमताबाद (अजा) से हरिपद बर्मन, इंग्लिश बाजार से अमल भादुरी, शांतिपुर से स्वपन दास, पानीहाटी से रत्ना देबनाथ, हावड़ा मध्य से बिप्लबमंडल, उत्तरपाड़ा से दीपांजन चक्रवर्ती, सिंगूर से डॉ. अरूप कुमार दास, चन्दननगर से दीपांजन कुमार गुहा, चुंचुड़ा से सुबीर नाग, हरिपाल से मधुमिता घोष, तमलुक डॉ. हरे कृष्णा बेरा, मेदिनीपुर से शंकर गुच्छैत, पूर्वस्थली से प्राणकृष्ण तपदार, कटवा से कृष्णा घोष, सैथिया सेकृष्णा कांत साहा और नलहाटी से अनिल सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके पहले दो सूचियां जारी की जा चुकी हैं।

भवानीपुर में सुवेंदु ने ममता को खूब सुनाया

टीएमसी डबल डिजिट पार नहीं करेगी

भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करने पहुंच भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि तृणमूल डबल डिजिट पार नहीं करेगी। यह ट्रिपल

डिजिट नहीं होगा। वे बंगाल को मोदीजी के हाथों में छोड़ना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि मोदीजी ने नंदीग्राम की तरह ममता बेनर्जी को सीरियसली हराने के लिए विपक्षी नेता को भेजा है। वे हिम्मत के साथ निकले हैं। वे भी बदलाव चाहते हैं। आई पैक ने जो किया है, उससे हमारा कोई लेना-देना नहीं है। अधिकारी ने कहा कि आप नंदीग्राम की जितनी ज़्यादा ज़िम्मेदारी लेंगे, मैं उतने ही ज़्यादा वोटों से ममता बनर्जी को फिर से हरा पाऊंगा।

ओवैसी ने हुमायूं की पार्टी से मिलाया हाथ

बंगाल में घुटन महसूस कर रहे लोग

जनता उन्नयन पार्टी के संस्थापक हुमायूं कबीर और एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बंगाल चुनावों के लिए अपनी पार्टियों के गठबंधन की घोषणा की। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुमायूं कबीर ने कहा कि हम पूरे राज्य में 20 रैलियां करेंगे। पहली रैली 1 अप्रैल को बहरामपुर में ओवैसी के साथ होगी। वहीं, ओवैसी ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल के लोग घुटन महसूस कर रहे हैं। उनकी पार्टी ने हुमायूं की पार्टी से हाथ मिलाया है।

फिरहाज हकीम ने ममता के लिए मांगे वोट

भवानीपुर चुनाव क्षेत्र में प्रचार करते हुए फिरहाज हकीम ने दावा किया कि ममता बनर्जी ने पूरे बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की जीत पक्की करने का जिम्मा अपने कंधों पर लिया है। उन्होंने हमें अपने घर की जिम्मेदारी दी है। हमें उस जिम्मेदारी को पूरा करना है और लोगों के पास जाकर बस यही कहना है, ममता इधर-उधर खड़ी नहीं हैं। तृणमूल को वोट दें।

लोकसभा में 32 संशोधनों के साथ ध्वनिमत से पारित हुआ 'वित्त विधेयक-2026'

सिर्फ शिकायती है विपक्ष का रवैया, मेरे किसी भी जवाब के दौरान सदन में नहीं रहते कांग्रेस, द्रमुक व टीएमसी के सदस्य

हरिभूमि ब्यूरो ▶▶ नई दिल्ली

विपक्ष पर जमकर बरसीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, बोलीं-

- तृणमूल और द्रमुक सांसदों को क्रमशः बांग्ला और तमिल भाषा में जमकर सुनाई खरी खोटी, हुआ हंगामा
- वित्त मंत्री ने पिछले महीने 1 फरवरी को लोकसभा में 2026-27 के लिए पेश किया था केंद्रीय बजट
- इस वर्ष यह उनके द्वारा संसद में लगातार पेश किया गया नौवां बजट है

पश्चिम-एशिया सहित खाड़ी के इलाके में जारी युद्ध के भारत पर पड़ते प्रभावों के बीच लोकसभा ने बुधवार को 32 संशोधनों के साथ 'वित्त विधेयक-2026' को ध्वनिमत से अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। जिससे सरकार की बजट संबंधी प्रक्रिया का एक अहम चरण पूरा हो गया है। यह विधेयक वित्त वर्ष-2026-27 के केंद्रीय बजट प्रस्तावों जैसे 53.47 लाख करोड़ के कुल व्यय को कानूनी आधार प्रदान करता है। जो कि 31 मार्च को समाप्त हो रहे मौजूदा वित्त वर्ष की तुलना में 7.7 फीसदी अधिक है। अब इस विधेयक को राज्यसभा की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। उच्च-सदन से हरी झंडी मिलने के बाद ही बजट को पूरी तरह से पारित माना जाएगा। निचले सदन में कुल करीब 48 घंटे तक हुई व्यापक चर्चा के बाद इस विधेयक को स्वीकृति दी गई है। वित्त मंत्री ने पिछले महीने 1 फरवरी को लोकसभा में 2026-27 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया था। इस बार उनके द्वारा सदन में पेश किया गया यह नौवां बजट है। केंद्र द्वारा विधेयक में लाए गए संशोधन मुख्य रूप से कर प्रस्तावों से जुड़े हुए हैं। कुल 12.2 लाख करोड़ रुपए के कुल पूंजीगत व्यय में 44.4 लाख करोड़ के सकल कर राजस्व संग्रह और 17.2 लाख करोड़ रुपए की सकल उधारी का प्रस्ताव है। बजट के साथ आयकर अधिनियम 2025 को 819 धाराओं से घटाकर 536 धाराओं के साथ पेश किया जा रहा है। यह 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा।

बांग्ला, तमिल में साधा विपक्ष पर निशाना

उन्होंने कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके के सांसदों की सदन में बनी हुई अनुपस्थिति को लेकर उन्हें आड़े हाथों लिया। इस दौरान वित्त मंत्री ने बांग्ला और तमिल भाषा में टीएमसी और द्रमुक पर तंज कसते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन के दलों को हर वक्त सिर्फ शिकायत करने की आदत सी बन गई है। जिसमें भी ये खासतौर पर सदन में पूरी एकता के साथ सरकार का विरोध करते हैं। जबकि वहीं, इनके द्वारा उठाए गए तमाम मुद्दों पर सरकार की तरफ से मजबूत अंदाज में जवाब दिया जाता है यानी जब कभी मैं, सदन में जवाब देती हूं, तब विपक्ष से टीएमसी, द्रमुक या कांग्रेस के सदस्य उपस्थित नहीं रहते हैं। इस वाक्य को निर्मला ने तमिल में दोहराते हुए द्रमुक पर कटाक्ष किया। जबकि दूसरी ओर उन्होंने बांग्ला में टीएमसी पर पश्चिम-बंगाल में 3.7 लाख चाय बागान श्रमिकों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। जिस वक्त वित्त मंत्री सदन में अपनी बात रख रही थी। उस वक्त द्रमुक सांसद डॉ.टी.सुमति लोकसभा में मौजूद थी। तभी सीतारमण ने कहा कि मोदी सरकार जिस महिला आरक्षण संशोधन बिल को संसद की स्वीकृति के लिए यहां सदन में लाना चाहती है। उसका तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विरोध कर रहे हैं। जिससे साफ है कि तमिलनाडु की प्रदेश सरकार का ये विरोध राजनीतिक दृष्टि से किया जा रहा है।

दीर्घकालिक विकास संग मजबूत होगी अवसंरचना

लोकसभा में दिए अपने जवाब में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस विधेयक को न केवल राष्ट्र निर्माण की दिशा में आगे बढ़ने वाला एक महत्वपूर्ण कदम बताया। बल्कि ये भी स्पष्ट किया कि इसकी मदद से देश के किसानों, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों (एमएसएमई) और सहकारी क्षेत्र के साथ ही विकसित भारत के लक्ष्य, रोजगार सृजन, हरित ऊर्जा और डिजिटल गवर्नेंस को काफी बढ़ावा मिलेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों के साथ ही बुनियादी अवसंरचना का विकास भी गति पकड़ेगा। उन्होंने कहा, राष्ट्र निर्माण केवल एक दिन का काम नहीं है। बल्कि यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हमारा बजट देश के 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करता है। भारत सुधार की ओर क्रमिकता से नहीं, बल्कि स्वतः ही आगे बढ़ रहा है। जिसके केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अर्थव्यवस्था को रिफॉर्म एक्सप्रेस बनाने का लक्ष्य मुख्य रूप से शामिल है। हमारा ये बजट 5 सिद्धांतों पर आधारित है। जिसमें हम विश्वास आधारित कर प्रशासन पर जोर दे रहे हैं। साथ ही आम जनता के जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए के साथ-साथ व्यापार को भी बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं। हमारे इन कदमों से रोजगार सृजन होगा और अर्थव्यवस्था का विकास भी गति पकड़ेगा।

कांग्रेसी सरकारों की गलतियों को भुगत रहे

वित्त मंत्री के विपक्षी दलों की लोकसभा में अनुपस्थिति के बयान का सबसे पहले विपक्ष से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) की सांसद सुप्रिया सुले ने विरोध जताया। उसके साथ टीएमसी, सपा व अंत में द्रमुक की ओर मुखालफत की गई। सुप्रिया के आरोपों पर उन्होंने कहा, मुंबई में कुश्ती (विपक्षी दलों के बीच) और यहां सदन में नूरा कुश्ती हो रही है। कांग्रेस को लेकर सीतारमण ने कहा कि तत्कालीन यूपीए सरकार पूर्व में आई एक छोटी सी वित्तीय आपदा में ही हिल गई थी। मोदी सरकार ने कोरोना महामारी जैसी वैश्विक संकट में भी देश को हिलने नहीं दिया। तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दौर में देश में 22 महीने तक देश में महंगाई दर दो अंकों वाली बनी हुई थी। कांग्रेस सरकार ने 2008-09 में राजकोषीय घाटे की तमाम धनराशि को तेल कंपनियों के खाते में डालकर उनके मत्थे मढ़ दिया था।

वित्त विधेयक की खास बातें

- पूंजीगत व्यय-12.2 लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव है।
- राजकोषीय घाटा- वित्त वर्ष-27 के लिए जीडीपी का 4.3% रहने का अनुमान है।
- वित्त वर्ष-2025-26 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4% था।
- विधेयक से आयकर दरों, सीमा शुल्क व अन्य करों में किए गए बदलाव प्रभावी होंगे।
- केंद्र की 2026-27 के लिए आर्थिक नीतियों की रफ्तार बढ़ेगी, जिसका उद्देश्य दीर्घकालिक विकास, अवसंरचना को बढ़ावा देना है।
- कर नियमों में सरलीकरण के लिए एक नए आयकर विधेयक को मंजूरी दी गई है।
- रक्षा मंत्रालय के लिए सवार्धिक 7.85 लाख करोड़ का प्रावधान
- लिबरलाइज्ड रेमिटेंस योजना के तहत टीसीएस को कम करके 2% किया जाएगा।
- नई कर व्यवस्था में 12 लाख तक की आय पर कोई आयकर नहीं लगाया गया है।
- वेतनभोगी करदाताओं के लिए मानक कटौती की ये संख्या 12.75 लाख रुपए तक हो सकती है।
- इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई और गैर-ऑडिट वाले मामलों में ये 31 अगस्त 2026 होगी।
- आयकर से जुड़े अपीलीय ट्रिब्यूनल में लंबित मामलों को कम करने, करदाताओं को सहूलियत प्रदान करने के प्रयास जारी हैं।
- टीडीएस 5%, 20% से घटाकर 2% कर दिया है।

रेलवे ने 5 वर्षों में बढ़ती यात्री मांग को पूरा करने के लिए 1,024 ट्रेनें शुरू कीः अश्विनी वैष्णव

रेल मंत्री ने लोकसभा में बताया, 907 ट्रेनों का विस्तार किया, 168 ट्रेनों की आवृत्ति बढ़ाई और 4,651 कोचों की संख्या में वृद्धि की

अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 के बीच त्योहारों और छुट्टियों के दौरान 74,800 विशेष ट्रेनें चलाई गईं

हरिभूमि ब्यूरो ▶▶ नई दिल्ली

भारतीय रेलवे ने पिछले पांच वर्ष के 2021-22 से 2025-फरवरी 2026 तक 1024 ट्रेनें शुरू की, 907 ट्रेनों का विस्तार किया, 168 ट्रेनों की आवृत्ति बढ़ाई गई और 4651 कोचों की संख्या बढ़ाई है। यह जानकारी केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी।

उन्होंने बताया, चूंकि रेलवे नेटवर्क राज्यों की सीमाओं तक फैला हुआ है, इसलिए नेटवर्क की जरुरत के अनुसार इन सीमाओं के पार भी ट्रेनें शुरू की जाती हैं। हालांकि, प्रारंभ/समाप्ति के आधार पर, भारतीय रेलवे ने 2021-22 से 2025-26 (फरवरी 2026) के दौरान पूर्वी/उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित विभिन्न स्टेशनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए 444 ट्रेन सेवाएं शुरू की हैं, जिनमें बिहार राज्य में पड़ने वाले स्टेशनों के लिए निम्नलिखित 75 जोड़ी ट्रेनें शामिल हैं।

वैष्णव ने जानकारी दी कि अनारक्षित कोचों में यात्रा करने वाले यात्रियों की मांग को पूरा करने के लिए, रेलवे ने सामान्य श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए सुविधाओं में भी उल्लेखनीय वृद्धि की है। अकेले पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, विभिन्न लंबी दूरी की ट्रेनों में 1250 सामान्य कोचों का उपयोग किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष (फरवरी 2026 तक) में, 860 कोचों को स्थायी रूप से नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, जनरल और नॉन-एसी स्लीपर कोचों का उपयोग करने वाले यात्रियों को अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए, मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों की संरचना संबंधी मौजूदा नीति में 22 कोचों वाली एक ट्रेन में 12 (बारह) जनरल और स्लीपर श्रेणी के नॉन-एसी कोच और 8 (आठ) एसी कोच शामिल हैं, जिससे जनरल और नॉन-एसी स्लीपर कोचों का उपयोग करने वाले यात्रियों को अधिक सुविधा मिलती है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा, अनारक्षित सीटों का लाभ उठाने के इच्छुक यात्रियों की सुविधा के लिए, भारतीय रेलवे किफायती यात्रा के लिए अनारक्षित गैर-एसी यात्री ट्रेनें/एमईएमयू /ईएमयू आदि चलाती है, जो मेल/एक्सप्रेस सेवाओं में उपलब्ध अनारक्षित सीटों (कोचों) के अतिरिक्त हैं। वैष्णव ने बताया कि भारतीय रेलवे में, ट्रेनों की यात्री संख्या व्यस्त और कम व्यस्त समय के दौरान बदलती रहती है। व्यस्त समय के दौरान, खास तौर पर लोकप्रिय मार्गों पर, ट्रेनों की क्षमता पूरी रहती है, जबकि कम व्यस्त समय में और कम व्यस्त मार्गों पर, ट्रेनों का उपयोग कम होता है। प्रतीक्षा सूची की स्थिति पर नियमित रूप से निगरानी रखी जाती है और अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए भारतीय रेलवे ने कई कदम उठाए हैं, जैसे नई ट्रेनों का शुभारंभ, मौजूदा ट्रेनों की आवृत्ति में वृद्धि/विस्तार, मौजूदा ट्रेनों में स्थायी रूप से भार वृद्धि आदि।

मुख्यमंत्री ने अपने जन्मदिन पर वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को दी बड़ी सौगात चीतों के पुनर्वास के लिए बनने वाले विशेष बाड़े का भूमिपूजन भी किया

नौरादेही में संरक्षित प्रजाति के कछुओं को जल में विमुक्त कर जैव विविधता संरक्षण का संदेश दिया

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

- मुख्यमंत्री ने ग्रामीण परिवेश में आम के वृक्ष की छांव में खाट पर बैठकर भोजन किया
- भोजन के पूर्व उन्होंने गो माता को गुड-चारा भी खिलाया

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि नौरादेही टाइगर रिजर्व को भविष्य में एक और बड़ी पहचान मिलने जा रही है। आने वाले समय में यह क्षेत्र मप्र में चीतों का तीसरा सुरक्षित आवास बनेगा। इससे मध्यप्रदेश के वन्य-जीव पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही हमारी जैविक संपदा और भी समृद्ध होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बुधवार को सागर जिले के वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व (नौरादेही) में संरक्षित प्रजाति के कछुओं को जल में विमुक्त कर जैव विविधता संरक्षण का नव संदेश दिया। यहां चंबल नदी और भोपाल से लाए गए 14 कछुए भी मुक्त विचरण के लिए बामनेर नदी में छोड़े।

कृषक परिवार ने कलश रखकर, चंदन रोली का तिलक से स्वागत किया

मुख्यमंत्री डॉ. यादव का किसान हरदास रैकवार के खेत पर पहुंचने पर कृषक परिवार ने कलश रखकर, चंदन रोली का तिलक लगाते हुए पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण परिवेश में आम के वृक्ष की छांव में खाट पर बैठकर भोजन किया। भोजन के पूर्व उन्होंने गो माता को गुड-चारा भी खिलाया। मुख्यमंत्री ने बुंदेली भोजन की तारीफ की और कढ़ी, बिर्रा की रोटी, समां के चावल की खीर, खीचला-पापड़ आदि व्यंजनों का स्वाद चखा।

जन्मदिन पर बच्चियों को खिलाई काजू कतली, प्रदान किए ड्राइविंग लाइसेंस

मुख्यमंत्री डॉ. यादव का जन्मदिवस पर रहली में अभूतपूर्व स्वागत और अभिनंदन किया गया। मुख्यमंत्री ने अपने जन्मदिन पर सभी बच्चियों को अपने हाथों से काजू कतली खिलाई और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने वहां मौजूद 8 बच्चियों को ड्राइविंग लाइसेंस सर्टिफिकेट भी प्रदान किए। डॉ. यादव ने कहा कि सरकार बेटियों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

पीएम मोदी, शाह समेत दिग्गजों ने दी बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और अन्य प्रमुख नेताओं ने सीएम डॉ. मोहन यादव को बधाई दी। पीएम मोदी और शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश की प्रगति की सराहना की और उन्हें दीर्घायु तथा निरंतर सेवा का आशीर्वाद दिया। योगी आदित्यनाथ समेत कई अन्य नेताओं ने भी शुभकामनाएं भेजी।

युद्ध-विराम की कोशिशें

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध-विराम के इच्छुक दिख रहे हैं, लेकिन ईरान ने किसी समझौते या बातचीत को 'अभी नहीं और कभी नहीं' बताया है। ऐसा लगता है, राष्ट्रपति ट्रंप पाकिस्तानी फील्ड मार्शल मुनीर की मदद से युद्ध-विराम की कोई सूरत खोज रहे हैं, लेकिन ईरान के प्रवक्ता ने ऐसी किसी भी बातचीत या कोशिश से इनकार किया है। आज ईरान तल्खी और नाराजगी से भरा हुआ है। उसके प्रवक्ता ने तो यहां तक इशारा कर दिया है कि ट्रंप जैसे व्यक्ति से कोई बातचीत या समझौता नहीं किया जाएगा। मोटे तौर पर ईरान की मांग है कि अमेरिका यह माने कि उसने आक्रमण किया और यह भी आश्वासन दे कि दोबारा कभी हमला नहीं करेगा। किसी भी बातचीत या युद्ध-विराम की दिशा में बढ़ने के लिए ईरान की ये मांगें गलत नहीं हैं। कोई भी देश अपनी सुरक्षा का आश्वासन चाहेगा, तभी किसी समझौते या युद्ध-विराम के लिए तैयार होगा। अमेरिका का जो रवैया या इतिहास रहा है, उसे कोई भी पश्चिम एशियाई देश कैसे भूल सकता है? अमेरिकी नीति या रणनीति अपने हित को एकतरफा सुरक्षित करने की रही है।

यहां सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि क्या अमेरिका वाकई युद्ध-विराम चाहता है? अगर वह समझौता चाहता है, तो फिर पश्चिम एशिया में 1,000 विशेष सैनिकों की तैनाती क्यों कर रहा है? ये सैनिक पैराशूट से उतरकर जमीनी लड़ाई में माहिर हैं, तो क्या ईरान में जमीनी लड़ाई शुरू होने वाली है? ईरान के पड़ोसी अफगानिस्तान में जमीनी लड़ाई का जैसा त्रासद इतिहास अमेरिका पहले लिख चुका है, उसे लोग भूले नहीं हैं। अंततः निराश और परेशान होकर उसे अफगानिस्तान से लौटना पड़ा था। जमीनी लड़ाई की ओर बढ़ने का मतलब यही है कि हवाई जंग में अमेरिका और इजरायल को मनचाही कामयाबी नहीं मिल रही है। जो युद्ध सप्ताह भर के लिए सोचकर शुरू किया गया था, वह 26 दिन से जारी है और इसके दुष्परिणाम पूरी दुनिया भुगत रही है। ट्रंप अपने स्वभाव के अनुरूप ही लगभग रोज एकतरफा दावे कर रहे हैं। एक दावा यह भी है कि ईरान समझौता करना चाहता है। इसके जवाब में ईरान ने जो कहा है, उस पर गौर करने की जरूरत है। ईरान ने कहा है, 'अपनी हार को समझौते का नाम न दीजिए। आपके खोखले वादों का युग समाप्त हो चुका है। क्या आपके आंतरिक संघर्ष इस हद तक पहुंच गए हैं कि आप आपस में ही बातचीत कर रहे हैं?' साफ है, ईरान अब ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा, जिससे उसकी पराजय का कोई संदेश दुनिया में जाए। आज सबसे जरूरी बात यह है कि अमेरिका युद्ध-विराम के लिए हालात तैयार करे।

सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि क्या अमेरिका युद्ध-विराम चाहता है? अगर वह समझौता चाहता है, तो पश्चिम एशिया में विशेष सैनिकों को क्यों उतार रहा है?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 15 सूत्रीय युद्ध-विराम योजना की पेशकश की है। दूसरी ओर, ईरान की पांच प्रमुख मांगें हैं। जैसे, युद्ध की तत्काल समाप्ति, भविष्य में ईरान पर कोई सैन्य हमला नहीं, क्षति के लिए ईरान को मुआवजा, होर्मुज जलडमरूमध्य पर औपचारिक नियंत्रण, मिसाइल कार्यक्रम पर कोई प्रतिबंध नहीं। क्या अमेरिका या इजरायल इन शर्तों को मानेंगे? दोटूक यह स्वीकार करना चाहिए, ईरान की युद्ध के प्रति दृढ़ता, भाषा और व्यवहार अकल्पनीय है। अमेरिकी विशेषज्ञ भी मान रहे हैं कि कथित रूप से आठ युद्ध रोकने का दावा करने वाले ट्रंप अपने नौवें युद्ध में फंस गए हैं, जिससे निकलने के लिए उन्हें सबसे पहले अपनी नाक से समझौता करना पड़ेगा। समय की मांग है कि अमेरिका अब इजरायल के साथ मिलकर हालात की ईमानदार समीक्षा करे और दुनिया में अमन-चैन की राह निकाले।

एकध्रुवीय विश्व का भ्रम टूट गया

यहां स्कैन करें

जोरावर दौलत सिंह | इतिहासकार और रणनीतिकार

जैसे-जैसे युद्ध आगे बढ़ेगा, अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्रों को हुए नुकसान अधिक स्पष्ट होते जाएंगे, इससे वाशिंगटन एक गंभीर शांति-वार्ता को लेकर अपनी राय बना सकता है।

ईरान के खिलाफ जारी अंतहीन युद्ध को अब विश्व व्यवस्था में एक निर्णायक मोड़ के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिका से आखिर इतनी बड़ी गलती हुई कैसे? वास्तव में, संघर्ष में उतरने से पहले तेहरान को लेकर वाशिंगटन की तीन महत्वपूर्ण धारणाएं थीं।

पहली, व्हाइट हाउस का मानना था कि बेशक एकध्रुवीय व्यवस्था का चरम-काल बीत चुका है, फिर भी विश्व शक्ति संतुलन उसके अनुकूल है, क्योंकि उसके प्रतिद्वंद्वी या तो अन्य संघर्षों में उलझे हुए हैं (जैसे- रूस यूक्रेन के साथ) या घरेलू व क्षेत्रीय मामलों में मुब्तिला हैं (जैसे- चीन पूर्वी एशिया में)। वेनेजुएला में जिस आसानी से उसने सफलता पाई थी, उससे भी उसे खुद के सर्वशक्तिमान होने का विश्वास था। उसे लगा कि अलग-थलग पड़े ईरान को कुचलने का यह सुनहरा अवसर है।

दूसरी, ईरान में सत्ता-परिवर्तन के लिए व्यापक बमबारी को पर्याप्त माना गया। यह उस अमेरिकी सिद्धांत के अनुकूल था, जिसके तहत वह लक्षित देश के नेतृत्व और उसके कमान व नियंत्रण केंद्रों को पूरी तरह से खत्म कर देता है। यह अवधारणा पश्चिमी युद्ध रणनीति का अभिन्न हिस्सा रही है। इसमें तीव्रता से की गई सैन्य कार्रवाई से दुश्मन को झटका लगता है और वह तुरंत पीछे हट जाता है या आत्मसमर्पण कर देता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से जमीनी जंग के खिलाफ घरेलू दबाव और लॉजिस्टिक मुश्किलों के कारण विनाशकारी बमबारी अभियान के प्रति अमेरिका का आकर्षण बढ़ा है।

तीसरी, अमेरिका का मानना था कि उसके ताकतवर सहयोगी देश युद्ध का भार उठाने में मदद करेंगे। पश्चिम एशिया में युद्ध को आगे बढ़ाने के लिए वह अन्य मोर्चों से संसाधनों व सैन्य उपकरणों को इधर-उधर कर सकता था। इतना ही नहीं, अमेरिका के क्षेत्रीय सहयोगियों को भी एक संपत्ति के तौर पर देखा गया, जिनके पास कई जगहों पर फैले ठिकाने थे। इनका इस्तेमाल एक ऐसी सैन्य कार्रवाई के लिए हो सकता था, जो ईरान को पछाड़ दे और उसकी जवाबी कार्रवाई को मुश्किल बना दे।

इन तीनों धारणाओं को लेकर अमेरिका कितना गलत था, यह अब स्पष्ट हो गया है। ईरान अकेला नहीं था और जून 2025 में 12 दिनों के संघर्ष के बाद उसके रणनीतिक सहयोगी देशों ने उसकी सैन्य तैयारियों को आगे बढ़ाने में मदद की है। निस्संदेह, बमबारी से अमेरिका को सामरिक सफलताएं मिलीं, लेकिन वह वहां की राजनीतिक व्यवस्था, महत्वपूर्ण संस्थाओं और ईरानी जनता के संकल्प को तोड़ पाने में विफल रहा है।

दूसरी बात, इस संघर्ष में अमेरिकी सहयोगी नेटवर्क लाभ के बजाय एक बोझ साबित हुआ है। जैसा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भी माना है कि फारस की खाड़ी और पश्चिम एशिया के अमेरिकी ठिकानों पर ईरान ने जिस तेजी व प्रभावी तरीके से पलटवार किया, वह आश्चर्यजनक था। जबकि, ये ठिकाने सामरिक कार्रवाइयों के लिए बेहद अहम माने जाते थे। उपग्रह से मिली तस्वीरें बताती हैं कि पांच देशों में स्थित सात अमेरिकी ठिकानों पर 25 जगहों पर हमले हुए, जिनसे चेतावनी रडार, रसद भवन, ईंधन भंडारण कंटेनर आदि को नुकसान पहुंचा। पश्चिम एशिया में अमेरिका के सहयोगी देशों और उनके महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों पर ईरानी पलटवार से यही एहसास हुआ कि इस जंग में 'दोनों का विनाश' तय है। यह ऐसा तथ्य है, जिसे अमेरिका के प्रखर राष्ट्रवादी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। यही कारण है कि जब ईरान के 'साउथ पार्स' गैस क्षेत्र पर इजरायली हमले के जवाब में तेहरान ने खाड़ी क्षेत्र के ऊर्जा केंद्रों पर हमले किए, तो राष्ट्रपति ट्रंप फौरन कदम पीछे खींचने को मजबूर हुए।

अपनी कुशल सैन्य रणनीति व तकनीकी उपलब्धियों के बूते ईरान ने इस कदर मजबूत प्रतिरोधी क्षमता हासिल की है। ईरान को नाटो और अमेरिकी सेना के चश्म से देखा गया, जिनको अलग-अलग भू-रणनीतिक उद्देश्यों के लिए विकसित किया गया है। जबकि, सीमित संसाधनों वाले एक स्वतंत्र देश होने के नाते ईरान ने अपनी भू-राजनीतिक जरूरतों के अनुसार सैन्य रणनीति विकसित की है। उसने ऐसे हथियारों पर मेहनत की, जो दुश्मन के स्रोत पर पलटवार करने में सक्षम हो। ये हथियार निस्संदेह दशकों में बने मिसाइल व ड्रोन के उन्नत भंडार थे, जो न सिर्फ हवाई बमबारी से बचने में सक्षम थे, बल्कि अमेरिकी-इजरायली रक्षा कवच को आसानी से भेद सकते थे। हालांकि, उसकी यह रणनीति कोई छिपा रहस्य नहीं था। पिछले संघर्ष में उसने इसका कुछ हद तक प्रदर्शन भी किया था।

अनवरत बमबारी के बावजूद अमेरिका इस बार ईरान की सैन्य ताकत को कमजोर करने या उसकी राजनीतिक व्यवस्था को तोड़ पाने में विफल रहा है। युद्ध के शुरुआती चरण में जिन उद्देश्यों का जिक्र व्हाइट हाउस और पेंटागन ने किया था, वह अब तीन हफ्तों के बाद हास्यास्पद ही लग रहे हैं। अब अमेरिका इस जंग के दुष्परिणामों से निपटने में अधिक व्यस्त है, जैसे- घटता घरेलू समर्थन, वैश्विक आर्थिक अस्थिरता का खतरा, ऊर्जा बाजार को लगने वाला झटका और लंबी सैन्य कार्रवाई के लिए जरूरी लॉजिस्टिक मदद।

विश्वसनीय रिपोर्टों से पता चलता है कि अमेरिका ने कई बार युद्धविराम का प्रस्ताव रखा है। ईरानी विदेश मंत्री ने भी सार्वजनिक तौर पर ऐसी रिपोर्टों की पुष्टि की है। हालांकि, वाशिंगटन अब भी इस युद्ध को एक ऐसे समझौते के साथ समाप्त करना चाहता है, जिससे उसके क्षेत्रीय दबदबे में कोई बड़ी कमी या उसकी सैन्य उपस्थिति पर आंच न आए। दूसरी ओर, ईरान कहीं अधिक स्थायी शांति का पक्षधर है और क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे में इस कदर बदलाव चाहता है, ताकि उसके सुरक्षा हितों को पर्याप्त महत्व मिले। जाहिर है, दोनों पक्ष बिल्कुल विपरीत ध्रुव पर खड़े हैं और तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के बिना उनमें सहमति बनना करीब-करीब नामुमकिन है। जैसे-जैसे युद्ध आगे बढ़ेगा, अमेरिका व उसके मित्र राष्ट्रों को होने वाले नुकसान अधिक स्पष्ट होते जाएंगे, जिसके कारण वाशिंगटन एक गंभीर शांति-वार्ता को लेकर फिर से अपनी राय बना सकता है।

कुल मिलाकर, अमेरिका की घरेलू राजनीति से इस युद्ध का भविष्य जुड़ा हुआ है। यह स्थिति इस जंग को और अधिक अनिश्चित बना रही है, क्योंकि तर्कसंगत राष्ट्रीय सोच उन भू-राजनीतिक विचारों से प्रभावित हो सकती है, जो पश्चिम एशिया में 'अनवरत युद्ध' की तरफदारी करते हैं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

नाम जप के साथ राम का काम करना भी जरूरी

यहां स्कैन करें

रमेशभाई ओझा | प्रसिद्ध कथा वाचक

रामनवमी, यानी भगवान श्रीरामचंद्र प्रगटोत्सव संपूर्ण भारत और विदेशों में सनातन धर्मावलंबियों द्वारा श्रद्धा से मनाया जाता है। रामो विग्रहवान धर्मः का अर्थ है, श्रीराम धर्म के मूर्तिमंत स्वरूप हैं। कहा भी गया कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चरित्र आदर्श मानव जीवन की आचार संहिता है। श्रीराम अनंत गुण गण निलय हैं। वह जितने धीर हैं, उतने ही महान वीर हैं। वीरता और धीरता के इस अद्भुत समन्वय को मन में रखते हुए जब हम रामनवमी मनाएं, तो श्रीराम के पथ पर चलने की प्रेरणा हमें मिलेगी।

जीवन मंगल कब होता है, जब दो बातें हों। पहली, जीवन गतिशील हो और दूसरी, जीवन की गति की दिशा सही हो। वह गंगा की भांति नित्य प्रवहमान हो। भगवान राम मंगल के भवन और अमंगल का हरण करने वाले हैं- *मंगल भवन अमंगल हारी द्रवउ सो दसरथ अजिर बिहारी। करि प्रनामु रामहि त्रिपुरारी। हरषि सुधा सम गिरा उचारी।।* जीवन में नित्य आनंद, शांति और सुख चाहिए, यह सबकी मांग है। इसे यदि एक शब्द में कहें, तो सबको 'राम' चाहिए, क्योंकि नित्य सुख, आनंद और शांति को मिलाकर यदि कोई एक शब्द बनता है, तो वह राम ही है। राम की चाह जीवमात्र के हृदय में स्वाभाविक रूप से विद्यमान है। राम को कैसे पाएं? यह रास्ता भगवान राम खुद दिखाते हैं- *निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा।।* यानी जिसका मन निर्मल होता है, वही मुझे प्राप्त करता है।

भगवान राम का अवतरण निष्क्रिय सज्जनता को सक्रिय करने और सक्रिय सज्जनता को संगठित करने के लिए हुआ था। रामनवमी पर विशेष :

बात निर्मल मन की है। ऐसा नहीं है कि संस्कृत का प्रकांड विद्वान ही भगवान को प्राप्त करता है या जिसने बड़ी तपस्या की हो, उस पर ही वह कृपा करते हैं। तपस्या, पूजा-पाठ, दान-पुण्य, तीर्थयात्रा, सत्संग, सब मन की शुद्धि के साधन हैं। मन की शुद्धि होगी, तो श्रीराम कृपा करके मिलेंगे, क्योंकि राम कृपा साध्य हैं। वह क्रिया साध्य नहीं हैं, पुरुषार्थ से मिलने वाली वस्तु नहीं हैं। वह केवल अनुग्रह साध्य हैं।

आज लोग श्रीराम का स्मरण तो करते हैं, लेकिन लोकसेवा नहीं करते। ऐसे लोग सोए हुए भक्त हैं। सिर्फ राम का नाम ही नहीं जपना है, बल्कि उनका काम भी करते रहना है। हनुमानजी केवल राम का नाम नहीं लेते थे, बल्कि प्रभु का काम भी करते थे। ऐसी भक्ति ही समाज को जाग्रत और राम को प्रसन्न करती है। याद कीजिए, सीता माता की खोज में जब हनुमानजी लंका पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि विभीषणजी सोए हुए हैं। वह भगवान का नाम तो लेते हैं, पर उनका काम नहीं करते। हनुमानजी ने उन्हें राम काम के लिए तैयार किया और पूछा कि रावण सीता माता का हरण करके ले आया है, उनकी मुक्ति के लिए आपने कोई प्रयास किया? हनुमानजी की प्रेरणा से विभीषण राम-काम में जुट गए।

भक्ति में शक्ति के बदले कायरता देखने को मिले, तो यह विश्वास का अभाव है। वह सोई हुई भक्ति है और निष्क्रिय भक्ति समाज को नुकसान पहुंचाती है। भगवान राम का अवतरण निष्क्रिय सज्जनता को सक्रिय करने के लिए और सक्रिय सज्जनता को संगठित करने के लिए हुआ था। आज भी हमें श्रीराम जैसे चरित्रों की जरूरत है, जो हमारी सोई हुई भक्ति को जाग्रत कर सके। वर्तमान विश्व में अहंकार, मोह, मेरा-मेरा के चलते ही मारामारी है। रामचरितमानस के अरण्य कांड में प्रभु राम भाई लक्ष्मण को बताते हैं कि काम, क्रोध, लोभ और मोह ही मनुष्य से पाप कराते हैं, इसलिए रामराज्य में राजशाही थी, मगर उन्होंने लोकशाही की भांति अपना राज्य चलाया। उनके राज्य में प्रजा हर प्रकार से सुखी थी।

दरअसल, स्वार्थ चोटिल होने पर ही जीव धर्म की बात करता है। आप स्वयं अनुभव करें, कैकेयी के जीवन में धर्म की आड़ में 'धर्माभास' किस तरह प्रकट होता है। राम को वनवास और भरत को राज्य! यह सुनकर राजा दशरथ मर्माहत हो उठते हैं। कैकेयी को समझाते हुए वह कहते हैं, आखिर यह अनर्थ तुम किसलिए कर रही हो? तुम जानती हो कि पूरी अयोध्या राम को साधु कहती है। कैकेयी तर्क देती हैं, मैं भी तो राम को साधु मानती हूं। आप स्वयं निर्णय करें कि भोग श्रेष्ठ है या त्याग? भारतीय मनीषा त्याग को ही श्रेष्ठ कहती है। राम चूंकि साधु हैं, अतः राज्य का त्याग करके वन जाना ही उनके लिए श्रेष्ठ धर्म है। इसलिए, आज के धर्माभास को पहचानने की सबसे अधिक जरूरत है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

इच्छा मृत्यु का अर्थ

सृष्टि चक्र में जीवन और मृत्यु का अटूट संबंध है। *गीता* में लिखा है- *जातस्य ही ध्रुवो मृत्युः ध्रुव जन्म मृतस्य च,* यह जितना निश्चित है कि जन्म के बाद मृत्यु है, उतना ही निश्चित है कि मृत्यु के बाद नया जन्म है। इसलिए जन्म और मृत्यु को सौंदर्य प्रदान करने का प्रयत्न ऋषियों ने किया है। उनका प्रयास रहा है कि जीवन आनंदमय रहे, मृत्यु महोत्सव बन जाए। इसके लिए वैदिक, जैन, बौद्ध सभी धर्मों ने कुछ न कुछ उपाय दिए हैं।

मृत्यु आए, तो इतनी शीघ्रता से आ जाए कि न जाने वाले को एहसास हो, न उसके करीबियों को अंदाजा हो। न आए, तो वर्षों की प्रतीक्षा के बाद भी द्वार पर दस्तक देती रहे, अंदर न आए। जाने वाला तैयार है, भेजने वाले तैयार हैं, पर मृत्यु नखरे करती रहे कि नहीं आऊंगी। इन्हीं स्थितियों में मानव की निर्णय क्षमता की परीक्षा होती है। ऐसी ही परीक्षा को पास करते हुए तेरह वर्ष से कोमा में पड़े हरीश राणा और उसके परिवार को बहुत बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम निर्णय ने भारतीय चिंतन के पुराने निर्णय को ही पुष्ट किया है। संविधान ने व्यावहारिक रूप से यह सुविधा अब दी है, जबकि शास्त्रों ने पहले से ही दे रखी थी। जीवन नरक न बन जाए, मृत्यु विभीषिका न बन जाए, इसके लिए कुछ विधियों का आविष्कार भारत वर्ष में बहुत पहले ही हुआ था।

दूसरी ओर, वैज्ञानिक आविष्कारों ने मनुष्यों को दो सुविधाएं प्रदान की हैं- पहला, जीवन को दीर्घ बनाया है। दूसरा, कृत्रिम ढंग से भी जीने की सुविधा दी है। वैसे, हमारे मनीषियों ने माना है कि जीवन छोटा हो या बड़ा, पर सौंदर्यपूर्ण हो, गरिमामय हो, अर्थबोध से भरा हो, चैतन्य से भरा हो। जब ये सब समाप्त होने लगें, तब चिकित्सा सुविधाओं से भी किनारा करना अनुचित नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी इच्छा मृत्यु पर अपने निर्णय में ऐसे ही संकेत किए हैं। जीवन में गरिमा व सम्मान सर्वोपरि है।

हमारे अध्यात्म या जीवन में इच्छा मृत्यु से ऊपर भी एक और व्यवस्था है - मृत्यु की कला। पूर्ण होश-हवास में जीवन को प्रभु या प्रकृति को अर्पित कर देना। मैं प्रत्येक आती-जाती श्वास का साक्षी रहूं। जीवन वीणा के मंद-मंदतर होते प्रत्येक स्पंदन का आनंद लूं। इसी अवस्था को समाधि मरण, पंडित मरण, संथारा आदि नाम दिया जाता है। हमारा समाज जानता है कि यह उपलब्धि कुछ दुर्लभतम साधकों को ही प्राप्त होती है।

जाने वाला तैयार है, भेजने वाले तैयार हैं, पर मृत्यु नखरे करती रहे कि नहीं आऊंगी। इन्हीं स्थितियों में मानव की निर्णय क्षमता की परीक्षा होती है। यहां शास्त्रों ने भी समाधान बताया है।

जहां बहुत आवश्यक हो, कोई विकल्प न रहे, वहां इच्छा मृत्यु भी है और पंडित मरण भी। शास्त्र की दृष्टि से एक सामान्य स्थिति है और दूसरी विशिष्ट। इच्छा मृत्यु में देह पीड़ा से छुटकारा है, पंडित मरण में आत्मदोषों से छुटकारा है। यह ऐसी अवस्था है, जब जीवन-मरण की इच्छा नहीं रहती है। अंततः एक सही मनुष्य जीवन इच्छाओं का सुंदर संयोजन और संतुलन ही तो है।

बहुश्रुत श्री जय मुनि जी

रेसेप तैय्यप एर्दोगन | राष्ट्रपति, तुर्किए

दुनिया में शांति और स्थिरता चाहने वाले देशों को उस आग में घी नहीं डालना चाहिए, जिसे गलत तरीके से भड़काया गया है। हम शांति, न्याय और स्थिरता स्थापित करने के लिए पूरी ताकत और मौजूद सभी तरीकों से प्रयास करते रहेंगे।

हिन्दुस्तान | 75 साल पहले | 26 मार्च, 1951

बिहार का खाद्य संकट

अन्न की दृष्टि से देश के जितनी भी कमी वाले इलाके हैं, उनमें बिहार सबसे अहम प्रतीत होता है। बिहार को गम्भीर अन्न-संकट का सामना करना पड़ रहा है। उत्तरी बिहार में किसानों, विशेषकर खेतिहर मजदूरों की दयनीय अवस्था हो गई है।

उत्तरी बिहार के कुछ अभाव ग्रस्त इलाकों का दौरा करके एक ब्रिटिश समाचार-पत्र का संवाददाता लौटा है। उसका कहना है कि पर्याप्त पोषण के अभाव में लोग बीमार पड़ कर मरने लगे है। देहातों में तो लोग दो-दो तीन-तीन दिन के भीतर एक-दो मुट्ठी भर अन्न अथवा दाल खाकर जिन्दगी बसर कर रहे हैं। बिहार के चार अलग-अलग प्रदेशों से भूख के कारण करीब-करीब 43 मौतें होने के समाचार प्राप्त हुए हैं। बिहार के इस गम्भीर खाद्य संकट पर देश में सर्वत्र आमतौर पर चिन्ता अनुभव जायेगी। भारत के प्रधानमंत्री ने तो देश की जनता को यह खुला आश्वासन दिया है कि उनकी सरकार किसी को भी अन्न के अभाव में भूखों नहीं मरने देगी। यदि त्याग की आवश्यकता होगी, तो सभी समान रूप से त्याग करेंगे और देश में जितना भी अनाज होगा, उसे समान रूप से बांट कर खायेंगे। बिहार के अन्न संकट के दो कारण तो सर्वविदित हैं। एक तो यह कि पिछले वर्ष बिहार में बाढ़ का प्रकोप रहा। दूसरे, समय पर वर्षा नहीं हुई और सूखा पड़ गया, जिससे शीतकालीन फसलें कुण्ठित हो गयीं।

किन्तु ब्रिटिश पत्र के संवाददाता ने लिखा है कि बिहार में जो अन्न सुलभ है, उसका भी यथोचित वितरण नहीं हो पा रहा है। यदि वह त्रुटि है, तो बिहार सरकार इसको तो अवश्य ही दुरुस्त कर सकती है और प्राप्त अन्न के वितरण की समुचित व्यवस्था कर सकती है। आशा है वितरण की व्यवस्था के अभाव में किसी के भूखों मरने की नौबत नहीं आने दी जायेगी। भारत के खाद्य मंत्री श्री मुन्शी ने भारतीय संसद में इस बात से इन्कार किया है कि बिहार में भूख के कारण कोई मौत हुई है। उन्होंने कहा कि जिन तीन आदमियों के भूख के कारण मरने की बात कही जाती है, उनमें से एक तो तीन महीने पहले बुखार से मरा और दूसरे की तपेदिक से मृत्यु हुई, ऐसा प्रतीत होता है कि भूख के कारण जितनी मौतें होने के समाचार प्राप्त हुए हैं, उन सब की जांच अभी नहीं हो पायी है और श्री मुन्शी का खण्डन सिर्फ एक रिपोर्ट से ही संबंधित है।

दिल्ली को हरित बनाएगा यह बजट

साल 2026-27 के लिए दिल्ली की भाजपा सरकार ने 1,03,700 करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जो 'विकसित दिल्ली, हरित दिल्ली' का ऐतिहासिक सपना साकार कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साहसी नेतृत्व में, दिल्ली ने विकास के एक नए युग की शुरुआत की है। यह बजट सिर्फ आंकड़ों का संग्रह नहीं, बल्कि दिल्ली की नई पहचान है- आधुनिक सड़कों, स्मार्ट और सतत जल आपूर्ति, यमुना की सफाई, ग्रामीण और किसान विकास, महिला सशक्तिकरण और सुगम परिवहन- हर पहल में जनता की सुविधा और शहर की आत्मनिर्भरता की नींव रखी गई है। हर नीति में साफ लक्ष्य, ठोस योजना व क्रियान्वयन है, जो दिल्ली को विश्वस्तरीय सुविधाओं वाला, हरित और विकसित शहर बनाएगा।

दिशांत आनंद, टिप्पणीकार

जिस सोच के साथ दिल्ली का बजट तैयार किया गया, उसे देखकर यही एहसास हो रहा है कि हमारी राजधानी की जिम्मेदारी बहुत सुरक्षित हाथों में है और वह भविष्य के बारे में भी सोचती है। 1,03,700 करोड़ रुपये के बजट में 'ग्रीन बजट' की घोषणा सुनकर मन खुश हो गया। जब हमने 21 प्रतिशत बजट को पर्यावरण, पेड़ लगाने, प्रदूषण नियंत्रण और हरित ऊर्जा से जोड़ा है, तो यह साफ है कि हमारी सरकार न सिर्फ आज की जरूरतें पूरी कर रही है, बल्कि कल की सांसों की रक्षा भी कर रही है। इस नजरिये से देखें, तो यह बजट निश्चय ही तारीफ के काबिल है।

इतना ही नहीं, स्वास्थ्य के लिए 13,030 करोड़ रुपये, शिक्षा के लिए 19,148 करोड़ रुपये, पानी व बिजली की सुरक्षा के लिए जल बोर्ड और ऊर्जा विभाग को मजबूत आवंटन, ये सिर्फ अंक नहीं हैं, ये तो हमारे घरों में मौजूद महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की दैनिक जिंदगियों की गारंटी हैं। जब आपने स्कूली लड़कियों को शिक्षा के लिए मुफ्त साइकिल देने जैसे छोटे-अच्छे कदम भी बजट में शामिल किए, तो महसूस होता है कि हमारी सरकार सच में 'घर-घर' तक पहुंचने की दिशा में काम कर रही है। विकास और सुरक्षा के साथ-साथ 'महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा' को बजट में प्राथमिकता देना बताता है कि भाजपा सरकार हर दिल्लीवासी मां-बहन की आवाज को संवेदनशीलता से सुनती है। एक दृढ़, संतुलित और भविष्योन्मुखी बजट बनाने के लिए दिल्ली की सरकार को बधाई देनी चाहिए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सिर्फ एक राजधानी नहीं, बल्कि एक स्वस्थ, सुरक्षित और सुंदर नगर बनती जा रही है, जिस पर हम सबको गर्व है।

सोनू गर्ग, राजनीतिक कार्यकर्ता

अनुलोम-विलोम

दिल्ली बजट

कई पुराने वायदे अब तक अधूरे

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने कार्यकाल के दूसरे बजट में योजनाओं की झड़ी लगा दी। ऐसा होना ही था। अब कमोबेश सभी राज्य सरकारों पर लोक-लुभावन बजट पेश करने की बड़ी जिम्मेदारी होती है। मगर इनमें मुख्य बात यह होनी चाहिए कि जिन योजनाओं का एलान किया जा रहा हो, उनका जमीन पर अनुपालन भी हो। योजनाएं जमीन पर कारगर होनी चाहिए। वे फाइलों और सरकारी कार्यालयों में ही सिमटकर न रह जाएं। जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले थे, तब भाजपा ने यहां की हर महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये देने का वायदा किया था, परंतु चुनाव जीतने के बाद जब उसकी सरकार बनी, तो इस वायदे को जमीन पर उतारने में काफी समय लगा, अब भी लग रहा है। इससे भी बड़ी बात यह है कि इस योजना को जब रूप दिया जाने लगा, तो तरह-तरह के नियम अथवा शर्तों की वकालत की जाने लगी, जबकि चुनाव के समय जब इसका एलान किया गया था, तब किसी तरह की शर्त की बात नहीं कही गई थी। क्या इसे मतदाताओं के साथ धोखा नहीं कहेंगे? इसी तरह, बजट में विद्यार्थियों, बुजुर्गों, महिलाओं और गिग कामगारों के लिए भी कई तरह की योजनाएं लाने का एलान किया गया है। उम्मीद यही करेंगे कि उनका हश्र 2,500 रुपये के वायदे जैसा न हो। सरकार की कोशिश उन योजनाओं को सरल रूप में लागू करने की होनी चाहिए, ताकि जनता को असलियत में यह एहसास हो कि सरकार उसके हित में काम कर रही है। कथनी और करनी में एकरूपता लाना हर सरकार का फर्ज होना चाहिए।

शैलबाला कुमारी, गृहिणी

यह बजट व्यावहारिक कम और दिखावे का प्रदर्शन ज्यादा है। ऐसा इसलिए, क्योंकि पिछली बार भी बजट का बड़ा हिस्सा खर्च नहीं हुआ, जिसकी ओर कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव ने भी इशारा किया है। उनके मुताबिक, पिछले साल राजस्व लक्ष्य पूरे नहीं हो पाए, जिससे आर्थिक स्थिति कमजोर हुई। उनका कहना है, संशोधित आंकड़े यही बताते हैं कि सरकार राजस्व जुटाने में पूरी तरह से विफल रही और राजकोषीय घाटा 22 प्रतिशत से अधिक पहुंच गया। इसका मतलब है कि वित्तीय अनुशासन के नियमों का जबर्दस्त उल्लंघन हुआ है। इतना ही नहीं, इस बार जो घोषणाएं की गई हैं, उनके लिए पैसे किस तरह जुटाए जाएंगे, इसका भी स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया है। दिल्ली की सरकार को समझना चाहिए कि लोग अब घोषणाओं को तथ्यों की कसौटी पर कसते हैं। अगर उनको लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, तो वे मुखर होने में भी संकोच नहीं करते।

सुमन कुमार, टिप्पणीकार

मोबाइल फोन निर्माण में नई मंजिलें

भारत में मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग पिछले 5 वर्षों में 13 लाख से ज्यादा नौकरियां सृजित कर चुका है। खास मोबाइल फोन इंडस्ट्री में हार्डवेयर डिजाइनिंग, चिप मेकिंग और असेंबली तक नई तकनीक से जुड़े कौशल अहम हो गए हैं। कैसे? जानकारी दे रहे हैं करिअर कोच सोनिक सौरभ

देश का मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम पिछले एक दशक में तेजी से उभरकर वर्तमान में 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का हो गया है। हाल के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2024-25 में मोबाइल उत्पादन लगभग 5.4-5.5 लाख करोड़ रुपये और निर्यात करीब 2 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इस सेक्टर ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 12-15 लाख रोजगार सृजित किए हैं, जो पीएलआई, स्पेक्स और मेक इन इंडिया जैसी नीतियों के चलते 2028 तक 25-30 लाख तक पहुंचने का अनुमान है।

एक अनुमान के अनुसार 25 फीसदी से ज्यादा आईफोन 2030 तक भारत में बन रहे होंगे। जैसे-जैसे यह इंडस्ट्री बढ़ रही है, कंपनियों को ऐसे पेशेवरों की जरूरत है, जो मशीनों और उत्पादन प्रक्रिया की समझ रखें, प्रोडक्शन लाइन संभाल सकें, गुणवत्ता बनाए रखें और नई तकनीकों को तेजी से अपनाएं।

मैन्युफैक्चरिंग में भारत की बढ़त

भारत अब केवल फोन असेंबली तक सीमित नहीं है, बल्कि कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन की ओर भी तेजी से बढ़ रहा है। इससे युवाओं के लिए नए अवसर बन रहे हैं। सरकारी योजनाओं के चलते एपल, सैमसंग, फॉक्सकॉन, डिक्सॉन और लावा जैसी कंपनियों ने भारत में बड़े स्तर पर उत्पादन शुरू किया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, चेन्नई, श्रीपेरंबुदूर, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे क्षेत्र मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के प्रमुख हब बन चुके हैं, जहां रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध हैं।

कौन-कौन से करिअर विकल्प

शुरुआत में प्रोडक्शन इंजीनियर, क्वालिटी इंजीनियर, टेस्ट इंजीनियर, एसएमटी (सर्फेस माउंट टेक्नोलॉजी) ऑपरेटर और सप्लाई चेन एग्जीक्यूटिव जैसी भूमिकाएं मिलती हैं। अनुभव के साथ प्रोसेस इंजीनियर, ऑटोमेशन इंजीनियर, ऑपरेशंस मैनेजर और प्रोडक्ट मैनेजर जैसे पदों तक पहुंच सकते हैं। आगे चलकर प्लांट हेड, मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्टर और सप्लाई चेन स्ट्रेटेजिस्ट जैसी वरिष्ठ भूमिकाओं में रणनीतिक फैसले लेने की जिम्मेदारी होती है।

योग्यता और अनिवार्य कौशल

पीसीएम के साथ 12वीं इस क्षेत्र में अच्छा आधार देती है। इसके बाद बीटेक/बीई (इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मेक्ट्रॉनिक्स, प्रोडक्शन), डिप्लोमा या बीएससी (इलेक्ट्रॉनिक्स) जैसे विकल्प चुने जा सकते हैं। हालांकि, आज सिर्फ डिग्री काफी नहीं है। एसएमटी लाइन ऑपरेशन, पीसीबी असेंबली, ऑटोमेशन, इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स, सिक्स सिग्मा, एसएपी/ईआरपी और बेसिक डाटा एनालिटिक्स जैसे कौशल जरूरी हैं। ये स्किल्स मशीनों के संचालन, प्रोडक्शन को बेहतर बनाने और डाटा के जरिए काम को अधिक कुशल बनाने से जुड़े हैं और इनकी इंडस्ट्री में काफी मांग है।

इंटर्नशिप और शुरुआती अनुभव : इंडस्ट्री में एंट्री के लिए इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप अहम भूमिका निभाती हैं। छात्र मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों, ईएमएस कंपनियों या स्किल ट्रेनिंग सेंटर के जरिए शुरुआती अनुभव ले सकते हैं। इससे प्रैक्टिकल समझ बढ़ती है और नौकरी मिलने की संभावना भी मजबूत होती है।

स्किल बढ़ाने के रास्ते

इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में कौशल बढ़ाने के लिए बिट्स पिलानी द्वारा स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, सी-डैक के एम्बेडेड सिस्टम्स और हार्डवेयर कोर्स, तथा नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल के प्रोग्राम्स उपयोगी और इंडस्ट्री रेडी विकल्प हैं।

कितना मिलेगा वेतन

मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में विशेष रूप से वैश्विक कंपनियों में काम करने से बेहतर एक्सपोजर और तेजी से करिअर में आगे बढ़ना संभव है, क्योंकि यहां प्रोसेस, टेक्नोलॉजी और स्केल तीनों ही बड़े स्तर पर होते हैं। इस क्षेत्र में एंट्री लेवल पर औसत वेतन 3 से 8 लाख रुपये सालाना तक होता है। 3 से 6 वर्ष के अनुभव पर यह 8 से 18 लाख रुपये तक पहुंच सकता है। ऑपरेशंस और सप्लाई चेन से जुड़ी वरिष्ठ भूमिकाओं में 25 लाख से 60 लाख रुपये या उससे अधिक का पैकेज संभव है।

कुछ महत्वपूर्ण संस्थान और संबंधित पाठ्यक्रम

- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के विभिन्न केंद्र, इनमें एम. टेक इन इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, बी.एस. इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, एम. टेक इन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और वीएलएसआई, एम. टेक इन आरएफ और माइक्रोवेव इंजीनियरिंग जैसे कोर्स इस क्षेत्र के बड़े पदों पर सीधे पहुंचने का रास्ता बनेंगे। कुछ अन्य कोर्स हैं :
- **सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत :** एम. टेक इन वीएलएसआई और एम्बेडेड सिस्टम: svnit.ac.in
- **नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (एनआईईएलआईटी) :** पीसीबी डिजाइन आदि, nielit.gov.in
- **प्रधानमंत्री कौशल केंद्र (पीएमकेके) :** मोबाइल रिपेयरिंग और अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण कोर्स nsdcindia.org/pmkk

कैसे मिलेगा प्रवेश : प्रवेश के लिए बीटेक या बीएस कोर्स में दाखिले हेतु जेईई मेन और जेईई एडवांस्ड जैसी परीक्षाएं देनी होंगी। एमटेक के लिए गेट जैसी प्रवेश परीक्षाएं देनी होती हैं। वहीं, पीएमकेके और एनआईईएलआईटी में मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स के लिए 10वीं/12वीं पास छात्र आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद सेंटर पर दाखिला मिलता है।

सेमीकंडक्टर स्किल की मांग

डिजिटल युग में सेमीकंडक्टर उद्योग को 'भविष्य की रीढ़' माना जाता है। मोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग से लेकर स्पेस टेक्नोलॉजी तक माइक्रोचिप्स की अहम भूमिका है। युवाओं के लिए यह क्षेत्र उच्च कौशल, अच्छा वेतन और निरंतर प्रगति वाला करिअर बन रहा है। चिप विशेषज्ञों की मांग भी तेजी से बढ़ रही है और अनुमान है कि 2030 तक वैश्विक स्तर पर इस कौशल के दस लाख लोगों की जरूरत बनेगी।

कोर्स : छात्र बीटेक या बीई (इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स, वीएलएसआई डिजाइन या सेमीकंडक्टर इंजीनियरिंग) जैसे कोर्स चुन सकते हैं, जो चिप डिजाइन, एम्बेडेड सिस्टम, सर्किट डिजाइन और माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी की गहन समझ विकसित करते हैं। इसके अतिरिक्त बीएससी (इलेक्ट्रॉनिक्स/ नैनोटेक्नोलॉजी/ माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स) जैसे कोर्स भी इस क्षेत्र में प्रवेश के लिए उपयुक्त विकल्प हैं।

25-30
लाख तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बनने का अनुमान है 2028 तक पीएलआई, स्पेक्स और मेक इन इंडिया जैसी नीतियों के चलते, मोबाइल फोन मैन्यूफैक्चरिंग इकोसिस्टम में।

जॉब/करिअर

- सशस्त्र सीमा बल (गृह मंत्रालय, भारत सरकार) में कॉन्स्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन किए जा रहे हैं। इसके तहत कॉन्स्टेबल ड्राइवर, गार्डनर आदि पद भरे जाएंगे। आवेदन ऑनलाइन करना होगा।

कुल पद : 827
अंतिम तिथि: 20 अप्रैल 2026
आवेदन प्रक्रिया : एसएसबी की वेबसाइट **ssb.gov.in** पर लॉगइन करें।

- मध्य प्रदेश लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट सोसायटी, भोपाल में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद रिक्त हैं। नियुक्ति अनुबंध के आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन करना होगा।

कुल पद : 770
अंतिम तिथि: 03 अप्रैल 2026
आवेदन प्रक्रिया : संबंधित वेबसाइट है- **chayan.mponline.gov.in**

- बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल जज (जूनियर डिविजन) के पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं।

कुल पद: 173
अंतिम तिथि: 30 अप्रैल 2026
आवेदन प्रक्रिया : आयोग की वेबसाइट है- **bpsc.bihar.gov.in**

- जनपद आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश) में संविदा के आधार पर आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों की भर्तियां की जाएंगी। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट या समकक्ष होगी।

कुल पद : 159
अंतिम तिथि: 15 अप्रैल 2026
आवेदन प्रक्रिया : ऑनलाइन। वेबसाइट है- **upanganwadibharti.in**

- सशस्त्र सीमा बल, भारत सरकार में हेड कॉन्स्टेबल के विभिन्न पदों (इलेक्ट्रिशियन, वेटरिनरी आदि) पर ऑनलाइन आवेदन करने का मौका है।

कुल पद : 233
अंतिम तिथि: 20 अप्रैल 2026
आवेदन प्रक्रिया : सशस्त्र सीमा बल की आधिकारिक वेबसाइट है -**ssb.gov.in**

- महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, ओडिशा में जूनियर ओवरमैन, टेक्नीशियन, अनुवादक समेत अन्य पदों पर ऑनलाइन आवेदन करने का अवसर है।

कुल पद : 667
अंतिम तिथि: 06 अप्रैल 2026
आवेदन प्रक्रिया : एमसीएल की वेबसाइट **mahanadicoal.in** पर जाएं।

- इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्राइवेट सेक्रेटरी ग्रेड-I के पदों पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है। मान्यता प्राप्त संस्थान से लॉ की डिग्री होना अनिवार्य होगा।

कुल पद : 195
अंतिम तिथि: 01 अप्रैल 2026
आवेदन प्रक्रिया: कोर्ट की वेबसाइट है- **allahabadhighcourt.in**

(नोट :आवेदन करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट से अपने स्तर पर जांच कर लें।)

उर्दू जुबान में मौकों की कमी नहीं

एक्सपर्ट टिप्स

डॉ. संजीब कुमार आचार्य
सीनियर करिअर काउंसलर

■ मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से उर्दू मेजर सब्जेक्ट से बीए कर रहा हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि भविष्य में मेरे लिए उर्दू मेजर विषय में कोई स्कोप है या नहीं?
-अबू जायद

उर्दू में बीए करने के बाद आपके लिए करिअर के अच्छे अवसर हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी कौशल विकसित करना और उच्च शिक्षा लेना अहम है। अगर आप दीर्घकालिक स्थिर करिअर चाहते हैं, तो एमए, नेट/जेआरएफ करके लेक्चरर, प्रोफेसर या शिक्षक बन सकते हैं। स्कूल, कॉलेज और मदरसों में उर्दू शिक्षकों की अच्छी मांग है। ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन भी मजबूत क्षेत्र है। सरकारी दफ्तरों, अदालतों, पब्लिशिंग और मीडिया में उर्दू जानने वालों की जरूरत होती है। आप पत्रकारिता, कंटेंट राइटिंग और डिजिटल मीडिया में भी काम कर सकते हैं, खासकर उर्दू अखबार और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में। सरकारी नौकरियों में भी भाषा कौशल काम आता है। आर्काइव, संस्कृति मंत्रालय और पब्लिक रिलेशंस जैसे विभागों में उर्दू विशेषज्ञों की जरूरत होती है। इसके अलावा रिसर्च, कैलिग्राफी, स्क्रिप्ट राइटिंग और साहित्य से जुड़े करियर भी विकल्प हैं। करिअर को मजबूत बनाने के लिए अंग्रेजी, कंप्यूटर, कंटेंट राइटिंग और डिजिटल स्किल्स सीखना जरूरी है। उर्दू को मास कम्युनिकेशन, कानून या सिविल सर्विस की तैयारी के साथ जोड़ने से अवसर और बढ़ जाते हैं। इसलिए उर्दू में स्कोप है, लेकिन सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपनी भाषा के साथ आधुनिक और रोजगारपरक कौशल कितनी समझदारी से जोड़ते हैं।

■ मैं ग्यारहवीं का छात्र हूं। आईआईटी परीक्षा की तैयारी के लिए आपका मार्गदर्शन चाहता हूं। क्या एक साल की तैयारी से ही आईआईटी की परीक्षा पास करना संभव है?
-आशुतोष मौर्य

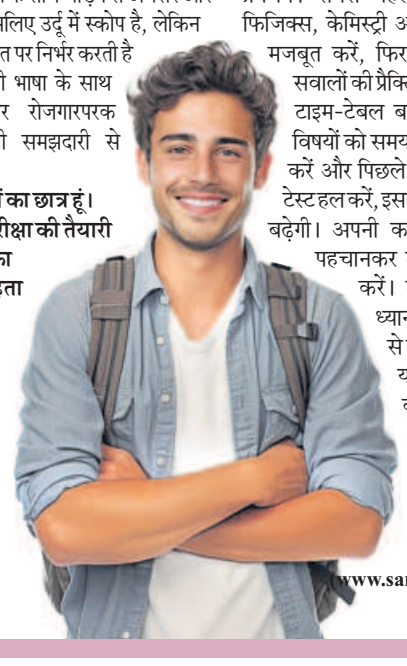

एक साल में आईआईटी-जेईई की तैयारी चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन सही रणनीति और मेहनत से इसे हासिल किया जा सकता है। समय की चिंता छोड़कर सकारात्मक सोच के साथ तैयारी शुरू करें। सफलता की कुंजी है- कॉन्सेप्ट की मजबूत समझ, नियमित अभ्यास और समय प्रबंधन। सबसे पहले एनसीईआरटी से फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के बेसिक्स मजबूत करें, फिर एडवांस लेवल के सवालों की प्रैक्टिस करें। एक संतुलित टाइम-टेबल बनाएं और रोज तीनों विषयों को समय दें। नियमित रिवीजन करें और पिछले वर्षों के पेपर व मॉक टेस्ट हल करें, इससे स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगी। अपनी कमजोरियों को जल्दी पहचानकर उनपर लगातार काम करें। मोबाइल और अन्य ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहें। अच्छे शिक्षक या किसी भरोसेमंद कोचिंग का मार्गदर्शन आपकी तैयारी को बेहतर बना सकता है और एक साल में ही सफलता दिला सकता है।

(www.sanjibacharya.com)

कैसा होना चाहिए आज का रिज्यूमे

रिज्यूमे अब सिर्फ जानकारी का दस्तावेज नहीं रहा, बल्कि यह आपकी सोच, कार्यशैली और टीम में आपके वास्तविक योगदान को प्रभावी ढंग से पेश करता है। यही बदलाव दर्शाता है कि पुराने रिज्यूमे को अधिक असरदार व करिअर केंद्रित बनाना क्यों जरूरी है।

करिअर टिप्स

बदलते कामकाजी माहौल में अपनी योग्यता को प्रभावी ढंग से पेश करना जरूरी है। वजह है कंपनियों का प्रोजेक्ट्स में योगदान और समस्या समाधान जैसे कौशलों पर ध्यान देना। इस कारण रिज्यूमे में अब कुछ परिवर्तन किए जाने लगे हैं-

- **डिजिटल प्रोफाइल :** कंपनियां गिटहब, बेहांस या लिंक्डइन जैसी प्रोफाइल भी देखती हैं, जहां आपके असल प्रोजेक्ट्स और कौशल साफ नजर आते हैं। इसलिए इनके लिंक रिज्यूमे में डालना जरूरी है।
- **कौशल पर जोर :** रिज्यूमे में अपना प्रोजेक्ट योगदान, तकनीकी ज्ञान और इंटर्नशिप या फ्रीलांस अनुभव दिखाएं। इससे प्रोफाइल नियोक्ता की नजरों में असरदार व भरोसेमंद लगेगी।
- **डिजिटल टूल्स की जानकारी :** एआई, एसईओ, डिजाइन टूल्स जैसी आधुनिक तकनीकों का प्रयोग दिखाएं। यह प्रोफाइल को आधुनिक और पेशेवर दिखाता है।
- **कीवर्ड्स और एटीएस :** रिज्यूमे एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम से भी स्कैन होते हैं। इसलिए सही कीवर्ड्स समरी, स्किल्स और एक्सपीरियंस में शामिल करें, ताकि यह आसानी से शॉर्टलिस्ट हो सके।

-श्वेता राकेश

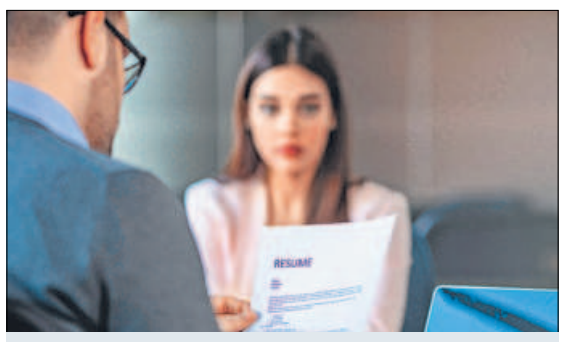

पुराने और नए रिज्यूमे में अंतर

■ पहले रिज्यूमे की शुरुआत में लंबा प्रोफाइल परिचय लिखा जाता था। अब छोटा और सीधा प्रोफाइल सारांश पर्याप्त है। ■ पहले केवल शिक्षा और काम का विवरण पर्याप्त था, अब कौशल, प्रोजेक्ट्स और डिजिटल अनुभव मायने रखते हैं। ■ अब बहुत गहन निजी जानकारी, जैसे-जन्मतिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति आदि जरूरी नहीं रहे। ■ टाइम्स न्यू रोमन या एरिअल जैसे फॉन्ट के बजाय पढ़ने में आसान फॉन्ट व स्पष्ट लेआउट चलन में हैं।

भेजें अपना सवाल

करिअर या शैक्षिक कोर्स संबंधी आपके मन में कोई उलझन है या कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें अपने सवाल नीचे दी गई ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ उसके जवाब देंगे। इस ईमेल आईडी का उपयोग करें
nayiraheincareer@gmail.com

रोजनामचा

पं. राघवेन्द्र शर्मा
ज्योतिषाचार्य

स्कैन करें
भविष्यफल और व्रत-त्योहार जानने के लिए

मेष : मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। संयत रहें। दांपत्य सुख में वृद्धि होगी। नौकरी में बदलाव के साथ तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। आय में भी वृद्धि होगी।

वृष : मन परेशान हो सकता है। आत्मविश्वास में कमी रहेगी। धैर्यशीलता बनाए रखने का प्रयास करें। कारोबार में भागदौड़ अधिक रहेगी। लाभ के अवसर मिलेंगे।

मिथुन : मन में शांति और प्रसन्नता रहेगी। दांपत्य सुख में वृद्धि होगी। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। कारोबार में वृद्धि होगी। लाभ के अवसर मिलेंगे।

कर्क : आत्मविश्वास में कमी रहेगी। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं। पिता की सेहत का ध्यान रखें। भागदौड़ की अधिकता रहेगी।

सिंह : मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। आत्मविश्वास में कमी रहेगी। संयत रहें। नौकरी में अफसरों का सहयोग तो मिलेगा, परंतु कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकता है।

कन्या : आत्मविश्वास में कमी रहेगी। मन परेशान रहेगा। आत्मसंयत रहें। व्यर्थ के क्रोध से बचें। पिता की सेहत का ध्यान रखें। भागदौड़ अधिक रहेगी। खर्च बढ़ेंगे।

तुला : आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, परंतु धैर्यशीलता में कमी हो सकती है। संयत रहें। कला और संगीत के प्रति रुझान बढ़ सकता है। सेहत का ध्यान रखें।

वृश्चिक : आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे, परंतु मन अशांत हो सकता है। धैर्यशीलता बनाए रखें। अपनी भावनाओं को वश में रखें। परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं।

धनु : मन प्रसन्न रहेगा। आत्मविश्वास भी भरपूर रहेगा। किसी मित्र के सहयोग से आय में वृद्धि हो सकती है। कारोबार में वृद्धि होगी। भागदौड़ अधिक रहेगी।

मकर : संयत रहें। धैर्यशीलता बनाए रखें। जीवनसाथी की सेहत का ध्यान रखें। माता-पिता का साथ मिलेगा। कारोबार के विस्तार के लिए माता से धन प्राप्त होगा।

कुंभ : मन परेशान रहेगा। आत्मसंयत रहें। धैर्यशीलता बनाए रखें। किसी मित्र के सहयोग से आय वृद्धि हो सकती है। परिवार के किसी बुजुर्ग से धन मिल सकता है।

मीन : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, परंतु संयत रहें। परिवार की सेहत का ध्यान रखें। पिता का साथ मिलेगा। किसी मित्र के सहयोग से आय में भी वृद्धि हो सकती है।

व्रत और त्योहार | पंचांग | पं. ऋषिकांत गोस्वामी

26 मार्च, गुरुवार, **शक संवत्:** 05, चैत्र, (सौर) 1948, **पंजाब पंचांग:** 13, चैत्र मास प्रविष्टे 2083 **इस्लाम:** 06, शव्वाल, 1447 **विक्रमी संवत्:** चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि प्रात: 11.49 मिनट तक पश्चात नवमी तिथि, आद्रा नक्षत्र सायं 04.19 मिनट तक पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र, शोभन योग रात्रि 12.32 मिनट तक। चंद्रमा मिथुन राशि में (दिन रात)। **सूर्य उत्तरायण।** दोपहर 01.30 मिनट से अपराह्न 03 बजे तक राहुकालम्। दुर्गाष्टमी। रामनवमी व्रत (स्मार्त) मध्याह्न व्यापिनी नवमी कर्क लग्न में। श्री राम जन्म महोत्सव।

वास्तु सलाह | आचार्य मुकुल रस्तोगी

हमने एक फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन खरीदी है, लेकिन हम उस पर फैक्ट्री लगा नहीं पा रहे हैं। कुछ सरकारी व्यवधान भी आ रहा है।
-हर्षित पुंज, रांची

- आपकी जमीन पूर्व मुखी है, जो दिशा के अनुसार शुभ है, किंतु उसका ढलान अग्नि कोण की ओर है, यह अच्छा नहीं होता और कई बार कानूनी समस्या कर सकता है।
- ढाल को पूर्व दिशा की ओर करें। भूमि में कुछ दिन लगातार कमलगट्टे डालें। संभव हो तो कुछ दिन वहां पर गाय रखें। इसके अग्नि कोण में लगातार कुछ दिन किसी बर्तन में अग्नि जलाएं। दक्षिण दिशा में लाल रंग की कोई वस्तु रखें। प्लॉट की उत्तर पूर्व दिशा में तुलसी का जोड़े से पौधा लगाएं। गुरुवार को एक पौधा ब्रह्मस्थान पर भी लगाएं।

वर्ग पहेली : 8279

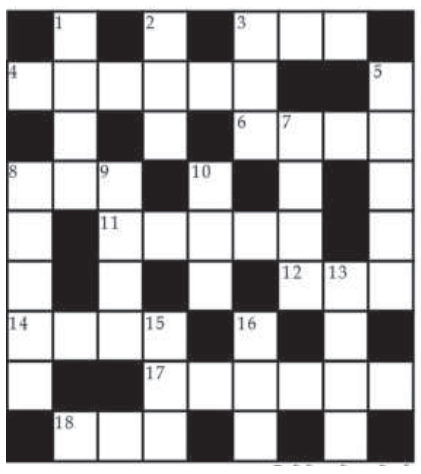

बाएं से दाएं
3. द्रव पदार्थ में क्रिया करके तरल और सार भाग को अलग करना; विदीर्ण करना; टुकड़े करना (3)
4. झंकार; झन झन की आवाज; झुनझुनी (6)
6. अल्पवयस्क; कम उम्र का; छोटी अवस्था का (4)
8. अवयव; भागीदार; हिस्से; वे दल जिनके मेल से नया संयुक्त दल बना हो (3)
11. कोई पता ठिकाना न होना; गायब होना; लुप्त होना (3,2)
12. कसना; जकड़ना; गांठना (3)
14. अफसोस; रंज; चाह; लालसा; हार्दिक इच्छा (4)
17. किसी क्षेत्र में पहला काम करना; शुरुआत करना (3,3)
18. भरना; लीन होना; समा जाना (3)

ऊपर से नीचे
1. पानी भरने का घाट (4)
2. भूनने का काम कराना; बड़े नोट को छोटे रुपयों में बदलवाना (3)
3. बड़ा दरवाजा; तोरण; सिंहद्वार (3)
5. घोड़े जैसी आवाज निकालना; हींसना (5)
7. अजगर; बड़ा सांप (4)
8. घबराने का भाव; अधीरता; उद्विग्नता; किंकर्तव्यविमूढ़ता; बेचैनी; हड़बड़ी (5)
9. चौंसठ कलाओं में से किसी भी कला का ज्ञाता; अभिनेता; चित्रकार; रचनाकार (4)
10. कष्ट पहुंचाना; तंग करना; दिल दुखाना (3)
13. अध्यक्षता; सभापतित्व; सदर का पद (4)
15. आंच से गरम होना; तपस्या करना (3)
16. अंतर मिटना; साथ लगना; भेंट होना (3)

हरीश चन्द्र सन्सी, विविधा विधा, दिल्ली
(उत्तर अगले अंक में)

वर्ग पहेली : 8278

	1स		2क	ठो	र	3प्र	या	4स
5ब	द	ना	मी			णा		म्मा
	र		6ज	7न	स	म	र्थ	न
8मा		9र		ग		क		क
10ल	र	ज	ना		11बा	र	बा	र
अ		त		12रा		ना		ना
13से	क	प	का	जा	14ना		15आ	
बा		द			16च	ट	का	ना
17ब	र	क	त	हो	ना		र	

सुडोकू : 8261 *आसान

		8	9		3	4		
		4	2		5	3		
5								6
	1		7		9		2	
2				1				3
	3		6		2		4	
3								7
		2	3		8	1		
		1	4		7	5		

खेलने का तरीका : दिमागी खेल और नंबरों की पहेली है यह। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएं। साथ ही 3x3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहेली का हल हम कल देंगे।

सुडोकू : 8260

7	4	6	2	9	3	8	5	1
8	3	9	5	4	1	7	6	2
5	2	1	7	8	6	3	4	9
2	5	4	6	7	8	1	9	3
1	6	3	9	2	4	5	7	8
9	7	8	3	1	5	4	2	6
4	8	2	1	5	9	6	3	7
6	1	7	4	3	2	9	8	5
3	9	5	8	6	7	2	1	4